वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक 4

भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2011

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट की फीडबैक **fsu@rbi.org.in** पर दी जा सकती है।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा एल्को कॉर्पोरेशन, ए2/73, शाह एंड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई- 400013 में मुद्रित।

प्रस्तावना

वैश्विक वृद्धि में मंदी की संभावना की पृष्ठभूमि में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों की उल्लेखनीय अनिश्चितता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल-पुथल के दौर में है। दूसरी ओर, हमारे जैसे विकासशील बाजारों के सामने अकस्मात पूंजीगत बहिर्वाहों का जोखिम है तथा/या निधीयन मूल्यों में वृद्धि का जोखिम है। इन दोनों ही से देशी अर्थव्यवस्था की स्थिरता को खतरा हो सकता है।

देशी क्षेत्र में, वृद्धि-मुद्रास्फीति के प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 2011-12 में वृद्धि के मंद हो जाने की आशंका है जबकि मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं उच्च बनी हुई हैं, हालांकि हाल ही में स्फीतिकारक दबावों में कुछ सहजता आने के संकेत भी हैं। उच्च वैश्विक एनर्जी मूल्यों के कारण देश की बाह्य स्थिति पर लगातार दबाव बना हुआ है। विनिमय दर में तीव्र कमी के कारण एक बार फिर रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति पर ध्यान केंद्रित हो गया है। राजकोषीय लक्ष्यों के पूरा न होने के कारण देशी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गए हैं। अनिश्चित वैश्विक परिवेश तथा देशी प्रतिकूल परिस्थितियों ने देशी वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल बढ़ा दी है।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र मजबूत तथा गतिशील बना हुआ है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और वे अत्यधिक रूप से लीवरेज भी नहीं हैं। बासल III के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा कुछ बड़े बैंकों द्वारा बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने से विनियामक पूंजी का बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम प्रोफाइल के साथ समरूपता में सुधार होगी। आस्ति की गुणवत्ता को लेकर कुछ चिंता अभी भी है हालांकि उन्नत या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करें तो भारतीय बैंकों के एनपीए अनुपात अनुकूल हैं। आस्ति गुणवत्ता में निहित प्रवृत्तियों तथा कुछ क्षेत्रों में अत्याधिक ऋण वृद्धि के बारे में रिज़र्व बैंक सजग है और एक सकारात्मक प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए प्रयत्नशील है।

एफएसडीसी के कार्यरत हो जाने के एक साल बाद, उसकी उप समिति काउंसिल की प्राथमिक परिचालन शक्ति के रूप में सामने आई है जबकि स्वयं काउंसिल समग्र पर्यवेक्षण करती है। उप समिति प्रणाली में स्थिरता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जबकि वह काउंसिल के मैंडेट के अनुरूप बेहतर अंतर-विनियामक समन्वयन तथा और अधिक वित्तीय समावेशन तथा साक्षरता लाने के लिए प्रयत्नशील है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का यह चौथा अंक है। प्रत्येक अंक में वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिमों के आकलन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है - कवरेज में भी और प्रणालीगत जोखिम को मापने और उनके निर्धारण में विश्लेषणात्मक साधनों के बारे में भी।

एफएसआर के इस अंक में, पहली बार, प्रणालीगत स्थिरता के बारे में जोखिमों के संबंध में एफएसडीसी की उप-समति के सामूहिक विचार दिए गए हैं। इसलिए, उम्मीद है कि यह अंक पिछले अंकों की तुलना में वित्तीय प्रणाली के सम्मुख जोखिमों का कुछ और संपूर्ण आकलन प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट को कुछ अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों-सेबी, आइआरडीए तथा पीएफआरडीए के विचारों से लाभ पहुंचा है और एफएसडीसी की उप समिति के सदस्यों की टिप्पणियों से इसमें और निखार आया है।

बाजार के सहभागियों और हितधारकों के विभिन्न वर्गों के विचारों को ध्यान में रख कर, रिज़र्व बैंक द्वारा पहला प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण प्रारंभ करने से प्रणालीगत जोखिम आकलन समृद्ध हुआ है। पहले के विश्लेषण में और सुधार किया गया है - नेटवर्क विश्लेषण माडल में गैर - बैंक संस्थाएं शामिल कर ली गई हैं; रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में स्थिरता संकेतकों को जोड़ते हुए एक संपूर्ण संकेतक तैयार किया गया है जो वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिमों की दिशा उपलब्ध कराता है; और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खंडों की गतिशीलता का आकलन करने के लिए कई सिंगल फैक्टर सेंसिटिविटी स्ट्रैस टैस्ट और मैक्रो फाइनैन्शियल टैस्ट किए गए हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट तथा उसके प्रभाव से यह स्पष्ट हो गया है कि 'जोखिम' सर्वव्यापी है और, अक्सर, पहले से उसके प्रभाव के बिंदु का पता लगाना मुश्किल होता है। एफएसआर के पहले के किसी अंक में, मैने केंद्रीय बैंकरों के काम की तुलना एक बहुत बड़े पत्थर को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने में सिसीफस के काम से की थी क्योंकि पत्थर नीचे आना ही है। मैं फिर से सिसीफस का उल्लेख करना चाहूंगा। इस बार चोरी कर रहे अपने पड़ोसी, आटोलिकससे* जो अपने मवेशियों के खुरों के नीचे निशान लगा देता था ताकि मिट्टी में उनके जाने का रास्ता पता चल सके। इसलिए, यदि जोखिम के गंतव्य स्थान का पता नहीं चल सकता, तो हमें उसके मार्ग तथा यात्रा का पता लगाना चाहिए ताकि भविष्य में जोखिमों की चेतावनी दी जा सकें।

डॉ. डी. सुब्बाराव
22 दिसंबर, 2011

* गुडहार्ट, सीएई (2004): 'सम न्यू डायरेक्शन्स फार फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी'

विषय वस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	
चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची	**i – ii**
विहगावलोकन	**1**
अध्याय I : समष्टि आर्थिक परिदृश्य	**6**
अध्याय II : वित्तीय बाज़ार	**15**
अध्याय III : वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और लचीलापन	**26**
अध्याय IV : वित्तीय क्षेत्र का विनियमन और बुनियादी सुविधाएं	**45**
अध्याय V : प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन	**62**
प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	63
प्रणालीगत चलनिधि सूचक	65
नेटवर्क विश्लेषण	67
बैंकिंग स्थिरता संबंधी उपाय	72
समष्टिगत वित्तीय दबाव परीक्षण	74
परिशिष्ट :कार्यविधियाँ	77

बॉक्स की सूची

2.1	भारतीय इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेशकों और म्युचुअल फंडों के व्यापार का रुख	23
3.1	यूरो क्षेत्र संकट और भारतीय बैंकों पर प्रभाव	27
3.2	बिजली और दूरसंचार क्षेत्र में बाधाएं और पुनर्गठन वृद्धि	32
3.3	बैंकों की बचत ब्याज दरों का अविनियमन : एक विश्लेषण	34
4.1	डाइनैमिक प्रावधानीकरण	49
4.2	प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक (जी-एसआईबी) के लिए प्रस्तावित नीतिगत सुधार	50
4.3	आभासी बैंकिंग	54
5.1	नेटवर्क विश्लेषण अवधारणाएं	69

चार्ट की सूची

1	वित्तीय स्थिरता मैप	1
2	वित्तीय स्थिरता संकेतक	1
1.1	समष्टि आर्थिक स्थिरता मैप	6
1.2	समष्टि आर्थिक स्थिरता संकेतक	6
1.3	यूएस और यूरोप के पीएमआई	7
1.4	चीन और यूएस का व्यापार संतुलन	7

		पृष्ठ सं.
1.5	सोवरीन ऋण और उधार उच्च बना रहा	8
1.6	बाहरी क्षेत्र भेद्यता सूचक	8
1.7	बाहरी क्षेत्र दबाव	9
1.8	विभिन्न क्षेत्रों में मंदी	9
1.9	स्थिरता/ मंदी दर्शाता पीएमआई	9
1.10	घरेलू मांग घटकों में मंदी	10
1.11	भारत तथा विश्व के अन्य देशों में मुद्रास्फीति	10
1.12	भारत तथा विश्व के अन्य देशों में खाद्य सामग्री तथा ऊर्जा में मुद्रास्फीति	10
1.13	राजकोषीय दबाव सूचकांक में उछाल	11
1.14	ब्याज लागत में उछाल एवं लाभ में गिरावट	12
1.15	औद्योगिक क्षेत्र का परिदृश्य	13
1.16	रिटेल ऋण और रिटेल एनपीए के अनुपात में बढ़ोतरी	13
1.17	अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक	14
1.18	आवास ऋण और आवास एनपीए अनुपात में बढ़ोतरी	14
2.1	वित्तीय बाज़ार स्थिरता मानचित्र	15
2.2	वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक	15
2.3	सोवरीन सीडीएस मूल्य 5 वर्ष-परिपक्वता	16
2.4	सोवरीन सीडीएस मूल्य 5 वर्ष-परिपक्वता	16
2.5	अमरीका, यूरोप और भारत में इक्विटी बाज़ार आधारित सूचकांक में अस्थिरता	16
2.6	विभिन्न एजेसियों द्वारा यूरोप की सोवरीन रेटिंग	17
2.7	यूरोपियन बृहत एवं बैंक स्टॉक सूचकांक	17
2.8	यूरो और अमरीकी डालर में लिबोर-ओआइएस स्प्रेड	17
2.9	बाह्य वाणिज्यिक उधार के साथ जमा शेष	17
2.10	2011 में वित्तीय संस्थागत निवेशक द्वारा निवल खरीद और भारतीय रुपया	18
2.11	चालू और पूंजी खाता निवल प्रवाह	18
2.12	विविध परिपक्वता में सरकारी प्रतिभूतियों पर आय	19
2.13	ईसीबी और एफसीसीबी की परिपक्वताएं	19
2.14	भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति	20
2.15	विदेशी मुद्रा व्याप्ति अनुपात	20
2.16	बाह्य घाटा वाली मुद्राएं और व्यापक मुद्रा सूचकांक	21
2.17	यूएस$/भारतीय रुपये के तीन और छह माह की परिपक्वता अवधि में आफशोर और आनशोर वायदा दर में अंतर	21
2.18	जुलाई अंत में अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया हेतु विश्लेषक पूर्वानुमान का विस्तार	21

पृष्ठ सं.

2.19	विभिन्न बाजारों का ऐतिहासिक उतार- चढाव	22
2.20	इक्विटी में नकदी बनाम व्युत्पन्न कुल बिक्री और उनका अनुपात	22
2.21	नकदी इक्विटी में व्यापार का विन्यास	22
2.22	व्युत्पन्न इक्विटी में व्यापार का विन्यास	22
2.23	निफ्टी लाभ बनाम विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवल बिक्री	23
2.24	निफ्टी लाभ बनाम निवल संस्थागत गतिविधि	23
2.25	ओआइएस में व्यापार की संख्या और मात्रा	24
2.26	ओआइएस में व्यापार की संख्या और बकाया कल्पित आय	24
3.1	संबंधित देश के सांकेतिक एकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में यूरोपीय बैंकों के समेकित विदेशी दावे	27
3.2	भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं (सहायक संस्थाओं सहित) का हिस्सा-सितंबर 2011	27
3.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चयनित तुलन पत्र मदों की वृद्धि दर	28
3.4	तुलनपत्र में शामिल और इतर आस्तियों में बैंक समूहों का हिस्सा - सितंबर 2011	28
3.5	बैंकिंग स्थिरता मैप	29
3.6	बैंकिंग स्थिरता संकेतक	29
3.7	बैंक समूहों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	29
3.8	विभिन्न देशों में बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	29
3.9	सकल ऋणों व अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों और स्लिपेज की वृद्धि दर की प्रवृत्ति	30
3.10	सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर छमाहियों में	30
3.11	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात - अन्य देशों की तुलना में	30
3.12	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात बनाम प्रावधान कवरेज अनुपात-अन्य देशों की तुलना में	30
3.13	सकल बैंकिंग प्रणाली ऋण और अनर्जक आस्तियों में क्षेत्रवार हिस्सा - सितंबर 2011	31
3.14	अनर्जक आस्तियों और ऋण की वृद्धि दर - सितंबर 2011	31
3.15	बिजली और दूरसंचार का योगदान	32
3.16	बैंक दल के बीच एक्सपोजर का संवितरण	32
3.17	बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों को बकाया बैंक क्रेडिट के हिस्से के रूप में अनर्जक और पुनर्गठित लेखे	32
3.18	बिजली क्षेत्र में बैंकऋण का अलग-अलग विवरण	32
3.19	बिजली क्षेत्र और इसके संघटकों को दिए गए ऋण की वृद्धि दर	32
3.20	उपार्जन के संघटकों की वृद्धि दर	33
3.21	कुल आस्तियों के प्रतिशत रूप में शीर्ष 10 उधारकर्ता-जून 2011	33
3.22	चालू खाता/बचत खाता(सीएएसए) बनाम जमाराशियों की लागत - सितंबर 2011	34
3.23	बचत बैंक जमा दर में 100 आधार अंकों की वृद्धि का निवल ब्याज मार्जिन(एनआइएम) पर प्रभाव	34

		पृष्ठ सं.
3.24	भारत के सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में ऋण और जमाराशियों के वितरण को दर्शानेवाला लोरेंज कर्व- जून 2011	35
3.25	उद्योगों को बैंक-ऋण जोखिमवार	35
3.26	नकदी कमी का अनुपात-जून 2011	35
3.27	200 बीपीएस के शॉक के कारण एनआईआई में गिरावट	36
3.28	200 बीपीएस के शॉक के कारण पूंजी निधियों में गिरावट	36
3.29	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय मानदंड	36
3.30	ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय मानदंड-मार्च 2010	37
3.31	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की वित्तीय मजबूती के संकेतक	37
3.32	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की निधियों के स्रोतों में शेयर	38
3.33	ऋण जोखिम: सकल ऋण: विभिन्न दबाव परिदृष्यों के तहत वाणिज्य बैंकों की पूंजी और अनर्जक आस्तियों पर प्रभाव: सितंबर 2011	40
3.34	ऋण संकेन्द्रण जोखिम: विभिन्न दबाव परिदृष्यों के तहत वाणिज्य बैंकों की पूंजी और अनर्जक आस्तियों पर प्रभाव :सितंबर 2011	41
3.35	दबावग्रस्त परिदृष्य में बैंकों की नकदी स्थिति - बैंकों के घाटे की समस्या - चलनिधि आस्ति परिभाषा-2: सितंबर 2011	43
3.36	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक दबाव परीक्षण-जून, 2011 में पूंजी स्थिति पर आघातों का प्रभाव	43
4.1	पूंजीगत आवश्यकताओं में कुछ प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि से लेंडिंग स्प्रेड पर प्रभाव	47
4.2	बासल II के तहत उन्नत मानदंडों का ढांचा	48
4.3	एफएसडीसी का कार्यक्षेत्र	51
4.4	एफएसडीसी उप-समिति का तकनीकी दल	51
4.5	प्रतिचक्रीय प्रूडेंशियल विनियम-वाणिज्यिक स्थावर संपदा	52
4.6	प्रतिचक्रीय प्रूडेंशियल विनियम-खुदरा आवासीय ऋण	52
4.7	प्रतिचक्रीय प्रूडेंशियल विनियम-पूंजी बाज़ार	52
4.8	भारतीय वित्तीय प्रणाली के खंड	53
4.9	मूल्य में प्रवृत्तियां	54
4.10	मात्रा में प्रवृत्तियां	54
4.11	आरटीजीएस प्रणाली में बैंकों का नेटवर्क (दो अलग-अलग दिनांकों में)	55
4.12	आरटीजीएस प्रणाली में अंतर्दिवसीय भुगतान का पैटर्न (मूल्य और मात्रा)	56
4.13	कुछ चुने हुए बैंकों का अंतर्दिवसीय भुगतान पैटर्न (मूल्य)	57
4.14	कुछ चुने हुए बैंकों का अंतर्दिवसीय भुगतान पैटर्न (लेन-देनों की संख्या)	57
4.15	बैंकों के बीच डेरिवेटिव एक्पोजर की नेटवर्क संरचना	58
4.16	20 कोर बैंकों के बीच डेरिवेटिव एक्सपोजर की नेटवर्क संरचना	59

पृष्ठ सं.

5.1	प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के प्रतिक्रियाकर्ताओं द्वारा पहचान किए गए प्रणालीगत जोखिम	63
5.2	जोखिम जिसका प्रबंधन देश के लिए अत्यंत कठिन है	64
5.3	जोखिम जिसका प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के लिए अत्यंत कठिन है	64
5.4	उच्च प्रभाववाली घटना की संभाव्यता	64
5.5	वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में विश्वास के स्तर में परिवर्तन	65
5.6	प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक	66
5.7	अंतरबैंक बाजार में बैंक समूह वार क्रियाकलाप	67
5.8	पिछले एक साल के क्रियाकलाप में प्रतिशत में बदलाव	67
5.9	अंतरबैंक बाजार शेयर : सितम्बर 2010	67
5.10	अंतरबैंक बाजार शेयर: सितम्बर 2011	68
5.11	भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना - सितंबर 2010	68
5.12	भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना - मार्च 2011	68
5.13	भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना - सितंबर 2011	68
5.14	व्युत्पन्नी बाजार में शेयर	70
5.15	व्युत्पन्नी नेटवर्क-सितंबर 2011	70
5.16	भारतीय वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क	71
5.17	वित्तीय प्रणाली की नेटवर्क संरचना	71
5.18	सबसे बड़े निवल उधारकर्ता बैंक की विफलता के कारण संक्रमण	71
5.19	जेपीओडी और बीएसआई का संचलन	72
5.20	टॉक्सीसिटी सूचकांक का संचलन	72
5.21	भेद्यता सूचकांक का संचलन	73
5.22	प्रपाती प्रभाव का संचलन	73
5.23	अनुमानित कमी: प्रणालीगत स्तर	74

सारणियों की सूची

2.1	स्पीयरमेन का रैंक कोरिलेशन विश्लेषण	23
3.1	लाभप्रदता अनुपात	33
3.2	ऋण जोखिम: सकल ऋण: विभिन्न दबाव परिस्थितियों के तहत विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से नीचे रहने वाले वाणिज्य बैंकों का सकल ऋण: सितंबर 2011	40
3.3	ऋण जोखिम: क्षेत्रीय - सितंबर 2011	40
3.4	ऋण केन्द्रीकरण जोखिम- दबावपूर्ण स्थितियों में वाणिज्य बैंकों का विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से नीचे रहना - सितंबर 2011	41
3.5	ब्याज दर जोखिम - बैंक बही	41
3.6	ब्याज दर जोखिम - कारोबार बही(संशोधित अवधि दृष्टिकोण)	42

		पृष्ठ सं.
3.7	दबावग्रस्त परिदृष्य में बैंकों की नकदी स्थिति पर प्रभाव- चलनिधि आस्ति परिभाषा-1: सितंबर 2011	43
4.1	भारिबैं/डीएसबी के साथ निपटान सदस्य	60
5.1	वैश्विक घटना का देशीय वित्तीय व्यवस्था में प्रभाव	64
5.2	वैश्विक और देशी वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में विश्वास	65
5.3	शीर्ष के पांच निवल उधारकर्ताओं की विफलता के कारण कुल पूंजीगत हानि (बैंकिंग प्रणाली पूंजी की प्रतिशतता के रूप में)	70
5.4	अंतर सेक्टर एक्सपोज़र	71
5.5	समष्टिगत अर्थशास्त्रीय प्राक्कलन	74
5.6	विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हुए अनुमानित सकल एनपीए अनुपात	75
5.7	विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हुए अनुमानित सीआरएआर	75
5.8	बैंक समूहवार अनुमानित एनपीए (मल्टीवैरिएट पैनल प्रतिगमन)	75
5.9	बैंक समूहवार अनुमानित एनपीए (मल्टीवैरिएट पैनल प्रतिगमन)	76
5.10	अनुमानित सेक्टोरल एनपीए	76

चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची

एएसीएस	जैसे सहकारी समितियों पर लागू
एबीसीपी	परिसंपत्ति आधारित वाणिज्यिक पेपर
एडीएक्सवाय	ब्लूमबर्ग - जे पी मॉर्गन एशिया डॉलर सूचकांक
एएमसी	परिसंपत्ति प्रबंध कंपनियां
बीबीए	ब्रिटिश बैंकर संघ
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीआर अधिनियम	बैंककारी विनियमन अधिनियम
बीएसई	मुंबई शेयर बाज़ार
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक
बीएसएमडी	बैंकिंग प्रणाली पोर्टफोलियो बहुआयामी घनता
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएएसए	चालू खाता बचत खाता
सीबीएलओ	संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
सीसीबीएस	विदेशी मुद्रा बेसिस स्वैप
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी
सीडी	जमाराशियों में ऋण का अनुपात/जमा प्रमाणपत्र
सीडीएस	ऋण चूक अदला-बदली(स्वैप)
सीआईजीएस	कनान इंस्टिट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीस
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीआरएआर	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसए	ऋण सहायता अनेक्सेस
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यकीय संगठन
सीवीए	ऋण मूल्य समायोजन
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआर	आपदा से उभरना
डीएसबी	प्राधिकृत निपटान बैंक
डीएक्सवाय	अमरिकी डॉलर सूचकांक
ईबीपीटी	प्रावधानित राशियों तथा कर के पूर्व अर्जन
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार/यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम
ईएफएसएफ	यूरोपियन वित्तीय स्थिरता सुविधा
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
एफएएसबी	वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड
एफसी	वित्तीय समूह
एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफएमएसआई	वित्तीय बाज़ार स्थिरता सूचक
एफएसए	वित्तीय सेवा प्राधिकरण
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसआई	वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक/ वित्तीय स्थिरता संकेतक
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार समिति
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएक्स	विदेशी मुद्रा
एफ एंड ओ	वायदा सौदा और विकल्प संविदा
जीसीएफ	सकल पूंजी निर्माण
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद
जीएफसीई	सरकारी अंतिम उपयोग व्यय
जी - एसआईबी	विश्व स्तर पर प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण बैंक
एचआईबीओरआर	हांगकांग अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएएस	अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक
आईएएसबी	अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड
आईडीएफ	मूलभूत सुविधा ऋण निधि
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सूचना मानक
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनआर	भारतीय रुपया

आईआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएस	ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली)
आईएसडीए	अंतर्राष्ट्रीय स्वैप तथा डेरिवेटिव संघ
जेपीओडी	संकट का संयुक्त अनुमान
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसीआर	चलनिधि व्याप्ति अनुपात
एलईआई	कानूनी ईकाई का पहचान करने वाला
एलआईबीओआर-ओआईएस	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर- एक दिवसीय सूचकांकबद्ध स्वैप
एमएफ	पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड)
एमएसआई	समष्टि स्थिरता संकेतक
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीएम	बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करना (मार्क-टू-मार्केट)
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	जमा राशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	गैंर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमा स्वीकार न करनेवाली- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
एनबीएफसी-एसआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
एनडीएफ	गैर-सुपुर्दगी योग्य वायदा
एनईसीएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनपीए	अनर्जक परिसंपत्ति/ अग्रिम
एनपीएस	नई पेंशन प्रणाली
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाज़ार
ओडी	ओवरड्राफ्ट
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओआईएस	एक दिवसीय सूचकांक स्वैप
ओएमओ	खुले बाज़ार परिचालन
ओटीसी	काउंटर पर
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीआर	प्रावधानन कवरेज अनुपात
पीई	निजी ईक्विटी
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमआई	क्रय प्रबंधकों के सूचकांक
पीओडी	संकट की संभाव्यता
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि
एसआईएफआई	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था
एसएलआई	प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
टीआई	टॉक्सीसिटी सूचकांक
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
वीएआर	जोखिम-मूल्य
वीएआर	वेक्टर स्वत: रिग्रैशन
वीआई	भेद्यता सूचकांक
वीआईएक्स	उतार चढाव सूचकांक
डब्ल्यूजी	कार्यकारी दल
डब्ल्यूएमए	अर्थोपाय अग्रिम
डब्ल्यूएमएस	धन-संपदा प्रबंधन सेवाएं
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
वाय-ओ-वाय	वर्ष-दर-वर्ष

विहगावलोकन

बाज़ार के सहभागियों और हितधारकों ने देशी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर विश्वास रखा और वह स्थिर बनी रही और कड़े तनाव परीक्षण ने प्रणाली के लचीलेपन को साबित किया।

तथापि, जून 2011 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के प्रकाशन से अब तक अनिश्चित वैश्विक वातावरण के बीच वित्तीय स्थिरता के लिए कुछ जोखिम पैदा हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी वित्तीय प्रणाली की विश्व के साथ बढ़ती सहबद्धता और एकात्मकता यूरो क्षेत्र और यूएसए में सोवरीन ऋण संकट के द्रुत गति से बढ़ने और दीर्घकाल मंदी की प्रतिकूल प्रवृत्ति के सामने अर्थव्यवस्था/प्रणाली की लोचनीयता को आजमा रहे हैं।

अल्पावधि समाष्टिआर्थिक चुनौतियां ऊपर उठ रही है, जबकि वित्तीय बाज़ारों को उच्च अस्थिरता अनुभव करनी पड़ी। भारतीय बैंक, सीआरएआर में कमी होने और निकट भूतकाल में अनुत्पादक आस्तियों के स्तर में उछाल आने के बावजूद तगड़े रहे। बासल III के अंतर्गत बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताएं और चलनिधि आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक चरणबद्ध करना होगा। वित्तीय क्षेत्र का नेटवर्क निकटता से गोलबंद पाया गया है, बैंकों के लिए मुख्य उधारकर्ताओं बैंकिंग क्षेत्र के लिए बाधा बन सकते थे। वित्तीय बाज़ार मूलभूत संरचना ने किसी बड़ी बाधा के बिना कार्य करना जारी रखा।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विभिन्न माडलों/संकेतकों के माध्यम से परिमाणात्मक मूल्यांकन और प्रणालीगत जोखिमों के नापदंड की क्षमता को मज़बूत बनाने के प्रयास प्रतिबिंबित करती है। व्यापक परामर्श के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन को समीक्षात्मक महत्व देकर, एक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण किया गया है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली लोचनीय बन गई है..... हितधारक उसकी स्थिरता के बारे में आश्वस्त हैं

1. रिज़र्व बैंक को पहले प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया देनेवालों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चिंतित होने के बावजूद, देशी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर अपना विश्वास प्रकट किया। समष्टि वित्तीय तनाव परीक्षणों की एक श्रृंखला बैंकिंग क्षेत्र की आस्तिगुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता पर समष्टि आर्थिक वेरिएबल का प्रभाव डालने के लिए आजमायी गयी थी। कड़े तनाव परिदृश्यों के अंतर्गत, पूंजी पर्याप्तता स्तर विनियामक अपेक्षाओं से ऊपर रहे। फिर भी, वित्तीय स्थिरता के लिए कुछ जोखिम बने हुए हैं, जैसा कि वित्तीय स्थिरता मैप और संकेतकों के अनुसार जोखिमों में आयामी वृद्धि द्वारा दर्शाया गया है (चार्ट 1 और 2)।

चार्ट 1: वित्तीय स्थिरता मैप[1]

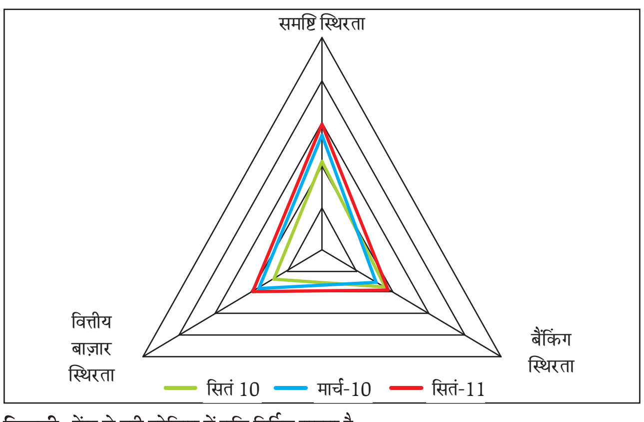

टिप्पणी: केंद्र से दूरी जोखिम में वृद्धि निर्दिष्ट करता है
स्रोत: भारिबैं स्टाफ गणनाएं

चार्ट 2: वित्तीय स्थिरता संकेतक

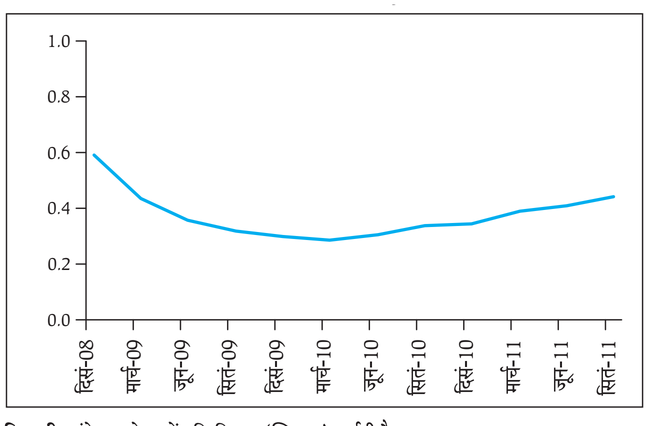

टिप्पणी: संकेतक वेल्यू में वृद्धि निम्नतर 'स्थिरता' दर्शाती है
स्रोत: भारिबैं स्टाफ गणना

[1] वित्तीय स्थिरता मैप और संकेतक भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र स्थिरता स्थिति दर्शाते हैं। वित्तीय स्थिरता संकेतक (एफएसआइ) तीन प्रमुख संकेतकों पर अर्थात् समष्टि स्थिरता संकेतक (एमएसआइ), वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक (एफएमएसआइ) और बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआइ) पर आधारित है। एफएसआइ को एमएसआइ, एफएमएसआइ और बीएसआइ, जो इस रिपोर्ट के क्रमश: I, II, और III में प्रस्तुत किया गया है, के सामान्य औसत आधार पर निकाला गया था। प्रणालियां इस रिपोर्ट के अनुबंध में प्रस्तुत की गई हैं।

समष्टि आर्थिक वातावरण

वैश्विक समष्टि आर्थिक वातावरण के लिए जोखिम बढ गए हैं ....

2. पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन से अब तक, जैसे कि समष्टि आर्थिक स्थिरता मैप और संकेतकों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, यूरोपीयन सोवरिन ऋण संकट और वैश्विक मंदी ने वैश्विक और देशी स्थितियों को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। वैश्विक समष्टि आर्थिक वातावरण में हुई यह अनिश्चितता जारी बनी रहने की अपेक्षा है, भले ही सभी क्षेत्रों में रिकवरी धीमी बनी रहेगी। प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण इस धारणा को भी उजागर करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और वित्तीय प्रणाली को जिनका सामना करना पड़ता है, ऐसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से वैश्विक जोखिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी.....

3. उत्तरोत्तर एकीकृत वैश्विक, आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में भारत का वृद्धि निष्पादन व्यापार, वित्त, पण्य और विश्वास माध्यमों द्वारा प्रभावित हुआ है। वैश्विक पहलुओं के मापदंड में और साथ ही ब्याज दर वृद्धि के संचयी प्रभाव और उच्च मुद्रास्फीतिकारक दबावों जैसे देशी झंझावातों के कारण देशी मांग धीमी हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र में मंदी और निजी उपभोग में धीमी गति के कारण सेवा क्षेत्र की भविष्य की वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है।

मुद्रास्फीतिकारक दबाव उच्च हैं पर हल्के हो रहे हैं.....

4. भारत में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही है। वैश्विक पण्य कीमतें, जिन में ऊर्जा कीमतें भी शामिल हैं, मुद्रास्फीति जोखिमों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तथापि, जैसाकि अपेक्षित था, मुद्रास्फीतिकारी दबाव दिसंबर 2011 में हल्के हुए हैं और मार्च 2012 के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए बेसलाइन अनुमान 7 प्रतिशत है।

बाह्य क्षेत्र फ्रंट पर जोखिम बढ़ गए....

5. भारत में बाह्य क्षेत्र, विश्व व्यापार मात्रा की धीमी वृद्धि और कमजोर होती वैश्विक मांग के कारण जोखिमों का सामना कर रहा है। तेल की लगातार उच्च कीमतें और भारत द्वारा बुलियन, मशीनरी और इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आयात में वृद्धि ने हाल ही की तरणशील वृद्धि को अंशतः निष्प्रभावी कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा बढ़ गया है। आगे जाकर, निर्यातों में और कमी हो सकती है अगर उन्नत स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी बनी रहती है।

राजकोषीय उपायों का नियंत्रण सीमित रहा, जबकि कंपनी निष्पादन कम हुआ

6. राजस्व वसूलियों में कमी और सहायता व्यय में वृद्धि के कारण सकल देशी उत्पाद के 4.6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के बजट लक्ष्य में प्राप्ति वर्ष 2011-12 के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। इससे राजकोषीय उपायों का नियंत्रण कम होगा जिससे अन्य क्षेत्रों के तनाव को संबोधित किया जा सके। तथापि, भारतीय सोवरीन ऋण बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि वह अधिकांश घरेलू संस्थाओं द्वारा धारित किया जाता है, अतः उसकी औसत परिपक्वता उच्च है और उसकी लागत सकल देशी उत्पाद की वृद्धि की दर से कम है।

7. प्रविष्टियों की उच्च लागत, ब्याज दरें और देशी और बाह्य मांग में कमी भी कार्पोरेट क्षेत्र में घटते मार्जिनों में प्रतिबिंबित हो रही है।

वित्तीय बाज़ार

सोवरीन ऋण स्तरों की स्थिरता पर चिंताएं, वैश्विक वित्तीय बाज़ारों की मुख्य प्रेरक थीं

8. पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशित होने से अब तक की अवधि अनिश्चितता और उच्चतर अस्थिरता से जानी जाएगी। यूरोपीयन ऋण स्तर और निम्नतर श्रेणी निर्धारण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कुछ तनाव पैदा हुआ है। यूरोपीयन सोवरीन ऋण संकट जो मूलतः ग्रीस में प्रारंभ हुआ, वह कोर यूरोपीयन राज्यों में फैलने की आशंका है। बाज़ार सहभागियों की मुख्य चिंताएं वृद्धि के पूर्वानुमानों कमी थी जो आस्ति मूल्यों, विशेष रूप से जो वृद्धि संवेदनशील थे, में कमी की ओर ले जा रहे थे। ये गतिविधियां मौद्रिक और राजकोषीय सहारे की कमजोर प्रभावशीलता के बोध से कटु बन रही थीं।

वित्तीय बाज़ार और संस्थाओं के लिए सोवरिन ऋण जोखिम से संभाव्य संसर्ग बना रहा।

9. यूएस और यूरोप में सोवरिन ऋण श्रेणी निर्धारण में कम श्रेणी निर्धारण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और उन के निधिवाले बाज़ारों पर आघात करनेवाला प्रभाव पड़ गया। सोवरिन ऋण समस्याओं ने बैंकों को सोवरिन बांड धारिताएं और रिपो को सोवरिन बांड धारिताएं और रिपो के लिए निम्नतर संपार्श्विक मूल्य और केंद्रीय बैंक निधियन के माध्यम से प्रभावित किया। आगे, बैंकों ने स्पष्ट और अस्पष्ट सरकारी गारंटियों से घटा हुआ लाभ प्राप्त किया। बाज़ार पर संक्रामक प्रभाव अंतर-बैंक उधार बाज़ार में गिरता हुआ पण्यावर्त, उभरती लागत और घटती परिपक्वता के रूप में देखा गया।

उभरती बाज़ार आस्तियों के लिए जोखिम निवारण ने भावनाओं को ठेस पहुंचाई

10. उक्त गतिविधियां, ईक्विटी और ऋण जैसी उभरती बाज़ार आस्तियों से पूंजी प्रवाह को उलटाने का कारण बनी। भारत जैसे देश ने, बाहरी घाटे के साथ एक चालू खाता अधिशेष के साथ एक बृहतर मुद्रास्फीति का सामना किया। जोखिम से बचने का मौजूदा माहौल और भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट भारतीय कंपनियों द्वारा उनके विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय

बांड (एफसीसीबी) और बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के संबंध में झेली जा रही पुनर्वित्त चुनौतियों को और जटिल बना सकता है। संकट-पूर्व के वर्षों में शून्य या बहुत ही कम कूपन पर जारी किए गए एफसीसीबी के लिए देशी स्रोतों के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित ऊंची ब्याज दरों पर पुनर्वित्त की आवश्यकता होगी।

बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि स्थितियां आमतौर पर सहज बनी रही

11. पिछली एसएसआर के प्रकाशन के बाद से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की कमी जो आम तौर पर रिजर्व बैंक की अपेक्षानुसार सहज बनी रही परंतु नवंबर 2011 के दूसरे सप्ताह से इसमें वृद्धि होने लगी। मौद्रिक नीति के रुझान से संगतता तथा विद्यमान तथा भावी चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2011 में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु खुले बाजार के परिचालन प्रारंभ किए।

इक्विटी बाजार में उभरते हुए सूक्ष्म संरचनागत मुद्दों पर निगरानी की जरूरत है

12. इक्विटी में डेरिवेटिव व्यापार की मात्रा में वृद्धि देखी गई जबकि नकदी बाजार में कारोबारी मात्रा में इसके अनुरूप परिवर्तन नहीं हुए। डेरिवेटिव कारोबार में मालिकाना व्यापार का हिस्सा भी बढ़ रहा है। नकदी खंड में खुदरा भागीदारी सहित गैर संस्थागत सहभागियों की हिस्सेदारी में कमी हुई है। सूचना की विषमता से उत्पन्न होने वाले बाज़ार का विस्थापन रोकने और प्रमोटरों द्वारा शेयरों के निजी तौर पर गिरवी रखे जाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। भारतीय इक्विटी बाजार में उभरती हुए सूक्ष्म संरचना पर ध्यान पूर्वक निगरानी की जरूरत है।

वित्तीय संस्थाएं

यूरो क्षेत्र संकट का भारतीय बैंकों पर सीधा प्रभाव सीमित है, लेकिन फंडिंग पर कुछ दबाव उभर सकते हैं

13. ज्यादा प्रभावित यूरोपीय देशों के साथ भारतीय बैंकों का एक्सपोजर नगण्य है। इसलिए, यूरो क्षेत्र सार्वभौम ऋण संकट का भारतीय बैंकों पर सीधा प्रभाव न पडने का अनुमान है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में फंडिंग पर दबाव बैंकों और कंपनियों को विदेशी धन की उपलब्धता और लागत दोनों ही रूप में प्रभावित कर सकता है, इस तरह के कुछ संकेत पहले से ही उभर रहे हैं।

बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध रही हालांकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात में कुछ गिरावट देखी गई

14. जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और मूल सीआरएआर में हाल ही में देखी गई गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। बैंकिंग प्रणाली का सीआरएआर मार्च 2011 के अंत के 14.2 फीसदी से गिरकर सितंबर 2011 के अंत में 13.5 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान मूल सीआरएआर अनुपात 10 प्रतिशत से गिरकर 9.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि, दोनों अनुपात विनियामक अपेक्षा क्रमशः नौ और छह प्रतिशत से उपर ही बने रहे। लीवरेजिंग अनुपात बासल III के तहत तीन प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा के सामने लगातार छह प्रतिशत के आसपास बना रहा।

आस्ति गुणवत्ता में कुछ कमी देखी गयी; हांलाकि, एनपीए अनुपात अन्य देशों की तुलना में अनुकूल बने रहे

15. स्लिपेज में वृद्धि ऋण वृद्धि से ज्यादा रही जिसके चलते बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आई। मार्च और सितंबर 2011 के बीच कुल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया। प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में भी इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में आस्ति गुणवत्ता की कमी की पहचान की है। विभिन्न देशों के एनपीए अनुपातों की तुलना से पता चलता है कि हाल ही की गिरावट के बावजूद, अन्य देशों की तुलना में भारतीय बैंक बेहतर स्थिति में है।

पावर तथा दूरसंचार क्षेत्रों की आस्तियों में क्षति/ पुनर्गठन में वृद्धि हुई, हालांकि इन क्षेत्रों में वृद्दिशील ऋण वृद्धि समग्र ऋण वृद्धि से ज्यादा रही

16. पावर तथा दूरसंचार क्षेत्रों में पुनर्गठित तथा क्षत आस्तियों में - ये दोनों ही बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के महत्वपूर्ण घटक हैं - हाल ही के महीनों में वृद्धि हुई है। मार्च 2011 के 5.0 प्रतिशत की तुलना में जून 2011 में इन क्षेत्रों में पुनर्गठित खातों की राशि बैंकिंग क्षेत्र में पुनर्गठित खातों का 8.5 प्रतिशत थी। इन क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण काफी उच्च स्तर पर था - बैंकिंग क्षेत्र में समग्र ऋण वृद्धि में भी अधिक- इसको देखते हुए इन खंडों में आस्ति गुणवत्ता पर सावधानी में निगरानी किए जाने की जरूरत है।

बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव है, हालांकि दक्षता अनुपातों में कुछ सुधार देखने को मिला

17. उच्चतर ब्याज खर्च तथा उच्चतर प्रावधान आवश्यकताओं के कारण बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव पडा, हालांकि दक्षता अनुपातों में निरंतर सुधार होता रहा। निवल ब्याज आय सितंबर 2010 के 40.7 प्रतिशत की तुलना में कम होकर सितंबर 2011 में 15.5 प्रतिशत रह गई जबकि पीएटी वृद्धि एक वर्ष पहले के 31 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2 प्रतिशत रह गए। गैर ब्याज आय की तुलना में परिचालन खर्च भी बहुत तेजी से बढ़े। भविष्य में, उच्च जमाराशि दरों, ऋण वृद्धि

में संभावित मंदी तथा आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के कारण अर्जन पर और अधिक दबाव पड सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र का 'नेटवर्क' टियरयुक्त है, लेकिन अंतर बैंक एक्सपोजर पर सीमा के कारण परस्पर जोखिम कम हो जाएगा

18. बैंकिंग क्षेत्र में द्विपक्षीय एक्सपोजर नेटवर्क 'टियरयुक्त' है जिसके कारण यह कम स्थिर है क्योंकि अधिकांश संबद्ध बैंकों की विफलता का परस्पर प्रभाव प्रणाली पर पडता है। संभावित परस्पर प्रभाव संबद्ध जोखिमों, यदि बडे उधारग्राही विफल हो जाएं, में वृद्धि हुई है लेकिन अंतर बैंक एक्सपोजर पर विनियामक सीमा के चलते ऐसे जोखिम में कमी हो जाती है।

बैंक आघात सह सकते हैं लेकिन अत्यंत दबाव की स्थिति में लाभप्रदता पर प्रभाव पड सकता है

19. अनेक दबाव परीक्षणों में बैंकों की अलग-अलग जोखिमों को सह सकने की क्षमता का आकलन किया गया। कडे ऋण जोखिम दबाव वाली स्थिति में भी बैंकिंग क्षेत्र आघात सहने की स्थिति में है, हालांकि कुछ बैंक दबाव में आ सकते हैं। सेक्टरवार एनपीए पर दबाव पडने के कारण बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित होते देखा गया, हालांकि पूंजी पर्याप्तता पर यह प्रभाव सीमित ही रहा। ब्याज दर जोखिमों का ट्रेडिंग बुक पर प्रभाव सीमान्त रहा; बैंकिंग बुक में जोखिम उच्चतर थे लेकिन उनका प्रबंधन किया जा सकता था। चलनिधि जोखिमों के कारण कुछ चिंता हो सकती है लेकिन एसएलआर पोर्टफोलियो की स्थिति सहज बनी हुई है।

बैंकों के बीच संकट निर्भरता कम बनी हुई है

20. बैंकिंग स्थिरता उपाय, जो बैंकिंग क्षेत्र में संकट निर्भरता का मॉडल तैयार करने का प्रयत्न करते हैं, दिखलाते हैं कि ऐसी निर्भरता लगातार निम्न स्तर पर बनी हुई है, हालांकि बैंकिंग स्थिरता इन्डेक्स में कुछ मामूली सी वृद्धि दिखाई दी है। हाल ही की अवधि में बैंकिंग प्रणाली की प्रत्याशित कमी (अर्थात अत्यंत हानि की स्थिति में आस्तियों में अनुमानित हानि) निरंतर गिर रही है, जिसका अभिप्राय है कि इस मॉडल के अधीन अत्यंत प्रणालीगत हानियों के चलते भी बैंकिंग प्रणाली आघात सह सकने की स्थिति में है।

दबाव परीक्षण एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा आघात सह सकने की क्षमता दिखलाते हैं हालांकि फंडिंग के लिए बैंकों पर निर्भर रहने से जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं

21. एनबीएफसी की लाभप्रदता में सुधार हुआ हालांकि आस्ति गुणवत्ता में कुछ गिरावट देखने में आई। ऋण जोखिम दबाव परीक्षण दिखलाते हैं कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी कडे दबाव सह सकने की क्षमता रखती हैं। तथापि, यह क्षेत्र अपनी फंडिंग के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर रहता है। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए गए उधार की वृद्धि की दर एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण की वृद्धि की दर से अधिक रही। ऐसी निर्भरता से बैंकों और एनबीएफसी दोनों ही के लिए जोखिम हो सकता है। बैंकिंग प्रणाली में किसी भी प्रकार की उथल पुथल होने की स्थिति में एनबीएफसी के सामने फंडिंग की समस्या हो सकती है। दबाव के समय, एनबीएफसी बहुत तेजी से डीलिवरेज की प्रवृत्ति दिखलाती हैं जिसके कारण बैंकों पर दबाव पड सकता है।

बीमा तथा पेंशन क्षेत्र 'आटोमेटिक स्टेबलाइजर' के रूप में कार्य करते हैं लेकिन उन पर परस्पर प्रभाव पडने का जोखिम बना हुआ है

22. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह माना जाता है कि बीमा तथा पेंशन खंड वित्तीय स्थिरता में अपना योगदान देते हैं क्योंकि सामान्यतया वे केवल दीर्घावधि के ही निवेश करते हैं। भारतीय बीमा क्षेत्र के पास पर्याप्त पूंजी है परंतु इसके उल्लेखनीय रूप से बैंकिंग प्रणाली से जुडे होने के कारण यहां परस्पर जोखिम हो सकते हैं, भारतीय वित्तीय प्रणाली के 'नेटवर्क' विश्लेषण से भी इसका पता चलता है। इस क्षेत्र में पूंजी जुटाने और पर्याप्त पुनर्बीमा करने की क्षमता को इसकी निरंतर स्थिरता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है।

विनियामक बुनियादी ढांचा

प्रणालीगत स्थिरता के पर्यवेक्षीण के लिए एफएसडीसी फ्रेमवर्क भलीभांति काम कर रहा है

23. वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति इसके प्राथमिक परिचालन अंग के रूप में सामने आई है और इसकी चर्चाओं में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां, विनियामकों के बीच समन्वयन और वित्तीय समावेशन तथा साक्षरता शामिल होते हैं।

बासल III व्यवस्था अपनाना - भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में है लेकिन उनके समक्ष कई चुनौतियां भी है

24. बासल III दिशानिर्देशों की तुलना में भारतीय बैंकों का मौजूदा पूंजी आधार और चलनिधि की स्थिति शुरुआत से ही बहुत सहज है। भविष्य की ओर देखें तो पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, हालांकि इसकी सही राशि की गणना अभी की जानी है। अनुभवजन्य अध्ययनों से यह पता चलता है कि उधार देने के स्प्रेड की वृद्धि के माध्यम से संवृद्धि

दर पर बासल III का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। रिज़र्व बैंक बासल III के अधीन भारतीय बैंकों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है - इसके कार्यान्वयन समय का निर्धारण इस बात को ध्यान में रख कर किया जाएगा कि इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के समरूप बनाया जा रहा है, हालांकि आईएएफआरएस 9 अप्राप्य लक्ष्य बना हुआ है

25. रिजर्व बैंक का एक कार्य समूह आईएएफआरएस अभिमुख वातावरण में अबाध ट्रांजिशन को आसान बनाने में प्रयासरत है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि आईएएफआरएस 9 को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है: आईएएफआरएस और वर्तमान नियामक दिशानिर्देशों के बीच वर्गीकरण और वित्तीय संपत्ति के माप पर मतभेद जारी हैं, और लेनदेन के उचित मूल्यों के आकलन में कठिनाइयां हैं, जहां बाजार प्रथाओं या मानक के संदर्भ में भारत में बहुत ज्यादा मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

आरटीजीएस प्रणाली का नेटवर्क सुव्यवस्थित है लेकिन अंतर दिन की देरी के नेटवर्क में वृद्धि हुई जोखिम के लिए नेतृत्व कर सकते हैं

26. साथ-साथ सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) का नेटवर्क अपेक्षाकृत कम स्तर टायरिंग के साथ सुव्यवस्थित है। हालांकि, आरटीजीएस प्रणाली में लेनदेन के निपटान के अंतर्दिवसीय प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि सदस्यों द्वारा लेनदेन के निपटान में एक हद तक विलंब हो रहा है। इससे प्रणाली में चलनिधि जोखिम में बढ़ोतरी हो सकती है और यह संचालनात्मक मामलों में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है जिसके कारण ऋण और प्रणालीगत जोखिम सामने आ सकता है। ऐसे निपटान के प्रवृतियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है। यह सिस्टम में चलनिधि का जोखिम बढ़ा सकता है और किसी परिचालनात्मक घटना के प्रभाव को बहुत अधिक कर सकता है। इस प्रकार के निपटान की प्रवृत्ति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जानी चाहिए।

ओटीसी डेरिवेटिव कारोबार में प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है

27. ओटीसी डेरिवेटिव अनुबंधों से भारतीय बैंकों के बीच अंतर-संबंध में बढ़ोतरी हुई है, विशेष रूप से उनके मध्य जो व्युत्पन्न बाजार में अति सक्रिय हैं। यह प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही है क्योंकि, खासकर कठिन दौर में, ऐसे व्युत्पन्न अनुबंधों में 'गलत आंकलन संबंधी जोखिम' प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। बासल III के तहत संशोधित नियामक मानदंडों और ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देनों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्षीय निपटान ऐसे जोखिमों को कम करता है परंतु जोखिमों पर ध्यानपूर्वक निगरानी करने की जरूरत बनी हुई है, उदाहरण के लिए व्यापक दबाव परीक्षणों के माध्यम से जिसमें कठिन परिस्थितियां शामिल हैं।

सीसीआईएल का लचीलापन ... स्ट्रेस टेस्ट में अंतर-संबंध और प्रणालीगत जोखिमों को शामिल करने की आवश्यकता है

28. अनेक स्ट्रेस और बैंक परीक्षण अभ्यासों से पता चलता है कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) में यथोचित तौर पर विभिन्न बाजारों में झटके से उबरने की क्षमता है। भविष्य में, सीसीआईएल को सामान्यीकृत बाजार विफलताओं की स्थितियों के लिए अपने लचीलेपन का आकलन करने तथा जोखिम प्रबंधन ढ़ांचे में वित्तीय बाजार और बैंकों के बीच अंतर-संबंधों के प्रभाव को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

29. घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए निस्संदेह जोखिम, विशेष रूप से वैश्विक जोखिम मौजूद है। पिछले एफएसआर के प्रकाशन के बाद कुछ जोखिमों में बढ़ोतरी आई है और इन पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है। समष्टि अर्थव्यवस्था में घट रही घटनाओं और बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय सुदृढ़ता के संकेतकों से कुछ चिंताएं उभर रही है क्योंकि वित्तीय बाजारों में तेजी से गिरावट के साथ-साथ अति अस्थिरता का माहौल है। कुल मिलाकर, प्रणाली मजबूत है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रही हलचलों के प्रभाव सहित अस्थिरता का अच्छी तरह से सामना करने के लिए तैयार है। बाजार के प्रतिभागी भी प्रणाली की स्थिरता के बारे में आश्वस्त हैं।

अध्याय I

समष्टि आर्थिक परिदृश्य

जून 2011 में तीसरे एफएसआर के प्रकाशन के बाद वैश्विक जोखिम में वृद्धि हुई है। यूरो क्षेत्र में सोवरीन ऋण संकट के गहराने से बढ़ रही अनिश्चितताओं और अमेरिका में मंदी के कारण व्यापार और वित्त चैनल के माध्यम से वैश्विक और भारत अर्थव्यवस्था के लिए गिरावट संबंधी जोखिम सामने आ रहा है। इसलिए, इस पर बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। बाह्य क्षेत्र के जोखिम में बढ़ोतरी की संभावना है। तेल की कीमतों में उछाल से भी दुबारा पटरी पर आ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष गिरावट संबंधी जोखिम है और घरेलू मुद्रास्फीति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लाभ मार्जिन में कमी आई है जो घरेलू और वैश्विक कच्चे माल और ब्याज लागत में बढ़ोतरी के कारण कम मूल्य निर्धारण शक्ति का संकेत है। आवास की कीमतों में कुछ समय तक नरमी के पश्चात तेजी आई है। हालांकि परिसंपत्ति गुणवत्ता में कुछ गिरावट देखी गई है, तथापि आवास क्षेत्र में चूक की दर वैश्विक संकट के पश्चात उच्च चूक स्तर की तुलना में बहुत कम रही। समग्र तौर पर, जून 2011 के अंतिम मूल्यांकन के बाद से, समष्टि आर्थिक परिदृश्य से होने वाले जोखिम में वृद्धि हुई है।

पिछले मूल्यांकन के बाद समष्टि आर्थिक जोखिम में बढ़ोतरी

1.1 जून 2011 में मूल्यांकन के बाद से, समष्टि आर्थिक वातावरण से उत्पन्न जोखिम (चार्ट 1.1) में वृद्धि हुई है। वैश्विक मंदी और सोवरीन ऋण संकट से वैश्विक जोखिम और बाह्य क्षेत्र भेद्यता में गिरावट आयी है की गिरावट के लिए नेतृत्व किया है। घरेलू संवृद्धि कमजोर हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति के जोखिमों में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष की पहली छमाही में राजस्व की उम्मीद से कम संग्रह के मद्देनजर वित्तीय संभावनाओं में ह्रास हुआ है। लाभ मार्जिन में हो रही कमी से कॉर्पोरेट क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। हालांकि, घरेलू क्षेत्र द्वारा कम लीवरेज करने के कारण जोखिमों में कुछ कमी आयी है। फिर भी, समग्र समष्टि आर्थिक तनाव में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वैश्विक संकट (चार्ट 1.2) के बाद के स्तर से नीचे बनी हुई है।

चार्ट 1.1 : समष्टि आर्थिक स्थिरता मैप[1]

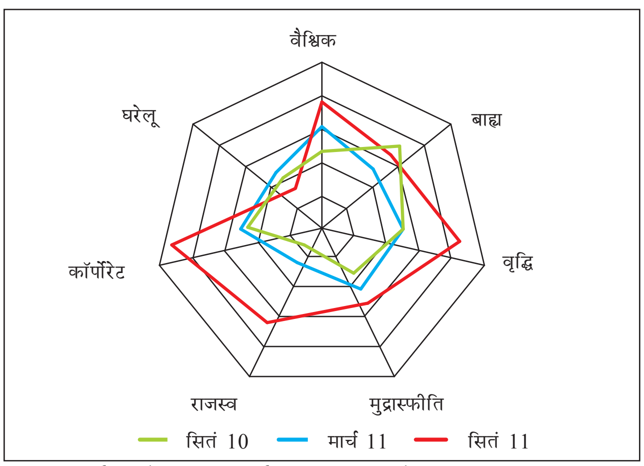

नोट : केंद्र से दूरी जाखिम में बढ़ोतरी दर्शाता है
स्रोत : आरबीआई के स्टाफ की गणना

चार्ट 1.2: समष्टि आर्थिक स्थिरता संकेतक[2]

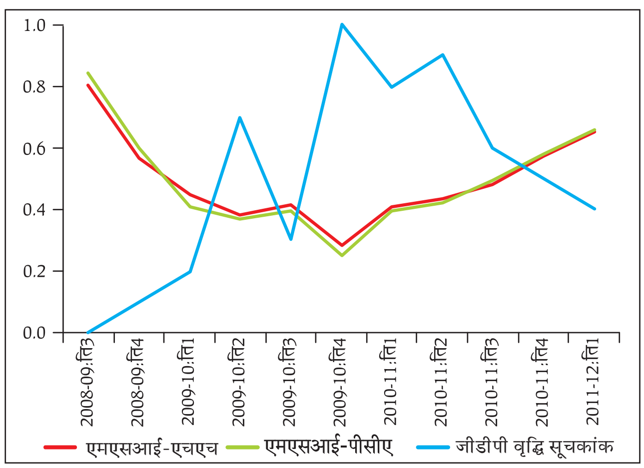

नोट: संकेतक के मूल्यांकन में बढ़ोतरी निम्न स्थिरता को दर्शाता है

[1] समष्टि आर्थिक स्थिरता मैप के लिए इस्तेमाल के लिए की गई पद्धति पर जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक देखें।

[2] बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति की गुणवत्ता के साथ घरेलू क्षेत्र का संबंध स्पष्ट नहीं है और दिए गए ऋण में घरेलू क्षेत्र को दिए गए कम हिस्से को देखते हुए, समष्टि आर्थिक स्थिरता संकेतक में इस क्षेत्र को वर्तमान में शामिल नहीं किया गया है। दो तरीकों का प्रयोग कर चार्ट 1.1 निर्दिष्ट अन्य विशेष जोखिमों को एक समष्टि आर्थिक स्थिरता संकेतक में शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले, प्रत्येक जोखिम को सूचकांक (एमएसआई-एचएच) में बराबर भारांक दिया गया है। दूसरे तरीके में, भारांक को मुख्य घटक विश्लेषण (एमएसआई-पीसीए) का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। दोनों तरीके एक ही तरह के परिणाम देते हैं।

वैश्विक समुत्थान होने में काफी समय लगने के आसार

1.2 पूर्व प्रत्याशाओं के विपरीत, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समुत्थान में काफी समय लग सकता है। सितंबर 2011 से विभिन्न एजेंसियों ने अमेरिका तथा यूरो क्षेत्र के उनके विकास अनुमानों को निम्नतर करते हुए संशोधित किया है। अमेरीकी अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक बेरोजगारी तथा धीमी वृद्धि से जूझ रही है। वित्तीय अनिश्चितता, आवास बाजार क्षेत्र में मंदी, नवीकृत वित्तीय दबाव तथा नरम कारोबार एंव उपभोक्ता मनोभावों की वजह से डाउनसाइड रिस्क बढा है। यूरो क्षेत्र में उच्च लोक घाटे तथा ऋण, निम्न संभाव्य आउटपुट तथा बढते बाजार के तनाव से उनके विकास के पहलुओं पर दबाव पड रहा है। कमजोर राष्ट्रीय तुलन पत्रक, अधिक बेरोजगारी तथा आवास बाजार क्षेत्र में दीर्घकालीक मंदी से धीमी निजी खपत तथा गतिविधियों में ढील को बढावा मिला है। यूरोपीयन यूनियन की हाल ही वार्ता बाजार के नकारात्मक रूख को पलटने में विफल रही है। चीन में भी वृद्धि दर जो पहले प्रत्याशित थी, उससे कम हीं उम्मीद की जा रही है। अग्रवर्ती दृष्टि संकेतक जैसे क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) निम्न स्तर की ओर जा रहा है, यद्यपि अमेरिका में जहाँ कि विनिर्माण क्षेत्र के मामले में मामूली इजाफा और बेरोजगारी की दर में कमी तथा क्रिसमस शॉपिंग डाटा से समुत्थान के बेहतर संभावनाओं को बल मिला है। विषमता के कारण यूरोपीयन पीएमआइ 2012 में यूरोप में मंदी के मज़बूत संकेत देते हुए संकुचित स्तर तक पहुँच चुकी है, जो कि बहुत सारे पूर्वानुमान करने वाले की भी समझ है। (चार्ट 1.3)

1.3 सोवरीन रेटिंग्स के दृष्टिकोण में कुछ गिरावट आयी है। निकट भविष्य में यूरो क्षेत्र के देशों के बीच सोवरीन रेटिंग्स की एक श्रृखंला के डाउनग्रेड होने की उम्मीद है। इनमें से कुछ के लंबे समय हेतु और डाउनग्रेड की जाने की उम्मीद है। इससे आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी तथा आर्थिक मंदी जारी रहेगी।

चार्ट 1.3: यूएस और यूरोप के पीएमआई

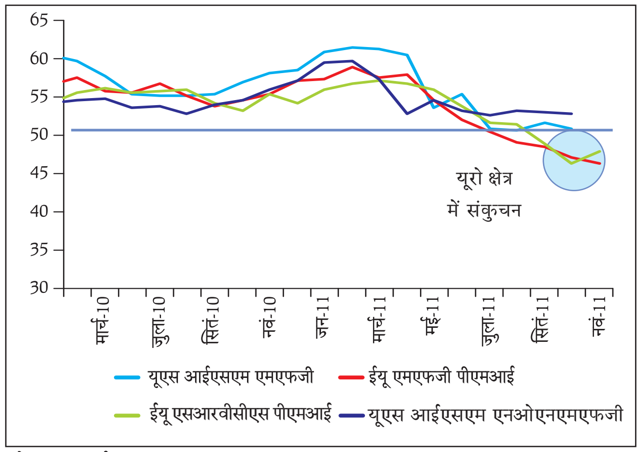

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.4: चीन और यूएस का व्यापार संतुलन

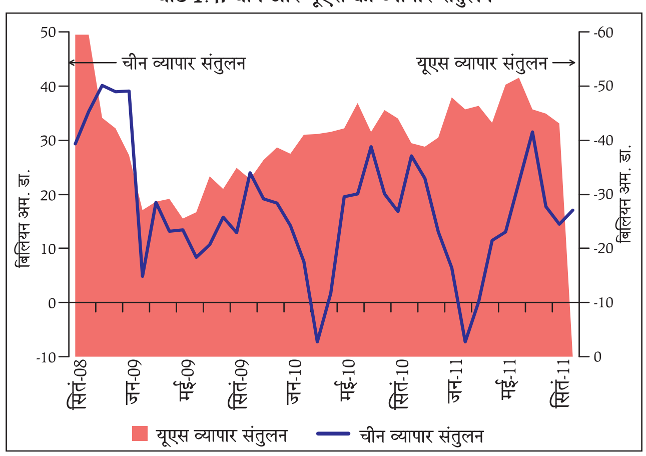

स्रोत: ब्लूमबर्ग

वैश्विक असंतुलन, संकट का एक प्रमुख कारण, उच्च स्तर पर बरकरार

1.4 जैसा कि विगत रिपोर्ट में वर्णित है, वैश्विक असंतुलन के संरचनात्मक कारणों का पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया है। चीन का व्यापार संतुलन ज्यादातर उच्च अधिशेष क्षेत्र में रहता है। अमेरिका का व्यापारीय घाटा, संकट के प्रभाव में कुछ सहजता के बाद बढ़ रहा है तथा लगातार बड़ा होता जा रहा है (चार्ट 1.4)। पुनर्संतुलन की प्रक्रिया, व्यापार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चीनी अर्थव्यवस्था का सफल पुनर्संतुलन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रभाव की उत्पत्ति करेगा।[3]

[3] क्रिस्टीन लागार्डे, प्रबंध निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आइ एम एफ तथा विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अवसर और चुनौतियाँ, सी पीटर सीरिज ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जुलाई 26, 2011

उच्च सोवरीन ऋण का बने रहना .... वैश्विक समुत्थान को आगे निरूत्साहित कर सकता है

1.5 कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की उधारी तथा सोवरीन ऋण दोनों का उच्च स्तर जारी है। (चार्ट 1.5) सरकार तथा बाज़ारों के बीच परस्पर क्रिया अधिक जटिल एंव अधिक खतरनाक बन गयी है।[4] साथ ही, सोवरीन ऋण समस्याओं का समाधान अधिक कठिन प्रतीत हो रहा है तथा मूल रूप में परिकल्पित से ज्यादा समय ले सकता है। दीर्घकालिक मंदी को देखते हुए, ऋण स्तरों में कटौती संरचनात्मक उपायों को बढ़ावा देगी, जो कि कुछ मामलों में राजनैतिक रूप से समीचीन नहीं हो सकता है। ऋणयुक्त तथा 'मददगार' राष्ट्र दोनों को समस्या के प्रभावी समाधान तथा साख को कमजोर होने से बचाने के लिए कदम बढाने हेतु कुछ राजनैतिक विरोधों पर काबू पाना होगा। साथ ही, वर्तमान समय पर उच्च ऋण स्तर संभावित मंदी के प्रभाव से निपटने में वित्तीय गतिशीलता को सीमित करती है। सोवरीन ऋण पर नियंत्रण रखने के लिए आर्थिक वृद्धि का मजबूत होना आवश्यक है। दूसरी ओर, जब भी वित्तीय समेकन उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है, तो यह वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं तथा वैश्विक स्तर पर अल्प समय के लिए माँग को और कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, घाटे में एक प्रतिशत अंक तक की कटौती, दो साल तक लगभग आधे प्रतिशत तक विकास को कम कर सकती है। तथापि, ऋण में कटौती, मूल ब्याज दरों को कम करते हुए लंबे समय तक आउटपुट बढाने का कार्य करती है तथा करों में कटौती[5] के लिए जगह बनाती है। विश्वसनीय राजकोषीय समेकन उपायों का, आत्मविश्वास में सुधार के कारण, अल्पावधि में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बाहरी क्षेत्र में जोखिम बढोत्तरी की ओर........ .

1.6 भारत में बाहरी क्षेत्र के लेन देन में प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियां दिखालाई देती हैं। बाहरी क्षेत्र भेद्यता सूचकांक (चालू खाता घाटा, वर्तमान प्राप्ति में वर्तमान भुगतान का अनुपात, कुल ऋण में अल्प अवधि ऋण का शेयर, सकल घरेलू उत्पाद तथा ऋण स्टॉक के अनुपात पर आधारित) पिछले समय में एक अपट्रेंड को रिकार्ड किया है जो कि बाहरी क्षेत्रों के जोखिम की वृद्धि को दर्शाता है। (चार्ट 1.6)

1.7 विश्व व्यापार संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों हीं ने विश्व व्यापार परिमाण में कम वृद्धि की संभावना व्यक्त की है जो कि कमजोर वैश्विक माँग को दर्शाती है। यद्यपि रुपए के मूल्य में

चार्ट 1.5: सोवरीन ऋण और उधार उच्च बना रहा

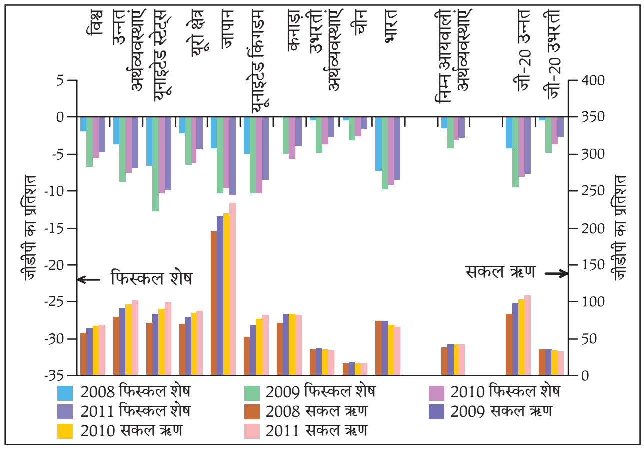

स्रोत: आईएमएफ, फिस्कल मानीटर

चार्ट 1.6: बाहरी क्षेत्र भेद्यता सूचक

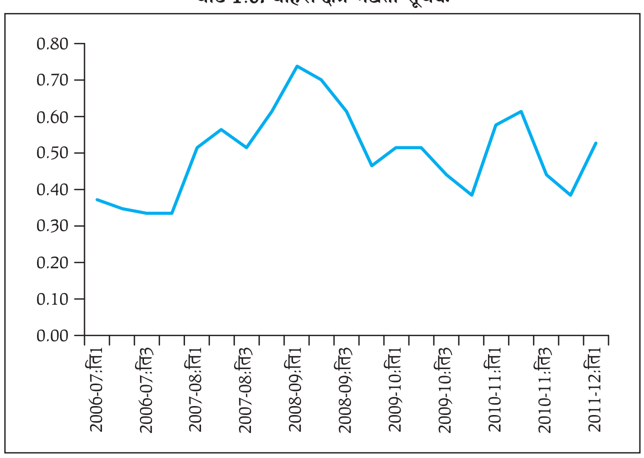

स्रोत: भारिबैं स्टाफ गणनाएं

[4] सी आइ जी एस (कैनन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़) में बीआइएस के बोर्ड निदेशक के अध्यक्ष एंव बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर क्रिश्चयन नोयर द्वारा दिए गए मुख्य वक्तव्य - इएचईएसएस (इकोल्स डेस हॉउट्स इट्यूड्स एन साइन्सेज सोशलस्) इंटरनेशनल सिम्पोजियम 3 अक्टूबर 2011

[5] *Op.cit.*

गिरावट से भारतीय निर्यात को आंशिक रूप से राहत मिलेगी, फिर भी 2011-12 की दूसरी छमाही में विकसित देशों में मंदी के कारण भारतीय निर्यात के प्रमुख आयातक देशों में शामिल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के विकास में कमी होने से निर्यात कम हो सकता है। इसी प्रकार, अदृश्य क्षेत्र, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर सेक्टर में प्राप्तियों पर विकसित देशों में मंदी की गंभीरता पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, तेल की बढ़ी हुई कीमतें और सोना-चांदी, मशीनों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात में वृद्धि के कारण आयात में निरंतर बढ़ोतरी बनी रही है। अद्यतन आंकड़े दर्शाते हैं, कि व्यापार संतुलन में और अधिक अंतर उत्पन्न हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 की पहली तिमाही में बढ़ी हुई सीएडी (चार्ट 1.7) में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ी हुई सीएडी के कारण उच्चतर पूँजी अंत:प्रवाह आवश्यक हो जाएगा। इस संदर्भ में यूएसए तथा यूरो क्षेत्रों में आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों से जुड़े मंदी जोखिम से बचने का प्रभाव, विशेषरूप से भारत में वित्तीय निवेश संस्थाओं द्वारा निवेश पर, अति महत्त्वपूर्ण होगा।

1.8 यद्यपि चालू वर्ष के दौरान दोहरी मंदी/दोहरा घाटा और अधिक बढ़ने वाली है, फिर भी यह राजकोषीय हानि के बजाए वैश्विक कारण है, जो कि सीएडी की वृद्धि में योगदान दे रहा है। इसके बाद भी, राजकोषीय सुदृढ़ता से सीएडी में कुछ हद तक सुधार होगा।

घरेलू विकास की गति में गिरावट

1.9 व्यापार तथा वित्तीय संबंधों और बढ़ती हुई घरेलू ब्याज दरों से उत्पन्न वैश्विक मंदी तथा सार्वत्रिक ऋण समस्याओं का घरेलू विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से मांग की कमी, संरचनात्मक अवरोध तथा बाह्य तथा आंतरिक ऋण दोनों पर व्यय का औद्योगिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही, सरकार द्वारा बाज़ार से लिए गए उधार में वृद्धि के कारण निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में कमी हो सकती है।

1.10 यद्यपि 2011-12 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में विकास अच्छा रहा है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में मंदी तथा निजी क्षेत्र के उपभोग में कमी का प्रतिकूल प्रभाव विकास को आगे बढ़ाने पर पड़ेगा (चार्ट 1.8)। सितंबर और अक्तूबर 2011 के लिए सेवा क्षेत्र के लिए पीएमआई (क्रय प्रबंधन सूचकांक) 50 से भी कम रहा, जो कमी को दर्शाता है लेकिन इसमें नवंबर माह में कुछ सुधार हुआ है। सितंबर 2011 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए पीएमआई (क्रय प्रबंधन सूचकांक) पिछले 30 माह के न्यूनतम स्तर (चार्ट 1.9) से कुछ अच्छा रहा है। निर्माण क्षेत्र के लिए पीएमआई (क्रय प्रबंधन सूचकांक) में कमी मुख्य रूप से नए कारोबार में कमी तथा सितंबर

चार्ट 1.7: बाहरी क्षेत्र दबाव

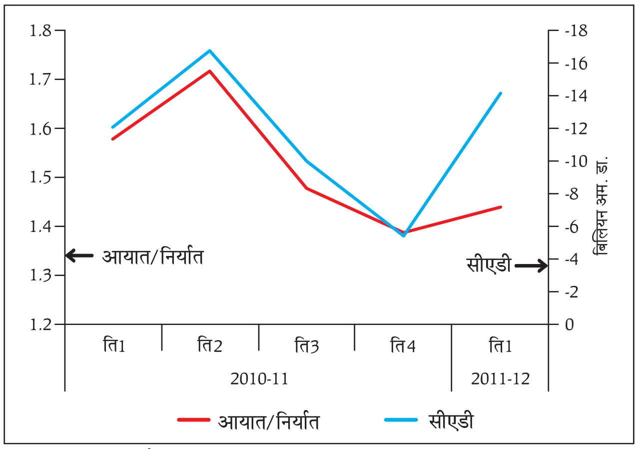

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.8: विभिन्न क्षेत्रों में मंदी

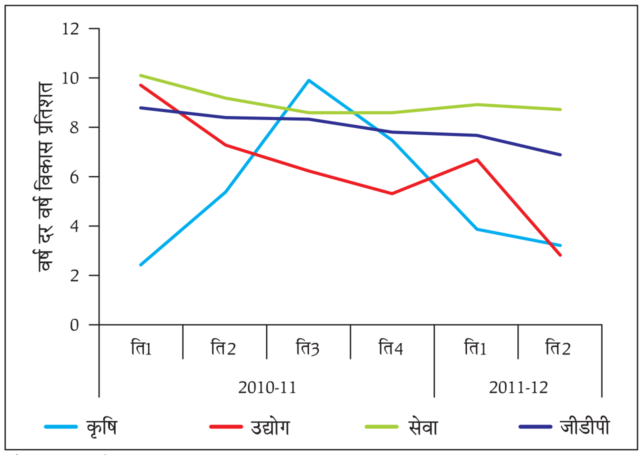

स्रोत: सीएसओ

चार्ट 1.9: स्थिरता/मंदी दर्शाता पीएमआई

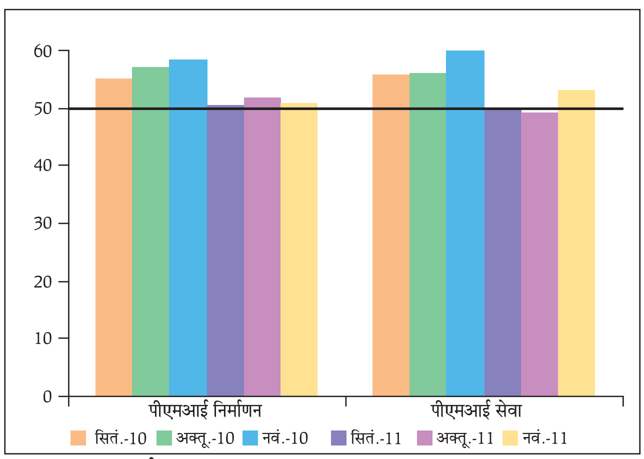

स्रोत: एचएसबीसी मार्किट

2011 में निर्यात आदेशों में कमी के कारण रहा है। सेवा क्षेत्र में प्रगति भी बाद में अक्तूबर 2011 में व्यापार गतिविधियों में निरंतर कमी तथा नई मांगों में कमी के कारण धीमी पड़ गई।

1.11 मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा में परियोजनाओं की धीमी मंजूरी तथा क्रियान्वयन, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में वृद्धि की समस्याओं को परिलक्षित करने वाली धीमी वैश्विक विकास तथा निवेश में कमी के कारण 2011-12 के लिए न्यूनतम अपेक्षित जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि को 8.0 प्रतिशत से घटाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया गया।

घरेलू मांग में भी कमी दर्ज की गई

1.12 भारत में विकास का मुख्य वाहक, विशेष रूप से मंदी के समय, घरेलू मांग रहा था, जो कि इस समय थोड़ा धीमा पड़ रहा है। 2011-12 की प्रथम छमाही में इसके घटक जैसे- निजी उपभोग, सरकारी उपभोग और निवेश में कमी दर्ज की गई है (चार्ट 1.10)। निरंतर तथा धीमे वैश्विक सुधार को देखते हुए, स्थायी विकास के लिए घरेलू व्यापार का पुनर्जीवन घरेलू मांग पर, विशेष रूप से निवेश, पर टिका है।

जब घरेलू मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही

1.13 दूसरी तिमाही से कमजोर वैश्विक विकास के कारण अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं, विशेषकर कच्चे तेल के दाम में थोड़ी ही कमी आई है। ब्रेंट और दुबई फतेह के दाम (जो भारतीय बास्केट का अंग है) में थोड़ी ही कमी आई है। उपर्युक्त प्रवृत्ति को दर्शाते हुए, विकसित और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के हेडलाइन संकेतक उन क्षेत्रों/लक्ष्यों से ऊपर रही जिन क्षेत्रों/लक्ष्यों को लेकर स्थिति सहज है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और भारत के मामले में, घरेलू मांग ने मुद्रास्फीति कारक दबावों को बढ़ाया (चार्ट 1.11)। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के घटकवार विश्लेषण से यह बात सामने आयी है कि हालांकि भारत ने ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव को सफलतापूर्वक कम किया है, लेकिन वे उच्च स्तर पर बने रहे (चार्ट 1.12)

1.14 दूसरी तिमाही की समीक्षा में यह पाया गया कि मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति दोनों कारकों, अर्थात् सकल मांग में कमी की मात्रा, कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों का स्वरूप, उन पण्यों के संदर्भ में आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई जहां ढ़ांचागत असंतुलन और पेट्रोलियम और कोयले की कीमतों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने से प्रभावित होगा। दिसंबर 2011 से मुद्रास्फीति का भारी दबाव कम होना शुरू हो गया है तथा मार्च 2012 के लिए थोक

चार्ट 1.10: घरेलू मांग घटकों में मंदी

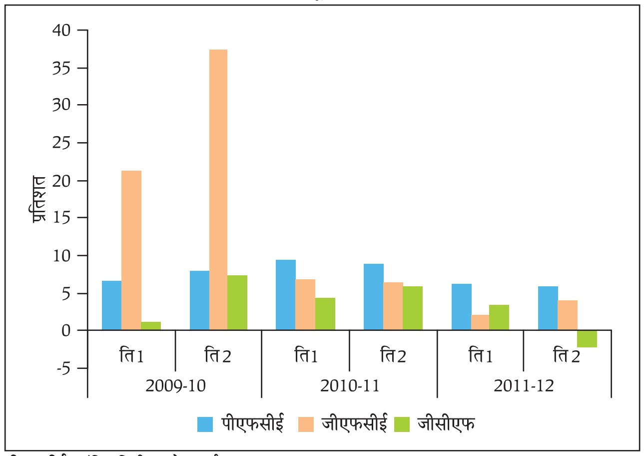

पीएफसीई: अंतिम निजी उपभोग खर्च
जीएफसीई: अंतिम सरकारी उपभोग खर्च
जीसीएफ: सकल पूंजी निर्माण
स्रोत: सीएसओ

चार्ट 1.11: भारत तथा विश्व के अन्य देशों में मुद्रास्फीति

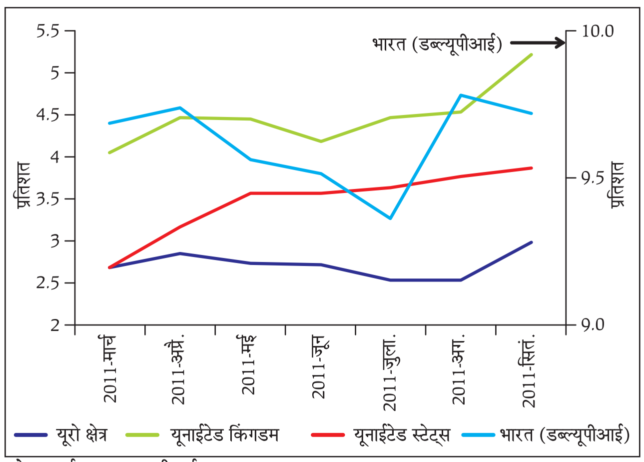

स्रोत: आईएमएफ, आरबीआई

चार्ट 1.12: भारत तथा विश्व के अन्य देशों में खाद्य सामग्री तथा ऊर्जा में मुद्रास्फीति

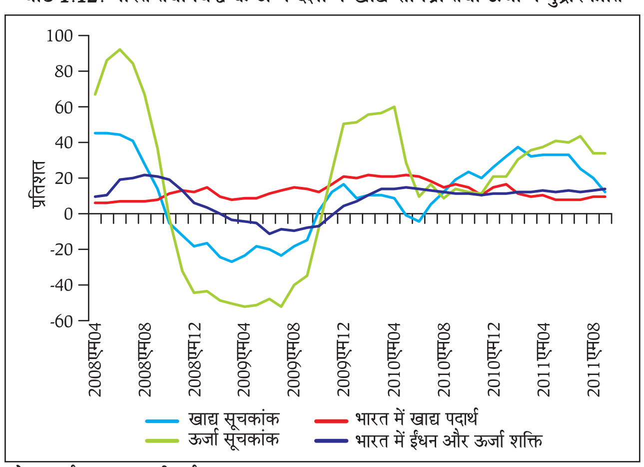

स्रोत: आईएमएफ, आरबीआई

मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) मुद्रास्फीति की आधार रेखा 7 प्रतिशत अनुमानित है। तथापि, आकस्मिक प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है और मुद्रास्फीति का जोखिम निरंतर बढ़ता जा रहा है।

1.15 विनिमय दर में गिरावट से मुद्रास्फीति बढ़ती है क्योंकि इससे तेल तथा अन्य आयातित सामान की लागत बढ़ती है जोकि समग्र उत्पादन के लिए निविष्टियों का काम करती हैं। राजकोषीय घाटा बढ़ने से मुद्रास्फीति पर घरेलू मांग में मंदी का प्रभाव पड़ सकता है और राजकोषीय घाटे से चालू खाता घाटा बढ़ सकता है जोकि आगे चलकर विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। सप्लाई शॉक्स के बने रहने से, विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में आवधिक वृद्धि के कारण, जिनका समूची अर्थव्यवस्था पर तीक्ष्ण प्रभाव पड़ता है, मांग में कमी के कारण मौद्रिक नीति उपायों के नियंत्रणकारी प्रभाव निष्फल हो रहे प्रतीत होते हैं। मुद्रास्फीति अनुमान जोकि निरंतर उच्च स्तर पर बने हुए हैं, से भी मूल्य स्तर में गिरावट नहीं आने पा रही है।

1.16 दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से, कृषि में ढ़ाचागत असंतुलन, आधारभूत ढ़ांचागत क्षमतावरोध और तेल एवं कोयले जैसे मुख्य सामान की प्रशासित असामान्य कीमतों से भी मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम रहता है।

1.17 अन्य विभिन्न समष्टि एवं क्षेत्रीय उत्प्रेरकों के अलावा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता प्रभावित होती है। उच्च मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव जितना अधिक होगा उतना ही अधिक आस्ति गुणवत्ता प्रभावित होगी। मुद्रास्फीति की प्रतिक्रियास्वरूप मौद्रिक नीति के काम करने के तरीके एवं ब्याज दर चक्र में परिवर्तन के आधार पर, आस्ति के विषम लोच एवं बैंकों के दायित्व उपार्जन को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्चतर नीतिगत ब्याज दरें वित्तीय बाज़ारों को प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से विनिमय दर, बांड एवं शेयर बाजारों को बाजार मूल्य लेखाकरण (मार्क-टू-मार्केट एकाउंटिंग) के कारण, बैंक की विशिष्ट जोखिमों के आधार पर, उपार्जन पर दबाव, उच्चतर पूंजी की जरूरत एवं व्यवस्था की भी संभावना हो सकती है। यद्यपि, केवल निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति समष्टि अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय स्थिरता लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी यह सतत रूप से मुख्य पूर्व-शर्त बनी हुई है।

बढ़ता हुआ राजकोषीय दबाव वृद्धि एवं मुद्रास्फीति को बुरी तरह प्रभावित करता है

1.18 हाल ही में राजकोषीय दबाव बढ़ गया है तथा निरंतर उच्च स्तर पर बना हुआ है (चार्ट 1.13)। इस दबाव के और बढ़ने की संभावना है क्योंकि चालू वर्ष के दौरान वित्तीय चूक (फिस्कल स्लिपेज) का जोखिम बढ़ गया है। राजस्व वसूलियों में मंदी तथा खाद्यान्न में संभावित वृद्धि, खाद तथा ईंधन से संबंधित आर्थिक सहायताएं वर्ष 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के बजटीय लक्ष्य को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम सात महीनों के दौरान राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 45.5 प्रतिशत रही जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 65.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 की प्रथम छमाही के दौरान, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण व्यय पर दबाव पड़ सकता है। और फिर पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान आर्थिक सहायताओं और ब्याज भुगतानों में क्रमश: 22.0 प्रतिशत और 19.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जबकि योजना व्यय में मात्र 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजना व्यय में गिरावट, विशेष रूप से पूंजी व्यय, ने वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अप्रैल-सितंबर 2011 के दौरान प्राथमिक घाटा वार्षिक लक्ष्य को पार कर गया है जबकि प्रथम सात महीनों के दौरान राजस्व और वित्तीय घाटा

चार्ट 1.13: राजकोषीय दबाव सूचकांक में उछाल[6]

(1981-82=100)

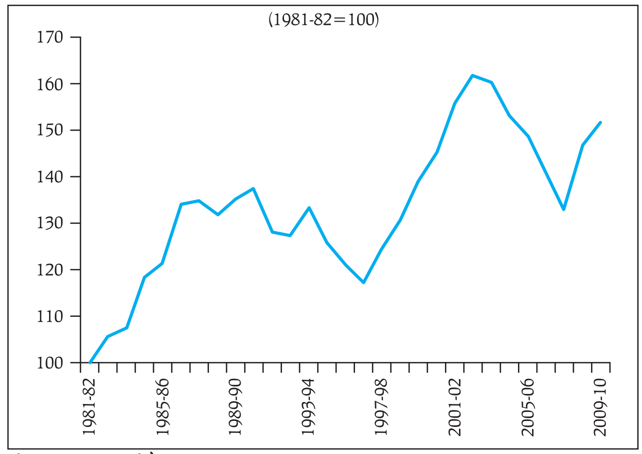

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

[6] बाल्डेक्की, इमेनुएल, जेम्स मैकहफ तथा इवा पेत्रोवा, 2011, ''मेज़रिंग फिस्कल वलनरेबिलिटी एंड फिस्कल स्ट्रेस: अ प्रपोज्ड सेट ऑफ इंडिकेटर्स'', आई.एम.एफ. वर्किंग पेपर 11/94 तथा बाल्डेक्की, इमेनुएल, इवा पेत्रोवा, नजीम बेल्होसिने, गेब्रिएला डोब्रेस्कु तथा समां मज़रानी, 2011, ''असेसिंग फिस्कल स्ट्रेस'', आई.एम.एफ. वर्किंग पेपर 11/100 में सुझाई गई पद्धति पर आधारित। प्रस्तुत प्रक्रिया में तीन संकेतकों यथा सकल प्राथमिक शेष, सकल राजकोषीय घाटा तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बकाया देयताओं का उपयोग किया गया है।

क्रमश: अपने वार्षिक लक्ष्यों के 79 और 74 प्रतिशत से अधिक हैं। सरकार ने बढ़ी हुई बाजार उधारियों की घोषणा कर दी है। 2011-12 की अनुपूरक अनुदान मांगों की दूसरी बैच जिसमें ₹56,848 करोड़ के शुद्ध नकद व्यय सहित ₹63,180 करोड़ का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है, की घोषणा नवंबर 2011 में की गई। तथापि, भारत का सरकारी ऋण बनाए रखने लायक है क्योंकि इसे अधिकांशत: घरेलू संस्थाओं द्वारा लिया जाता है, इसकी औसत परिपक्वता उच्च है तथा लागत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम।

1.19 वर्तमान समय में कई सारे कारक वित्तीय समेकन को बाधित करते प्रतीत होते हैं। वृद्धि एवं मांग में मंदी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर वसूलियों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। निश्चल तेल कीमतों तथा मुख्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (न्यू.स.मू.) में वृद्धि के साथ आर्थिक सहायता व्यय पर भी दबाव पड़ने की संभावना है। बाज़ार की कमजोर स्थितियां भी विनिवेश योजना को संकट में डाल सकती है। वित्तीय चूक (फिस्कल स्लिपेज) सरकार की उधारी ब्याज लागत को बढ़ा सकती है जो बाद में राजकोषीय घाटा एवं दबाव पर प्रतिक्रियात्मक प्रभाव डाल सकती है।

कच्चे माल तथा ब्याज की बढ़ती हुई लागत और घटी हुई मूल्य निर्धारण शक्ति का प्रभाव कार्पोरेट सेक्टर के गिरते हुए मार्जिन में दृष्टव्य है

1.20 कार्पोरेट मार्जिन्स पहली दो तिमाहियों में गिर रहीं हैं। बिक्री और कर पश्चात लाभ का अनुपात वर्ष 2011-12 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान वर्ष 2010-11 की पिछली तिमाही में अपने स्तर की तुलना में 200 आधार बिन्दु से भी अधिक गिर गईं जोकि निविष्टियों तथा ब्याज की बढ़ती हुई लागतों एवं घरेलू मांग में मंदी को प्रदर्शित करती हैं (चार्ट 1.14)। अब तक बिक्री में ब्याज लागतों के बढ़ते हुए अंश तथा सकल लाभ ईंगित करते हैं कि कार्पोरेटों के मार्जिनों पर मौद्रिक कठोरता का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से पड़ रहा है।

1.21 फर्मों के परिणाम कमजोर स्थिति को प्रकट करते हैं जिसकी वजह निविष्टियों की कीमतों, ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी, मांग में मंदी तथा कुछ आधारभूत ढ़ांचागत अवरोध हो सकते हैं, इसीलिए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सेवा पर दबाव पड़ सकता है। मांग की स्थितियों में कुछ मंदी थी जैसा कि भा.रि.बैं. की औद्योगिक परिणाम सर्वेक्षण (चार्ट 1.15) में उत्पादन, आदेश पुस्तकों, क्षमता संदोहन, आयात तथा निर्यात संबंधी मदों में दिखाया गया है। यह मंदी लघु आकार की कंपनियों में और अधिक थी।

चार्ट 1.14: ब्याज लागत में उछाल एवं लाभ में गिरावट

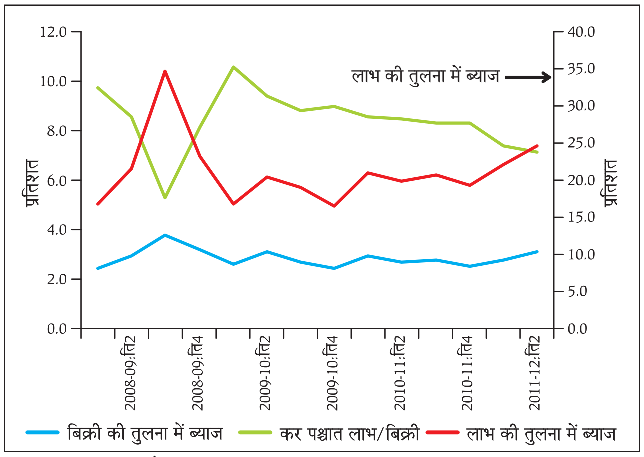

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 1.15: औद्योगिक क्षेत्र का परिदृश्य

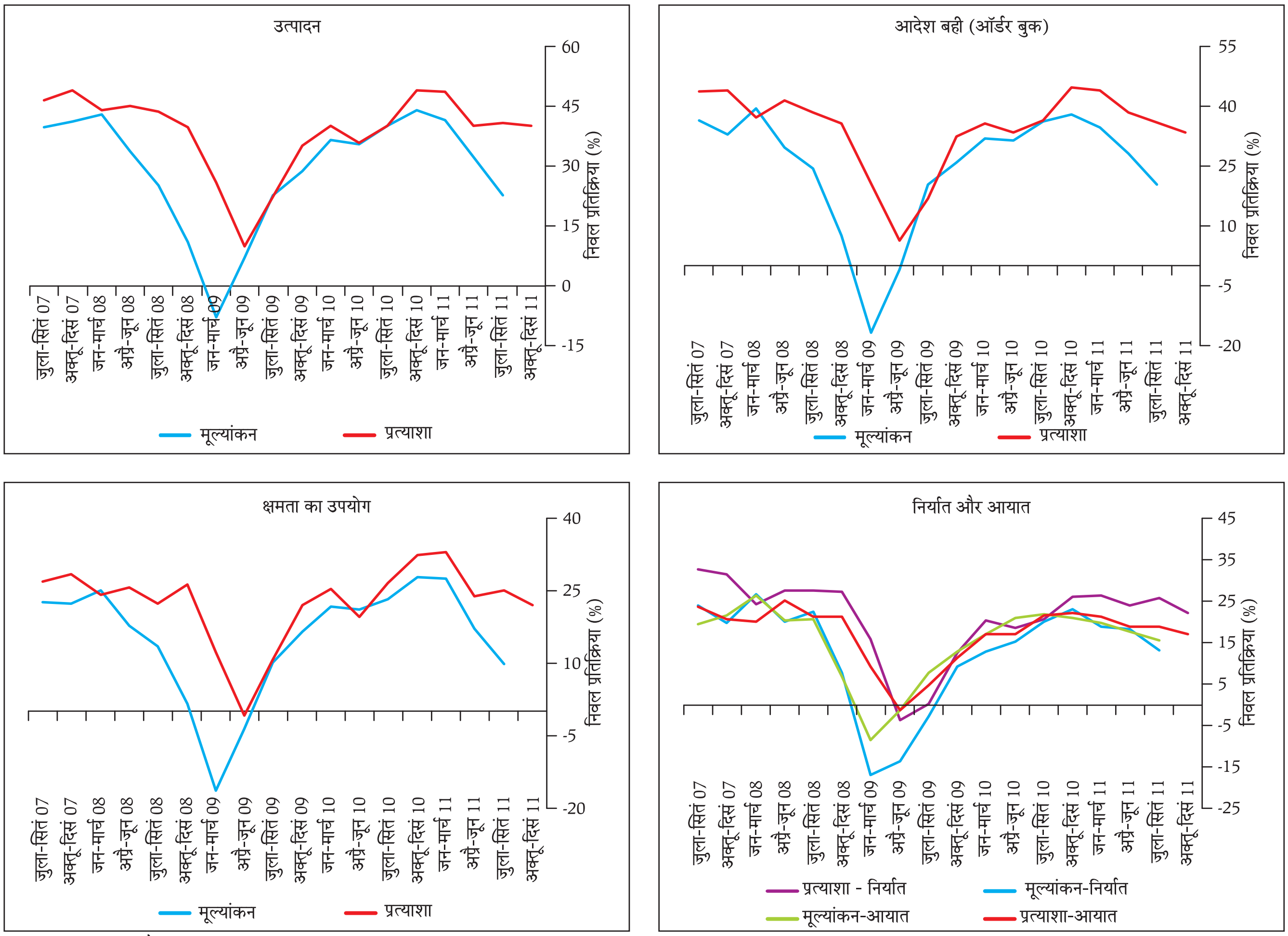

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

हालाँकि कीमत बढ़ने से ऋण की लागत में बढ़ोतरी होती रही, फिर भी घरेलू क्षेत्र को दिए गए ऋण की मात्रा में और परिसंपत्ति की गुणवत्ता के स्तर में भी गिरावट दर्ज हुई.... किंतु मामूली सी

1.22 मुद्रास्फीति के असर और ऋण की लागत में हुई बढ़ोतरी ने रिटेल ऋण पर खास प्रभाव तो नहीं छोड़ा है, तथापि, रिटेल ऋण में आई गिरावट के लिए आधारभूत (बेस) प्रभाव को कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में कुछ हद तक खराब हुई है, फिर भी एनपीए अनुपात का स्तर 2009 और 2010 में पहुंचे चरम स्तर से काफी नीचे रहा (चार्ट 1.16)।

चार्ट 1.16: रिटेल ऋण और रिटेल एनपीए के अनुपात में बढ़ोतरी

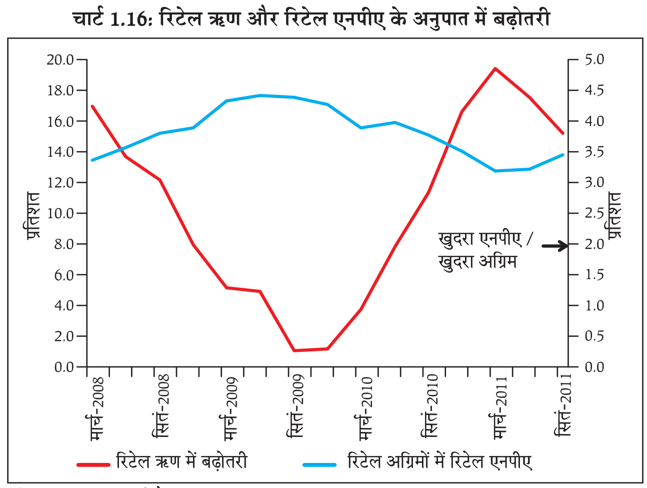

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

..... और आवासों की कीमत लगातार बढ़ती रही

1.23 पंद्रह शहरों के समावेश वाले रेसिडेक्स के औसत भारांक पर आधारित अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक से आवास की कीमत में आई तेजी पता चलती है।[7] ऋण की बढ़ती लागत और कम बिक्री संबंधी रिपोर्टें आने के बावजूद 2011-12 की पहली छमाही में आवास की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं (चार्ट 1.17)।

1.24 आवास की कीमतों और ब्याज की लागत में हुई बढ़ोतरी की दृष्टि से आवास ऋण की मात्रा में हुई कमी काफी महत्व रखती है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता कुछ हद तक खराब हुई है, किंतु आवास क्षेत्र के मामले में एनपीए अनुपात का स्तर 2009 और 2010 के चरम स्तर से काफी कम रहा (चार्ट 1.18)।

चार्ट 1.17: अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक

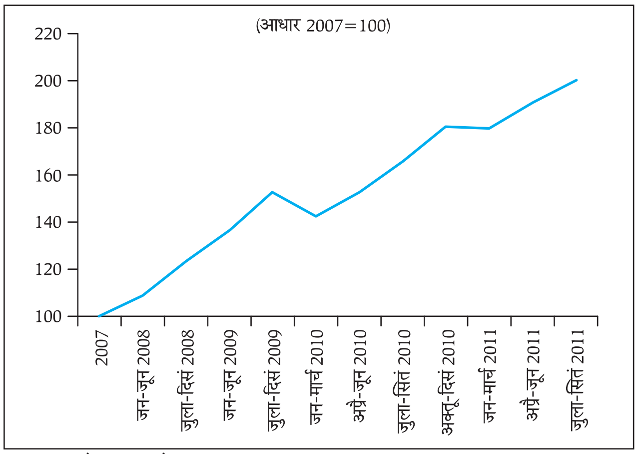

स्रोत : राआबैंक, रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा किए गए परिकलन

चार्ट 1.18: आवास ऋण और आवास एनपीए अनुपात में बढ़ोतरी

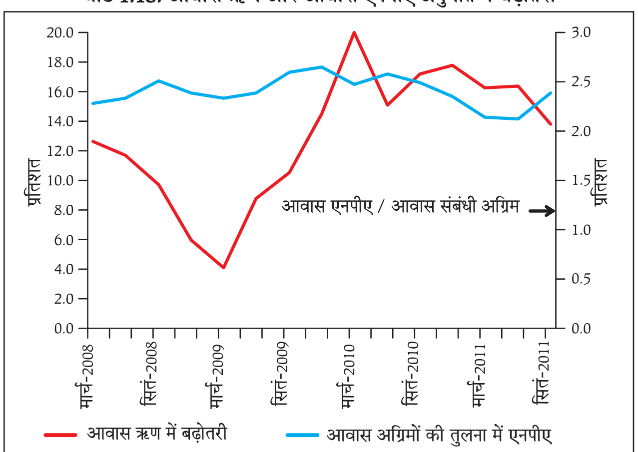

स्रोत : रिज़र्व बैंक स्टाफ

निष्कर्ष

1.25 दीर्घकालीन मंदी, राष्ट्रिक कर्ज के दबदबे और विश्वसनीय समाधान तंत्र के अभाव के चलते वर्तमान में सारे विश्व में अनिश्चित स्थिति पैदा हो गई है। भारत में व्यापार, वित्त, पण्य-वस्तु और कान्फिडेंस चैनलों के माध्यम से इन वैश्विक घटनाओं का प्रभाव महसूस किया गया। प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों और समूचे राष्ट्र के स्तर पर दीर्घकालीन खाद्य मुद्रास्फीति, ऊर्जा की ऊँची कीमतें, कतिपय क्षेत्रों में क्षमता के अभाव से पैदा होने वाले अवरोधों और निवेश कार्यकलापों की गति धीमी होने जैसे कारक लंबे समय तक उच्च संवृद्धि बनाए रखने के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। औद्योगिक और सेवा दोनों क्षेत्रों में ढीलापन के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अदृश्य मदों के कारोबार की गति में धीमापन के साथ-साथ अन्य व्यापारों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव, बड़े पैमाने पर किए गए तेल के निर्यात तथा बुलियन, मशीनों और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में आई तेजी आदि से भी चालू खाता घाटा बढ़ने के संकेत मिले।

1.26 वर्ष की पहली छमाही में वित्तीय घाटे में हुई बढ़ोतरी के चलते अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव बढ़ गया। मंद संवृद्धि, कतिपय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के ऊँचे मूल्य, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी, बाज़ार में विनिवेश के लिए अनुकूल स्थिति और ऊँची ब्याज दरें राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर रोड़ा बन गई हैं।

1.27 मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की प्रत्याशा का स्तर ऊँचा बना रहा तथा वर्तमान में इससे कृषि क्षेत्र में ढांचागत असंतुलन, बुनियादी संरचना के क्षमता निर्माण में अवरोध, प्रमुख पण्य-वस्तुओं के नियंत्रित मूल्य में अराजकता, विनिमय दर में ह्रास और वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी होने की वजह से ऊर्ध्वमुखी जोखिम पैदा होने की आशंका है। दिसंबर 2011 से मुद्रास्फीतिजन्य दबाव में मामूली गिरावट आने लगी है और यह आकलन किया गया है कि मार्च 2012 के लिए थोक मूल्य सूचकांक वाली मुद्रास्फीति का बेसलाइन पूर्वानुमान 7 प्रतिशत रहेगा। किंतु इसमें अचानक कोई अनिश्चित स्थिति पैदा हो सकती है।

1.28 वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ने के फलस्वरूप कार्पोरेट क्षेत्र में कमजोरी दिखाई पड़ रही है और इस क्षेत्र की संवृद्धि की गति धीमी हो गई है। तथापि, रिटेल ऋण में लगातार उच्च संवृद्धि से घरेलू क्षेत्र की क्षमता का पता चलता है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में भी गिरावट देखी गई, किंतु एनपीए का स्तर 2009 और 2010 के उच्चतम स्तरों से काफी नीचे बना रहा।

1.29 समग्र रूप से समष्टि-आर्थिक दबाव बढ़ता रहा है, किंतु इसका स्तर वैश्विक संकट के परिणामी प्रभाव से पहुंचे स्तर से काफी नीचे है।

[7] रेसिडेक्स राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला शहर-वार आवास मूल्य सूचकांक है। शहर-वार आवास ऋण का प्रयोग अखिल भारतीय सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित दो कारणों को ध्यान में रखते हुए भारांक के रूप में किया जाता है : (क) आवास की कीमत में होने वाला घट-बढ़ इस प्रकार सामने आए कि वह अन्य भारांकों (उदाहरणार्थ आबादी, परिवारों की संख्या, कुल जमा-राशि/ऋण की राशि) के प्रयोग से पता चलने वाले परिवर्तनों से अलग दिखाई पड़ सके, तथा (ख) वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में आवास ऋणों का निष्पादन चिंता का विषय है।

अध्याय II

वित्तीय बाज़ार

संपूर्ण विश्व और घरेलू वित्तीय व्यवस्था, प्रणालीगत जोखिम का सामना कर रही हैं और यह जोखिम हाल के समय में और भी गहरा गया है। रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग कम किए जाने एवं खराब आर्थिक परिदृश्य के कारण प्रमुख एवं गैर-प्रमुख दोनों क्षेत्रों में वित्तीय बाज़ार की स्थिति अत्यधिक खस्ताहाल हुई है। विभिन्न करेंसियों में अल्प एवं दीर्घकालीन निधि प्रदान करने वाले बाज़ारों पर दबाव बढ़ गया है जिसकी वजह से वित्तीय एवं गैर-वित्तीय फर्मों को दीर्घकालीन निधि जुटाने में अत्यधिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय बाज़ार में कारोबार का रुझान इसलिए धीमा है क्योंकि उनका मानना है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक और राजकोषीय हस्तक्षेप का प्रभाव काफी हद तक कम रहा है। इतनी उच्च स्तरीय अस्थिरता के कारण विदेश में बाज़ार के सहभागियों को बाज़ार की नब्ज़ पहचानना मुश्किल हो गया है। इन घटनाओं के चलते भारत में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय फर्मों द्वारा विदेश से लिए जानेवाले उधार पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। भारत के इक्विटी एवं विदेशी मुद्रा बाज़ार में अत्यधिक अस्थिरता के साथ-साथ भारी सुधार करने की ज़रूरत दरपेश रही है। फलस्वरूप निवेशकों की भावनाओं पर जो प्रभाव पड़ा था उसकी आंशिक भरपाई इस वर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में हुए सुधार से हो गई। हालांकि, अपेक्षा से अधिक सरकारी उधार, साथ ही वृद्धि-दर की खोई हुई गति की वजह से घरेलू वित्तीय बाज़ारों पर दबाव पड़ सकता है।

वित्तीय बाज़ार में बढ़ती हुई चिंताएं

2.1 भारत में वित्तीय बाज़ारों की हालत ठीक थी किंतु जून 2011 में जारी की गई पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से लेकर इस अवधि के दौरान स्थिति बदतर हो गई है। इस अवधि के दौरान घरेलू जोखिम में मामूली वृद्धि हुई है। बाहरी जोखिमों का प्रभाव घरेलू वित्तीय स्थिरता पर पड़ने लगा है। जितने भी घरेलू बाज़ार हैं, उनमें से विदेशी मुद्रा और इक्विटी बाज़ारों पर काफी दबाव दिखाई दिया है। वित्तीय बाजार स्थिरता मानचित्र[1] और वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक (एफएमएसआइ)[2] (चार्ट 2.1 एवं 2.2)[3], जिसमें न केवल बाज़ार के वेरियबल शामिल हैं बल्कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में निधि प्रदान करने की चलनिधि -

चार्ट 2.1 : वित्तीय बाज़ार स्थिरता मानचित्र

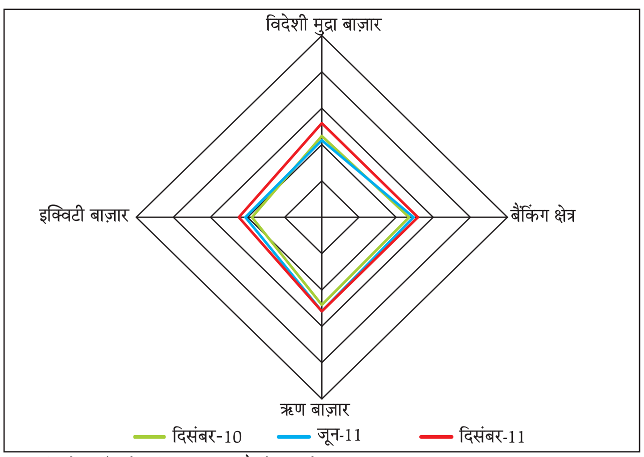

टिप्पणी: केंद्र बिंदु से दूरी का आशय है जोखिम में वृद्धि
स्रोत: भा. रि. बैं. स्टाफ गणना

चार्ट 2.2 : वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक

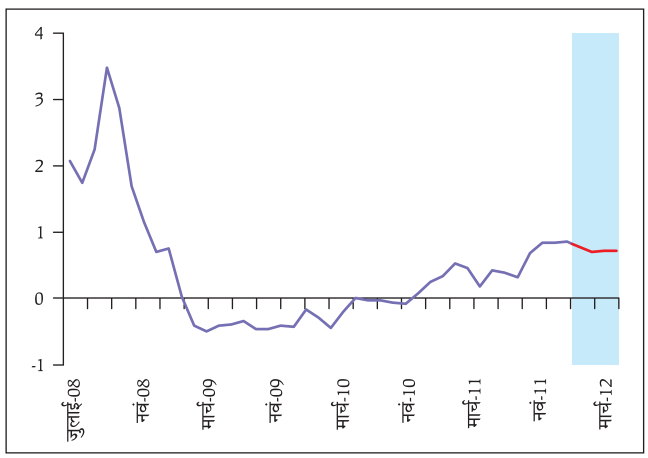

टिप्पणी : संकेतक मूल्य में वृद्धि न्यूनतम स्थिरता दर्शाती है जन 12 से मार्च 2012 तक पूर्वानुमानित मूल्यों को छायांकित किया गया है।
स्रोत : भा. रि. बैं. स्टाफ गणना

---

[1] वित्तीय बाज़ार स्थिरता मैप, विभिन्न बाज़ारों में दबाव में वृद्धि का विजुअल प्रदर्शन है। किसी भी चर का केंद्र बिंदु से अलग स्थित होना यह दर्शाता है कि अस्थिरता के माध्यम से मापा गया दबाव बढ़ रहा है। यह अपनी गणना में इक्विटी, ऋण एवं विदेशी मुद्रा बाज़ार की स्थिति को लेता है। इसके अतिरिक्त, मैप में बैंकों की निधि प्रदान करने की स्थिति को भी गणना में लिया गया है।

[2] वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक में ऋण, विदेशी मुद्रा बाज़ार, इक्विटी बाज़ार और बैंकिंग क्षेत्र के चरों में होने वाले परिवर्तनों को गणना में लिया जाता है। संकेतक का डिजाइन बैंक आफ कनाडा के मॉडल के समान है जो विकसित अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया है। वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक को भारतीय बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। उच्च मूल्य अधिक जोखिम दर्शाते हैं।

[3] तौर-तरीके इस रिपोर्ट के अनुबंध में बताए गए हैं।

स्थिति भी शामिल है, ने विपरीत रूख अपनाना शुरू कर दिया। एफएमएसआइ के पूर्वानुमान यह बताते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है वही स्थिति मार्च 2012 तक बनी रहेगी।

वैश्विक सरकारी बाण्ड बाज़ार, सारणी क्षेत्र से बाहर रहे

2.2 वित्तीय संकट के कारण निजी क्षेत्र के तुलनपत्र में डेलिवरेजिंग अत्यधिक रही और फलस्वरूप उसमें हुई गिरावट को राजकोषीय-वृद्धि से पूरा किया गया। संकट का दौर प्रारंभ होने के बाद से विश्व अर्थव्यवस्था अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रही है, वहीं अर्थव्यवस्था में लड़खड़ाते सुधार की स्थिति ने लोक-वित्त पर और अधिक दबाव बना दिया है। ग्रीस को छोड़कर, पुर्तगाल और आयरलैंड ने भी उबारने वाले पैकेज का सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त, स्पेन और इटली के सरकारी बाण्ड बाज़ारों में भी अत्यधिक अस्थिरता बनी रही है (चार्ट 2.3)। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यूरोप का ऋण-संकट अपनी परिधि से बाहर निकलकर प्रमुख क्षेत्रों तक फैल रहा है। यहाँ तक कि फ्रांस और जर्मनी के सीडीएस (ऋण-चूक विनिमय) मूल्य यह दर्शाते हैं कि यूरोप में उबारने वाले पैकेजों की लागत बढ़ रही है (चार्ट 2.4)।

2.3 कुछेक यूरोपीय सरकारी बाण्डों के बाज़ार को अपने स्थान से हटना पड़ा है, यहां तक कि ग्रीस के मामले में तो उसे व्यावहारिक रूप से बंद ही कर दिया गया है। यूरोपीय वित्तीय स्थिरता निधि का उपयोग बढ़ा दिया गया है तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक, संकट का सामना करने के लिए गैर-परंपरागत मौद्रिक उपायों का प्रयोग कर रहा है। अमरीका में, अमरीकी तिजोरियों की रेटिंग कम हो जाने से अमरीकी तिजोरियों को छोड़कर अन्य समस्त बाज़ारों को उसने निर्मम तरीके से मंदी की स्थिति में ढकेल दिया है। अमरीकी तिजोरी बाण्डों पर मिलने वाला प्रतिफल ऐतिहासिक रूप से निम्नतर स्तर तक गिर गया है।

.... जो अस्थिरता की वांछित सीमा के उल्लंघन का कारण बना हुआ है

2.4 यूरोप में सरकारी बाण्डों के संबंध में रेटिंग की कार्रवाई ने बाज़ार की भावनाओं को और भी पस्त कर दिया है। जहां अमरीका में राजकोषीय विस्तार को दुरुस्त करके वापस सही हालत में लाने एवं यूरोप में और अधिक उबारने वाले पैकेज लाने की शर्तों पर राजनीतिक सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं वित्तीय बाज़ारों में कारोबार अत्यधिक अस्थिरता की हालत से गुजरा है। VIX[4], अनिश्चितता का एक उपाय, (अमरीकी इक्विटी बाज़ार में) जो वांछित सीमा 30 से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ गया और यूरोप तथा भारत में अपने प्रतिपक्षों को भी उक्त सीमा से ऊपर खींच ले गया है (चार्ट 2.5)।

चार्ट 2.3 : सोवरीन सीडीएस मूल्य 5 वर्ष-परिपक्वता

(आधार अंकों में)

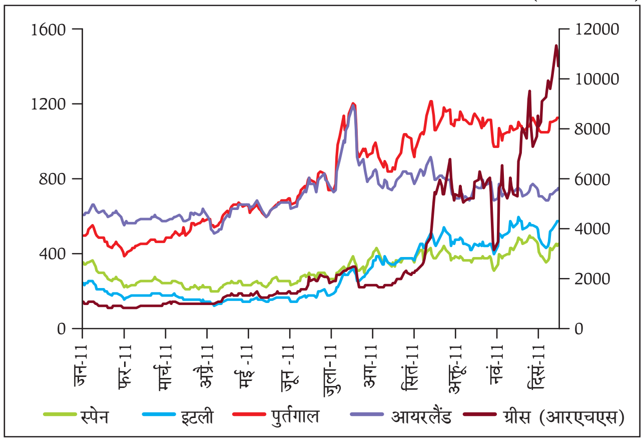

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.4 : सोवरीन सीडीएस मूल्य 5 वर्ष-परिपक्वता

(आधार अंकों में)

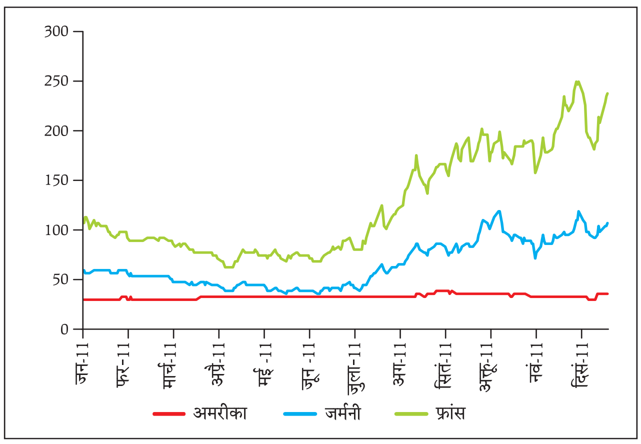

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.5 : अमरीका, यूरोप और भारत में इक्विटी बाज़ार आधारित सूचकांक में अस्थिरता

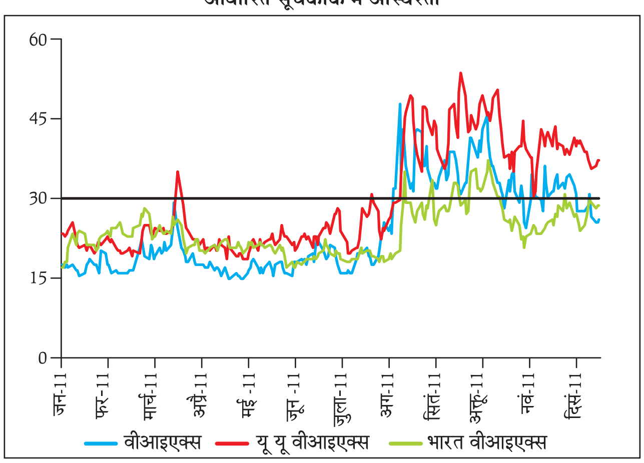

स्रोत : ब्लूमबर्ग

[4] वीआइएक्स ऐसा सूचकांक है जो बाज़ार की भावी अस्थिरता का अनुमान प्रस्तुत करता है। यह अमरीकी एसएंडपी 500 स्टॉक बाज़ार सूचकांक पर ऑप्शंस पर की गई स्ट्राइक की लंबी श्रृंखला के मूल्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार, सारणी में यूरोपियन यूनियन वीआईएक्स तथा भारत वीआइएक्स क्रमश: यूरोपियन यूरोस्टाक तथा भारतीय निफ्टी सूचकांक में ऑप्शंस के मूल्यों पर आधारित हैं। इसे प्राय: 'भय मापक' कहा जाता है।

राजकोषीय दबाव बैंकों के स्वास्थ्य तक फैल गया ....

2.5 अमरीका और यूरोप में हाल में हुई रेटिंग में कमी (चार्ट 2.6) यह दर्शाती है कि इसमें प्रभावित करने की इतनी अधिक क्षमता थी कि उसने सरकारी ऋण की गुणवत्ता को तो जर्जर बनाया ही, साथ ही संबंधित बाज़ार पर भी दबाव बना दिया। सरकारी ऋण जोखिम की मार यूरोप के बैंकों और उनके निधि उपलब्ध कराने वाले बाज़ारों पर पड़ी। ऐसे समय में जब सरकारी ऋण का जोखिम बढ़ रहा होता है, तो बैंकों के सामने मीयादी निधि जुटाने के लिए पूंजी बाज़ार में पहुंच बनाने की चुनौती पैदा हो जाती है। क्योंकि सरकारी ऋण की गुणवत्ता और उसका आर्थिक - निष्पादन दोनों ही बैंकिंग प्रणाली की शक्ति के इनपुट हैं। फलस्वरूप, यूरोप में बैंकों के स्टॉक में बृहत् बाज़ार सूचकांक की तुलना में तेज़ी से सुधार हुआ (चार्ट 2.7)।

लिबोर बाज़ार को बाधित करने वाला ....

2.6 सरकारी ऋण की खराब स्थिति के फलस्वरूप बैंक एक-दूसरे को उधार देने के लिए कम इच्छुक थे। इसका प्रभाव लिबोर बाज़ार में तीन प्रकार से पाया गया, राशि, लागत और उधार-परिचालन की परिपक्वता। बाज़ार में टर्नओवर गिर गया। लागतें बढ़ गईं और अंतर-बैंक उधारों की परिपक्वता अवधि छोटी होती जा रही है। लिबोर-ओआइएस का स्प्रेड, अमरीकी डालर एवं यूरो दोनों में बढ़ता चला गया (चार्ट 2.8)। प्रतिपक्ष में जोखिम उठाने की भूख कम होने के कारण बैंकों ने अपनी अधिशेष राशियों को ईसीबी (बाह्य वाणिज्यिक उधार) में लगाने को तरजीह दी। ईसीबी में जमा राशि काफी तेज़ी से बढ़ती जा रही है (चार्ट 2.9)।

चार्ट 2.6 : विभिन्न एजेंसियों द्वारा यूरोप की सोवरीन रेटिंग

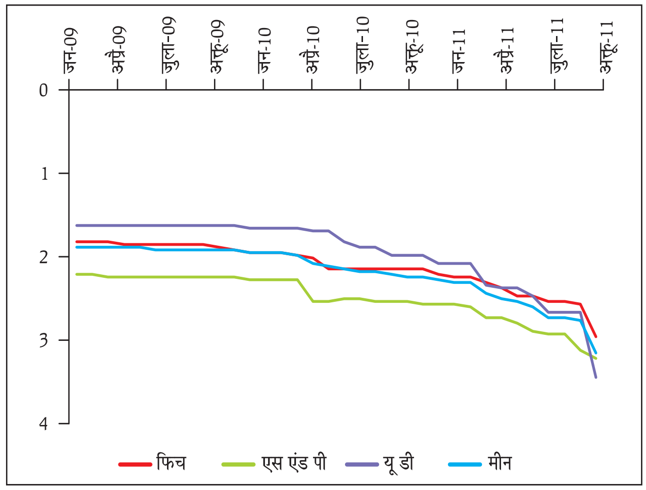

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.7 : यूरोपियन बृहत एवं बैंक स्टॉक सूचकांक (सामान्यीकृत, 3 जनवरी, 2011 = 100)

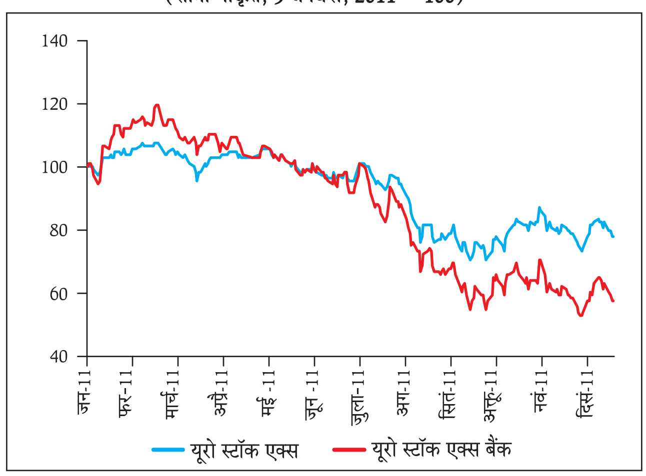

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.8 : यूरो और अमरीकी डालर में लिबोर-ओआइएस स्प्रेड (3 महीने में)
(आधार अंक में)

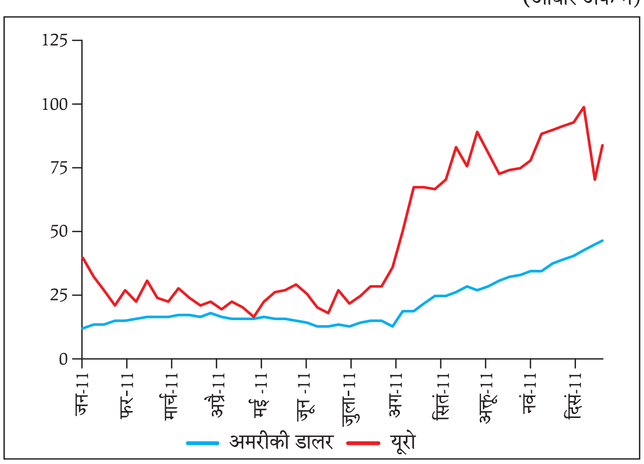

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.9 : बाह्य वाणिज्यिक उधार के साथ जमा शेष
(बिलियन यूरो में)

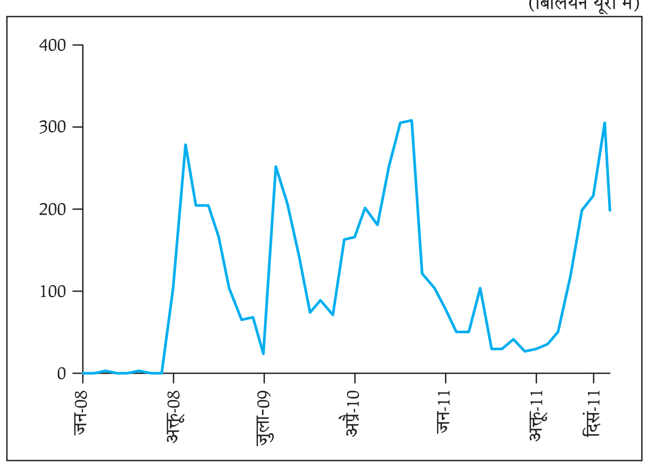

स्रोत : ब्लूमबर्ग

....और घरेलू संस्थाओं के लिए अमरीकी डालर में निधि उपलब्धता महंगी होती गई

2.7 बैंकों के पास धारित अंतर-देशीय आस्तियां खासी मात्रा में हैं और ऋण जोखिम अन्य देशों से निकलकर बैंकों तक, जिनमें भारत शामिल है, फैल चुका है। भारत की फर्मों को दिए जाने वाले वित्त और पूंजी निवेश हेतु सीमा पार के ऋण में काफी गिरावट आई है। भारत में वित्तीय और गैर वित्तीय फर्मों, दोनों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारों के उगाहने में होने वाली समस्याओं के संदर्भ में कुछ कथाश्रित स्वरूप के प्रमाण हैं। भारतीय फर्मों और बैंकों के लिए यूरोपियन बैंक की वित्त पोषण चिंताएं अपने परिचालन हेतु विदेशी पूंजी के उगाहने में चुनौती पेश कर सकती हैं। यूरो/यूएस में विनिमय मुद्रा आधारित अदला-बदली (सीसीबीएस) काफी कटौती पूर्ण दरों पर व्यापार करते हुए यह प्रदर्शित कर रही है कि यूरोपियन बैंकों के लिए यूएस डॉलर वित्त पोषण की लागतों में वृद्धि हुई है। सीसीबीएस में कटौती स्वरूप यह अतिरिक्त लागत भारतीय बैंकों तक विस्तारित हो सकती है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर राजकोषीय और मौद्रिक अवलम्बों की वजह से अधोगामी झुकाव

2.8 मौद्रिक नीति की दरें पहले ही अपनी निचली सीमाओं में अथवा उनके निकट हैं और कर्ज का स्तर इतना अधिक है कि उसके लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की संभावना बहुत कम रह जाती है। ईसीबी द्वारा यूरोप में बाज़ारों को स्थिर करने के दो दौर में किए गए प्रयासों से यूरोपीय सरकारी बांड बाज़ारों में फैलता संक्रमण सीमित नहीं हो पाया है। संयुक्त अमेरिका में मात्रात्मक ढिलाई और नीतिगत दरों को विस्तारित अवधि तक कम करने की पूर्व-प्रतिबद्धता के विविध कार्यक्रमों का अपेक्षित स्तर से कम प्रभाव हुआ है। वित्तीय बाज़ारों में तनाव को बढ़ाने में इस विश्वास ने योगदान दिया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रभावी मौद्रिक और राजकोषीय हस्तक्षेप की संभावनाएं कम हो गई हैं।

निवेशकों का जोखिम उठाने के व्यवहार से जोखिम से बचने के व्यवहार की ओर पलटना

2.9 वर्तमान में सरकार और बैंक जिन तनावों से गुज़रे हैं उससे पूर्व, निवेशक जोखिम उठाने की मन:स्थिति में थे। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूर्व में कम ब्याज दरों ने आय की खोज के लिए उकसाया। पोर्टफोलियो के लिवरेज ऋणों, संकटपूर्ण कर्ज और उच्च आय वाले बांडों जैसी अधिक जोखिम वाली आस्तियों में निवेश द्वारा उच्च आय की प्राप्ति की ओर झुकाव की प्रवृत्ति के संकेत थे। मजबूत राजकोषीय स्थिति और बेहतर आर्थिक संभावनाओं के जोर पर उच्च आय वाली उभरती बाजार आस्तियां जैसे भारतीय बांड और इक्विटी इस प्रवृत्ति के प्रमुख लाभान्वित होने वालों में से थे। तनाव बढ़ने के साथ-साथ निवेशक तेजी से अपनी क्रियाओं को विपरीत दिशा में ले जाने लगे हैं (चार्ट 2.10 और 2.11)।

चार्ट 2.10 : 2011 में वित्तीय संस्थागत निवेशक द्वारा निवल खरीद और भारतीय रुपया

(करोड ₹ में)

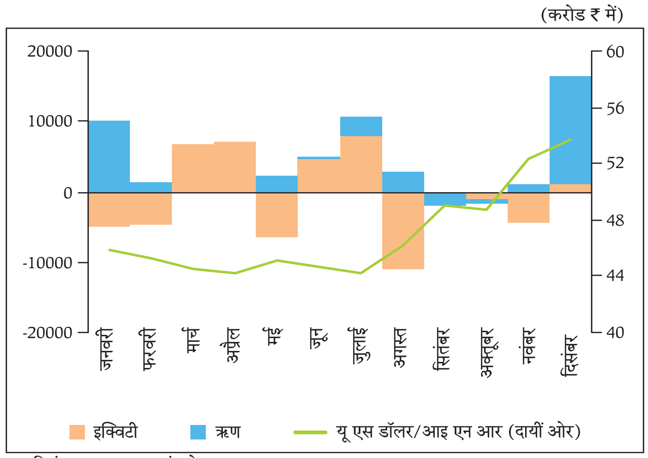

14 दिसंबर 2011 तक आंकड़े

स्रोत : सेबी, ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.11: चालू और पूँजी खाता निवल प्रवाह

(मिलियन यू एस डॉलर में)

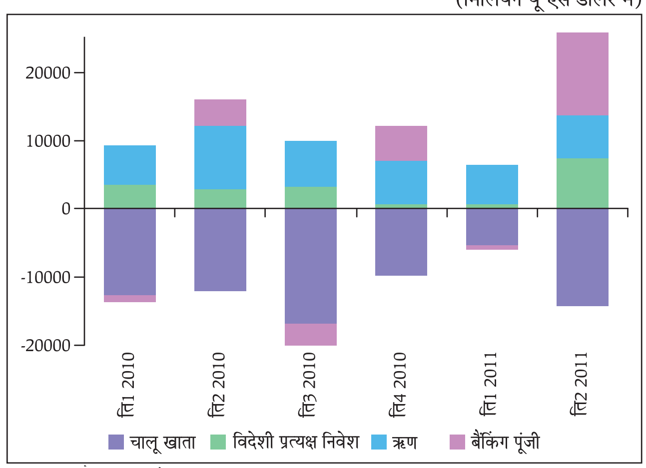

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत सरकार के बांड बाज़ार में संक्रामक जोखिम हेतु उच्चतम सीमा निर्धारित

2.10 अतीत की तुलना में हाल के कुछ महीनों में भारत सरकार के बांड बाजार में काफी अधिक उतार-चढ़ाव रहा है बांड बाज़ार में उतार-चढ़ाव अन्य के अतिरिक्त अपेक्षित से कहीं अधिक आपूर्ति (सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के उत्तर अर्धवर्ष के लिए उधार कैलेंडर ₹2.2 लाख करोड़ पर घोषित किया जो बजटीकृत राशि से ₹52,872 करोड़ अधिक था) और महंगाई की प्रवृत्ति की अनिश्चितता के कारण हुआ। वित्तीय वर्ष 2011-12 के बाद के अर्धवर्ष के लिए सरकार के उधारों में अनपेक्षित वृद्धि से अन्य बातों के अतिरिक्त ब्याज दरों में भारी वृद्धि हुई और 10 वर्ष के बांड पर आय 9 प्रतिशत के निकट पहुंच गया (चार्ट 2.12)। तथापि, यह बाजार, विदेश से मांग के आघातों से काफी हद तक सुरक्षित है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश (वर्तमान में सरकार के लिए उच्चतम सीमा यूएस 15 बिलियन डालर है और केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए यूएस 550 बिलियन डालर से अधिक का बकाया है) पर उच्चतम सीमा निर्धारित है और लिए गए कर्ज मुख्यत: घरेलू संस्थाओं विशेषत: वाणिज्य बैंकों के पास हैं।

चार्ट 2.12: विविध परिपक्वता में सरकारी प्रतिभूतियों पर आय
(प्रतिशत में)

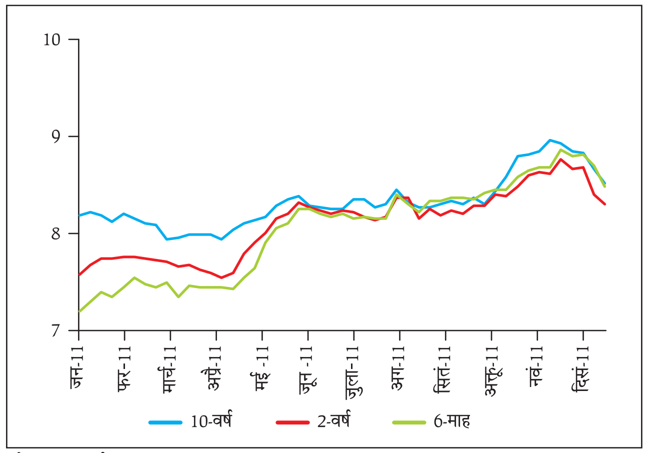

स्रोत : ब्लूमबर्ग

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है

2.11 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) घरेलू बचत और निवेश के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक है। घरेलू और विदेशी उधारों के बीच उच्च ब्याज दरों के अंतर, फर्मों को विदेश से उधार लेने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप चंद कार्पोरेट तुलन-पत्रों में उच्च मुद्रा विसंगतियां देखी जाती हैं। किंतु, यूरोप से उत्पन्न वर्तमान तनाव बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं।

चार्ट 2.13: ईसीबी और एफसीसीबी की परिपक्वताएं
(मिलियन यू एस डॉलर : जून 2011 के अनुसार)

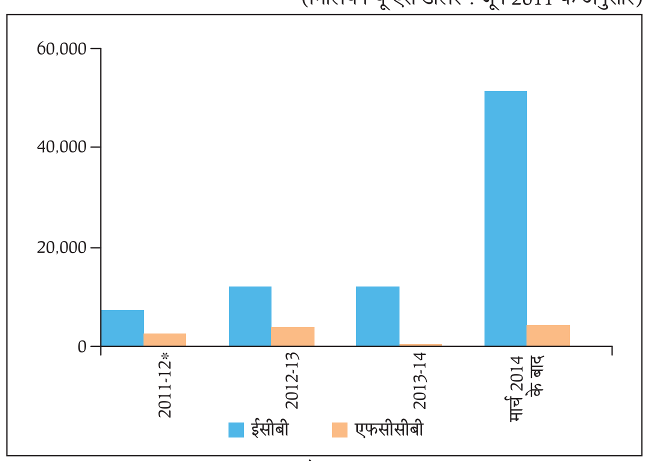

* आंकड़े अक्तूबर 2011 से मार्च 2012 तक के हैं
स्रोत : भा.रि.बैंक

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के लिए मोचन दबाव विद्यमान हैं .... पर्याप्त सावधानियां बरती गयी हैं

2.12 जून 2011 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह उजागर किया गया था कि कई फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के कारण जोखिमों का समाना करना पड़ रहा है जो निकट भविष्य में मोचन के लिए देय होने वाले हैं (चार्ट 2.13)। इसमें संभावित प्रणालीगत ज़ोखिम का भी उल्लेख किया गया है जो कई फर्मों के, इक्विटी के मूल्य काफी गिरने और परिणामस्वरूप मोचन आवश्यक हो जाने के कारण, वित्त पोषण के अभाव का सामना करने की वजह से उभर सकता है। ऋण प्राप्ति के विदेशी स्रोत, जोखिम विरोध में वृद्धि के परिणामस्वरूप (यूरोपीय कर्ज संकट के अनंतर) घटते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रुपया का हाल के महीनों में तीव्र मूल्यह्रास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मोचन की लागत बढ़ गयी है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय

बांड जो वित्तीय संकट के पूर्व के वर्षों में लिए गए थे और जिनके शून्य अथवा कम कूपन थे उन्हें घरेलू उधार से बदलना होगा जिसकी दरें आज काफी अधिक हैं। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के जारीकर्ताओं को हो रही कठिनाइयों को खत्म करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार से परामर्श कर विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों को कटौतीपूर्ण दरों पर पुन: खरीद करने की अनुमति दे दी है, ऐसे पुन: खरीद के लिए मार्गों को और प्रशस्त कर दिया है और स्वचालित रूट के अंतर्गत विदेशी उधारकर्ताओं से पुनर्वित्त प्राप्ति के लिए फर्मों को अनुमति दे दी है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्संरचना के प्रस्तावों पर, जिनमें परिवर्तन-मूल्य में बदलाव न हो, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए अनुमोदन रूट के अंतर्गत विचार किया जा रहा है।

देश की निवल विदेशी देयताओं की स्थिति में वृद्धि.....................

2.13 भारत पर अनिवासियों के निवल दावे (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों घटाव अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देयताएं) जून 2011 को समाप्त होने वाली तिमाही में यूएस $233.6 बिलियन पर मार्च 2011 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए से यूएस $14.2 बिलियन अधिक था। यह विदेशी देयताओं में भारी वृद्धि, मुख्यत: प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के कारण हुई, यद्यपि आरक्षित आस्तियों और विदेश में प्रत्यक्ष निवेश की भी वृद्धि हुई (चार्ट 2.14) इन देयताओं के अरक्षित भागों पर भारतीय रुपया के मूल्यह्रास के कारण मुद्रा विनिमयजन्य हानियों के होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

...... जबकि विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रहे हैं

2.14 विदेशी मुद्रा का भंडार, विदेशी दबावों को आत्मसात करने की क्षमता के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। पूंजी प्रवाह के बदलते स्वरूप के साथ, आयात की आवश्यकता को कवर करने हेतु विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार के मूल्यांकन के पारंपरिक दृष्टिकोण को व्यापक करने की आवश्यकता है जिसमें कई मानदंडों को जैसे- पूंजी प्रवाहों के आकार, गठन और विभिन्न पूंजी प्रवाहों के जोखिम प्रोफाइलों तथा साथ ही वैसे विदेशी दबावों के प्रकारों जिससे अर्थव्यवस्था ग्रस्त हो सकती है को शामिल किया जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार के कतिपय कवरेज अनुपात की प्रवृत्ति चार्ट 2.15 में प्रदर्शित की गई है।

विनिमय दर निर्धारित सीमा के बाहर चली गयी है

2.15 यूरोपीय ऋण की वहनीयता के संबंध में चिंताओं ने मौद्रिक संघ के भविष्य जैसे बृहत मुद्दे पैदा कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते सरकारी ऋण और विकास की क्षीण संभावनाओं से निपटने के लिए राजनीतिक मतैक्य के अभाव से पूंजी को सुरक्षित स्थानों पर लगाया जाने लगा है, जिससे उभरते हुए बाज़ार जैसे कि भारतीय रुपया के प्रति मनोभावना कमज़ोर पड़ गई है। उभरते बाजारों

चार्ट 2.14 : भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(बिलियन यूएसडॉलर में)

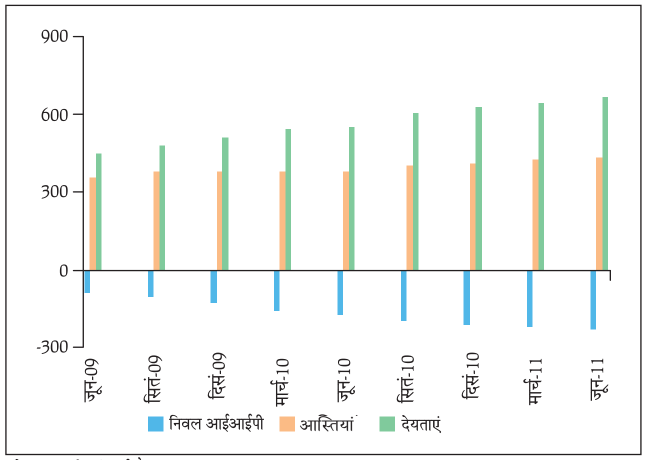

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 2.15 : विदेशी मुद्रा व्याप्ति अनुपात

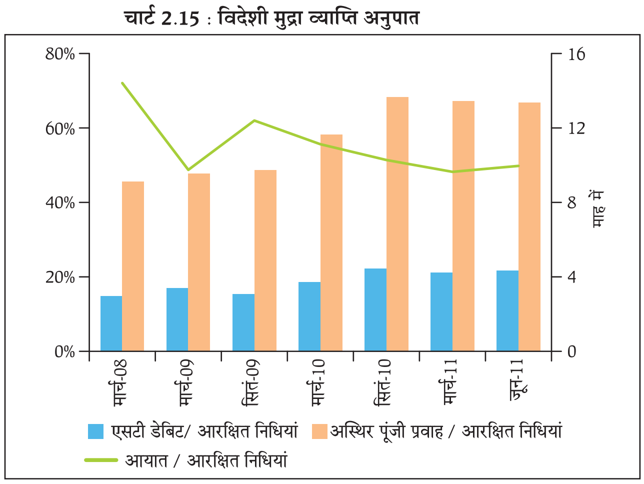

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जैसे भारत, टर्की और दक्षिण अफ्रीका जो चालू खाते में घाटे की स्थिति में हैं, की मुद्राओं में, चालू खाता अधिशेष वाले बाज़ारों की तुलना में अधिक मूल्यह्रास हुआ है (चार्ट 2.16)। पूर्व के विशिष्ट प्रदर्शन को देखते हुए स्थिरता की लंबी अवधि के बाद ऐतिहासिक ऊचाइयों को प्राप्त करने के लिए विनिमय दर ने स्थापित दायरे को तोड़ दिया है। कभी-कभी ऐसे समय पर ध्यान आफशोर भारतीय रूपये में हो रहे विकास और गैर-सुपुर्दगी वायदा बाजार (एनडीएफ) की ओर परिवर्तित हो जाता है। भारतीय रूपये के लिए आनशोर वायदा बाजार और गैर-सुपुर्दगी वायदा बाजार के मूल्यों में अंतर इस समयावधि में परिवर्तित होता रहता है (चार्ट 2.17)।

2.16 बाजार की अपेक्षा को विनिमय दर की चाल ने मिथ्या साबित किया है (चार्ट 2.18)। विनिमय दर में भारी उतार-चढ़ाव के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि नीति का उद्देश्य विनिमय दर की आस्थिरता को नियंत्रित करना और इससे यह सुनिश्चित करना है कि यह समष्टि आर्थिक स्थिरता को हानि न पहुंचा सके। भारतीय रूपये का तीव्र मूल्यह्रास वैश्विक गतिशीलता से संचालित है और इसके परिमाण तथा उतार-चढ़ाव की दिशा का प्रामाणिक समाधान बाह्य स्थिति, विशेष रूप से यूरोप में सरकारी कर्ज संकट पर निर्भर करता है।

अरक्षित कारपोरेट निवेश संबंधी चिंता का उन्मूलन रोकथाम उपायों से संभव

2.17 वर्ष 2008 में भारतीय रूपया, हाल में रूपए में हुए मूल्यह्रास की भांति स्थापित ट्रेडिंग रेंज को पार कर गया था और अनेक अत्यधिक अरक्षित निवेश वाली फर्मों को जो इस स्थिति से अनभिज्ञ थी, जकड़ लिया। सामूहिक डेरिवेटिव निवेशो के रूपांतरण और लेन-देन में हानि हुई और कई अत्यधिक (उदाहरण के लिए टेक्सटाइल में) संकट में फंस गये। इस कारण से रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमयन को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त किया और कुछ जटिल डेरिवेटिव निवेशों पर रोक लगा दी गई। बैंकों को यह प्रस्तावित[6] किया गया है कि वो जब भी कारपोरेट को निधि आधारित और गैर - निधि आधारित क्रेडिट सुविधा दें तो बैंक कारपोरेट के अरक्षित विदेशी मुद्रा के निवेश से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन करें और क्रेडिट जोखिम प्रीमियम में मूल्यांकित करें। बैंक अपने बोर्ड से अनुमोदित नीति के तहत कारपोरेटों की अरक्षित स्थिति के संबंध में एक सीमा निर्धारित करें। साथ ही अरक्षित निवेशों के संबंध में रिपोर्ट किए जानेवाले आंकड़ो को सुदृढ़ करें।

चार्ट 2.16 : बाह्य घाटा वाली मुद्राएं और व्यापक मुद्रा सूचकांक[5]

(जनवरी 2011 = 100)

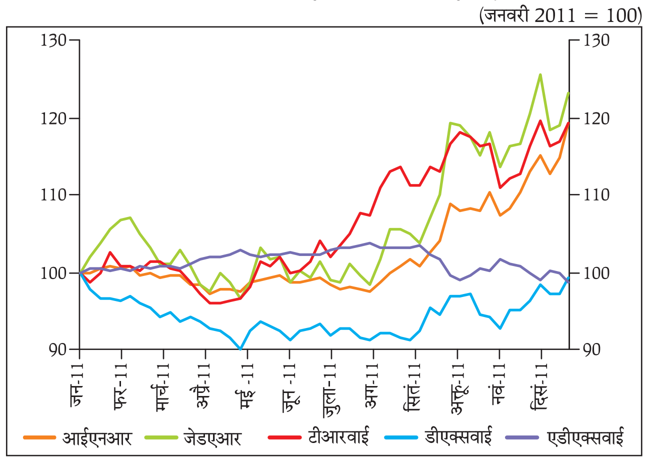

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.17 : यूएस$/भारतीय रुपये के तीन और छह माह की परिपक्वता अवधि में आफशोर और आनशोर वायदा दर में अंतर

(भारतीय रुपए में)

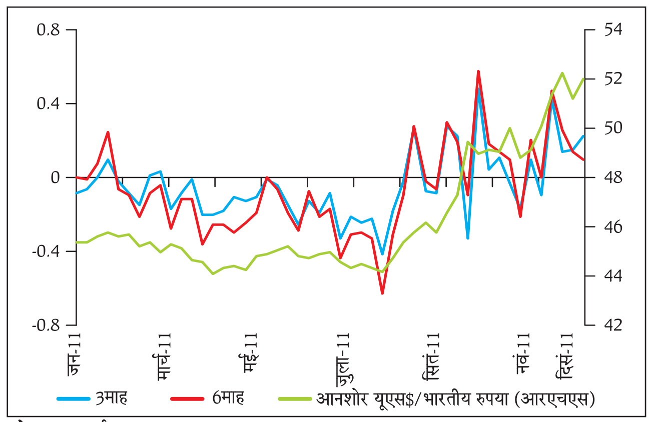

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.18 : जुलाई अंत में अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया हेतु विश्लेषक पूर्वानुमान का विस्तार (छायांकित क्षेत्र) वास्तविक पथ (हरे में) और इसके अक्तूबर अंत में (लाल में) मध्यमान का पूर्वानुमान

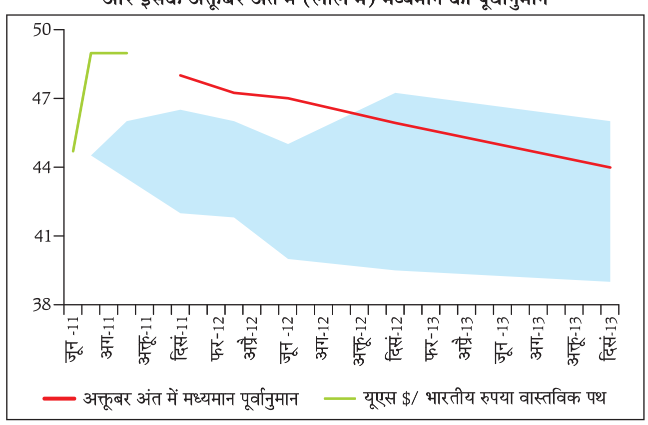

स्रोत : ब्लूमबर्ग

[5] डीएक्सवाई या अमरिकी डालर सूचकांक विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरिकी डालर के सामान्य मूल्य को दर्शाता है, ब्लूमबर्ग के लिए एडीएक्सवाई-जेपी मार्गन एशियन डालर इनडेक्स एक व्यापार है तथा अमरीकी डालर की तुलना में चलनिधि भारित सूचकांक एशियन मुद्राओं, चाइनीज़ यूआन, हांगकांग डालर, भारतीय रुपया, कोरियन ओन आदि उसके मूल्य हैं। चार्ट में वृद्धि डीएक्सवाई और एडीएक्सवाई को छोड़कर मूल्यह्रास को दर्शाता है जो क्रमश: अमरिकी डालर और एशियन मुद्राओं में बढ़त को दर्शाता है। जेडएआर दक्षिण अफ्रिकन रैंड है और टीआरवाइ न्यू टर्किश लीरा है।

[6] मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा, 25 अक्तूबर 2011।

विनिमय दर और इक्विटी बाज़ार का युग्म समस्या ला सकता है

2.18 भारतीय रूपये और घरेलू इक्विटी बाज़ार की सफलता एक दूसरे पर निर्भर है। प्रतिकूल जोखिम के समय दोनों के मध्य सहसंबंध अत्यधिक बढ़ जाता है। इक्विटी में विक्रय करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का मेल उनके यूएस डालर की मांग से हो जिससे उनके अधिकार क्षेत्र की पूंजी स्वदेश लौट सके। यह बाह्यता कि इक्विटी बाज़ार का चक्कर समष्टि आर्थिक को प्रभावित करनेवाली वस्तुएं जैसे विनिमय दर वित्तीय अथवा समाष्टि आर्थिक स्थिरता हेतु सहायक नहीं है (चार्ट 2.19)। दो बड़े संस्थागत निवेशकों का पारस्परिक प्रभाव अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और म्युचुअल फण्ड भी दिलचस्प है; जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआई) की गतिविधियों को प्राय: म्युचुअल फण्ड बाधित करता है। (बॉक्स 2.1)

भारतीय इक्विटी में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का वर्चस्व

2.19 भारतीय प्रतिभूति बाजार, अपनी हिस्सेदारी और नकदी के संयोजन के साथ-साथ डेरिवेटिव में संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरा है। बीते दो वर्षों में प्रतिदिन औसत नकद कुल कारोबार और शेयर बाजर में सुपुर्दगी में गिरावट आई है। यह इक्विटी डेरिवेटिव के व्यापारिक करार में मूल्य की तीव्र संवृद्धि के विपरीत है जहां बहुत से करारों में सूचकांक के विकल्प ने सूचकांक फ्यूचर्स का स्थान ले लिया है। हाल के कुछ महीनों में डेरिवेटिव बाज़ार टर्नओवर की तुलना में नकद बाजार टर्नओवर का अनुपात गिरा है (चार्ट 2.20)। व्यापारिक गतिविधि की संरचना में यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। जहां संस्थाओं की हिस्सेदारी स्थिर रही है, वहीं नकदी खंड में ग्राहको सहित गैर-संस्थागत ग्राहकों की हिस्सेदारी काफी तेजी से कम हुई है (चार्ट 2.21 और 2.22)। डेरिवेटिव खण्ड में स्वामित्व व्यापार का हिस्सा 2008-09 के 35 प्रतिशत

चार्ट 2.19: विभिन्न बाजारों का ऐतिहासिक उतार -चढ़ाव

(प्रतिशत में वार्षिकीकृत)

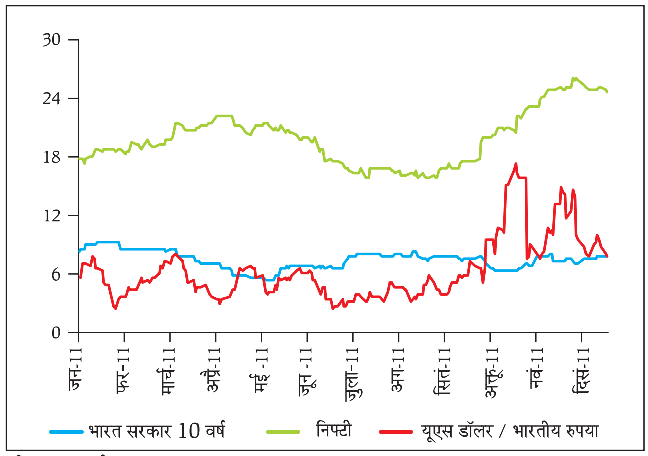

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.20 : इक्विटी में नकदी बनाम व्युत्पन्न कुल बिक्री (000 करोड़ रुपए में) और उनका अनुपात

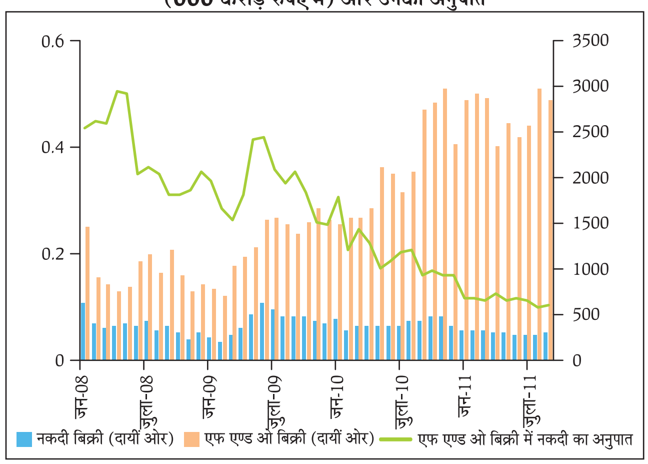

स्रोत: सेबी

चार्ट 2.21 : नकदी इक्विटी में व्यापार का विन्यास

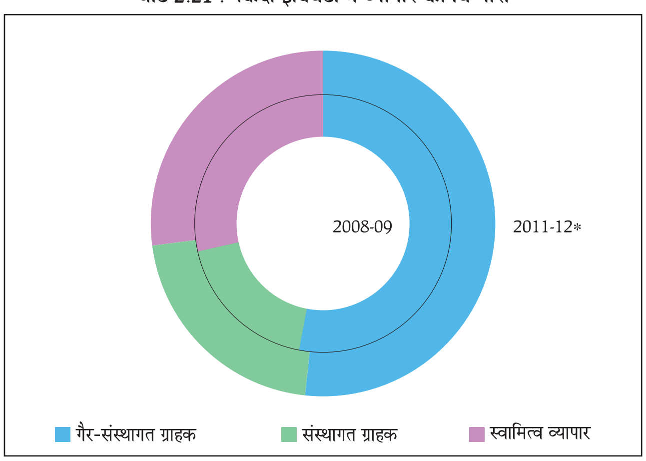

* 2011-2012 सितंबर, 2011 समाप्ति अवधि के लिए है

स्रोत : सेबी

चार्ट 2.22 : व्युत्पन्न इक्विटी में व्यापार का विन्यास

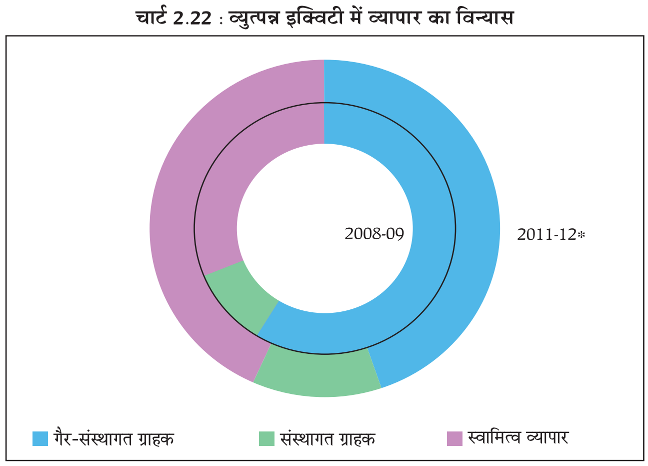

*2011-12 सितंबर, 2011 समाप्ति अवधि के लिए है

स्रोत : सेबी

बॉक्स 2.1: भारतीय इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेशकों और म्युचुअल फंडों के व्यापार का रुख [7]

पिछले दो दशकों में भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास का महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि संस्थागत निवेशकों में, विदेशी और घरेलू दोनों की भागीदारी बढ़ी है। वित्तीय संस्थागत समूह और म्युचुअल फंडों की इक्विटी बाजार पूंजीकरण में 10 प्रतिशत से भी अधिक की हिस्सेदारी रही है जो कुल बिक्री के 20 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान (जो कुल बिक्री के 65 प्रतिशत से भी अधिक रहा क्योंकि इन संस्थाओं का व्यापार केवल सुपुर्दगी के आधार का था) रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों और म्युचुअल फंडों द्वारा किए गए व्यापार के प्रभाव के प्राथमिक अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि इक्विटी बाज़ार विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाहों की तुलना में कहीं अधिक असुरक्षित है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जब बाज़ार की गतिविधि को बढ़ाया गया था तब म्युचुअल फंडों ने अच्छी भूमिका निभायी और इसका प्रभाव बाजार में देखा गया। जनवरी 2010-सितंबर 2011 के दौरान कुल 59 दिनों में वित्तीय संस्था समूह ने निवल आधार पर ₹ 500 करोड़ से भी अधिक की इक्विटी बेची थी। इन 59 दिनों में म्युचुअल फंडों के निवल क्रेता 39 दिनों अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशकों और म्युचुअल फंड के थे जो विपरीत निवेश पद्धति को दर्शाता है। यह तभी संभव हो पाता जब विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश पूरी अर्थव्यवस्था में होता। म्युचुअल फंडों का अधिकांश निवेश घरेलू बाज़ारों में था इसलिए निवेश में अंतर होना स्वाभाविक है। निवल विदेशी संस्थागत निवेशकों की तुलना में निवल म्युचुअल फंड के निवेश का अनुपात केवल 0.22 है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवल बिक्री और निवल संस्थागत गतिविधि (विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवल बिक्री म्युचुअल फंड के निवल गतिविधि का निवल है चाहे बिक्री या खरीद हो) के अनुसार निफ्टी लाभ को 20 प्रतिशत शीर्ष पर और 20 प्रतिशत अधोभाग पर उन दिनों दर्ज की गयी जिसे निम्नानुसार चार्ट 2.23 और 2.24 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.23: निफ्टी लाभ (%) बनाम विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवल बिक्री

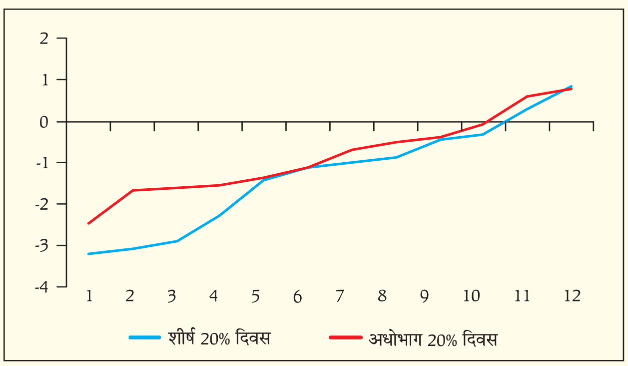

स्रोत: सेबी स्टाफ गणनाएं

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि दोनों मामलों में शीर्ष 20 प्रतिशत दिनों में अधोभाग के 20 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक नकरात्मक लाभ/प्रतिफल दर्शाता है जो वित्तीय संस्था समूह के निवल बक्रियों/निवल संस्थागत गतिविधि तथा निफ्टी लाभों के मध्य आपसी संबंध की कुछ मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट: 2.24: निफ्टी लाभ (%) बनाम निवल संस्थागत गतिविधि

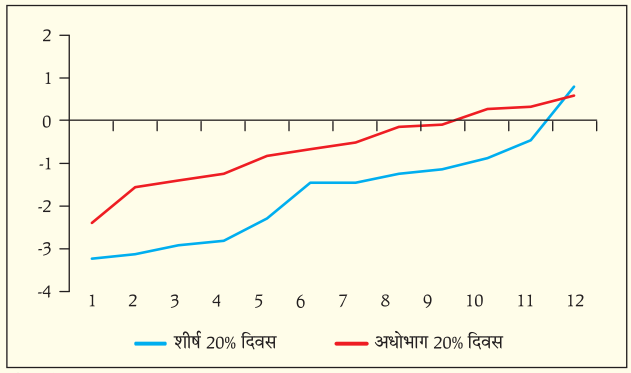

स्रोत: सेबी स्टाफ गणनाएं

20 प्रतिशत शीर्ष और अधोभाग के 20 प्रतिशत के उन दिनों के लाभों के बीच का अंतर निवल संस्थागत गतिविधि के मामले में अधिक स्पष्ट हुआ है और यह दर्शाता है कि निफ्टी लाभों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवल बिक्री के बीच के संबंध की तुलना में निवल संस्थागत गतिविधि और निफ्टी लाभों के बीच का संबंध और अधिक मजबूत है।

आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाने के लिए स्पीयर का रैंक कोरिलेशन टेस्ट का परिणाम नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 2.1: स्पीयरमेन का रैंक कोरिलेशन विश्लेषण

	निफ्टी लाभ और वित्तीय संस्था समूह निवल बिक्री	निफ्टी लाभ और निवल संस्थागत गतिविधि
स्पीयरमेन रैंक कोरिलेशन गुणांक	0.20 (1.60)*	0.43 (3.60)*

*कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े टी सांख्यिकी के हैं

स्रोत: सेबी स्टाफ गणना

जैसा कि देखा जा सकता है कि निफ्टी प्रतिफलों और निवल संस्थागत गतिविधि के बीच गुणांकों का आपसी संबंध 95 प्रतिशत के विश्वसनीय स्तर पर सांख्यिकीय रूप से बना रहा जब कि वही निफ्टी प्रतिफल और वित्तीय संस्थागत समूह के निवल बिक्री सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। यह प्राथमिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवल बिक्री उन दिनों बढ़ी हुई थी लेकिन म्युचुअल फंड की निवल गतिविधि ने मूल्य निर्धारण में काफी अच्छी भूमिका अदा की। हालांकि इन तथ्यों को बृहत सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ पुष्ट बनाने की आवश्यकता है तथापि, भारत में मार्च 2010 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में म्युचुअल फंडों की हिस्सेदारी को कुल वित्तीय आस्तियों में पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया गया था। इक्विटी म्युचुअल फंड के आस्ति आधार को बढ़ाने के लिए फुटकर ग्राहकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की आवश्यकता है क्योंकि म्युचुअल फंड का यह उत्पाद प्रथमत: उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था जो बाजार में संस्थागत भागीदारियों को बढ़ाएंगे। यह भारतीय इक्विटी बाज़ार को स्थिरता दिलाने में अच्छी भूमिका अदा करेगा।

से बढ़कर उल्लेखनीय रूप से 2010-11 में 48 प्रतिशत तक ऊपर उठा है, जहां गैर-संस्थागत ग्राहकों का हिस्सा उसी अवधि में 59 प्रतिशत से गिरकर 42 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय स्थिरता के हित में, इन सूक्ष्म-स्तर गतिविधियों की प्रणालीगत जोखिम के संभाव्य स्रोत के रूप में निगरानी रखने की आवश्यकता है।

भारतीय कंपनियों के प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखने से जोखिम

2.20 भारत में अधिकांश कारोबार-परिवार आधारित होता है और प्रवर्तक फर्म के कार्यों को संभालने में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों में औसत प्रवर्तकों की भागीदारी लगभग 48 प्रतिशत

[7] प्रणालीगत स्थिरता इकाई (एसएसयू) सेबी का योगदान

है। यह देखा गया है कि बहुत सी कंपनियों की इक्विटी कीमतें जिसमें प्रवर्तकों ने उनके शेयरों के बहुत बड़े भाग/हिस्सा को गिरवी रखा गया, उनकी कीमतें मार्जिनल कॉल के विफल होने के बाद और उधारकर्ताओं द्वारा शेयरों के बेचने संबंधी अनुमान के कारण बृहत् बाज़ार की तुलना में तेजी से गिरीं। ऐसी घटनाएं निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करतीं हैं और यह वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य में सेबी ने प्रवर्तकों के लिए प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का निर्धारण किया है जिसे अनिवार्य बनाया गया है ताकि वे गिरवी रखे गए शेयरों के ब्यौरों को बता सकें तथा गिरवी शेयरों की बिक्री और जारी संबंधी जानकारी कंपनी को दे सकें तथा कंपनी भी उन्हें प्रदान कर सके और इसके प्रत्युत्तर में इसे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जनता को सूचित किया जा सके। हाल ही में इसमें ऋणभार को शामिल करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण के दायरे को भी बढ़ाया गया है। गिरवी के कारणों के संबंध में प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखने बनाने के संबंध में पारदर्शिता की कमी, जिस कीमत पर गिरवी रखा गया है और उधारदाता द्वारा मार्जिन कॉल और बिक्री की शर्तें होती हैं वे बाज़ार में अनिश्चितता पैदा करती हैं।

गारंटीकृत निपटान के माध्यम से ओआईएस बाज़ार का मजबूत होना

2.21 भारत का ओटीसी (ओवर दि काउंटर) ब्याज-दर अदला-बदली बाज़ार व्यापक रूप में ओवरनाइट इंडेक्स स्वाप (ओआईएस) और बैंक द्वारा उपयोग किए गए, प्राथमिक व्यापारी और फर्मों (चार्ट 2.25) द्वारा बना हुआ है। भारत में स्वाप का बहुत बड़ा भाग बकाया कल्पित मूल्य (चार्ट 2.26) को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के 'ट्रेड कंप्रेशन' के माध्यम से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया है कि नकदी प्रवाहों का निपटान सीसीआईएल की गारंटी द्वारा किया जाएगा। यह इस बाजार से होने वाले प्रणालीगत जोखिम के एक बहुत बड़े भाग को नियंत्रित कर लेती है। सीसीआईएल किसी व्यापार के काउंटरपार्ट की बाजार-दर-बाजार स्थितियों में परिवर्तन के लिए 'वेरिएशन मार्जिन' और स्वाप स्थिति संबंधी संभाव्य भावी एक्सपोज़र के लिए 'प्रारंभिक मार्जिन' की उगाही करेगा।

निष्कर्ष

2.22 घरेलू वित्तीय बाज़ार ठीक-ठाक रहा किंतु वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में प्रतिकूल गतिविधियों के चलते कई सख्त झोंकों का सामना करना पड़ा। यूरोप के सरकारी बांड बाज़ार में हलचल का फैलाव उनके बैंकिंग प्रणालियों तक गया जो घरेलू फर्मों के लिए पूंजी का प्रमुख स्रोत था। प्रतिपक्षी जोखिम संभावनाओं की अधिकता तथा बैंकों की और सरकारी रेटिंग कम होने के कारण अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की

चार्ट 2.25 : ओआइएस में व्यापार की संख्या और मात्रा (000 करोड़ ' में)

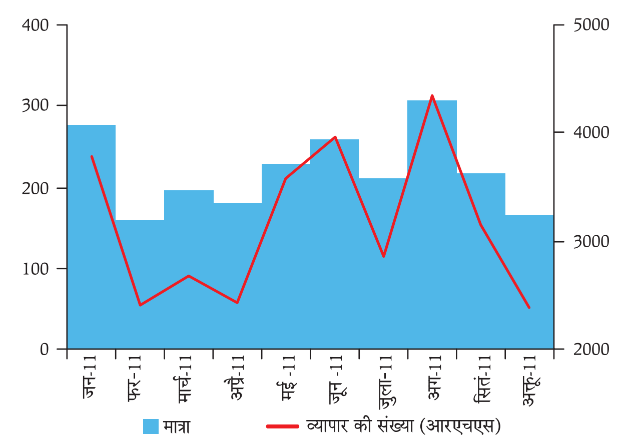

स्रोत : सीसीआइएल

चार्ट 2.26 : ओआइएस में व्यापार की संख्या और बकाया कल्पित आय (000 करोड़ ₹ में)

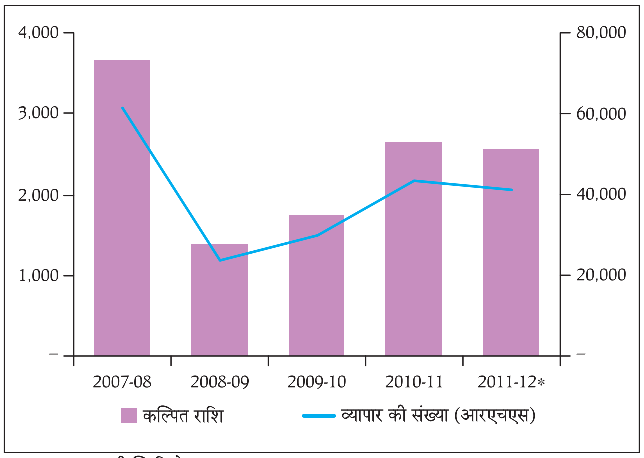

*अक्तूबर 2011 की स्थिति के अनुसार
स्रोत : सीसीआइएल

प्रवृत्ति जोखिम उठाने के बजाय जोखिम से बचने और सुरक्षित रहने की हो गई। इसका परिणाम पूंजी प्रवाहों का बड़े पैमाने पर वापसी रहा, बैंकिंग पूंजी सहित, और विदेशी मुद्रा वाली उधार राशियों को उगाहने में भारतीय फर्म और बैंकों द्वारा बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने घरेलू इक्विटी और विनिमय दर बाजार में उच्च अस्थिरता होने के कारण तीव्र गिरावट भी महसूस किया। इसी बीच घरेलू बांड बाज़ार इन ओवरसीज़ गतिविधियों के कारण व्यापक रूप से प्रतिरक्षित रही।

2.23 भारतीय रुपयों में मूल्यह्रास, चालू खाता घाटा का बढ़ना और निवल अंतर्राष्ट्रीय देयताओं का बढ़ना, यद्यपि यह तत्काल चिंता का विषय नहीं था फिर भी वाह्य क्षेत्रों ने असुरक्षा को बढ़ाया है। घरेलू इक्विटी बाज़ार में सुधार, भारतीय रुपयों में मूल्यह्रास और घरेलू ब्याज-दरों में वृद्धि के कारण अगली कुछ तिमाहियों में फर्मों द्वारा एफसीसीबी (और ईसीबी) देयताओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु माहौल खराब हुआ है। एक्सपोज़रों के लेन-देन और परिवर्तन असुरक्षित बना हुआ है जो कुछ फर्मों के लिए तकलीफ का कारण हो सकता है।

2.24 भारतीय इक्विटी बाज़ार की संरचना, इसका संगठन और शेयर बाजार के सहभागियों द्वारा लंबे समय बाद विकसित हुआ है। डेरिवेटिव्ज़ ट्रेडिंग के शेयरों में वृद्धि नकदी बाज़ार और मालिकाना ट्रेडिंग के उच्चतर समानुपात से संबंधित है और इन गतिविधियां को सर्वांगीणरूप से निगरानी करने की आवश्यकता है। प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि विषम जानकारियों से उभरने वाली गड़बडियों से प्रतिभूति बाज़ार का बचाव करें। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परिवारजन्य कारोबार के लिए प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को निजी गिरवी रखने के संबंध में पूर्ण प्रकटीकरण किया जाए।

अध्याय III

वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और लचीलापन

यूरो क्षेत्र संकट के बने रहने से आजकल वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, जो भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है। यूरोपीय बैंकों के लिए हाल ही में किये गये विनियमन संबंधी निर्धारणों से लीवरेज (ऋण पूंजी) कम होने की आशंकाएं बढ़ी हैं। भारतीय बैंकों पर सीधा असर तो सीमित रूप से ही पड़ने की संभावना है। जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी और स्थायी पूंजी के अनुपात निर्धारित न्यूनतम स्तर और अनर्जक आस्तियों के अनुपातों से स्पष्ट रूप से अधिक रहे, जिनसे पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ बनी रही, जो बड़े-बड़े उन्नत देशों और साथ ही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल स्थिति का संकेत है। तथापि, जोखिमभारित आस्तियों से पूंजी के अनुपात में लगातार गिरावट और आस्ति गुणवत्ता में कमी से संकेत मिलता है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं, यहां तक कि ऋण वृद्धि की गति से कहीं अधिक तेज रहे। अनर्जक आस्तियों को बढ़ाने में योगदान करने वाले प्रमुख क्षेत्र रहे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, खुदरा, भू-संपदा और मूलभूत क्षेत्र। मूलभूत क्षेत्र में, बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों में अनर्जन और पुनर्गठन देखने को मिला। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक से भी यह पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भेद्यता बढ़ी है। शहरी और ग्रामीण सहकारी क्षेत्रों तथा साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में आहित गुणवत्ता पर दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। पेंशन निधि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहली बार शामिल की गयी हैं और इन निधियों द्वारा निभायी जा रही प्रतिकारी भूमिका का वर्णन किया गया है। बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों के बीच अंतरबद्धता से चिंताएं बढ़ सकती हैं। वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए कई एकल कारक संवेदनशीलता दबाव परीक्षण किये गये। दबाव परीक्षणों के परिणाम से संकेत मिलता है कि बैंकिंग प्रणाली कई प्रकार के जोखिम-विशेष और क्षेत्र-विशेष आघातों को झेलने में समर्थ रहेगी।

सरकारी ऋण जोखिम और बैंक तुलन-पत्र प्रतिपुष्टिकारी दुष्चक्र में

3.1 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बाद की अवधि में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सरकारी ऋण के स्तर बनाये रखने की चिन्ताओं और साथ ही कम वृद्धि की संभावनाओं से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण और बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएं संभावना से अधिक बनी रही हैं, यहां तक कि यूरोपीय ऋण संकट परिघीय क्षेत्रों से प्रमुख क्षेत्र तक फैल गया है। अत्याधिक अन्तरसंबंध और अत्याधिक लीवरेज (ऋण-पूंजी) वाली वित्तीय संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से सरकारी ऋण जोखिमों का असर बैंकिंग क्षेत्र पर बढ़ जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

3.2 सरकारी ऋणों से बैंकों पर संक्रमण का प्रभाव फैलने के कई मार्ग हैं। सर्वप्रथम, सरकारी ऋण जोखिम में वृद्धि से बैंकों की सरकारी बॉंड धारिता पर हानि होती है, जिससे उनके तुलन-पत्र कमजोर हो जाते हैं। बासल-III के चलनिधि मानकों के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियों को दी जाने वाली वरियता को देखते हुए बैंक प्राय: अपनी सरकारी बांड धारिता के स्तर को बढ़ाते रहे हैं। दूसरे, रिपो बाजार में सरकारी ऋण अधिकांशत: संपार्श्विक के रूप में होते हैं और सहभागी इसके जोखिम में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। स्तर में गिरावट, यदि बहुत अधिक हो तो पात्र संपार्श्विक के समूह से ऐसा सरकारी बॉंड बाहर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिपक्षकार ऐसी प्रतिभूतियों पर हेयरकट बढ़ा देते हैं, जिससे उधार राशियों की लागत बढ़ जाती है। सरकारी ऋण जोखिम और बैंकिंग क्षेत्र के बीच निकट संबंध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक बढ़ा समष्टि-आर्थिक खतरा है, चूंकि एक देश में सरकारी ऋण से संबंधित समस्याओं का असर विदेशी सरकारी ऋण में बैंकों के निवेश तथा प्रभावित विदेशी क्षेत्र में घरेलू बैंकों एवं आस्तियों के प्रति बैंकों के प्रभावन (एक्सपोजर) के माध्यम से अन्य देशों में बैंकों तक फैल जाता है।

3.3 यूरोपीय बैंकों की पूँजी अपेक्षाएं बढ़ाने के संबंध में हाल ही में किये गये विनियमन संबंधी निर्धारण[1] से ऋण-पूंजी (लीवरेज) में बहुत कमी आ सकती है। यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अंतिम अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र के बैंकों को 30 जून 2012 तक 114.7 बिलियन यूरो की पूंजी राशि की आवश्यकता होगी। ईक्विटी बाजार की प्रचलित स्थितियों को देखते हुए, बैंकों के लिए

[1] अक्तूबर 2011 में, यूरो क्षेत्र के अग्रणी देश उपायों का एक पैकेज बनाने पर सहमत हुए, जो बढ़ते हुए सरकारी ऋण के कारण हो रही समस्याओं पर काबू पाने के संबंध में है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय क्षेत्र द्वारा धारित यूनानी सरकारी बॉंड पर 50 प्रतिशत हानि अथवा "हेयरकट" का प्रस्ताव शामिल है, जिससे 'यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा' लगभग 1 ट्रिलियन यूरो तक बढ़ गयी और यूरोपीय बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे सरकारी ऋण पर अपनी हानि को हिसाब में लेने के उपरांत काफी उच्च पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में कोर टियर 1 पूंजी का 9 प्रतिशत रखें।

बाजार से पूंजी जुटाना कठिन कार्य होगा। इसके अतिरिक्त अधिकांश सरकारों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि वे नयी निधियां उपलब्ध करवा सकें। आस्तियों की बिक्री करने से भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, चूंकि उनकी बिक्री पर होनेवाली हानि से विनियामक पूंजी में और कमी हो जाएगी। अत:अधिक संभावना है कि बैंक अपने ऋण प्रभाव पड़ेगा और यूरोप में ऋण संकट गहरा जाने की संभावना बढ़ जाएगी।

3.4 जब यूरोपीय बैंक लीवरेज में कमी लाएंगे, तो वे लीवरेज कम करने की व्यथा बाहर, और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे भारत पर प्रच्छन्न प्रभाव पड़ सकता है, चूंकि भारत पर यूरोपीय बैंकों के दावे भारत के एकल घरेलू उत्पाद के 8.6 प्रतिशत (चार्ट 3.1) हैं। तथापि भारतीय बेंकों पर प्रभाव, विशेषत: प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित रहने की संभावना है (बॉक्स 3.1)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

3.5 सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र आकार में 18.5 प्रतिशत (वर्ष-प्रति-वर्ष) तक वृद्धि हुई, जो मार्च 2011 के अंत की स्थिति की 18.8 प्रतिशत वृद्धि से कुछ ही कम है। सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार ऋण

चार्ट 3.1 :संबंधित देश के सांकेतिक एकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में यूरोपीय बैंकों के समेकित विदेशी दावे

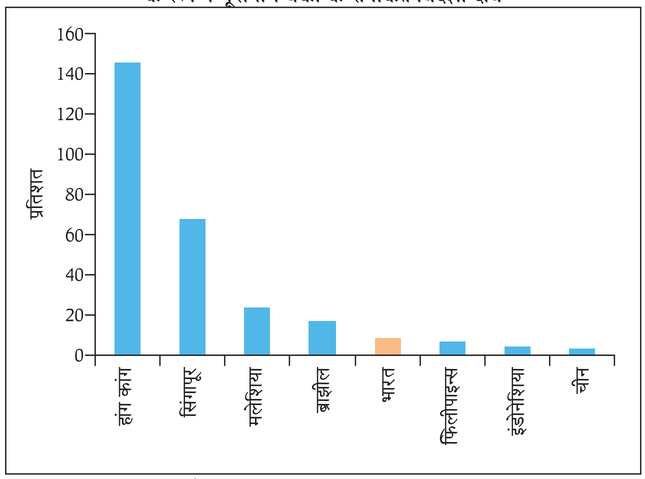

स्रोत :बीआइएस लोकेशनल बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स एण्ड आइएमएफ

बॉक्स 3.1: यूरो क्षेत्र संकट और भारतीय बैंकों पर प्रभाव

अति संवेदनशील देशों के प्रति नगण्य प्रभाव न होने के कारण भारतीय बैंकों पर वर्तमान में चल रहे यूरो क्षेत्र संकट का प्रथमस्तरीय प्रभाव सीमित रह सकता है। पहले तो, यूरोपीय संघ में भारतीय बैंकों की केवल 37 शाखाएं और तीन सहायक संस्थाएं हैं, जिनमें से पुर्तगाल, इटली, यूनान और स्पेन में कोई नहीं है। 37 शाखाओं में से 30 शाखाएं यूके में 3 शाखाएं बेल्जियम में और दो-दो शाखाएं जर्मनी और फ्रांस में है, तथा सभी 3 सहायक संस्थाएं यूके में हैं। सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र की समग्र आस्तियों में उनका मिला-जुला हिस्सा 3 प्रतिशत रहा (चार्ट 3.2)।

चार्ट 3.2: भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं (सहायक संस्थाओं सहित) का हिस्सा-सितंबर 2011

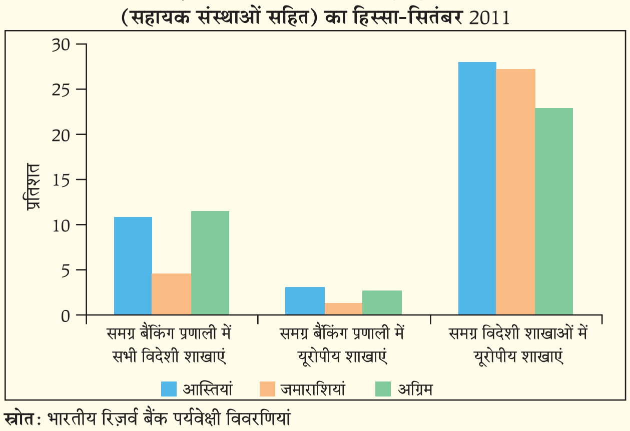

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

दूसरे, पुर्तगाल, यूनान और स्पेन में जारी किए गए बॉंडों के प्रति किसी भी भारतीय बैंक का कोई प्रभाव नहीं है, जबकि इटली के बॉंडों के प्रति प्रभावन नगण्य है। इन देशों से बाहर, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में बैंकों के प्रति निवेश प्रभावन (बड़े भारतीय बैंकों के प्रतिदर्श का) महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही जर्मनी और फ्रांस में कंपनियों के प्रति प्रभावन जोड़ लिया जाए। तीसरे, यूरोप में बैंकों के पास रखे जा रहे भारतीय बैंकों के बकाया नोस्ट्रो शेषों में पिछले कुछ महीने से गिरावट हो रही है। यूरोपीय संस्थाओं पर भारतीय बैंकों (पांच बड़े बैंकों का प्रतिदर्श) की विदेशी शाखाओं की निधीयन निर्भरता, यूके को छोड़कर, भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

तथापि, व्यापार सहित विभिन्न चैनलों से भारतीय बैंकों पर द्वितीय-स्तर का प्रभाव पड़ सकता है। यूरोपीय संकट संक्रमण के माध्यम से गहरा जाने की स्थिति में और परिणामस्वरूप, वैश्विक वित्तीय बाजार, विशेषत: यूरोप में, अवरूद्ध हो जाने पर विदेश में कार्यरत भारतीय बैंक शाखाओं के लिए निधीयन बाध्यताएं उभर कर आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उधार की लागत भी बढ़ सकती है। वस्तुत: बाजार सख्ती के कुछ संकेत पहले ही दिखाई देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में, बैंकों और कंपनियों दोनों को विदेशी मुद्रा संबंधी अपनी देयताओं का पुनर्वित्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, भारतीय फर्मों के विदेशी कर्ज में कमी का पुनर्वित्त करने के लिए आंतरिक चलनिधि (जिसके लिए बैंकिंग क्षेत्र प्रमुख प्रदाता है) से भरपाई करने की आवश्यकता होगी। इस रिपोर्ट के अध्याय II में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है।

वृद्धि (वर्ष-प्रति-वर्ष) 19.2 प्रतिशत के स्तर पर अच्छी बनी रही, हालांकि मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 22.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि से इसकी गति कम हुई है। वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की 16 प्रतिशत सांकेतिक वृद्धि के समय यह ऋण वृद्धि प्राप्त हुई। जमाराशियां बैंकिंग प्रणाली की कुल देयताओं के 80 प्रतिशत के निकट रही और कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों (चालू खाता और बचत खाता) का हिस्सा सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार लगभग 33 प्रतिशत रहा, जो मार्च 2011 के अंत की स्थिति लगभग 35 प्रतिशत से कम है। सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार जमाराशियों में वृद्धि 17.6 प्रतिशत (वर्ष-प्रति-वर्ष) रही, जो मार्च 2011 के अंत की स्थिति 17.8 प्रतिशत वृद्धि दर से कुछ ही कम है। परिणामस्वरूप, ऋण-जमा अनुपात मार्च 2011 के अंत की स्थिति 74.3 प्रतिशत से घट कर सितंबर 2011 के अंत में 73.4 प्रतिशत हो गया। (चार्ट 3.3)

चार्ट 3.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चयनित तुलन पत्र मदों की वृद्धि दर

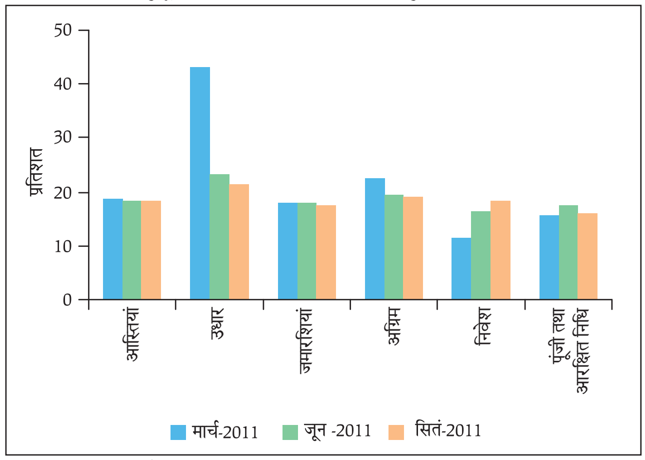

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

3.6 सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र के तुलनपत्र से इतर मदों से संबंधित प्रभावन (एक्सपोजर) बढ़ने जारी रहे। बैंक समूहों को देखें तो विदेशी बैंकों ने अपनी तुलनपत्र में शामिल आस्तियों के आकार की तुलना में तुलन पत्र से इतर आस्तियों में अनुपातहीन हिस्सा धारित रखना जारी रखा (चार्ट 3.4)। जैसे के इस रिपोर्ट के अध्याय IV में चर्चा की गयी है, बैंकों के बीच बढ़ते हुए व्युत्पन्नी सौदों से संबंधित प्रभावन दबाव के परिदृश्य में पूरी प्रणाली को भंग कर सकते हैं।

चार्ट 3.4: तुलनपत्र में शामिल और इतर आस्तियों में बैंक समूहों का हिस्सा - सितंबर 2011

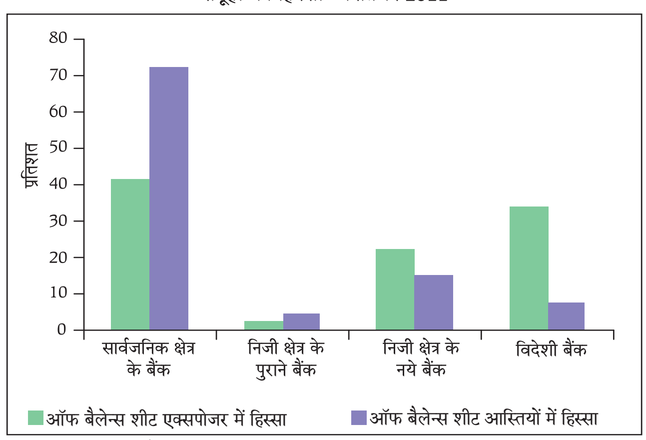

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक[2]

बैंकिंग क्षेत्र में भेद्यता बढ़ने की ओर......

3.7 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के समय से बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम बढ़े हैं। बैंकिंग क्षेत्र को उच्च निधीयन लागत के कारण लाभप्रदता दबावों का तथा मंदी होती अर्थव्यवस्था के कारण आस्ति गुणवत्ता से संबंधित दबावों का सामना करना पड़ा। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र से भी यह सिद्ध होता है जिसमें सुदृढ़ता, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के संबंध में होने वाले जोखिमों में तीनों दृष्टि से वृद्धि देखी जा सकती है। यद्यपि सुदृढ़ता संकेतक दर्शाते हैं कि पिछली अवधियों में स्थिति की तुलना में अब स्थिति बिगड़ी है, तथापि, अनुपात तो विनियामक अपेक्षाओं से अधिक रहे हैं। इसी प्रकार, जून 2011 को समाप्त तिमाही से आरंभ हुई बैंकिंग स्थिरता संकेतक की तिमाही श्रृंखला में वृद्धि से यह संकेत मिला है कि बैंकिंग क्षेत्र में भेद्यता बढ़ रही है। साथ ही, अगली दो तिमाहियों के लिए संकेतक का अनुमान

[2] पद्धति और विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया इस रिपोर्ट का अनुबंध देखें।

यह दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में गिरावट, अलबत्ता बहुत कम, जारी है (चार्ट 3.5 और 3.6)।

..... चूंकि पूंजी वृद्धि की दर और जोखिम प्रोफाइल असंबद्ध होने के कारण पूंजी में कमी

3.8 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के और कोर पूंजी के अनुपातों में गिरावट जारी रही, तथापि वे बासल I और II दोनों मानदंडों के अंतर्गत विनियामक न्यूनतम स्तर से अधिक रहे। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार 'पूंजी अनुपात' 14.5 प्रतिशत के स्तर से गिरकर मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 14.2 प्रतिशत हो गया और सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 13.5 पर स्थिर हो गया। 10.1 प्रतिशत से गिरकर 'कोर पूंजी अनुपात' मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत और सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 9.6 प्रतिशत हो गया। अन्य देशों से तुलना करने से स्पष्ट होता है कि भारत इस संबंध में अपने समकक्ष समूह देशों से पीछे है (चार्ट 3.7 और 3.8)।

3.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण पूंजी (लीवरेज) अनुपात[3] में कुछ गिरावट देखी गयी, जो मार्च 2011 के अंत की स्थिति 6 प्रतिशत से कम हो कर सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 5.9 प्रतिशत हो गया, तथापि बासल III की अपेक्षानुसार 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर की तुलना में तीन को छोड़कर सभी बैंकों का टियर I ऋण पूंजी (लीवरेज) अनुपात 4 प्रतिशत से अधिक रहा।

..... आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, चूंकि सरकने (स्लिपेज) की गति ऋण वृद्धि की गति से बहुत तेज रही।

3.10 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट हुई है। वस्तुत: आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को पहले सर्वांगी

चार्ट 3.5: बैंकिंग स्थिरता मैप

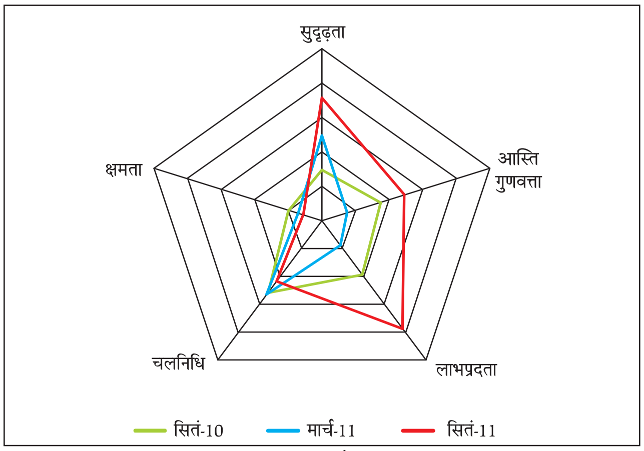

नोट: केंद्र बिंदु से दूरी जोखिम में वृद्धि का संकेत देती है
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 3.6: बैंकिंग स्थिरता संकेतक

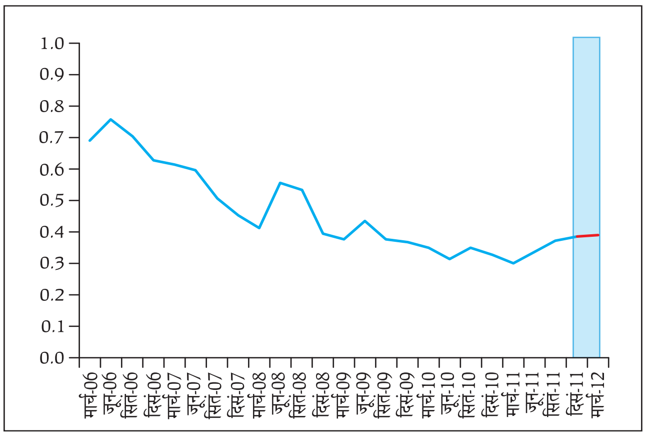

नोट: संकेतक मूल्य में वृद्धि स्थिरता में कमी दर्शाती है।
दिसंबर 2011 और मार्च 2012 पूर्वानुमानित मूल्य हैं, जिन्हें गहरे रंग से भरे क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना।

चार्ट 3.7: बैंक समूहों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

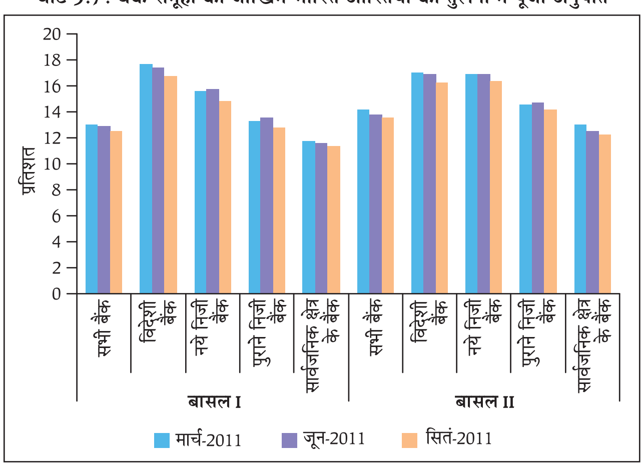

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.8: विभिन्न देशों में बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

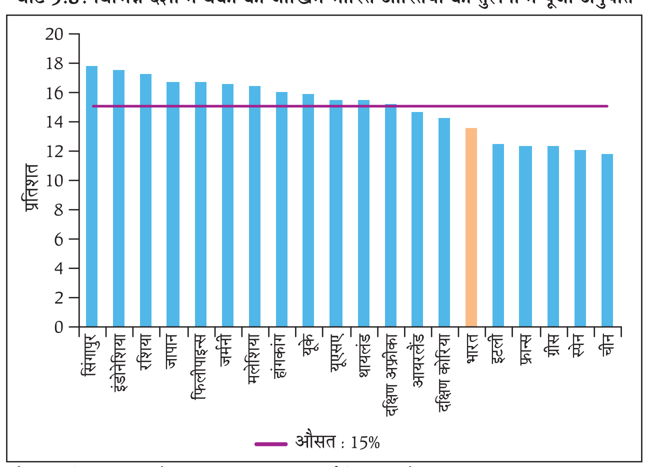

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक (एफएसआइ), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

[3] बासेल III विनियामक पूंजी ढांचे में ऋण पूंजी (लीवरेज) अनुपात आरंभ किया गया है और यह जोखिमरहित - आधारित उपाय है जिसमें तुलन पत्र में शामिल मदों और इतर मदों दोनों के प्रभाव दर्शाता है।

(सिस्टेमिक)जोखिम सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वालों ने सबसे अधिक संभावित जोखिम के रुप में माना है (इस रिपोर्ट के अध्याय V में विस्तार से वर्णन है)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2011 के अंत की स्थिति 2.3 प्रतिशत से बढ़ कर सितंबर 2011 के अंत में 2.8 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, निवल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2011 के अंत की स्थिति 0.09 प्रतिशत से बढ़ कर सितंबर 2011 के अंत में 1.2 प्रतिशत हो गया है, जब कि स्लिपेज अनुपात मार्च से सितंबर 2011 के बीच 1.6 प्रतिशत से बढ़ कर 1.9 प्रतिशत हो गया है।

3.11 सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों की 30.5 प्रतिशत वृद्धि दर (वर्ष-प्रति-वर्ष) ऋण वृद्धि की दर 19.2 प्रतिशत से बहुत अधिक रही। स्लिपेज (अर्थात् अनर्जक आस्तियों में हुई नई अभिवृद्धि) भी ऋण वृद्धि की दर से अधिक हुए हैं और ये सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 92.8 प्रतिशत (वर्ष-प्रति-वर्ष) की दर से बढ़े। अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर का विश्लेषण दर्शाता है कि 2011-12 की पहली छमाही में 25.5 प्रतिशत की वृद्धि दर 2006-2011 के दौरान पहली छमाहियों में औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से तीन गुण से भी अधिक है (चार्ट 3.9 और 3.10)।

3.12 अनर्जक आस्तियों में हाल ही में हुई तेज वृद्धि के बावजूद, भारतीय बैंकों में अनर्जन का स्तर बड़े उन्नत देशों और समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं दोनों में बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में अनुकूल है। तथापि प्रावधान कवरेज अनुपात[4] समकक्ष समूह देशों के औसत 90.7 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम रहा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 'प्रावधानकवरेज अनुपात' (तकनीकी बट्टे-खाते शामिल नहीं) 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार 58.9 प्रतिशत रहा, जो 31 मार्च 2011 की स्थिति (59.4 प्रतिशत) से कुछ ही कम है (चार्ट 3.11 और 3.12)।

चार्ट 3.9: सकल ऋणों व अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों और स्लिपेज की वृद्धि दर की प्रवृत्ति

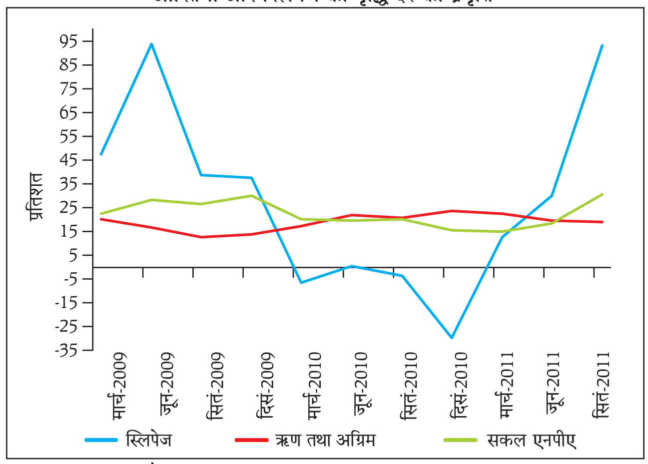

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.10: सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर छमाहियों में

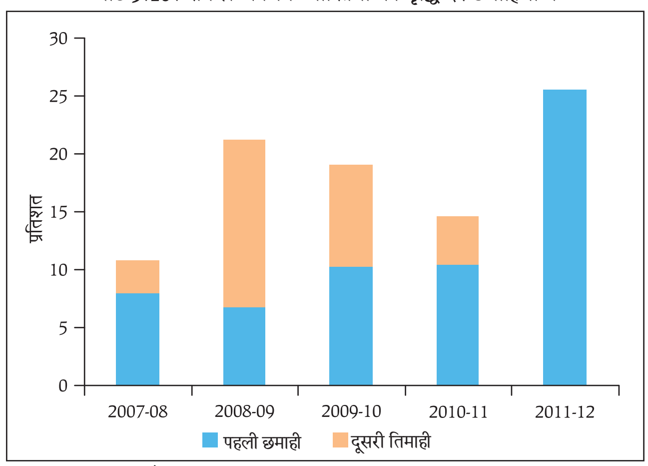

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.11: सकल अनर्जक आस्ति अनुपात-अन्य देशों की तुलना में

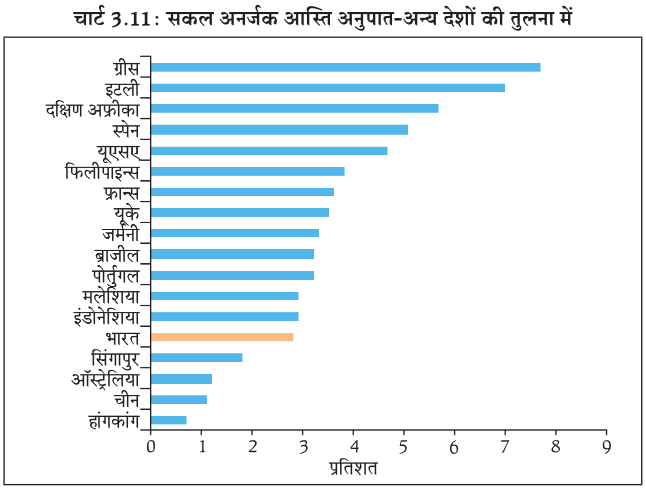

स्रोत : विश्व विकास संकेतक (डब्ल्यूडीआई), विश्व बैंक

चार्ट 3.12: सकल अनर्जक आस्ति अनुपात बनाम प्रावधान कवरेज अनुपात - अन्य देशों की तुलना में

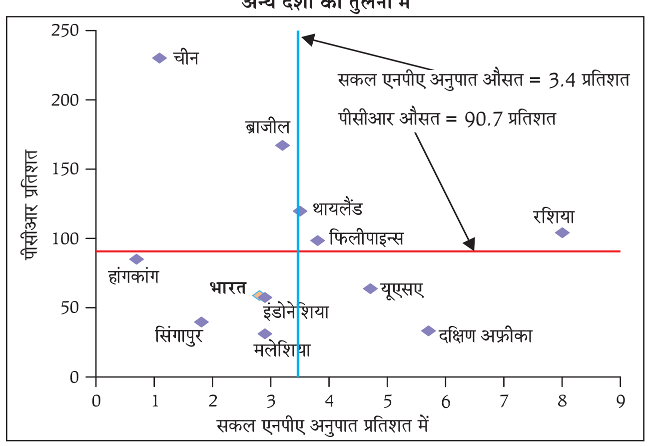

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेता (एफएसआइ), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

[4] प्रावधान कवरेज अनुपात सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रावधान करने से संबंधित अनुपात है और इससे निधियों की मात्रा का पता चलता है जो एक बैंक ने अपनी ऋण हानियों को कवर करने के लिए व्यवस्था की है।

3.13 अनर्जक आस्तियों की बढ़ोतरी के प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, खुदरा, स्थावर संपदा और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र की सकल अनर्जक आस्तियों में आया संयुक्त शेयर सितंबर 2011 के अंत में 85 प्रतिशत की। बैंकिंग प्रणाली की सकल अनर्जक आस्तियों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और खुदरा क्षेत्र का अंशदान क्रमश: 48 और 23 प्रतिशत था जो बैंकिंग प्रणाली के कुल अग्रिमों में उनके क्रमश:31 और 19 प्रतिशत की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। साथ ही, खुदरा क्षेत्र में मार्च 2010 से (चार्ट 3.13 और 3.14) गिरावट की प्रवृत्ति के पश्चात् अनर्जक आस्तियों में वृद्धि देशी गई। मूलभूत और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के मामले में अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर उनकी संबंधित बकाया राशियों की तुलना में उपेक्षाकृत अधिक थी। मूलभूत क्षेत्र में यद्यपि अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर बकाया ऋणों के अनुपात में 0.6 प्रतिशत पर कम ही रही तथापि बिजली और दूरसंचार के क्षेत्रो में अनर्जन और पुनर्गठन में वृद्धि देशी गई। तथापि, आगे बढते हुए यदि वृद्धि की दर कम होती है, इस क्षेत्र में आस्ति की गुणवत्ता आगे प्रभावित हो सकती है। यह प्रभाव बिजली के क्षेत्र में विशेषत: राज्य बिजली बोर्ड (बॉक्स 3.2) के पहले से चले आ रहे नुकसान के कारण अत्यधिक उग्र रूप में पड़ सकता है।

चार्ट 3.13: सकल बैंकिंग प्रणाली ऋण और अनर्जक आस्तियों में क्षेत्रवार हिस्सा - सितंबर 2011

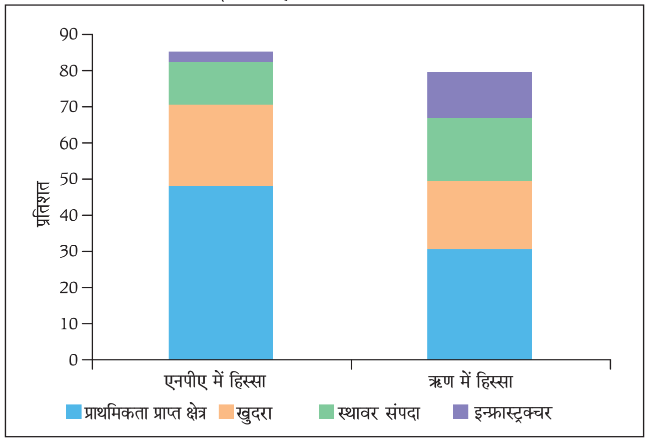

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवक्षी विवरणियां

3.14 मंदी अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में क्रेडिट वृद्धि में कमी होने के कारण आस्ति गुणवत्ता में आगे गिरावट होने की काफी संभावना है। इस संबंध में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की विस्तृत व्यावहारिक अध्ययन के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिससे यह प्रकट होता है कि सुदृढ़ क्रेडिट वृद्धि आस्ति गुणवत्ता में सुधार की परिचालक है जबकि क्रेडिट वृद्धि में कमी अनर्जक आस्तियों में वृद्धि होने के कारण आती है। आगे बिजली, दूरसंचार (उपर चर्चा की जा चुकी है और विमानन जैसे क्षेत्रों की हाल ही की गतिविधियों को देखते हुए इन प्रवृत्तियों की और भी पुष्टि होती है। तथापि, दबाव परीक्षणों की और भी पुष्टि होती है। तथापि, दबाव परीक्षणों की श्रृखंला में यह निर्दिष्ट होता है कि बैंकिंग क्षेत्र कतिपय वैयक्तिक बैंकों द्वारा अत्यधिक आधारों के मामले में कठिनाई का सामना किए जाने के बावजूद अनर्जक आस्तियों की वृद्धि से उत्पन्न हुई स्थितियों का सामना करने में सक्षम होगा। (पैराग्राफ 3.40 से 3.42)

चार्ट 3.14: अनर्जक आस्तियों और ऋण की वृद्धि दर-सितंबर 2011

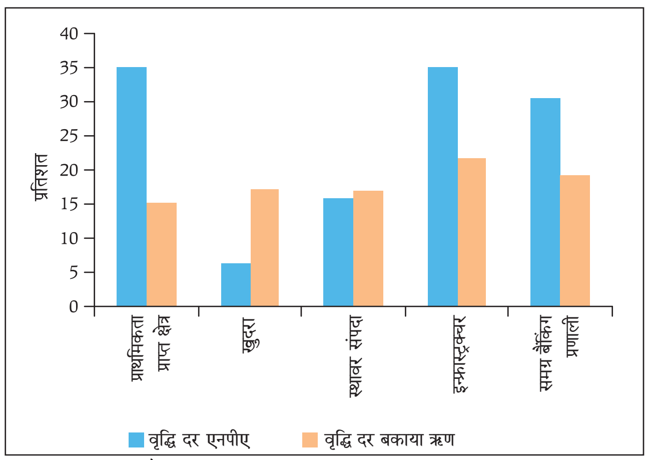

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवक्षी विवरणियां

.....लाभप्रदता में दबाव की स्थिति उत्पन्न होना

3.15 अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी और उच्चतर ब्याज व्यय होने के परिणामस्वरुप प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं बढ़ जाने के कारण बैंकों की लाभप्रदता में बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

3.16 सितंबर 2011 के अंत में ब्याज संबंधी आय (वर्ष-दर-वर्ष) 34.4 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि ब्याज संबंधी व्यय बढ़कर 46.7 प्रतिशत

बॉक्स 3.2: बिजली और दूरसंचार क्षेत्र में बाधाएं और पुनर्गठन वृद्धि

जून 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा आधाररत भाग को दिए गए ऋण का प्रमुख शेयर बिजली और दूरसंचार क्षेत्र का था जो क्रमशः 55 और 22 प्रतिशत था। सकल बैंक ऋण में उनका शेयर क्रमशः 7 और 3 प्रतिशत रहा। बिजली क्षेत्र में बैंकों के एक्सपोजर के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अधिकतम शेयर रहा और उसके पश्चात् क्षेत्र के बैंकों का रहा। इसी प्रकार दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों का अधिकतम एक्सपोजन रहा और उसके पश्चात् विदेशी बैंकों का रहा। (चार्ट 3.15 और 3.16)

चार्ट 3.15: बिजली और दूरसंचार का योगदान

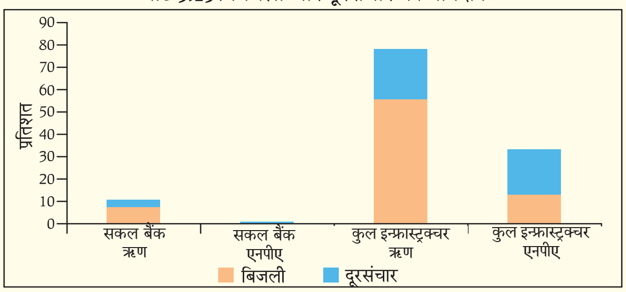

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 85 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 67 बैंकों का नमूना आकार
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

चार्ट 3.16: बैंक दलों के बीच एक्सपोजर का संवितरण

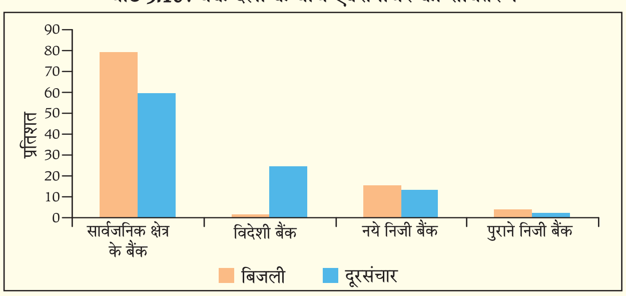

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 85 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 67 बैंकों का नमूना आकार
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

जून 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार बिजली और दूरसंचार के क्षेत्रों में अनर्जक और पुनर्गठन के मामले में वृद्धि हुई है। दोनों क्षेत्रों के पुनर्गठित लेखे जून 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र के कुल पुनर्गठन का 8.5 प्रतिशत पर बने रहे जबकि मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार वे 5 प्रतिशत थे। इसी प्रकार सकल बैंकिंग क्षेत्र के शेयर के रूप में अनर्जक लेखों के अनुसार अनर्जक आस्तियां 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.0 प्रतिशत हो गई। (चार्ट 3.17)।

चार्ट 3.17: बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों को बकाया बैंक क्रेडिट के हिस्से के रूप में अनर्जक और पुनर्गठित लेखे

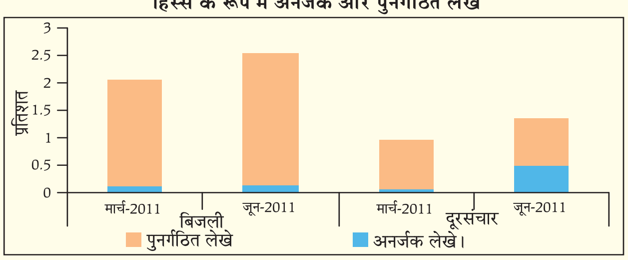

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 85 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने 67 बैंकों का नमूना साइज
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

बिजली क्षेत्र को दिए गए ऋण की वृद्धि दर सकल बैंकिंग क्षेत्र की ऋण-वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंची रही यद्यपि राज्य विद्युत बोर्डों को दिए जानेवाले ऋण में तेजी से कमी आई है। इस के साथ ही बिजली क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण की स्थिति स्पष्ट है जो बिजली जेनरेट करने के लिए दिए गए ऋण का अनुमानतः 55 प्रतिशत बैठता है जबकि राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों को दिया गया ऋण 25 प्रतिशत है (चार्ट 3.18 और 3.19)।

चार्ट 3.18: बिजली क्षेत्र में बैंकऋण का अलग-अलग विवरण

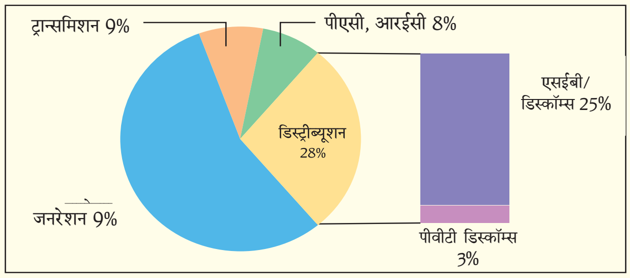

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 85 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने 67 बैंकों का नमूना साइज
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

चार्ट 3.19: बिजली क्षेत्र और इसके संघटकों को दिए गए ऋण की वृद्धि दर

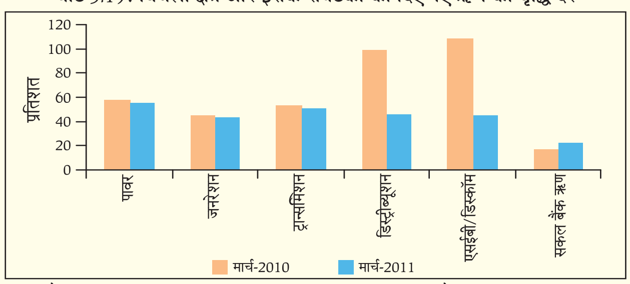

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 85 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने 67 बैंकों का नमूना साइज
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

बैंकों को बिजली क्षेत्र के मामले में अपने एक्सपोजर के आधार पर जिस जोखिम का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है, वह दो कारणों से है-राज्य विद्युत बोर्डों में बढ़ते हुए नुकसान और राज्य विद्युत बोर्डों में कर्ज का स्तर तथा बिजली निर्माण के लिए उपलब्ध ईंधन में कमी।

बारहवी पंचवर्षीय योजना (अगस्त 2011) के ड्राफ्ट एप्रोच के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड को दी गई सहायता का हिसाब लगाने से पूर्व वितरण सेवाओं का चालू नुकसान लगभग रु.70,000 करोड़ रहा। राज्य विद्युत बोर्ड का संचित नुसार परोक्ष रूप से पॉवर उत्पादकों को प्रभावित करता है क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड देश में बिजली के सबसे बड़े क्रेता हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों की खराब स्थिति के अलावा कोयले की आपूर्ति से संबंधित मुद्दे भी बिजली क्षेत्र पर दुष्प्रभाव डालते हैं। कुछ परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी रुकावटों का कारण रुकी पड़ी हैं। इस पृष्ठभूमि के कारण बहुत से उधारकर्ता इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के सतर्क हो गए हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों और कोयला आपूर्ति नुकसान/ बिजली परियोजनाओं में हुई देरी के साथ-साथ बिजली उत्पादन और विवरण (ऊपर की गई चर्चा के अनुसार) क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिया गया अधिक ऋण चिंता का विषय है।

हो गया। निवल ब्याज आय सितंबर 2010 के 40.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना के सितंबर 2011 में 15.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक बढ़ गई। परिचालन संबंधी व्यय भी (वर्ष-दर-वर्ष) पहली फीस आय और कम होती व्यापारिक आय के कारण 4.4 प्रतिशत की तुलना में ब्याजेतर उभय 15.2 प्रतिशत से अपेक्षाकृत उंची दर पर बढ़ गए।

3.17 परिणामस्वरुप प्रावधानीकरण और कर पूर्व उपार्जन में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) सितंबर 2010 के 24 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2011 में घटकर 10 प्रतिशत रह गई और कर पश्चात् लाभ सितंबर 2010 में हुई 31 प्रतिशत की तुलना में 2 प्रतिशत तक बढ़े। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रावधानीकरण और कर पूर्व लाभ 21.8 प्रतिशत बढ़े और कर के बाद लाभ 19.7 प्रतिशत तक बढ़े। कम होते लाभ मार्जिन और बढ़ते हुए प्रोविजन के बीच लाभप्रदता अनुपात ने मंदी ही दर्शायी (चार्ट 3.20 और सारणी 3.1)।

3.18 इसके साथ ही ऊंची ब्याजदरों के बने रहने के कारण मार्जिन पर दबाव होने के फलस्वरुप बैंकों के उपार्जन पर आगे दबाव पड़ सकता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधि हाल ही में बैंकों की बचत जमादरों का विनियामक होना है, जो वर्तमान उच्च ब्याजदर के परिवेश में खुदरा जमाराशियों पर ब्याज लागत को बढा सकता है (बॉक्स 3.3)। क्रेडिट में संभाव्य गिरावट और बढ़ती हुई ब्याज दरों के परिदृश्य में आस्तियों की क्रेडिट गुणवत्ता मे और अधिक गिरावट (पैराग्राफ 3.14 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार) होने के कारण अपेक्षाकृत उच्च प्रावधानीकरण बैंकों के निम्नलाभ आधार को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

लघु विदेशी बैंकों में ऋणकर्ताओं के संक्रेंद्रण जोखिम की प्रधानता

3.19 जून 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का औसत 10 प्रतिशत भाग शीर्ष 10 उधारकर्ताओं कम था। तथापि, ऐसे अनेक बाहरी बैंक (अधिकांशत: होते विदेशी बैंक) के, जहां इस बैंकों के कुछ सीमा तक संकेंद्रण जोखिम की ओर संकेत करते हुए कुल आस्तियों का 40 प्रतिशत भाग 10 शीर्ष उधारकर्ताओं का था (चार्ट 3.21)।

क्रेडिट और साथ ही जमाराशियों के संबंधक में भौगोलिक संकेंद्रण की प्रमुखता

3.20 पूरे देश में क्रेडिट और जमाराशियां दोनों की बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जनसांख्यिकी संबंधी वितरण इस विषमता को कुछ सीमा तक स्पष्ट करता है। किंतु 'विकास' स्पष्ट रूप से इस मामलें में प्रमुख कारण है। यदि हिसाब से देखें तो मूल बैंक-ऋण के 43 प्रतिशत से अधिक का उपयोग महाराष्ट्र और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

चार्ट 3.20: उपार्जन के संघटकों की वृद्धि दर

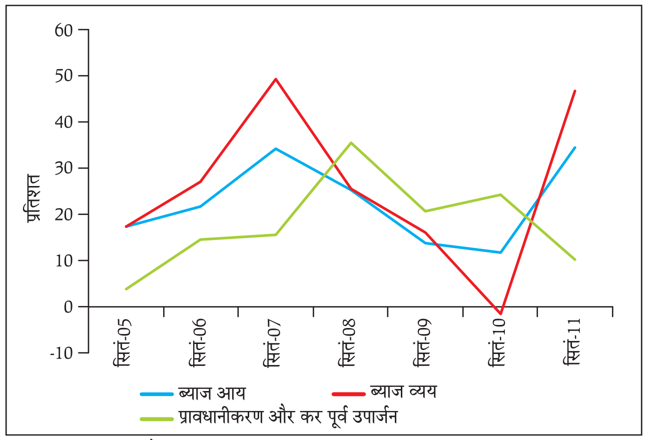

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी संबंधी विवरणियां

सारणी 3.1: लाभप्रदता अनुपात

		सितंबर 2009	सितंबर 2010	सितंबर 2011	मार्च 2011
क	(देयताओं के प्रतिशत रूप में प्रावधान और कर पूर्व उपार्जन) लाभ मार्जिन	1.2	1.2	1.1	2.3
ख	इक्विटी के प्रतिशत रूप में लीवरेज देयताएं	11.6	11.7	11.9	12.2
ग	प्रावधानीकरण और कर पूर्व (क + ख) इक्विटी पर प्रतिलाभ	13.4	14.3	13.6	27.8
घ	इक्विटी के प्रतिशत रूप में प्रावधान	3.0	3.7	4.5	7.4
च	कर पूर्व (ग-घ) इक्विटी पर प्रतिलाभ	10.4	10.6	9.1	20.3
छ	आयकर दर	65.5	67.0	66.9	66.7
ज	इक्विटी पर प्रतिलाभ (इ*एफ)	6.8	7.1	6.1	13.6
	आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.48	0.55	0.47	1.09
	लागत आय अनुपात (दक्षता अनुपात)	46.1	45.0	46.1	46.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

चार्ट 3.21: कुल आस्तियों के प्रतिशत रूप में शीर्ष 10 उधारकर्ता-जून 2011

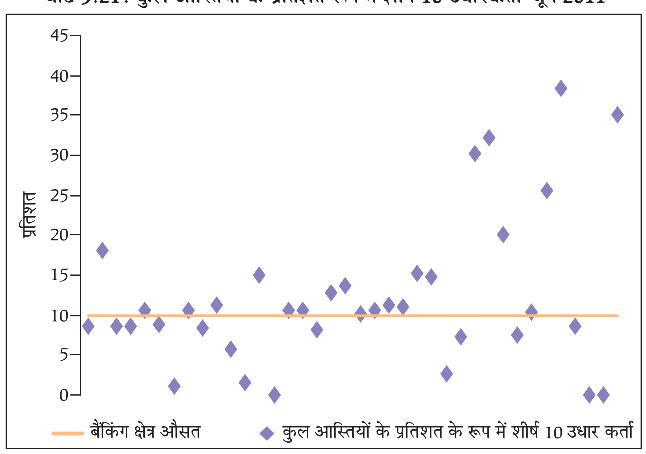

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 65 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने 38 बैंकों का नमूना साइज

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

बॉक्स 3.3: बैंकों की बचत ब्याज दरों का अविनियमन: एक विश्लेषण

भारत द्वारा किए गए वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रक्रिया के विश्लेषण से जो प्रमुख घटक उभरकर सामने आया, वह था जमा और उधार ब्याजदरों के विभिन्न ढांचे का अविनियामन। जमा साइड पर बचत जमा ब्याज दर ही विनियमित ब्याजदर बनी रही। बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर 1 मार्च 2003 से 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर अपरिवर्तित रही। क्षेत्रपार अनुभव के अनुसार अधिकांश देशों में बचत बैंक खातों में ब्याज दरें अविनियमित रही हैं और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बाजार ब्याजदरों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

बचत जमाराशियों की ब्याज दर में परिवर्तन लाने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के साथ आरंभ किया गया और उन्हें सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2010[5] से दैनिक उत्पाद आधार पर बचत बैंक खातों पर ब्याज अदा करें। बाद में मई 2011 में ऐसी जमाराशियों पर ब्याज की दरें 50 आधार अंकों द्वारा बढ़ाकर 4 प्रतिशत तक कर दी गई। 25 अक्तूबर 2011 से रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक खातों की ब्याज दरों की अविनियामित दर दिया जिसके अनुसार बैंकों को बचत खातों के ₹1 लाख तक की जमाराशियां पर समान ब्याज दर रखनी होगी और ₹1 लाख से अधिक की राशि की बचत जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें निर्धारित कर सकते हैं। उठाए गए इस कदम से मौद्रिक नीति के संचालन में सुधार की संभावना हो सकती है। बदलती बाजार स्थितियों के अनुरूप बचत जमादरों में बदलाव लाने से बचत खातों के आकर्षण को बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

बाजार स्थितियों के अनुरूप ब्याज दर होने से बचत जमा और अन्य नकदी। अत्याधिक अल्पावधि निधियों के बीच अवसर लागत होने की संभावना है। यद्यपि ऐसी नकदी और अत्यधिक अल्पावधि निधियों में निवेश सीमित होने कारण स्थानापन्न व्यवस्था संदिग्ध हो सकती है, विनियमन न होने से ग्राहकों में कुछ जोश आने की भी संभावना है।

बैंकों के लिए बचत जमाराशियों का प्रमुख आकर्षण यह है कि यह निधियों का कम लागत वाला स्रोत है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि कासा (चालू बचत खाता) जमाराशियों में उच्चतर शेयर रखने वाले बैंक (जिनका प्रमुख घटक बचत जमाराशि है) जमाराशियों पर अपेक्षाकृत कम लागत का लाभ उठाते है (चार्ट 3.22)।

तथापि, बैंकों के बीच कासा जमाराशियों का संवितरण समान नहीं है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, जो अभी तक नहीं थी, बढ़ सकती है क्योंकि कम कासा अनुपात वाले बैंक दरें बढ़ाकर ऐसी जमाराशियों को जुटाने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। यह प्रभाव पहले से ही देखा जा यकता है क्योंकि कुछ बैंकों ने विनियमन न होने पर बचत खाते पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। बैंक की लाभप्रदता पर ऐसी दरों की वृद्धि के प्रभाव की ध्यानपूर्वक निगरानी करनी होगी क्योंकि पहले ही बैंकों की निधियों की लागत बढ़ गई है और इस प्रभार की दर वृद्धि होने से बैंकों को निवल ब्याज मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा (चार्ट 3.23)। तथापि, यह प्रभाव ग्राहकों में व्याप्त असंतोष और अलग-अलग बैंकों द्वारा अपनाए गए लागत ढांचे के आधार पर लाभ हो सकता है। इस स्थिति के परिणामस्वरुप गिरती ब्याज दरों के परिदृश्य में बचत बैंक जमा दरें भी तदनुसार कम हो सकती है।

खुदरा जमाराशियों के लिए इस बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में बैंक नई-नई बचत जमाराशि संबंधी योजनाएं आरंभ कर सकते हैं क्योंकि हांगकांग में बचत जमाब्याज दरों का अविनियमन होने पर नए उत्पाद यथा संयुक्त बचत और जांच खातों और हांगकांग अंतरबैंक प्रस्तुत दर अथवा साइबर (एचआइबीओआर) संबद्ध बचत उत्पाद और ब्याज दरों के स्तरीय ढांचों की शुरुआत की गई। तथापि, इस बात की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि मिश्रीत और अपारदर्शी स्वरूप के उत्पादों के बेचे जाने की संभावना पर रोक लगाई जाए क्योंकि ऐसा करना आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं होगा। साथ ही, बैंक लेनदेन और सेवा भार लगाकर ब्याज लागत में वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप से कम कर सकते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त लागत की पूर्ति ग्राहकों की आधार से की जा सकती है।

चार्ट 3.22: चालू खाता / बचत खाता (सीएएसए) बनाम जमाराशियों की लागत-सितंबर 2011

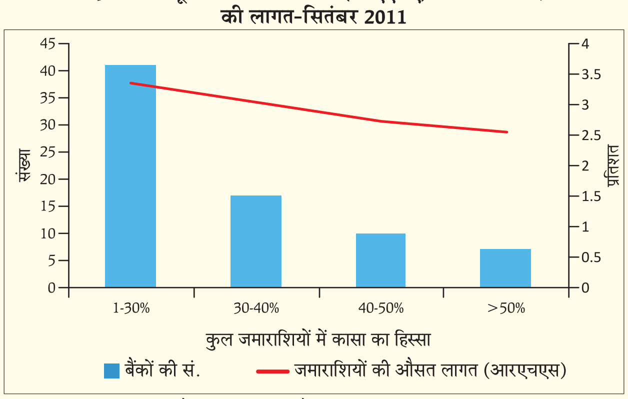

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना।

चार्ट 3.23: बचत बैंक जमा दर[6] में 100 आधार अंकों की वृद्धि का निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर प्रभाव

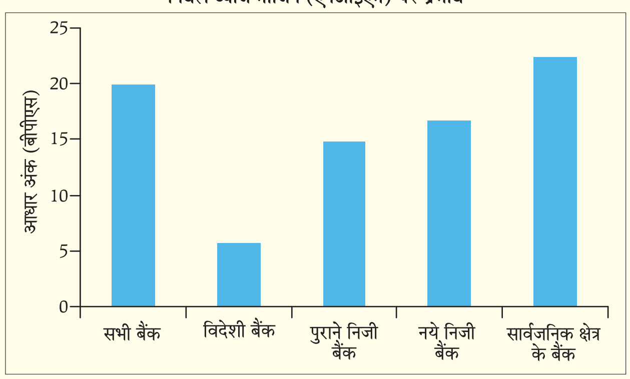

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई गणना

[5] दैनिक उत्पाद प्रणाली के प्रारंभ से पहले बचत जमा खाते पर ब्याज प्रत्येक कैलेंडर माह के 10वें दिन और आखरी दिन के बीच रखी गयी न्यूनतम राशि के आधार पर परिकलित किया जाता था और खातेदार के खाते में देय ब्याज तभी जमा किया जाता था, जब ब्याज की राशि कम से कम 1 रुपया और उससे अधिक हो।

[6] इसका प्रभाव इस धारणा के आधार पर गिना जाता है कि सभी बैंक अपनी बचत बैंक जमा राशि दर 100 आधार अंकों से बढ़ाते हैं।

में किया जाता है, जबकि कुल बैंक-जमा में इन दोनों क्षेत्रों का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है। ऋण और जमा दोनों में जिन राज्यों की हिस्सेदारी कम है, वे हैं उत्तर-पूर्व के राज्य, जम्मू और कश्मीर तथा छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक वर्ष के दौरान ऋण वितरण संबंधी गिनि गुणांक 74 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा, जबकि जमा-वितरण के मामले में यह गुणांक 68 प्रतिशत रहा (चार्ट 3.24)।

उच्च जोखिम वाले उद्योगों में ऋण की हिस्सेदारी बढ़ी

3.21 उच्च जोखिम वाले उद्योगों में सितंबर 2011 के अंत में ऋण की हिस्सेदारी में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मार्च 2011 के अंत में यह वृद्धि मात्र 16 प्रतिशत थी। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र ने ऋण का प्रमुख हिस्सा बटोरा है (चार्ट 3.25)।

नकदी जोखिम उच्च स्तर पर

3.22 बैंकिंग क्षेत्र के लिए नकदी जोखिम का अनुपात (कुल ऋण, अनिवार्य सीआरआर और एसएलआर एवं स्थायी परिसंपत्तियों की कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में गणना) औसतन 80 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा (चार्ट 3.26)। एक दबाव जांच विश्लेषण से मालूम हुआ है कि उच्च दबाव की स्थिति में एसएलआर निवेश बैंकों के लिए सहायक सिद्ध हुआ है तथा इससे उनका नकदी संबंधी दबाव खत्म हुआ है। (पैरा 3.49 और 3.50)

'प्रतिफल कर्व जोखिम' में कमी देखने को मिली

3.23 इससे संबंधित अनुपात (अबतक की सभी अनमेल बकिटों के जोड़ एवं जोखिम संवेदी परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रतिशत के रूप में गणना) जो मार्च 2011 में लगभग 3 प्रतिशत था, जून 2011 में घटकर 1.5 प्रतिशत रह गया, जो कम जोखिम की ओर संकेत कर रहा है।

बैंकिंग बही में दर्ज रिकार्ड के अनुसार, ब्याज-दर जोखिम में वृद्धि हुई है

3.24 बैंकिंग बही में दर्ज रिकार्ड के अनुसार, ब्याज दर जोखिम, आमदनी के नजरिये से देखने पर (बारह माह के अंतराल में 200 बीपीएस के शॉक के कारण एनआईआई में प्रतिशत गिरावट के रूप में माप), मार्च 2011 के लगभग 8 प्रतिशत से बढ़कर जून 2011 में लगभग 40 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। किंतु आर्थिक मूल्य की दृष्टि से, उक्त अवधि में उक्त जोखिम (बारह माह के अंतराल में 200 बीपीएस के मानक शॉक के कारण, निधि में प्रतिशत गिरावट

चार्ट 3.24: भारत के सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में ऋण और जमाराशियों के वितरण को दर्शानेवाला लोरेंज कर्व- जून 2011

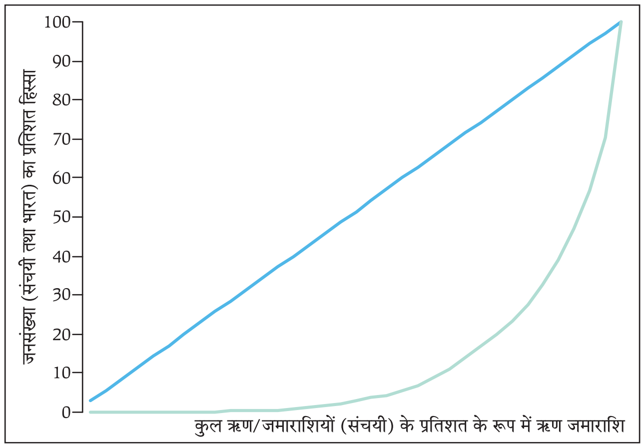

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 3.25: उद्योगों को बैंक ऋण-जोखिमवार

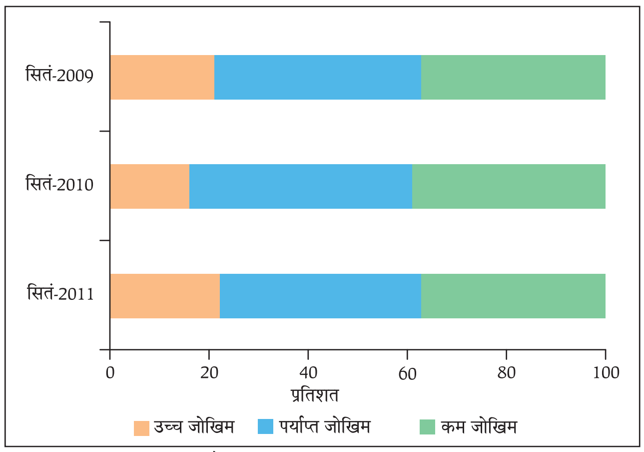

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना और सीआरआईएसआईएल

चार्ट 3.26: नकदी की कमी का अनुपात-जून 2011

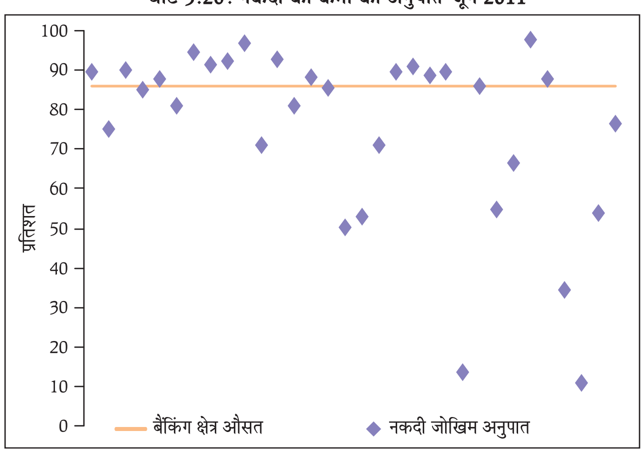

नोट: बैंकिंग क्षेत्र की 51 प्रतिशत आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने 32 बैंकों का नमूना साइज
स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

के रूप में माप), 10 प्रतिशत के मामूली जोखिम स्तर तक का सुधार देखने में आया है (चार्ट 3.27 और 3.28)।

3.25 बैंकिंग बही में प्रदर्शित प्रतिफल कर्व में विभिन्न प्रकार के प्रभाव की जांच करने हेतु एक दबाव परीक्षण विश्लेषण किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश बैंक ब्याज दर के शॉक को सहन करने में सक्षम हैं। (पैराग्राफ 3.43 और 3.44)

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर स्पष्ट दबाव

3.26 सहकारी बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांतों अर्थात् पारस्परिक आर्थिक सहायता एवं बचत और स्वयं सहायता को बढावा देने के उद्देश्य ने समय के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के महत्व को कायम रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों में शहरी सहकारी बैंकों को एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जाता है। जिन क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनमें उनकी प्रविष्टि को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत नये शहरी सहकारी बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किए जाने की उपयुक्तता का अध्ययन किए जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तावित शहरी सहकारी बैंक के स्थान निर्धारण के आधार पर उसकी न्यूनतम प्रवेशकालिक पूंजी का भी उल्लेख किया गया है। छत्र संगठन (अंबरैला आर्गेनाइजेशन) के रूप में शिखर स्तर के दो संगठनों की स्थापना करना रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है। उक्त संगठन भुगतान एवं निपटान सेवाएं तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा सामान्यत: दी जानेवाली अन्य सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे।

3.27 क्षेत्र की कुल संपत्तियों का 43.7 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास है, इन बैंकों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि जून 2011 के अंत में इनकी जमाराशियों और अग्रिमों में तगड़ी वृद्धि हुई है (चार्ट 3.29)। जबकि जून 2011 में सीआरएआर मार्च 2011 के

चार्ट 3.27: 200 बीपीएस के शॉक के कारण एनआईआई में गिरावट

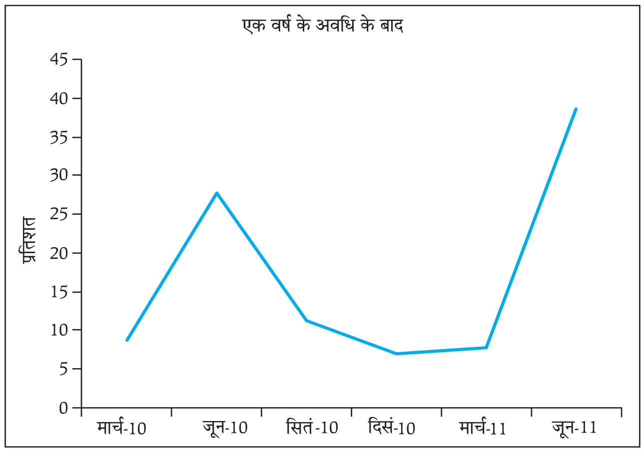

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 3.28: 200 बीपीएस के शॉक के कारण पूंजी निधियों में गिरावट

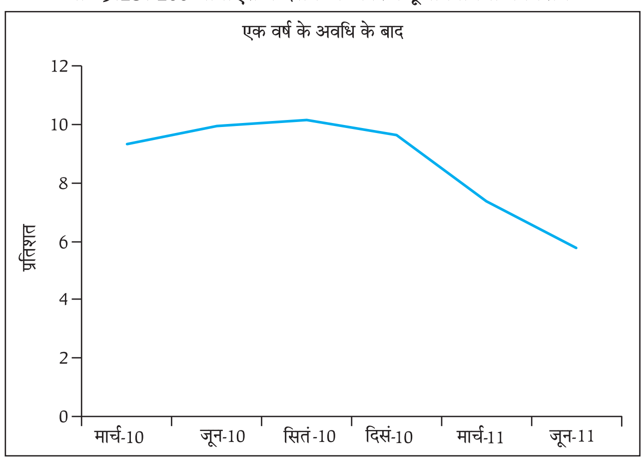

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 3.29: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय मानदंड

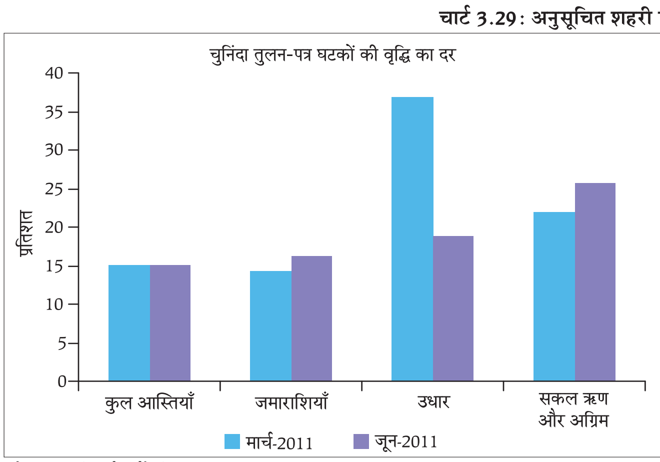

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

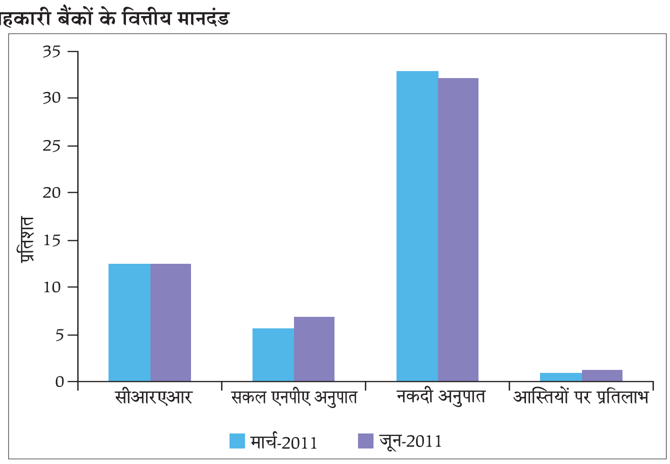

नोट: चलनिधि अनुपात= (नकदी + बैंकों के पास बकाया राशि + मांग तथा अल्पकाल में देय राशि + एसएलआर निवेश) / कुल आस्तियां

12.5 प्रतिशत से तनिक घटकर 12.4 प्रतिशत रह गया। सकल एनपीए, जो मार्च 2011 के अंत में 5.7 प्रतिशत था, जून 2011 के अंत मे बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया। इससे परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर दबाव परिलक्षित होता है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण जोखिम पर एक दबाव परीक्षण किया गया। इसके परिणाम से यह संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र एनपीए अनुपात में 50 प्रतिशत की वृद्धि को सहन कर सकता है, लेकिन एनपीए अनुपात के दुगना होने की स्थिति में यह दबाव में आ जायेगा (पैराग्राफ 3.51)।

ग्रामीण सहकारी क्षेत्र

ग्रामीण ऋण वितरण में अल्पावधि ऋणों का प्रभाव जारी

3.28 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (अल्पावधि संरचना), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (दीर्घावधि संरचना)[7] शामिल हैं, में बैंकिंग क्षेत्र की कुल परिसंपत्तियों का 9.2 प्रतिशत है। मार्च 2010 के अंत में ग्रामीण सहकारी बैंकों के कुल बकाया ऋण का लगभग 41 प्रतिशत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के खाते में था तथा इस विषय में प्राथमिक कृषि समितियों और राज्य सहकारी बैंकों का नंबर इसके बाद आता है। इसके साथ-साथ, कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों में दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत रही है, जिससे ग्रामीण ऋण वितरण में अल्पावधि संरचना का निरंतर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए 'जमाराशियां' संसाधनों का प्रमुख स्रोत रही हैं, जबकि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में 'उधारराशिया' प्रमुख स्रोत के रूप में देखी गई हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर, परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में दीर्घावधि संरचना के मुकाबले अल्पावधि संरचना की भूमिका सराहनीय रही है, हालांकि अनर्जक परिसंपत्तियों का अनुपात उच्च रहा है (चार्ट 3.30)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट, हालांकि लाभप्रदता में सुधार देखने में आया

3.29 जमा राशियां स्वीकार न करनेवाली एनबीएफसी जो आकार में बड़ी एवं प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण है अर्थात जिनकी परिसंपत्तियों का आकार रु.100 करोड़ और इससे ज्यादा है उन्हें एनबीएफसी-एन डी-एसआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा वे एनबीएफसी क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं। सितंबर 2011 के अंत में एनबीएफसी-एनडी-एसआई की वित्तीय मजबूती के संकेतकों ने बताया कि मार्च 2011 के बाद परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई है, हालांकि जून 2011 माह में समाप्त तिमाही के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है। तथापि, लाभप्रदता संकेतकों में मजबूती रही है (चार्ट 3.31) एनबीएफसी-एन डी - एसआई

चार्ट 3.30: ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय मानदंड-मार्च 2010

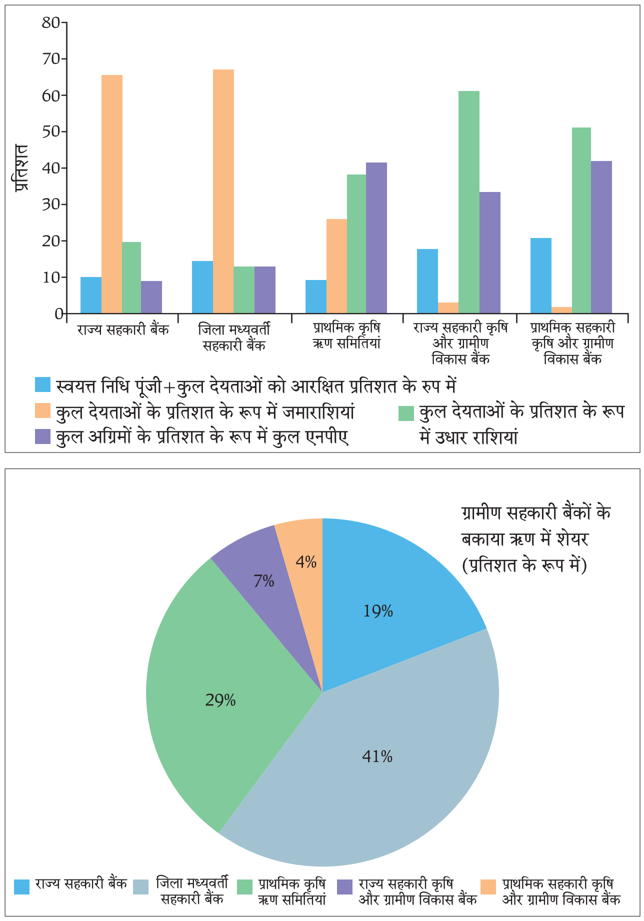

स्रोत: रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2011

चार्ट 3.31: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की वित्तीय मजबूती के संकेतक

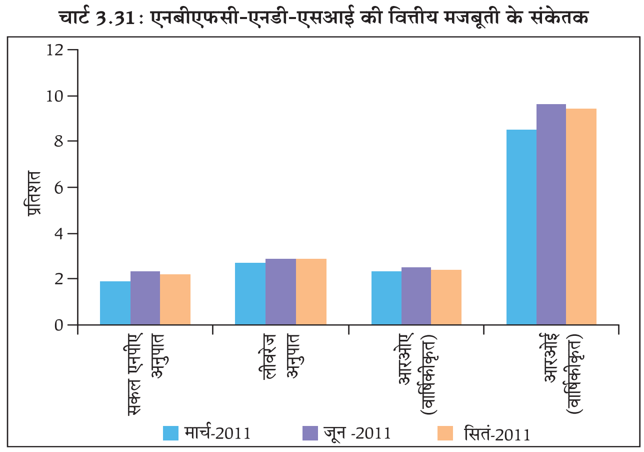

नोट: लीवरेज अनुपात: स्वाधिकृत निधियों के प्रति बाह्य देयताएं
बाह्य देयताएं: कुल देयताएं-स्वाधिकृतनिधियां
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

[7] एसटीसीबी -राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी-राज्य केंद्र सहकारी बैंक, पीएसीएस - प्राथमिक कृषि ऋण समिति, एससीएआरडीबीएस - राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और पीसीएआरडीबीज़ - प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

के संदर्भ में ऋण जोखिम पर एक दबाव परीक्षण किया गया है तथा परिणामों से संकेत मिला है कि वे ऋण जोखिम के तगड़े शॉक सहन करने में सक्षम हैं (पैराग्राफ 3.52 और 3.53)।

संसाधनों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर अत्याधिक निर्भरता देखने में आई है....

3.30 यह देखने में आया है कि एनबीएफसी-एनडी-एसआई अपने संसाधनों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर अत्याधिक निर्भरता हैं। उनके संसाधनों एवं निधि-प्रयोग का विश्लेषण करने पर यह तथ्य उजागर हुआ है। यदि बैंक इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहते हैं या अनिच्छुक हो जाते हैं तो एनबीएफसी क्षेत्र के समक्ष एक बहुत बढ़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। चूंकि एनबीएफ कंपनियों में यह लक्षण पाया गया है कि तनाव के दौरान त्वरित डि-लीवरेज करती हैं, अत: इससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी चिंता की स्थिति बन सकती है। हाल ही में उत्पन्न हुए वैश्विक संकट से यह संकेत मिलता है। वर्ष 2010-11 के दौरान, एनबीएफ कंपनियों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र से ली गई उधार राशि में 54.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा दिये गए ऋण में 30.4 प्रतिशत की बढोतरी हुई (चार्ट 3.32)।

3.31 एनबीएफ कंपनियों की बैंकों के साथ बढ़ती हुई अंत:संबद्धता तथा एनबीएफ कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों का बैंकों की तुलना में कम कठोर होने से अंतरपणन के अवसरों की संभावना बढ़ गई। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में भी इन्हें विशेष रूप से उजागर किया गया है तथा इस प्रकार के विनियामक अंतरपणन के रास्तों को बंद करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। संबंधी मामलों और विचारणीय विषयों के अध्ययन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2011 में एक कार्य-दल का गठन किया था। कार्य-दल ने अब अपनी संस्तुतिया प्रस्तुत कर दी है। संस्तुतियों का संबंध अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान विनियामक ढांचे को युक्तियुक्त बनाने, विवेकपूर्ण मानदंडों, बैंकों एवं एनबीएफ कंपनियों की विनियामक समरूपता, पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने कंपनी अभिशासन मानदंडों और प्रकटन से हैं। उक्त संस्तुतियों की जांच की जा रही है।

पेंशन निधियां [8]

.... अपनी दीर्घावधि दीर्घ-मात्र निवेश शैली में 'स्वचालित स्टेबलाइजर' की तरह कार्य कर रही हैं।

3.32 स्थिरता को सुनिश्चित करने में पेंशन निधियों का बहुविध महत्व है। प्रथम, हालांकि (संविभागीय कर्मण्यता की कमी के कारण) पेंशन निधियों को उनकी 'क्रय और धारण' नीति के कारण निष्क्रिय निवेशक

चार्ट 3.32: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की निधियों के स्रोतों में शेयर

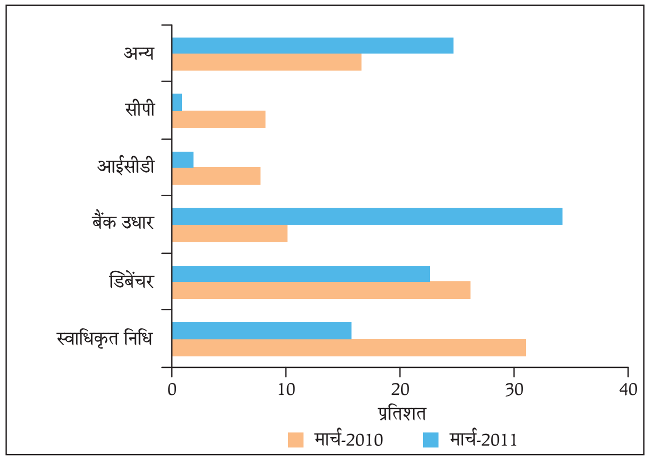

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

[8] स्रोत :पीएफआरडीए

कहा गया है, तथापि वे अपनी पर्याप्त उपस्थिति के कारण तथा बड़े स्तर पर औने-पौने बेचने की स्थिति में प्रतिकारी शक्ति के रूप में कार्य करने के कारण बाजार-स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा, पेंन्शन निधियां, दीर्घकालिक निवेश नीति के साथ बड़े पैमाने के शेयर धारक होने के कारण, निवेश प्राप्त करनेवाली कंपनियों में कंपनी अभिशासन की उच्च पद्धतियां कायम करने में सहज भाव से प्रमुख भूमिका निभाती है। तीसरे, पेन्शन निधियों को इक्विटी/ऋण लेख-पत्र में निवेश करने की अनुमति से वे न केवल ग्राहकों को बेहत्तर प्रतिफल प्रदान कर सकते हैं बल्कि उसी समय पूंजी बाज़ार विकसित करने में दोहरी भूमिका अदा कर सकते हैं।

3.33 भारत में पेन्शन फंड एण्ड रेग्युलेटरी ऑथरिटी को पेन्शन क्षेत्र के लिए विनियामक की भूमिका निभाने का अधिकार दिया गया है और यह 'राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली' तथा 'नई पेन्शन प्रणाली' का विनियमन कर रहा है। 'नई पेन्शन प्रणाली' में ऋण एवं बाज़ार जोखिम कम करने के लिए निवेश प्रबंधन दिशा-निर्देश बनाये गये हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत पेन्शन निधि प्रबंधक, तीन पृथक योजनाएं, जिनमें तीन आस्ति वर्ग अर्थात् (i) इक्विटी (ii) सरकारी प्रतिभूतियां (iii) ऋण जोखिम वाले निर्धारित आय लिखत शामिल हैं और जिनका 50 प्रतिशत इक्विटी में निवेश किया जा सकता हैं का प्रबंधन करते हैं।

3.34 पेन्शन फंड में टियर-I टियर-II नामक दो खाते हैं जो पेन्शन फंड निधि के संचयन चरण के दीर्घावधिक निवेश है और जो देयताओं की चुकौती के लिए खोले गये हैं। वहीं दूसरी ओर टियर-II खाता बार-बार (यहां तक कि तत्काल) आहरण की अनुमति देता है और उच्च आरक्षित निधि अपेक्षा लागू करता है। एक ऐसे फ्रेमवर्क, जिसमें निवेशकों को परिसमापन का विकल्प है, यदि टियर-II खाते के अंतर्गत निधियों का आकार बड़ा है तो ऋण मुक्ति दबाव में किसी तरह के आकस्मिक क्षणिक परिवर्तन से प्रतिभूति बाज़ार में बेलगाम हलचल मच सकता है और स्थिरता जोखिम भी उभर कर आ सकती है।

बीमा क्षेत्र[9]

अंतर्संबद्धता चिंता का विषय बना रहा

3.35 चूंकि जीवन बीमाकर्ताओं के संबंध में सभी मामलों में शोधन क्षमता अनुपात[10], विनियामक अपेक्षाओं से अधिक है, भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र भलीभांति पूंजीकृत है। तथापि हाल ही में अनिवार्य मोटर थर्ड पार्टी पूल में संगी पूंजीगत अपेक्षाओं में वृद्धि होने से चूंकि देयता अपेक्षाएं गैर जीवन बीमाकर्ताओं के लिए चिंता का सबब बन गये हैं इसीलिए गैर जीवन बीमा क्षेत्र में हामीदारी हानि भी हुई है।

3.36 बीमाकर्ता जोखिमों के लिए हामीदार बनते हैं, बशर्ते कि ये आंतरिक पूंजी द्वारा समर्थित हों अथवा इनमें पुनर्बीमाकरण की क्षमता हो। यह शेयरों का पुनर्बीमा करता है और जोखिमों के विविधिकरण की अनुमति देता है और उद्योग का स्थायित्व प्रदान करता है। इस समय भारत में किये गये अधिकतर बीमा जोखिमों के लिए पुनर्बीमा क्षमता आसानी से उपलब्ध है और यह बीमा कारोबार को समर्थन दे सकता है। पुनर्बीमा उद्योग के असफल हो जाने पर भी यह पुनर्बीमा सुरक्षा लेने के लिए मूल्य में वृद्धि कर सकता है।

3.37 कई बीमा कंपनियों के वित्तीय कोंगोलोमिरेट का अंश होने से बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में अंतर्संबद्धता चिंता का विषय है। कोंगलोमिरेट में बैंक से संबंधित कोई भी वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्दा बीमाकर्ता पर भारी प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के मध्य संपर्क भी बीमा कंपनियों के कुल बैंक एक्सपोज़र पर निर्भर करेगा। इसे अध्याय 5 में संक्रमकता विश्लेषण में प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय संस्थाओं की प्रतिरोध क्षमता-दबाव परीक्षण

3.38 काफी संख्या में वाणिज्यिक बैंकों (60 वाणिज्यिक बैंकों, जो कुल बैंकिंग खेत्र आस्तियों का 99 प्रतिशत) और शहरी (अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) क्षेत्र का एकल कारक संवेदनशीलता तनाव परीक्षण[11] किया गया ताकि उनका विभिन्न परिदृश्यों के अधीन कमजोरियों और एवं प्रतिरोधक्षमता का आकलन किया जा सके। अद्यतन उपलब्ध पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर एकल महत्वपूर्ण वेरिएबल (अन्य कंस्टेंट जोखिम कारक रखने वाले) के बारे में आघातों का प्रयोग करते हुए अलग-अलग बैंकों की आय संविभाग हानियों की स्थिति के संबंध में जांच की गई। इस प्रकार आकलित हानि मिसाल के तौर पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक अर्थात् विनियामक पूंजी पर्याप्तता अनुपात से संबंधित था। अलग-अलग बैंकों के बीच मिले-जुले असर को मिलाकर इसी तरह का एक विश्लेषण पूरी प्रणाली के लिए किया गया।

3.39 ऋण जोखिम दबाव परीक्षण ने आस्ति गुण में समय गिरावट परिलक्षित कर दिया है। इस परीक्षण में अलग-अलग आघातों के सैट अर्थात् (i) कुल अनर्जक आस्ति (समय ऋण), (ii) चुनिंदा क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अनर्जक आस्ति और (iii) बृहत्तम निजी जोखिम (जमाव) शामिल है। इन सभी परीक्षणों में यह मानते हुए कि प्रावधानों में वृद्धि होगी, सीधे अनर्जक आस्तियों (बैंक के तुलन पत्र के अनुसार वार्षिक बट्टे खाते डाले गये अनर्जक आस्ति मूल्य के कुल के तौर पर लिए गये) पर शॉक

[9] स्त्रोत: आईआरडीए

[10] सोलवेन्सी अनुपात (जोकि कंपनी के अपेक्षित सोलवेन्सी मार्जिन को उपलब्ध सोलवेन्सी अनुपात है) कंपनी के जोखिम उठाने की क्षमता का पैमाना है और यह विनियामक परिप्रेक्ष्य से विचार की जाने वाली कंपनी की क्षमता से 150% अधिक होना चाहिए।

[11] दबाव परीक्षण के ब्यौरे जानने के लिए कृपया रिपोर्ट का अनुबंध देखें।

अनुप्रयुक्त किये गये।[12] ये परीक्षण, अलग-अलग बैंकों के समग्र पूंजी पर्याप्तता और समग्र प्रणाली पर अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाओं (आय में गिरावट) के प्रभावों का आकलन करते हैं। कुल पूंजी बासल-II की अपेक्षाओं के अनुसार लिया गया है। यह मानते हुए कि आघात लगते रहते हैं दबाव परीक्षण स्टेटिक मॉड पर किया जाता है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबीज)

कभी कभार होने वाले ऋण जोखिम आघातों को सहने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त लोच है।

3.40 सामान्य अनर्जक आस्ति आघातों के लिए, अनर्जक आस्तियों में 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और 150 प्रतिशत (1 से 3 तक आघात) वृद्धि माना गया है। एक अन्य परिदृश्य के अनुसार फिर से योजनाबद्ध किये गये ऋणों का 40 प्रतिशत अनर्जक आस्ति (आघात-4) बन जाएंगे। इन दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि प्रणाली अनर्जक आस्ति आघातों को सहने के लिए समुचित रूप से तैयार हैं, परंतु भारी आघातों की स्थिति में कुछ बैंक दबाव में आ सकते हैं (चार्ट 3.33 और सारणी 3.2)।

क्षेत्रीय ऋण जोखिमों के कारण बड़े नकारात्मक आघात के मामले में लाभ प्रभावित हो सकते हैं

3.41 इस अभियान में चार अर्थात कृषि, विद्युत, वास्तविक क्षेत्र और दूर संचार क्षेत्र में ऋण जोखिम अरक्षतिता की जांच की गई। माना गया कि प्रत्येक क्षेत्र में आघात में 5 प्रतिशत बिन्दु तक वृद्धि हो सकती है। इन परीक्षणों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नकारात्मक आघात के प्रभाव का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। संवेदनशीलता विश्लेषण से पता चलता है कि संयुक्त आघात प्रणाली स्तरीय एनपीए अनुपात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है, जिसमें वास्तविक और कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। आगे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में एनपीए अनुपात में 5 प्रतिशत की वृद्धिशील वृद्धि के कारण पूंजी पर्याप्तता पर खासा (सारणी 3.3) असर नहीं पड़ेगा। चूंकि बैंक अपने क्षेत्रीय एक्सपोज़र को विशेष रूप से विविधता देते हैं व उनकी आन्तरिक सीमाएं भी हैं, इसलिए हानि सीमित है।

अधिकतर बैंक ऋण जोखिम केन्द्रीकरण के संदर्भ में प्रतिरोधक्षमता पूर्ण साबित हुए हैं

3.42 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अरक्षितता संकेन्द्रण का आकलन करने के लिए, यह परीक्षण एक ही समय में एक या अधिक चूक करने वाले उधारकर्ताओं पर पड़ने वाले असर पर ध्यान देता है। परीक्षण, शीर्ष-एक, शीर्ष -दो और शीर्ष-3, तीन अलग-अलग (आघात-1 से तीन) और सबसे बड़े समूहगत उधारकर्ता (आघात-4) के चूक पर गौर करता है। प्रणाली स्तर पर अग्रिमों का संकेन्द्रण कुछ संकुचित प्रतीत होता है, जबकि यह किसी एक बैंक में काफी

चार्ट 3.33: ऋण जोखिम: सकल ऋण: विभिन्न दबाव परिदृष्यों के तहत वाणिज्य बैंकों की पूंजी और अनर्जक आस्तियों पर प्रभाव: सितंबर 2011

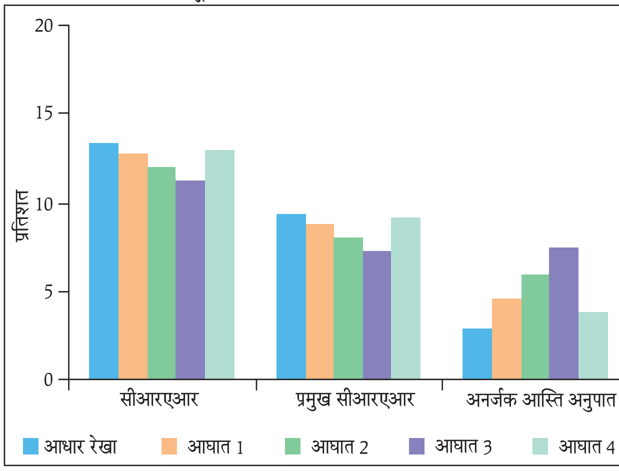

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

सारणी 3.2 : ऋण जोखिम: सकल ऋण: विभिन्न दबाव परिस्थितियों के तहत विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से नीचे रहने वाले वाणिज्य बैंकों का सकल ऋण: सितंबर 2011

	प्रभावित बैंक सीआरएआर 9% से कम		प्रभावित बैंक सीआरएआर 6% से कम	
	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)
आधार रेखा:	0	0.00	0	0.00
आघात 1:	1	0.10	3	19.70
आघात 2:	3	16.10	10	31.60
आघात 3:	12	27.50	20	46.20
आघात 4:	1	0.10	2	3.80

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

सारणी 3.3 : ऋण जोखिम: क्षेत्रीय - सितंबर 2011

प्रणाली स्तर			
	सीआरएआर	कोर सीआरएआर	एनपीए अनुपात
आधार रेखा:	13.27	9.39	2.85
आघात: प्रत्येक क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों में अतिरिक्त 5% वृद्धि			
संयुक्त क्षेत्र (विद्युत + दूरसंचार + कृषि + वास्तविक क्षेत्र)	12.92	9.02	4.90
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	13.20	9.31	4.59

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गई गणना

[12] बढ़ाये गये विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार मानक आस्ति 1 प्रतिशत अवमानक आस्ति 30 प्रतिशत संदेहास्पद और घाटे वाली आस्तियां 100 प्रतिशत रहीं

अधिक हो सकता है। प्रणाली स्तर पर औसत समूहगत अरक्षितता कुल अग्रिमों का मात्र 6.5 प्रतिशत है जिसकी तुलना में एक अकेले बैंक का उच्चत्तम समूहगत अरक्षतिता कुल अग्रिमों (चार्ट 3.34 और सारणी 3.4) का 19.1 प्रतिशत है। यह परिणाम इस बात की फिर से पुष्टि करता है कि अकेले/ समूहगत अरक्षतिता पर विनियामक/ विवेकपूर्ण मानदण्ड उच्चत्तम सीमा, बैंक पोर्टफोलियो को भलीभान्ति विविधतापूर्ण बनाता है।

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम: जोखिम काबू में रखे जा सकते हैं

3.43 प्रत्यक्ष ब्याज दर जोखिम जांचने के लिए कई तरह के परिक्षण किए गये, जो सब्याज आस्तियों और देयताओं के असंतुलन के पुनर्मूल्यन को दर्शाते हैं। परीक्षित आघातों में ब्याज दरों में कई तरह के परिवर्तन शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिफल वक्र में परिवर्तन हुआ। आघातों में (1) भारतीय राष्ट्रीय रूपये प्रतिफल वक्र में 250 बीपीएस समानान्तर उर्ध्ववर्ती बदलाव (2) 250 बीपीएस समानान्तर अधोगामी बदलाव आया (3) भारतीय राष्ट्रीय रूपये प्रतिफल वक्र: रेखकीय आधार पर होने 0 से 100 बीपीएस तक सीधी खड़ी होने तथा (4) भारतीय राष्ट्रीय रूपये प्रतिफल वक्र: रेखकीय तौर पर 250 बीपीएस से-100 बीपीएस तक उलटने का स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये परीक्षण बैंकों और कारोबारी बहियों के लिए अलग अलग किये गये।

3.44 बैंकिंग बहियों पर समग्र (निवल) प्रभाव की गणना आय हानि/ लाभ और संविभाग हानि/लाभ[13] युक्त करके की गई तथा इसके परिणाम स्वरूप निकाले गये हानि/लाभ का प्रयोग प्रभाग्रस्त सीआरएआर निकालने के लिए किया गया। परीक्षणों के लिए मूल्यांकन प्रभाव का आकलन यह मान कर किया गया कि एचटीएम पोर्टफोलियो बाज़ार के लिए चिह्नित किया गया होगा। चालू वर्ष लाभ हानि तथा आय विवरण पर प्रभाव दर्शाने के लिए सीआरएआर पर आय के प्रभाव का आकलन मात्र एक वर्ष के लिए माना जाता है। परिणाम दर्शाते हैं कि सबसे अधिक प्रभाव 250 बीपीए उर्ध्ववगामी समानान्तर भारतीय राष्ट्रीय रूपये प्रतिफल वक्र: से आया है (सारणी 3.5) कतिपय छोटे बैंकों को छोड़ कर अधिकांश बैंक, हालांकि विभिन्न परिपक्वता समूहों में विपरीत प्रभाव, जिसमें कुल हानि सन्निहित थे, से लगे आघातों का झेल पाये।

कारोबारी बहियों में ब्याज दर जोखिम: बैंक अपेक्षतया आसानी से आघात झेल पाये

3.45 परिणाम बताते हैं कि कारोबारी बहियों में प्रत्यक्ष ब्याज दर जोखिम का प्रभाव कम होगा जिससे यह प्रदर्शित होता है कि बैंक अपने ब्याज दर जोखिम अपेक्षाकृत बेहत्तर तरीके से संभालते हैं

चार्ट 3.34 ऋण संकेन्द्रण जोखिम: विभिन्न दबाव परिदृष्यों के तहत वाणिज्य बैंकों की पूंजी और अनर्जक आस्तियों पर प्रभाव: सितंबर 2011

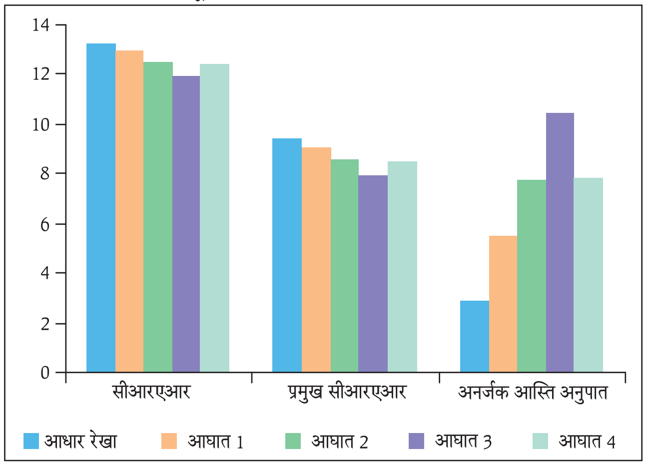

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

सारणी 3.4: ऋण केन्द्रीकरण जोखिम-दबावपूर्ण स्थितियों में वाणिज्य बैंकों का विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से नीचे रहना - सितंबर 2011

	प्रभावित बैंक (सीआरएआर 9% से कम)		प्रभावित बैंक (प्रमुख सीआरएआर 6% से कम)	
	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)
आधार रेखा:	0	0.00	0	0.00
आघात 1	1	0.01	0	0.00
आघात 2	1	0.01	3	19.70
आघात 3	1	0.01	4	20.90
आघात 4	1	0.01	3	19.70

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

सारणी 3.5: ब्याज दर जोखिम - बैंकिंग बही

	प्रणाली स्तर		प्रभावित बैंक (सीआरएआर 9% से कम)		प्रभावित बैंक (प्रमुख सीआरएआर 6% से कम)	
	सीआरएआर	प्रमुख सीआरएआर	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)
आधार रेखा:	13.27	9.39	0	0.00	0	0.00
बैंक बहियों पर निवल प्रभाव (अर्जन + पोर्टफोलियो)						
आघात 1	12.97	9.09	1	0.15	4	6.46
आघात 2	13.25	9.38	0	0.00	0	0.00
आघात 3	13.26	9.38	0	0.00	0	0.00
आघात 4	12.95	9.06	1	0.15	2	2.83
बैंक बहियों पर आय प्रभाव (अर्जन)						
आघात 1	13.27	9.39	0	0.00	0	0.00
आघात 2	13.25	9.38	0	0.00	0	0.00
आघात 3	13.27	9.39	0	0.00	0	0.00
आघात 4	13.26	9.38	0	0.00	0	0.00
बैंक बहियों पर मूल्यांकन प्रभाव (अवधि अंतराल विश्लेषण)						
आघात 1	12.85	8.97	1	0.15	4	6.46
आघात 2	13.27	9.38	0	0.00	0	0.00
आघात 3	13.26	9.38	0	0.00	0	0.00
आघात 4	13.01	9.13	1	0.15	3	4.42

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

[13] कुल (निवल) हानि/ लाभ = आय (हानि/ लाभ) + संविभाग(हानि/ लाभ)

(सारणी- 3.6)। इससे यह प्रतिबिम्बित होता है कि बैंक अपने समूह रचना में अच्छी तरह विविधता लाए हैं।

बैंकिंग प्रणाली पर विनिमय दर संचार का प्रभाव बहुत कम होगा

3.46 विदेशी मुद्रा जोखिम विनियम दर परिवर्तनों से व्युत्पन्न होता है जो वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं की स्थानीय मुद्रा मूल्य तथा तुलनपत्रेत्तर स्थितियों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। परीक्षण द्वारा बैंकों की विनिमय दर अरक्षितता, जिसके अंतर्गत सभी विनिमय दर संवेदी स्थितियां आती हैं, की जांच की जाती है। अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रूपये का 10 और 15 प्रतिशत तक अभिमूल्यन और अवमूल्यन एक पृथक आघात परिदृष्य बना देता है। आघातों के संभावित प्रभाव का आकलन बैंकों के अपने निवल खुले दुतरफा मुद्रा स्थितियों के अनुसार किया गया। दबाव परीक्षण प्रयोग के द्वारा बैंकों के निजी विदेशी मुद्रा निवल स्थितियों के आघातों का आकलन किया गया और फिर सीआरएआर के लिए संभावित हानियों में अभिव्यक्त किया गया।

3.47 दबाव परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि दबाव अन्तर्गत परिदृष्य पूरी प्रणाली के लिए तनिक सा बदल जाएगा, हालांकि यह तब भी 9 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से बढ़ जाएगा। यह हकीकत में नगण्य प्रत्यक्ष प्रभाव कई कारकों जिसमें (i) अति निम्न विदेशी मुद्रा अरक्षितता और (ii) ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही निवल अरक्षित स्थितियां शामिल हैं।

पूरी प्रणाली के लिए इक्विटी प्राईस इंडेक्स ड्रॉप का प्रभाव बहुत सीमित है

3.48 इक्विटी मूल्य जोखिम के तहत इक्विटी प्राईस इंडेक्स में गिरावट के आघात का अनर्जक आस्ति स्तर तथा बैंक पूंजी पर 40 प्रतिशत प्रभाव की जांच की गई। प्रणाली क्रमागत सीआरएआर आधार रेखा से मात्र 0.7 प्रतिशत बिन्दु घटेगा, जबकि बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के काफी ऊपर रहेगा। बैंकों के पूंजी बाज़ार अरक्षितता पर निर्धारित विनियामक सीमा पर विचार करके देखा जाए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकों के पास आम तौर निम्न पूंजी बाज़ार अरक्षितता रखते हैं।

सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों का तरलता जोखिम कम करने में भारी प्रभाव है

3.49 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के समय कई वित्तीय प्रणालियों में संवेदनशीलता विश्लेषण के नकदी जोखिम- जोखिम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, शामिल किया गया। विश्लेषण में यह माना गया कि तरल आस्तियां खुले बाज़ार में संपार्श्विकता के आधार पर की गई बाज़ार मूल्य के 10 प्रतिशत कटौती के साथ बेची गई जो हाल के वर्षों में अनुभवजन्य निष्कर्षों जैसे हैं। दबाव परीक्षण दो परिदृष्य उपस्थित करते है: पहले परिदृष्य के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियां प्रणालीगत जमाराशि आहरण करते समय सांविधिक

सारिणा 3.6 ब्याज दर जोखिम - कारोबार बही (संशोधित अवधि दृष्टिकोण)

	प्रणाली स्तर		प्रभावित बैंक (सीआरएआर 9% से कम)		प्रभावित बैंक (सीआरएआर 6% से कम)	
	सीआरएआर	प्रमुख सीआरएआर	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)	बैंकों की संख्या	समग्र आस्तियों में हिस्सा (%)
आधार रेखा:	13.27	9.39	0	0.00	0	0.00
आघात 1	11.91	8.02	7	5.25	7	5.25
आघात 2	13.11	9.23	3	2.08	1	0.17
आघात 3	12.86	8.98	5	2.80	5	2.80
आघात 4	12.03	8.14	7	5.25	7	5.25

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

चलनिधि अनुपात अपेक्षा घटाने पर उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि दूसरे परिदृष्य के अनुसार मात्र अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात ही चलनिधि हैं।

3.50 भारत में सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियां रखना एक अलग विशेषता है। इसके प्रभाव को प्रगृहीत करने के लिए चलायमानता जोखिम विश्लेषण चलनिधि आस्तियों के दो परिभाषाओं के साथ किया गया है। पहली परिभाषा के अनुसार चलनिधि आस्तियों के अंतर्गत नकदी, अतिरिक्त आरक्षित नकदी अनुपात, सभी अंतर्बैंक जमाराशियां और सभी सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश आते हैं; जिसके अनुसार बेसलाईन सिनारियो के अधीन 24.7 प्रतिशत चलनिधि अनुपात बनता है। जबकि चलनिधि आस्ति की दूसरी परिभाषा में नकदी, अतिरिक्त आरक्षित नकदी अनुपात, एक महीने में परिपक्व होने वाले सभी अंतर्बैंक जमाराशियां और एक महीने में परिपक्व होने वाले सभी सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश माने जाते हैं और बेसलाईन सिनारियो के अधीन नकदी आस्ति अनुपात 7.7 प्रतिशत निकाला जाता है। ये परिदृष्य दबाव की स्थिति में केवल अपनी नकदी आस्तियों के स्टॉक का प्रयोग करते हुए जमाराशि पलायन की राशियां पूरी करने के लिए बैंकों की क्षमता आंकने के लिए बनाये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नकदी अंतराल बढ़ जाते हैं तथा नकदी अनुपात कम हो जाते हैं। दबाव परिदृष्य के तहत नकदी स्थिति (सारणी- 3.7 चार्ट- 3.35) में ह्रास दिखाई देता है। विश्लेषण से यह प्रतिबिम्बित होता है कि गंभीर दबाव परिदृष्य में एसएलआर निवेश बैंकों को नकदी दाब को आसानी से झेलने में सहायता दे सकते हैं।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

अनर्जक आस्तियों में 50 प्रतिशत वृद्धि होने पर भी सामना करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं

3.51 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), जो शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, पर जून 2011 के अंत में उनके आस्ति संविभाग का प्रयोग करते हुए ऋण जोखिमों पर दबाव परीक्षण किया गया। परिणाम एकल अवयव संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित हैं। सीआरएआर पर आघातों के प्रभाव का परीक्षण तीन पृथक परिदृष्यों के तहत किया गया, जिसके अनुसार (i) अनर्जक आस्ति अनुपात में 50 प्रतिशत, (ii) अनर्जक आस्ति अनुपात में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है और (iii) बैंको ने कोई लाभ अर्जित नहीं कमाया है। यह पाया गया कि परिदृष्य 1 और 3 के अधीन माने गये आघातों का सामना आसानी से कर सकता है। पर, परिदृष्य (ii) (चार्ट 3.36) के अधीन इस क्षेत्र को कुछ दबाव झेलना पड़ सकता है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

समग्र अनर्जक आस्तियों में पाँच गुना वृद्धि का सामना कर पाए

3.52 एनबीएफसी-एनडी-एसआई मार्च 2011 के अंत की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार दो परिदृष्यों अर्थात (i) समग्र अनर्जक आस्तियों

सारणी 3.7: दबावग्रस्त परिदृष्य में बैंकों की नकदी स्थिति पर प्रभाव- चलनिधि आस्ति परिभाषा-1, : सितंबर 2011

	चलनिधि आस्ति अनुपात (प्रतिशत)
आधार रेखा :	24.69
आघात 1: 30 दिनों में कुल जमा का 10 प्रतिशत आहरण	17.05
आघात 2: 5 दिन तक प्रतिदिन 3 प्रतिशत जमा -आहरण	13.92

चलनिधि आस्ति परिभाषा 1- नकद, अतिरिक्त सीआरआर, अंत:बैंक जमा, एसएलआर निवेश

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ स्टाफ गणना

चार्ट 3.35: दबावग्रस्त परिदृष्य में बैंकों की नकदी स्थिति - बैंकों के घाटे की समस्या - चलनिधि आस्ति परिभाषा-2: सितंबर 2011

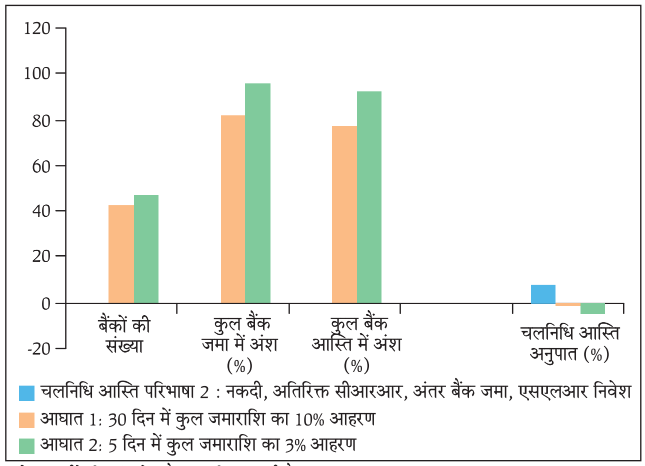

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 3.36: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक दबाव परीक्षण - जून, 2011 में पूंजी स्थिति पर आघातों का प्रभाव

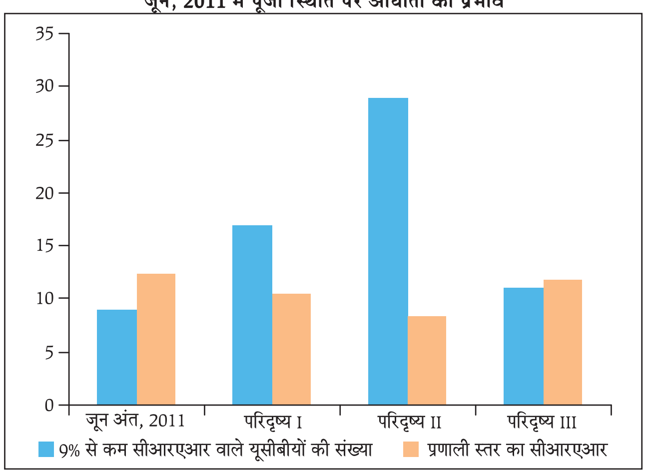

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

में दोगुनी वृद्धि और (ii) समग्र अनर्जक आस्तियों में दोगुनी वृद्धि के तहत के लिए ऋण जोखिमों पर दबाव परीक्षण किया गया। अनर्जक आस्तियों में वृद्धि को खराब, संदेहास्पद और हानि में रहने वाली श्रेणियों में उसी अनुपात में विभाजित किया गया है, जो अनर्जक आस्तियों के प्रचलित स्टॉक में मौजूद थे। अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं वर्तमान पूंजीं स्थिति से समायोजित किये गये।

3.53 संवेदनशीलता विश्लेषण के परीक्षण यह लक्षित करते हैं कि एनबीएफसी क्षेत्र पर्याप्त घोर ऋण जोखिम आघात सहन कर सकते हैं। दोनो परिदृष्यों में यह पाया गया कि प्रावधानीकरण में कमी थी। हालांकि सीआरएआर पर प्रभाव नगण्य था, क्योंकि इस क्षेत्र के पास विनियामक अपेक्षाओं के 15 प्रतिशत की तुलना में 35.1 प्रतिशत का उच्चतर सीआरएआर था।

निष्कर्ष

3.54 यूरो अंचल में मची उथल-पुथल ने यूरोपीय बैंकों द्वारा विशेष सुविधाओं को हटा लिए जाने की आशंकाओं को हवा दी। यद्यपि संकटग्रस्त इस क्षेत्र में अपने मामूली एक्सपोज़र के कारण भारतीय बैंकों से कोई प्रत्यक्ष प्रभाव अपेक्षित नहीं है तथापि निधियन के कारण परोक्ष प्रभाव देखे जा सकते हैं।

3.55 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र तथा संकेतक ने बैंकिंग क्षेत्र में भेद्यता और मज़बूती, लाभप्रदता तथा आस्ति कोटि जोखिमों में भारी वृद्धि के कारण स्थिरता को खतरे को उजागर किया है।

3.56 ऋणों में मार्च 2011 के अंत की स्थिति में 22.6 प्रतिशत की जो मज़बूत स्थिति थी वह सितंबर 2011 के अंत की स्थिति में घट कर 19.2 प्रतिशत रह गई। यह ऋण वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की 16 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बाबजूद प्राप्त की गई। सीआरएआर में गिरावट जारी रही और यह मार्च 2010 के 14.05 प्रतिशत से गिर कर सितंबर 2011 में 13.5 प्रतिशत पर आ गया, यद्यपि विनियामक न्यूनतम स्तर से यह काफी ऊपर ही रहा। भारत का 2.8 प्रतिशत वर्तमान सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मोटे तौर पर इसके बराबर देशों को औसत के बराबर ही रहा, किंतु सितंबर 2011 की अनर्जक आस्तियों की 30.5 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा 92.8 प्रतिशत की गिरावट ने 19.2 प्रतिशत की ऋण वृद्धि को भारी अन्तर से पीछे छोड़ दिया। अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के पीछे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, भूसंपत्ति बुनियादि क्षेत्र और खुदरा क्षेत्र का हाथ महत्वपूर्ण रहा। बैंकों की लाभप्रदता दबाव में आ गई क्योंकि बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण ब्याज पर होने वाले व्यय ब्याज से होने वाली आय से अधिक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एनआईआई और ईबीपीटी की गति धीमी हो गई।

3.57 ऊर्जा एवं दूर संचार का क्षेत्र मिला-जुला हिस्सा बुनियादि क्षेत्र ऋण का 77 प्रतिशत रहा और इसमें क्षति तथा रिस्ट्रक्चरिंग में वृद्धि देखी गई। ऊर्जा क्षेत्र के अग्रिम प्राय: ऊर्जा उत्पादन और राज्य विद्युत बोर्डों पर ही केन्द्रित होने से जोखिम इसलिए बहुत अधिक रहा क्योंकि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय अवस्था जर्जर थी और अधिकांश ऊर्जा परियोजनाएं कोयला आपूर्ति /बिलंब बहुत सी परियोजनाओं को ठप्प कर रहे थे।

3.58 उच्च ब्याज दरों के वातावरण की पृष्ठभूमि में और धीमे होते ऋण चक्र तथा सुस्त होती अर्थव्यवस्था, बिगड़ती आस्ति स्तर बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौती बन कर उभरेंगे। यह अपेक्षा है कि अनवरत उच्च ब्याज दरों और आस्तियों के ऋण कोटी में गिरावट के लिए अधिक प्रावधान के कारण लाभों पर दबाव से बैंकों की आधार रेखा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है।

3.59 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तरह शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को भी आस्तियों की कोटी पर पड़ने वाले भार को झेलना पडा। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के ऋण संवितरण में अल्पकालीन ऋण-संरचना की प्रधानता देखी गई। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मध्य आपसी संबंध काफी सुदृढ़ पाया गया क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने संसाधनों के लिए बैंकों ऋणों पर उल्लेखनीय रूप से आश्रित थीं।

3.60 पेन्शन निधियां, औने-पौने दामों पर की जा रही बिक्री का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतिरोधक की भूमिका अदा करके वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है तथा वे उन कंपनियों, जहां वे निवेश करते हैं, में कॉरपोरेट गवर्नेन्स में सर्वोत्तम प्रथाएं प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कतिपय अनर्जक आस्तियों के स्वरूप, जिनमें निवेशक को परिसमापन की स्वतंत्रता है, के मोचन दबाव में यकायक रुकावट प्रतिभूति बाज़ार की चाल को बेढंगा कर सकता है। भारतीय बीमा क्षेत्र अच्छी तरह पूंजीकृत है, क्योंकि इसकी ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित न्यूनतम विनियमों से काफी अधिक है। हालांकि बैंकिंग प्रणाली के साथ इसकी अंतर्संबद्धता चिन्ता का विषय बनी हुई है तथा और निगरानी किए जाने का आह्वान करता है।

3.61 दबाव परीक्षण क्रिया ने बैंकिंग प्रणाली की प्रतिरोध क्षमता को आंकने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान किया है। एकल कारक संवेदनशीलता गणना यह प्रस्तावित करते हैं कि प्रणाली जोखिम विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट कभी-कभार लगने वाले आघातों के सहने में सक्षम होगी और ब्याज-दर जोखिमों, विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होंगे। नकदी दबाव परीक्षण परिणाम यह दर्शाते हैं कि सांविधिक चलनिधि निवेशों ने बैंकों को पर्याप्त भारी जमाराशि खपत का सामना करने के योग्य बनाया। अनुसूचित शहरी बैंकों और एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर ऋण जोखिम दबाव परीक्षण ने यह उजागर किया कि विभिन्न परिदृष्यों के अंतर्गत सीआरएआर पर प्रभाव स्तब्धकारी नहीं होंगे।

अध्याय IV
वित्तीय क्षेत्र का विनियमन और बुनियादी सुविधाएं

वैश्विक स्तर पर दूसरे बैंकों की तुलना में भारतीय बैंकों की स्थिति मजबूत होते हुए भी वे बासल III को अपनाएंगे। इसके बावजूद नए मानकों के कारण बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लेंडिंग स्प्रेड में समायोजन करना होगा जिसका असर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर पड़ सकता है। यदि बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) के लिए किए गए निवेशों की गणना चलनिधि अनुपात के रूप में नहीं की जाती है तो भारतीय बैंकों को चलनिधि के नए मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अत: कुछ और भी करना जरूरी है। बासल II के उन्नत मानदंडों को अपनाने की प्रगति अब तक बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही है। किसी भी भारतीय बैंक के वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था (SIFI) के रूप में उभरने की संभावना नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय नीतियों में सुधार पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है क्योंकि प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) की मॉनीटरिंग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपने देश के महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) के लिए भी अपनाई जाती है। वित्तीय स्थिरता और विकास काउंसिल (FSDC) और इसकी उप समितियां वित्तीय प्रणाली में विद्यमान विनियामक कमियों को कम करने की दिशा में प्रयासरत हैं। बैंकों के डूबने से निपटने के लिए देश में समाधान निकालने की पद्धति को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। भुगतान और निपटान प्रणाली के पूर्णतया स्वस्थ रहने के बावजूद दिनभर (इंट्राडे) की चलनिधि की प्रवृति को मॉनीटर किया जाना जरूरी है। ओटीसी डेरिवेटिव्स बाजार में वैश्विक गतिविधियों के मद्देनजर डेटा संग्रह करना और बाजार को मॉनीटर करने के लिए विधिक निकाय अभिज्ञापक की स्थापना करना आवश्यक है। सीसीपी तक एक्सेस के लिए विभिन्न एक्सेस कंफिगरेशन उभर कर सामने आ रहे हैं। भारत में एक्सेस सामान्यत: डायरेक्ट ही होती है, भले ही नामित निपटान बैंकों द्वारा संकेंद्रण जोखिम की बात उठाई जाती हो। ओटीसी डेरिवेटिव्स में 'गलत राह अपनाने की जोखिम' ('Wrong way risks') से सावधानीपूर्वक निपटने और प्रणालीगत जोखिम और भुगतान प्रणाली में आपस की निर्भरता के संज्ञान के लिए सीसीआईएल की स्ट्रेस टेस्टिंग को अद्यतन करते रहने की जरूरत है।

विनियामक बुनियादी सुविधा

4.1 कमजोर विनियामक व्यवस्था और प्रभावहीन निगरानी को वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक जोखिम पैदा करने के कारकों में से माना जाता है जिसके कारण अंतत: वैश्विक वित्तीय संकट सामने आया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणालीगत जोखिम पर कराए गए पहले सर्वेक्षण में भी वित्तीय व्यवस्था के लिए 'विनियामक जोखिम' को महत्त्वपूर्ण जोखिमों में से एक पाया गया (अध्याय V)। संकट के बाद अंतरराष्ट्रीय नीति तैयार करने वालों ने संकट से मिले सबक को पूरा करने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए। इस रिपोर्ट के पिछले अंकों में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

भारत में बैंक बासल III की ओर तुलनात्मक रूप से अपनी मजबूत स्थिति के होते हुए भी आगे बढ़ेंगे ....

4.2 वैश्विक बैंक पूंजी और चलनिधि के मानकों में सुधारों को अंतिम रूप देने के साथ ही इन सुधारात्मक उपायों के सुविधाजनक ढंग से कार्यान्वयन पर जोर दिया जाने लगा है। जैसा कि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में चर्चा की गई है भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक भले ही मजबूत स्थिति में हैं, बासल III की ओर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। भारत में वाणिज्य बैंकों ने 31 मार्च 2009 को बासल II को अपना लिया था और उन्नत मानदंडों को अपनाने की तैयारी जारी है। भारतीय बैंकों की चलनिधि की स्थिति अच्छी है और उनका लीवरेज औसत बासल III के अधीन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है। भारतीय बैंकों का जटिल तुलनपत्रेतर स्थिति के प्रति एक्सपोज़र बहुत ही कम हैं और प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र से बचने के लिए उनमें विनियामक सुरक्षा उपाय अंतर्निहित हैं। साथ ही, बैंक अपना कारोबार मजबूत पूंजी आधार (भारतीय बैंकों का टियर 1 पूंजी 9 प्रतिशत है) के साथ शुरू करते हैं। अत: भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में बहुत अधिक संरचनात्मक बदलाव की जरूरत नहीं है लेकिन अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है।

.... लेकिन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है

4.3 प्राथमिक आकलन से पता चलता है कि बासल III के कार्यान्वयन के बाद बैंकों को अतिरिक्त पूंजी के लिए पर्याप्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन अतिरिक्त आवश्यकता का संक्षिप्त आकलन किया जाना अब तक बाकी है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आई एफ आर एस) को अपनाने के बाद 01 अप्रैल 2013 से बैंकों को अपने प्रारंभिक तुलन पत्र में पेंशन और ग्रैच्युटी संबंधी देयताओं के अपरिशोधित अंश को समायोजित

करना होगा। इसके अलावा बैंक ऋण और सकल घरेलू उत्पाद में आपसी संबंध, वित्तीय समावेशन की मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अधिक ऋण लेने वाले क्षेत्रों के कारण पूंजीगत जरूरतें और अधिक बढ़ने की संभावना है।

4.4 बासल III के कार्यान्वयन के कारण घरेलू बैंकों की अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं की वास्तविक मात्रा न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के स्तर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासल III के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा पर निर्भर करेगी जिसका विकल्प अभी भी विचाराधीन है (जैसा कि इस अध्याय के पैराग्राफ 4.12 और 4.13 में चर्चा की गई है)। हालांकि बैंकों के पास उपलब्ध शेयर पूंजी के वर्तमान स्तर; जीडीपी वृद्धि के अनुमान; मध्यम अवधि में बैंकों की अर्जक क्षमता; बासल III के अधीन निर्धारित विभिन्न विनियामक समायोजन/कटौती का असर; बाजार जोखिम के लिए व्यापार बही में अतिरिक्त पूंजी प्रभार का असर और दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम जैसे कारकों का असर निश्चित रूप से पड़ेगा।

उच्च पूंजी आवश्यकताओं के कारण बैंकों के लिए पूंजी की लागत बढ़ेगी और उनके लेंडिंग स्प्रेड का दायरा भी....

4.5 किसी भी स्थिति में उच्च पूंजी आवश्यकताओं के कारण बैंकों के लिए पूंजी लागत बढ़ेगी जिसके कारण लेंडिंग स्प्रेड भी बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। विकसित देशों में बासल III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दरों में अंतर बढ़ने से घरेलू बैंकों के विदेशी फंडिंग पर निर्भर होने की स्थिति में भारतीय बैंकों की पूंजी लागत पर असर पड़ सकता है।

.... वृद्धि पर थोड़े असर के साथ

4.6 बासल III को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरंभिक चिंता वित्तीय सेवाओं की लागत और उपलब्धता को लेकर है। बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न (BCBS) द्वारा कार्यान्वयन की बढ़ाई गई समय-सीमा से ऋण की आपूर्ति पर होने वाले दबाव का जोखिम कम होगा।

4.7 भारत में बैंकों के लेंडिंग स्प्रेड पर उच्च पूंजी आवश्यकता के कारण पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक अध्ययन[1] से पता चलता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात[2] में 100 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि करने से बैंकिंग उद्योग के लेंडिंग स्प्रेड में औसतन लगभग 10 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि होगी। इन आकलनों को आंतरिक रूप से विकसित विभिन्न मैक्रो मॉडल्स में शामिल करने पर जीडीपी की वृद्धि दर में मामूली गिरावट दिखती है। हालांकि यदि बैंकों को अतिरिक्त पूंजी बढ़ानी पड़े (बासल III के कार्यान्वयन के कारण या उच्चतर ऋण वृद्धि में सहायता के लिए) तो लेंडिंग पर इसका प्रभाव आनुपातिक रूप से अधिक पड़ेगा जबकि वृद्धि दर इसके परिणमस्वरूप कम हो जाएगा। बासल III के कार्यान्वयन के बाद जीडीपी पर पड़ने वाले प्रभाव को संकट की संभावना कम होने के कारण दीर्घकालिक आउटपुट से संतुलित किया जा सकता है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं में चूक की संभावना कम होने का अप्रत्यक्ष रूप से अच्छा प्रभाव भारत जैसे देशों की उभरती अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

लेंडिंग स्प्रेड पर प्रभाव निर्भर करेगा पूंजी के आरंभिक स्तर पर

4.8 लेंडिंग स्प्रेड में वृद्धि विभिन्न बैंकों के लिए अलग-अलग होती है जिसके प्रभाव का मूल्यांकन करने पर यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सबसे अधिक पाया गया (चार्ट 4.1)। पुनश्च, लेंडिंग स्प्रेड में वास्तविक वृद्धि और बासल III के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जीडीपी पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंकों की पूंजी पर्याप्तता का आरंभिक स्तर क्या है जो विभिन्न बैंकों में महत्त्वपूर्ण रूप से अलग-अलग है।

बासल III के तहत चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय बैंकों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हानि हो सकती है ...

4.9 भारतीय बैंक भले ही खुदरा कारोबार मॉडल का अनुसरण करते हैं और अल्पावधि/एक दिवसीय थोक फंडिंग पर ज्यादा निर्भर नहीं करते लेकिन उनके लिए बासल III के तहत चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। वर्तमान सांविधिक चलनिधि आवश्यकताओं के बदले रखी गई प्रतिभूतियों को यदि

[1] यह विश्लेषण 'मैक्रोइकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ बासल III' में प्रयुक्त तरीके पर आधारित है। इस विश्लेषण का आधार वाक्य है कि- बैंकों को ब्याज के रूप में और गैर-ब्याज आमदनी के रूप में होने वाली कुल आमदनी कुल ब्याज और गैर-ब्याज व्यय तथा पूंजी लागत के बराबर होती है। पूंजी लागत सामान्य रूप से जमाराशि की लागत और अन्य बाहरी देयताओं से अधिक होती है। इस बात को मानते हुए कि अन्य बातें समान रहेंगी, पूंजी में वृद्धि के फलस्वरूप बैंक के लिए लागत बढ़ेगी और इसे ऋण देने की दर में बदलाव करके ही ठीक किया जा सकता है क्योंकि अन्य सभी आस्तियों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। विश्लेषण के लिए 54 बैंकों को शामिल किया गया जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की 95% से अधिक आस्तियों का प्रतिनिधित्व था।

[2] उपर्युक्त विश्लेषण बासल III के कारण पूंजी पर्याप्तता में अतिरिक्त 100 बेसिस प्वाइंट की प्रभावी वृद्धि मानकर किया गया है जबकि भारतीय बैंकों की वर्तमान टियर I पूंजी है और इस पूंजी का अधिकतर हिस्सा कोर शेयर के रूप में है। पूंजी की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाना बाकी है और यह कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई समय-सीमा पर निर्भर करेगी और अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग होगी।

चार्ट 4.1: पूंजीगत आवश्यकताओं में कुछ प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि से लेंडिंग स्प्रेड पर प्रभाव

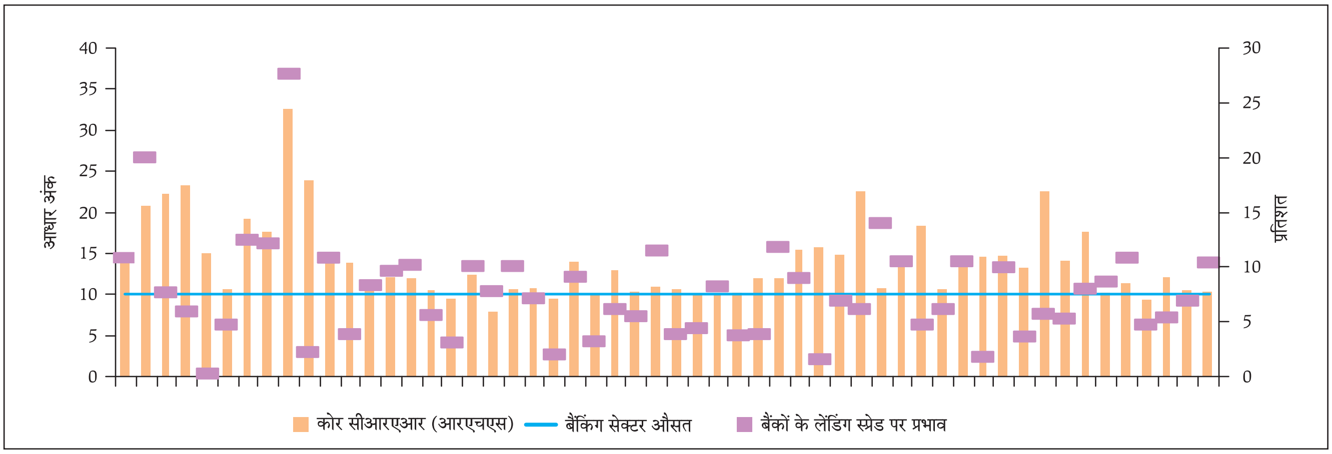

स्रोत: भारि बैंक स्टाफ गणना

चलनिधि अनुपात के रूप में नहीं माना जाता है तो हो सकता है कई भारतीय बैंक 100 चलनिधि कवरेज अनुपात (LCR) की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाएं। उच्च स्तर पर चलनिधि आस्ति रखने के लिए कहने से भारतीय बैंक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से घाटे में रहेंगे और इस बात पर अंतिम निर्णय लिया जाना जरूरी है कि किस हद तक एसएलआर प्रतिभूतियों को चलनिधि आस्ति रखने की बासल III आवश्यकताओं के रूप में माना जाए।

... बचत बैंक ब्याज दर को नियंत्रण मुक्त कर और छोटी बचत योजनाओं में अधिक ब्याज देने पर भारी मात्रा में खुदरा जमाराशि जुटाने में कठिनाई आएगी

4.10 इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एसएलआर प्रतिभूतियों को किस रूप में लेखांकित किया जाएगा, बासल III की अपेक्षाएं थोक फंडिंग पर रन ऑफ दरें लागू करती हैं, जो खुदरा जमा राशियों से काफी अधिक होता है जो ब्याज दरों में परिवर्तन और आंके गए ऋण जोखिम के प्रति थोक निधीयन की उच्च संवेदनशीलता संकल्पना को दर्शाता है। यह बैंकों को ज्यादा स्थायी खुदरा जमा राशि निधीयन के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि हाल की घटनाएं जैसे - बचत खातों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त करने (जो ब्याज दरों के प्रति खुदरा जमा की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है), डाकघर और अन्य सार्वजनिक जमा योजनाओं पर ब्याज बढ़ाने से पूरे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए अधिक मात्रा में खुदरा जमा राशि जुटाना मुश्किल होगा। बैंकिंग संस्थाओं के लिए दीर्घ अवधि का कर्ज जारी करने जैसे अन्य स्रोतों से फंडिंग कर चलनिधि की स्थिति अच्छी की जा सकती है लेकिन यह खुदरा जमा राशियों की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है।

चलनिधि के दबाव की परिस्थिति के लिए डेटा की आवश्यकताओं की भी अपनी अलग चुनौती होगी ...

4.11 चलनिधि मानकों के कार्यान्वयन में भारतीय बैंकों के लिए जो अन्य मुख्य चुनौती है वह है संबंधित डेटा सही-सही और सटीक ढंग से जुटाना और तार्किक सत्यता के साथ और उनकी अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए चलनिधि के दबाव की परिस्थिति का पूर्वानुमान करना, जैसा कि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चर्चा की गई है। चूंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारतीय वित्तीय बाजार ने दबाव के स्तर का अनुभव नहीं किया है इसलिए दबाव की स्थिति का सटीक ढंग से पूर्वानुमान लगाना एक जटिल काम होगा भले ही चलनिधि कवरेज अनुपात में माने गए दबाव स्तर को आधारिक स्तर की परिस्थिति माना जा सकता है।

शीघ्र ही बासल III के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ...

4.12 देश में बासल III नुस्खों के कार्यान्वयन का काम प्रगति पर है जिसमें चलनिधि संबंधी दिशा-निर्देश भी शामिल हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक चर्चा के लिए कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुक्रम और समय-सीमा के साथ शीघ्र ही संबंधित दिशा-निर्देश जारी करेगा। बासल कमेटी ने नई आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए 2018 तक की बढ़ाई गई समय-सीमा तय की है जिससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर सहयोग मिल सके।

... कार्यान्वयन के समय और तरीके पर निर्णय की जरूरत

4.13 इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण सवाल बासल III में के नुस्खों को कार्यान्वित करने से संबंधित है जैसे कि क्या भारत में त्वरित

कार्यान्वयन को पसंद किया जाएगा या नहीं और क्या वर्तमान में जारी अधिक कठोर पूंजी आवश्यकताओं को बनाए रखा जाएगा (वर्तमान में भारतीय बैंकों जोखिम भारित आस्ति अनुपात 9 प्रतिशत बनाए रखना जरूरी होता है जबकि बासल कमेटी ने इसके लिए 8 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया है)। कई देशों ने (जैसे कि यू.के और स्वीट्जरलैंड) ने बासल III के दिशा-निर्देशों को त्वरित / अधिक कठोर ढंग से कार्यान्वित करने की घोषणा की है। कुछ देशों में विनियामक संस्थाओं ने (उदाहरण के लिए स्वीडेन) ने भी कुछ इसी तरह के इरादे दिखाए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये मामले इस जरूरत पर आधारित होंगे कि इन मानकों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें तेजी से और इस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है कि ये वित्तीय प्रणाली और व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

बासल II के तहत उन्नत मानदंड: बड़े बैंकों को इन्हें अपनाना वांछनीय है ...

4.14 बासल II के तहत उन्नत मानदंडों को अपनाने के संबंध में बैंकों के लिए समय-सारणी की घोषणा कर दी गई है।[3] स्थिरता के दृष्टिकोण से बैंकों का माइग्रेशन आवश्यक है, खासकर उन बड़े बैंकों का जिसके पास अच्छी आस्ति है और जिनकी मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। उन्नत मानदंडों को अपनाने के बाद बैंक जोखिम के से बचने के लिए उन्नत उपाय करने और प्रबंध प्रणाली को अपना सकते हैं जो कि बैंक के कारोबार की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और किसी खास बैंक के जोखिम प्रोफाइल को ठीक करने के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी आवश्यकता से जुड़े हुए हैं जिससे वित्तीय संस्थाएं लचीलापन ला सकती हैं। साथ ही, उन्नत मानदंडों को न अपनाने से बड़े बैंकों की छवि पर भी असर पड़ सकता है।

... कुछ मुद्दों और परेशानियों के बावजूद

4.15 कार्यान्वयन का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है बैंकों का रुख बहुत उत्साहजनक नहीं है। इसके कारणों का पता करना कठिन नहीं हैं। सबसे पहले, उन्नत मानदंड मानकीकृत मानदंडों की तुलना में अधिक जटिल हैं (चार्ट 4.2)। इससे विकसित देशों की तुलना में भारतीय बैंकों को एकजुट होने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भारतीय बैंकों के लिए मात्रात्मक तकनीक की संकल्पना नई है जो कि बासल II के उन्नत मानदंडों का आधार है। इसलिए उन्हें बासल II के तहत पूंजी पर्याप्तता के लिए नई मात्रात्मक तकनीक के प्रति सहज होने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होगी और बैंकों को अपनी संस्था के अंदर कौशल विकसित करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे।

भारत में भविष्य को ध्यान में रखकर प्रावधान करने पड़ सकते हैं...

4.16 वित्तीय संकट के बाद पूंजी और प्रोविज़निंग आवश्यकताओं की प्रो-साइक्लीकलिटी पर समुचित ध्यान दिया गया गया है। परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काउंटर साइक्लिकल पूंजी और प्रोविज़निंग बफर लाने पर विचार किया जा रहा है। भारत में इंवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (IFR) की शुरूआत की गई है ताकि वित्तीय संकट के काफी पहले ही ब्याज दर में उतार-चढ़ाव को ठीक किया जा सके। स्पेन जैसे कुछ देश डायनामिक प्रोविज़निंग नियम लेकर आए हैं (बॉक्स 4.1)। निश्चित रूप से इन मानदंडों से अच्छे समय में प्रोविज़न तैयार करना सुनिश्चित होगा जिसका उपयोग बुरे वक्त में किया जा सकेगा और बैंक कम लाभप्रदता के बावजूद ऋण देने में सक्षम होंगे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम के लिए भविष्य को देखते हुए प्रोविज़निंग को अपनाना भारत में भी जरूरी है।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) के लिए नीतियों में प्रस्तावित सुधार लाए गए हैं ...

4.17 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) के लिए हाल के दिनों में नीतिगत पहल में नीतिगत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक (जी-एसआईबी) (बॉक्स 4.2)

चार्ट 4.2: बासल II के तहत उन्नत मानदंडों का ढांचा

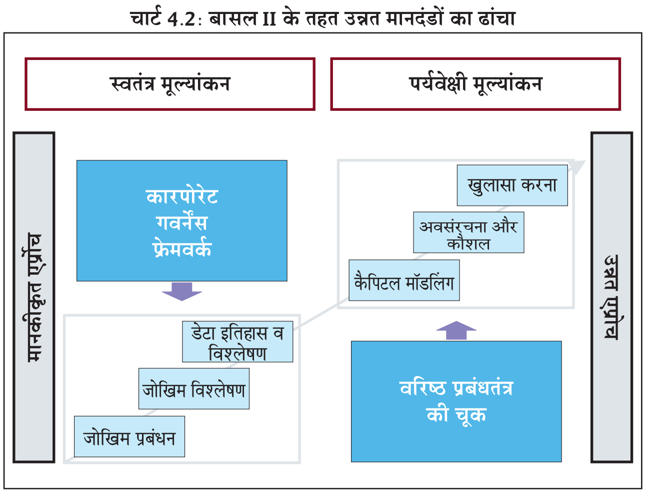

[3] वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मार्च 2010 के बॉक्स 6.1 में समय-सारणी तय की गई है। (http://rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=586#CH6)

बॉक्स 4.1: डाइनैमिक प्रावधानीकरण

ऐतिहासिक लागत-लेखाविधि के तहत तुलन-पत्र की तारीख को चिह्नित की गई हानियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि अनुभव यह रहा है कि कुछ अग्रिमों, जिनकी तुलन-पत्र की तारीख को वसूली का आसार वास्तव में कम है, को कतिपय तकनीकी कारणों से आगे कुछ समय तक अनर्जक माना जाता है। ऐसे अग्रिम जिनकी पहचान भविष्य में अनर्जक रूप से की जाती है, के लिए सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए। बैंक लोन से जुड़ी हानियों और आय का आकलन करने की मौजूदा पद्धति का एक वैकल्पिक एप्रोच है- 'डाइनैमिक प्रावधानीकरण'। डायनैमिक प्रावधानीकरण का आधार किसी भी क्रेडिट पोर्टफोलियो से जुड़ी हानियों की सांख्यिकी संभाव्यता से जुड़ा है और इसलिए लोन मंजूरी के समय ही इसके लिए व्यवस्था कर ली जाती है भले ही यह बाद में घटित हो या न हो। डाइनैमिक प्रावधानीकरण का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक लेखांकन समयावधि में बकाया लोन के लिए प्रावधान किए जाते हैं जो लम्बे समय में होनेवाली हानियों के आकलन को ध्यान में रखकर किया जाता है। सामान्य रूप से मौजूदा एप्रोच की तुलना में इस आधार पर प्रावधानीकरण कम स्तर पर करना होगा, लेकिन मजबूत आर्थिक गतिविधियों के चलते अचानक आए तेज उतार-चढ़ाव का कुछ नहीं किया जा सकता। बैंक के लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र पर लोन से जुड़ी हानियां वर्तमान की तुलना में आगे और अधिक सहज रूप से असर डालेगी क्योंकि डाइनैमिक प्रावधानीकरण में वास्तविक हानियों से कहीं अधिक सम्भावित हानियों को प्रमुखता दी जाती है।

स्पैनिश डाइनैमिक प्रावधानीकरण विधि, जिसे सांख्यिकी प्रावधानीकरण के रूप में भी जाना जाता है, में दो प्रकार के प्रावधानों की व्यवस्था है- सामान्य और विशेष। सामान्य प्रावधान के दो स्थिरांक है: α और β. डाइनैमिक प्रावधानीकरण मॉडल का रूप होता है: सामान्य प्रावधान$_t = \alpha^* \Delta C_t + \beta^* C_t - \Delta$ विशेष प्रावधान

जहां C_t लोन का स्टाक है, α पूरे चक्र में प्रत्येक इकाई के अप्रकट या स्वाभाविक हानियों को कवर करता है, β लम्बे समय के लिए अनुमानित अवधि के दौरान विशेष प्रावधानीकरण दर का औसत है। दोनों ही स्थिरांक ऋण हानि के ऐतिहासिक डेटा पर आधारित हैं। मजबूत ऋण वृद्धि और विशेष प्रावधानीकरण के निम्न स्तर के दौरान बीटा घटक धनात्मक होता है क्योंकि यह उठाई गई हानियों की बढ़ोत्तरी को रेखांकित करता है और मंदी के समय ये हानियां तुरंत विशेष हानियों के रूप में तब्दील हो जाती हैं और बीटा घटक ऋणात्मक हो जाता है। यद्यपि देखने में डाइनैमिक प्रावधानीकरण की प्रकृति पिछड़ी लगती है लेकिन यह पारदर्शी नियमों पर आधारित एप्रोच है जो प्रति-चक्रीय टूल के रूप में काम कर सकता है।

संदर्भ:

(क)डाइनैमिक प्रोविज़निंग- द एक्सप्रिएंस ऑफ स्पैन-जेसस साउरिना

(ख) टर्नर रिव्यू- ए रेगुलेटरी रेस्पॉंस टू द ग्लोवल बैंकिंग क्राइसिस, एफएसए

(ग) डाइनैमिक प्रोविज़निंग- इसूज़ एण्ड एप्लिकेसंस-फिओना मन एण्ड इयान माइकेल

(घ) द स्पैनिश एप्रोच - डाइनैमिक प्रोविज़निंग एंड अदर टूल्स, सांटिआगो फेरनांडेज़ दि लिस एंड अलिसिया गारसिया हेरेरो

व्यवस्थित समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल किया जाना

4.18 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए जोखिमों से निपटने के लिए नीतिगत उपायों में प्रमुख है कि राष्ट्रीय समाधान पद्धति (National Resolution regimes) में निरंतर सुधार लाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय प्रणाली में भारी छेड़छाड़ किए बिना और राजकोषीय बोझ डाले बिना किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा उठाए गए जोखिमों का निपटान किया जा सके। इसके लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने *प्रभावी समाधान पद्धतियों की प्रमुख विशेषताओं (key Attributes of Effective Resolution Regimes)* के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का एक सेट बनाया है जिसका उद्देश्य कानूनी फ्रेमवर्क और टूल्स में पाई जानेवाली खाई को पाटना है ताकि असफल हो रहे प्रणालीगत फर्मों, जिसमें बहु अधिकार-क्षेत्र में कार्य कर रही फर्में भी शामिल हैं, में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटान से संबंधित वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों के तहत पाई जाने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

कार्यान्वियन के लिए वैधानिक बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है

4.19 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के सरल समाधान के घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई अधिकार-क्षेत्रों में वैधानिक बदलाव की जरूरत है। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में जितना सहयोग आज है उससे भी कहीं अधिक सहयोग की जरूरत आगे बड़े पैमाने पर होगी ताकि एक अर्थक्षम और विश्वसनीय जी-एसआईएफआई समाधान योजना बनाई जा सके। उन्हें अपने पर्यवेक्षकों के संसाधनों तथा अधिदेशों को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है ताकि पर्यवेक्षकों को अपना कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता हो और वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्रियता से जोखिम की पहचान कर उसका निवारण कर सकें।

वित्तीय समूहों (एफसी) की निगरानी के लिए फ्रेमवर्क तैयार है

4.20 भारतीय संदर्भ में देखें तो वित्तीय समूहों (एफसी) की निगरानी के लिए सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क मौजूद है। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों (दिसम्बर 2010 और जून 2011 के अंकों) में फ्रेमवर्क के संबंध में चर्चा की गई थी और साथ ही इसे और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास भी किए गए थे। वितीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति, जिसके अधिदेश के अंतर्गत एफसी की निगरानी शामिल है, भी इन प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रिया को और अधिक सही ढंग से लागू करने पर विचार-विमर्श कर रहा है।

बैंक समाधान के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रावधान 'प्रमुख विशेषताओं' का पालन नहीं कर सकते हैं

4.21 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के भाग III और भाग III ए में घरेलू बैंकों से संबंधित जोखिमों के निपटान के लिए वैधानिक आधार दिया गया है जो बैंकिंग करोबार रोकने और बैंकिंग कम्पनी के समापन संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराता है। साथ ही,

बॉक्स 4.2: प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक (जी-एसआईबी) के लिए प्रस्तावित नीतिगत सुधार

वित्तीय स्थिरता बोर्ड और बासल समिति ने प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं से जुड़े संकटों के समाधान और उनके प्रभावों[4] को कम करने के लिए प्रस्तावों का एक सेट तय किया है। नीतिगत उपायों में निम्न शामिल है:

- असफल हो रही वित्तीय फर्मों का समाधान क्रमिक ढंग से और करदाताओं को नुकसान के जोखिम से दूर रखते हुए प्राधिकारियों की शक्तियों को मजूबत करने के लिए राष्ट्रीय समाधान पद्धति में सुधार लाने के लिए संदर्भ तौर पर नया राष्ट्रीय मानक अपनाना।
- समाधान योग्य आकलनों की जरूरतें, वसूली और समाधान योग्यताएं तथा प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक (जी-एसआइबी) के लिए संस्था विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करार
- जी-एसआईबी के लिए बासल III में उल्लिखित न्यूनतम क्षमता के अलावा अतिरिक्त हानियों को सहने के लिए क्षमता की अपेक्षाएं और
- मजबूत पर्यवेक्षी अधिदेशों के द्वारा और अधिक गहन और प्रभावी पर्यवेक्षीण तथा जोखिम प्रबंधन कार्यों, जोखिम डेटा समेकन क्षमताएं, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के लिए उच्च पर्यवेक्षी अपेक्षाएं वांछित हैं।

बासल समिति ने जी-एसआईबी की पहचान करने तथा हानियों को सहने की क्षमता बढ़ाकर संकट और असफलता की सम्भावना को कम करने के लिए तैयार की गई विवेकपूर्ण सुरक्षा-तंत्र संबंधी एक कार्य-प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। चुने गए संकेतकों से बैंक का आकार, उनकी परस्पर संबद्धता, एक दूसरे की जगह लेने की क्षमता (अर्थात उनके द्वारा उपलब्ध सेवाओं के मामले में आसानी से एक दूसरे की जगह ले लेने की क्षमता का होना या न होना), उनकी वैश्विक (अंतर्राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र) गतिविधि और इससे जुड़ी जटिलता आदि का पता चलता है। शुरू में इस कार्य-विधि को 73 बैंकों में प्रयोग किया गया और आरम्भिक तौर पर 29 बैंकों की पहचान प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक के रूप में की गई (एफएसबी द्वारा सूची प्रकाशित हो चुकी है) साथ ही, जी-एसआईएफआई की सूची प्रत्येक वर्ष नवम्बर महीने में अद्यतन की जाती है।

इन मानदंडों के अनुसार पहचान किए गए जी-एसआईबी को आगे चार वर्गों में बांटा जाएगा। इन पर पूंजी अधिभार लगाया जाएगा जो जो प्रथम वर्ग के लिए 01 प्रतिशत तथा चतुर्थ वर्ग के लिए 2.5 की रेंज में होगा। प्रणालीगत रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण बनने की स्थिति को रोकने और इस हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए 3.5 प्रतिशत के अधिभार के साथ एक पांचवे बकेट, जो वर्तमान में खाली है, की परिकल्पना भी की गई। बैंकों के वर्गीकरण में पर्यवेक्षी प्राधिकारियों का निर्णय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सिर्फ विशेष मामलों में ही इस प्रकार का निर्णय संकेतक आधारित एप्रोच की जगह ले सकता है।

अतिरिक्त हानि सहने की अपेक्षाएं सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी से ही पूरी की जाए। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे पर्यवेक्षीकों के विवेकाधिकारों से वैश्विक स्तर पर स्थापित उपर्युक्त योजना के तहत आकस्मिक पूंजी साधनों का इस्तेमाल किसी राष्ट्रीय स्तर पर हुई हानियों को सहने के लिए किया जा सकता है।

अधिभार पर बनाई गई नीति जनवरी 2019 से लागू होगी और 2016 से इस ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह नीति उन बैंकों पर लागू होगी जिन्हें नवम्बर 2014 में जी-एसआईएफआई के रूप में पहचाना जाएगा। परंतु समाधान संबंधी अपेक्षाएं प्रारम्भिक 29 बैंकों के सेट पर लागू की जाएगी और 2012 के अंत तक ये अपेक्षाएं पूरा कर ली जाएंगी।

इसमें समापन कार्यवाहियों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। हालांकि ये प्रावधान उपर्युक्त 'प्रमुख विशेषताओं' की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते।

4.22 इस संबंध में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) की भूमिका भी प्रासंगिक है जो सिर्फ 'भुगतान बॉक्स' प्रणाली के रूप में जमाकर्ताओं के दावों के भुगतान तक के सीमित अधिदेश के साथ कार्य करता है और बैंक समाधान का कोई अधिदेश प्राप्त नहीं है।

4.23 वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार कमीशन (FSLRC)को इन मुद्दों का समाधान ढूंढना चाहिए क्योंकि यह पूरे वित्तीय क्षेत्र के विधि निर्माण की समीक्षा करता है।

कोई भी भारतीय बैंक प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक (G-SIB) नहीं हैं... लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही नीतिगत पहलों पर नजर रखना आवश्यक है

4.24 निकट भविष्य में किसी भी भारतीय बैंक को प्रणालीगत रूप से विशेष महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक (जी-एसआईबी) के रूप में वर्गीकृत करने की सम्भावना नहीं है। लेकिन घरेलू नीति निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे नीतिगत बदलाव के अनुरूप चलने की जरूरत है क्योंकि प्रणालीगत रूप से विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक (एसआईबी) के साथ-साथ गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं यथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बीमा कम्पनियों के लिए एक नीतिगत कार्यप्रणाली विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ कनवरजेंश होना न कि अनुकूलन, भारत के लिए बेहतर मार्ग

4.25 सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) की ओर बढ़ने की तारीख जैसे-जैसे (यथा 01 अप्रैल 2013) नज़दीक आ रही है, बैंकों को इसके कार्यान्वयन से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से संकल्पना पर आधारित कुछ मतभेदों और साथ ही कारोबार से जुड़ी असमानताओं के परिणामस्वरूप भारत को कनवरजेंश मार्ग पर चलना पड़ा बजाए इसके कि वह 'अनुकूलन' का मार्ग पकड़ता।

अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक बोर्ड (आईएएसबी) और वित्तीय लेखाविधि मानक बोर्ड (एफएएसबी) के बीच संकल्पना आधारित मतभेदों के जारी रहने के बावजूद वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 9 (आईएफआरएस 9) एक चल लक्ष्य है

4.26 अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा वित्तीय साधनों से संबंधित लेखाविधि मानकों के संबंध में आईएएस 39 की जगह नया

[4] प्रस्ताव में 4 नवम्बर 2011 को जारी किए गए परामर्श पत्रों की सीरिज़ शामिल है। (http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_111104cc.pdf)

मानक आईएफआरएस 9 लाने का प्रस्ताव है जो वित्तीय क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आईएएस 39 को विस्थापित करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है जिसके साथ-साथ आईएफआरएस 9 के बेमेल प्रावधानों और सुरक्षित लेखाविधि संबंधी अपेक्षाओं को अंतिम रूप भी देना है। इसके चलते कन्वर्जन्स प्रक्रिया ऐसे बन गई है जैसे तेजी से बढ़ रहे लक्ष्य के पीछे यह दौड़ लगा रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के निर्धारण के लिए बने दो प्रमुख संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक बोर्ड (आईएएसबी) जो आईएफआरएस तैयार करता है तथा अमेरीका का वित्तीय लेखाविधि मानक बोर्ड (एफएएसबी) अभी तक वित्तीय लिखतों के लिए मानक तैयार करने के संबंध में कोई साझा एप्रोच विकसित करने में विशेष प्रगति नहीं कर पाई है। भारत में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और आकलन से संबंधित मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों और आईएफआरएस के बीच कई मतभेद हैं। आईएफआरएस नीति आधारित एप्रोच, जिसे वर्तमान में अपनाया जा रहा है, की तुलना में बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे कारोबार मॉडल पर अधिक ध्यान दे रहा है। यह बैंकों के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर रही है क्योंकि प्रबंधन को मानक में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ ही, लेन-देन में उचित प्रथाओं, भारत में जिनके संबंध में बाजार आधारित प्रथाओं या बेंचमाक्र से संबंधित पर्याप्त दिशानिर्देशों का अभाव है, की अपनी कठिनाइयां हैं। बैंकों को भी कुछ क्षेत्रों, यथा वित्तीय देयताओं के आकलन और उनकी पहचान, समेकन और अमान्यीकरण तथा दस्तावेजों के प्रकटन आदि के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बैंकों को आईटी सिस्टम के साथ-साथ एमआईएस को भी बदलने की जरूरत है ताकि आईएफआरएस की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

4.27 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी ओर से स्थिति के आकलन, दक्षता विकास को बढ़ावा देने, लाभार्थियों को शामिल करने और प्रगति की निगरानी के लिए कई उपाय शुरू कर दिए हैं। एक कार्य-दल का गठन किया गया है जो आईएफआरएस से जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों का समाधान करेगा और बदली हुई परिस्थिति में आईएफआरएस की ओर आसानी से बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

एफएसडीसी उप-समिति का एफएसडीसी के प्रमुख ऑपरेटिंग हथियार के रूप में बनकर उभरना

4.28 स्थापना के एक साल बाद एफएसडीसी और इसकी उप-समिति की कार्यप्रणाली धीरे-धीरे अपना आकार ले चुकी है। एफएसडीसी की उप-समिति परिषद के प्रमुख ऑपरेटिंग हथियार के रूप में उभरा है जबकि परिषद व्यापक पर्यवेक्षी की भूमिका निभा रहा है।

4.29 एफएसडीसी अपने प्रारम्भ होने से अबतक तीन बार बैठक आयोजित कर चुका है और अपनी प्रत्येक बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़ी स्थितियों के संबंध में चर्चा कर चुका है। इसने कॉर्पोरेट बांड मार्केट को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया है और इन्फ्रस्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ताकि बुनियादी क्षेत्र को निधि मुहैया कराई जा सके। प्रत्येक तिमाही में उप-समिति की एक बैठक आयोजित की जानी है और मार्च 2011 में आयोजित पहली बैठक से अब तक पांच बार बैठक आयोजित की जा चुकी है। उप-समिति ने परिषद के अधिकार-क्षेत्र में आनेवाली सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की। (चार्ट 4.3)

4.30 उप-समिति ने आईडीएफ गठित करने संबंधी आवश्यक कार्यप्रणाली की रूपरेखा पर चर्चा की- म्यूचूअल फंड या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में आईडीएफ की स्थापना करने संबंधी आदेश क्रमश: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं जबकि रिज़र्व बैंक ने आईडीएफ के प्रायोजक बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को भी आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया है। उप-समिति ने सरकार द्वारा प्रायोजित एनबीएफसी के क्रियाकलापों से प्रणाली के लिए उत्पन्न जोखिमों के बारे में चर्चा की और धन प्रबंध सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति एफसी की निगरानी से संबंधित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रहा है और ठोस संकट प्रबंध प्रणाली ला रही है।

4.31 उप-समिति के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकलापों के अंतर-विनियामक समन्वयन के लिए कार्यविधि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो तकनीकी दलों का गठन किया गया है। (चार्ट 4.4)

चार्ट 4.3: एफएसडीसी का कार्यक्षेत्र

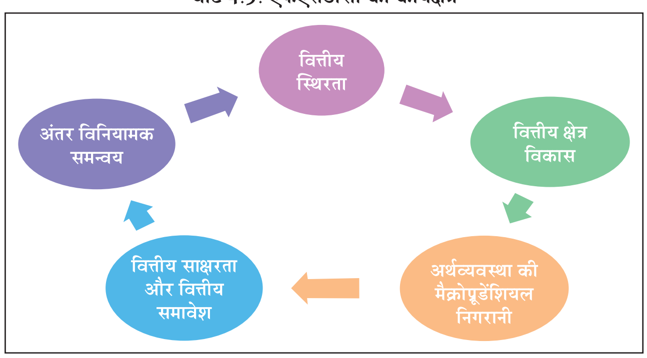

चार्ट 4.4 : एफएसडीसी उप-समिति का तकनीकी दल

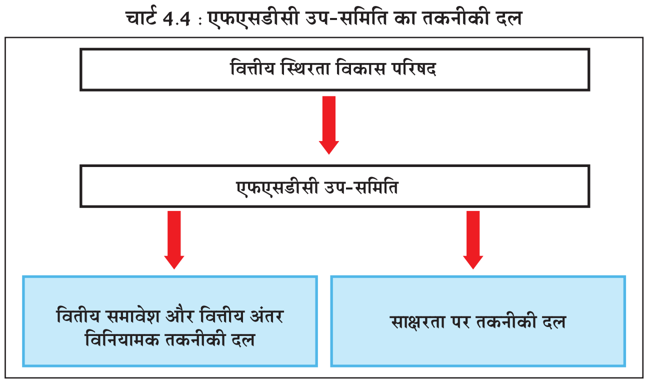

आर्थिक संकट के बाद बनाए गए नीतिगत उपायों में मैक्रोप्रूडेंशियल अपरिहार्य है

4.32 दिसम्बर 2010 की एफएसआर रिपोर्ट में वित्तीय नीति/विनियामक पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं के आकलन के लिए मैक्रोप्रूडेंशियल संबंधी नीतिगत पहलुओं के महत्व को रेखांकित किया गया जो व्यक्तिगत संस्थाओं की संकल्पना की तुलना में प्रणालीगत संकल्पना पर अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीत है।

4.33 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष प्रस्तुत किए गए वर्किंग-पेपर[5] जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विश्लेषण किया गया था, में इस अवधि के दौरान संस्थाओं और बाजार से जुड़े प्रणालीगत जोखिम को कम करने के क्षेत्र में मैक्रोप्रूडेंशियल की प्रभाविता की समीक्षा की गई। विश्लेषण से यह बात उभर कर आई कि इसके लिए सबसे अधिक उपयोग में लाए जा रहे लिखतों में से कई लिखत जोखिमों की पुनरावृत्ति को रोकने में प्रभावी हैं और यह वित्तीय क्षेत्र में अचानक आए संकट को रोकने के प्रतिसंवेदनशील है। हालांकि पेपर यह में यह भी स्वीकार किया गया है कि मैक्रोप्रूडेंशियल लिखतों के उपयोग में लागत भी जुड़ी है और साथ ही धीमी वृद्धि भी शामिल है। मैक्रोप्रूडेंशियल नीति को इन लागतों को सामने रखकर विचार करने की जरूरत है।

भारत मैक्रोप्रूडेंशियल लिखतों के उपयोग में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुका है

4.34 भारत के संदर्भ में देखें तो मैक्रोप्रूडेंशियल लिखतों का अधिक उपयोग विशेष रूप से पिछले एक दशक से किया जा रहा है। मैक्रोप्रूडेंशियल के नीतिगत लिखतों का उपयोग विशेष रूप से संकट-पूर्व स्थिति तथा संकट के समय पूर्व से अधिक सक्रियता से सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिसमें प्रोविज़निंग और जोखिम भारिता से जुड़ी स्थितियां भी शामिल हैं। (चार्ट 4.5 से 4.7)

धन प्रबंध सेवाओं के मौजूदा विनियमन की कमियों को दूर करने की जरूरत है

4.35 पिछली एफएसआर रिपोर्ट में धन प्रबंधन सेवाओं (डब्ल्यूएमएस) से जुड़े मौजूदा विनियमन की पुन: समीक्षा पर जोर दिया गया था। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे धन प्रबंध सेवाओं के संबंध में एक सर्वे किया था। सर्वे का उद्देश्य इस संबंध में बाजार से जुड़ी प्रथाओं की जांच करना, जोखिम की पहचान करना और विनियमन संबंधी कमी, यदि हो, का पता लगाना था।

4.36 वैश्विक रूप से अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और सर्वे से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है ताकि धन प्रबंध सेवाओं के लिए बेहतर विनियमन संबंधी रूपरेखा तैयार की जा सके। इसमें इन सेवाओं को उपलब्ध

चार्ट 4.5: प्रतिचक्रीय प्रूडेंशियल विनियम-वाणिज्यिक स्थावर संपदा

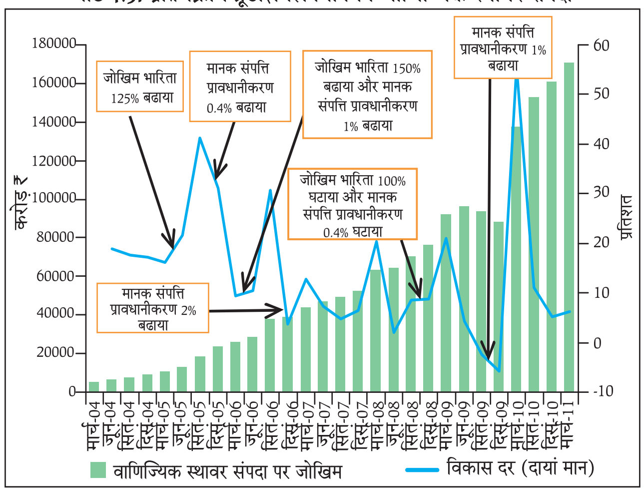

स्रोत: भारिबैंक पर्यवेक्षी आंकडे

चार्ट 4.6: प्रतिचक्रीय प्रूडेंशियल विनियम-खुदरा आवासीय ऋण

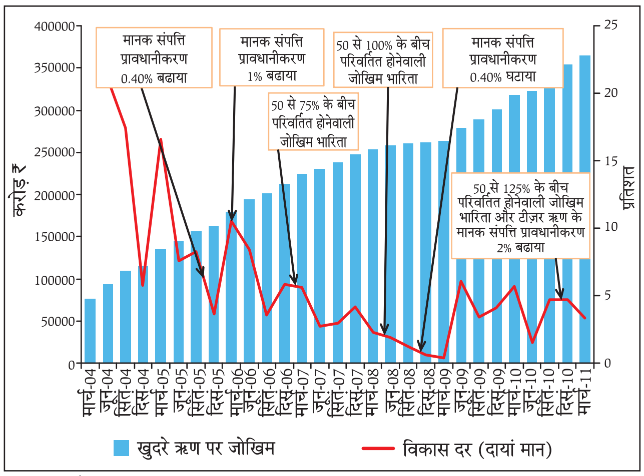

स्रोत: भारिबैंक पर्यवेक्षी आंकडे

चार्ट 4.7: प्रतिचक्रीय प्रूडेंशियल विनियम-पूंजी बाज़ार

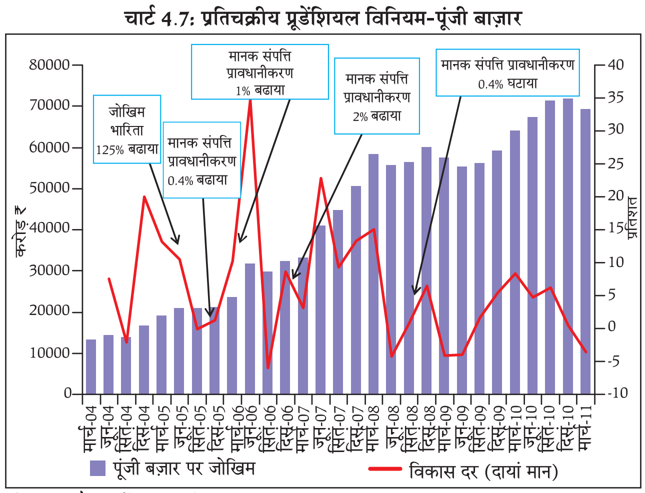

स्रोत: भारिबैंक पर्यवेक्षी आंकडे

[5] समष्टि विवेकसम्मत नीति: "वाट इंस्ट्रूमेंट एंड हाऊ टू यूज देम ? लेसन्स फ्रॉम कंट्री एक्सपिरियन्स"। सी लिम, एफ. कोलंबा, ए कोस्टा, पी. कोंगसामुट, ए. ओटानी, एम. सैयद, टी. वेजल और एक्स. वू. अक्तूबर 2011.

कराने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रोफेशनल योग्यताएं और समय-समय पर प्रशिक्षण तथा दक्षता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन, सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों तथा संस्था के लिए आचरण संहिता, उत्पाद अनुमोदन से संबंधित नीतिगत/प्रक्रिया संबंधी कागजात का दस्तावेज़ीकरण, ग्राहक से संबंधित जोखिम प्रोफाइलिंग और उत्पाद की उपयुक्तता, आंतरिक प्रणालियों को मजबूत करना तथा नियत्रंण, बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल हैं। साथ ही, एफएसडीसी की उप-समिति और इसके अंतर विनियामक तकनीकी दल इन मुद्दों की जांच कर रही है।

...और वित्तीय उत्पादों के वितरण में हितों के टकराव को दूर किए जाने की आवश्यकता है

4.37 वित्तीय उत्पादों के वितरण में होने वाले हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए डब्ल्यूएमएस फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के टकराव वित्तीय उत्पादों के प्रवर्तकों (उदाहरण के लिए बैंक, म्युचूअल फंड, बीमा कंपनियों आदि) और इन उत्पादों को बेचने वाले वितरकों (उदाहरण के लिए एजेंट, वित्तीय सलाहकार, वित्तीय योजनाकार आदि) के बीच में पैदा होते हैं। ये टकराव इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि वितरक एक साथ निवेशक और प्रवर्तक दोनों के ही एजेंट के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हैं। ये टकराव इस कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं कि वितरक अलग-अलग प्रवर्तकों के एक जैसे उत्पादों की मार्केटिंग कर रहा हो। ऐसी स्थिति में वितरक का किसी एक उत्पाद के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने और किसी ऐसे उत्पाद को अधिक बेचने की संभावना होती है जिसका प्रवर्तक उसे अधिक भुगतान करता है। जबकि इस प्रकार के टकराव किसी भी बाजार में हो सकते हैं लेकिन वित्तीय उत्पादों के मामले में इनका होना अधिक गंभीरता का विषय है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि एक तो वित्तीय उत्पाद अमूर्त होते हैं और दूसरा इनकी संकल्पना को समझना कठिन होता है और इनमें किए गए निवेश पर प्राप्त होनी वाली आय निकट भविष्य में प्राप्त नहीं होती। भारत में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता के निम्न स्तर को देखते हुए यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है।

आभासी बैंकिंग का भारत में स्वत: ही अस्तित्व नहीं है.....

4.38 जैसा कि पिछली एफएसआर में चर्चा की गई है, जिस तरह की आभासी बैंकिंग (बॉक्स 4.3) पश्चिम में समझी जाती है वैसी आभासी बैंकिंग का भारत में अस्तित्व नहीं है। एनबीएफसी, जिन्हें आभासी बैंकिंग से थोड़ा-बहुत मिलता-जुलता माना जाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में आती हैं। एनबीएफसी के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट वित्त कंपनियां जैसे चिट फंड, निधि कंपनियां, म्युचुअल फंड और सूक्ष्म वित्त कंपनियों को मोटे तौर पर भारत में आभासी बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा माना जा सकता है (चार्ट 4.8)।

..फिर भी ऐसे कुछ विनियामक अंतराल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

4.39 एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। फिर भी ऐसे कुछ विनियामक अंतराल हैं जिनके कारण विनियामक आर्बिट्राश की संभावना बनी रहती है। ऐसे कुछ अंतरालों के बारे में पिछली एफएसआर में प्रकाश डाला गया है और इन विनियामक अंतरालों को समाप्त करने के बारे में प्रयास जारी हैं। ये प्रयास इस तरह से किए जा रहे हैं कि ये एनबीएफसी की विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप सुसंगत हों और साथ ही ये जोखिमों से निपटने और आर्बिट्राश के अवसरों को कम करने के लिए उपयुक्त विवेकसम्मत विनियामकों की शुरुआत करें।

4.40 एनबीएफसी क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं के बारे में गठित कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इन मुद्दों के पहलुओं पर भी विचार किया है। सिफारिशों की जांच की जा रही है।

चार्ट 4.8: भारतीय वित्तीय प्रणाली के खंड

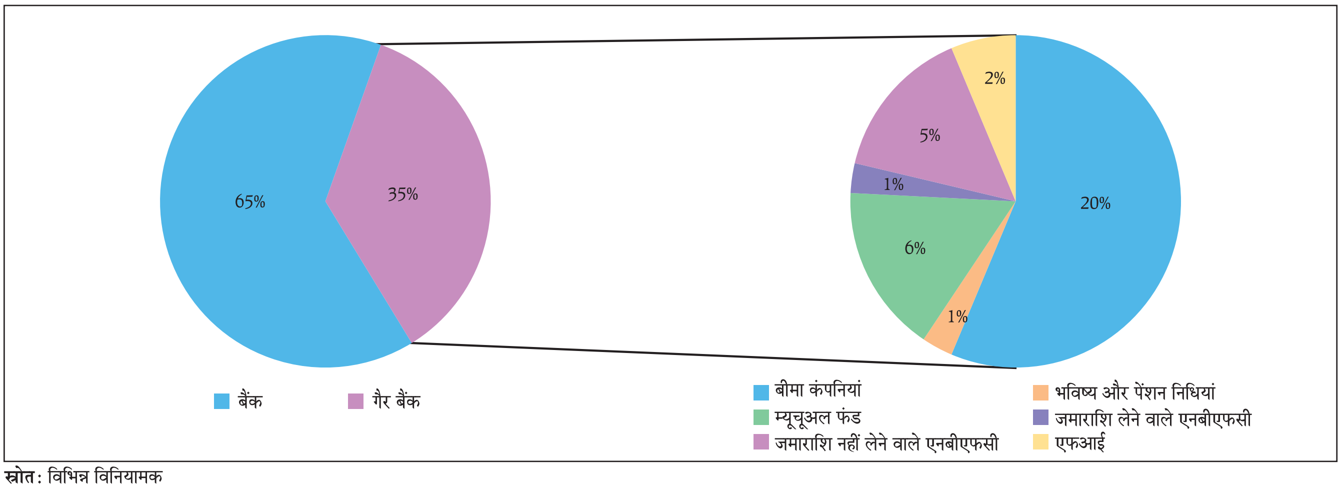

स्रोत: विभिन्न विनियामक

बॉक्स 4.3: आभासी बैंकिंग

एफएसबी आभासी बैंकिंग को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है- यह एक ऐसी क्रेडिट मध्यस्थता है जिसमें नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर की गतिविधियां और संस्थाएं शामिल होती हैं। आभासी बैंक जमा राशि जैसी देयताओं के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं (उदाहरण के लिए घर, कार्पोरेट, वित्तीय संस्थान) से धन जुटाते हैं जो कि कम अवधि के लिए होती हैं। उसके बाद इन निधियों का प्रयोग विभिन्न संपत्तियों जैसे मार्टगेज, ऑटो ऋण और अन्य दीर्घावधि संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है जो की निश्चित रूप से कम अर्थसुलभ होती हैं। बैंक भी यही कार्य करते हैं लेकिन दोनों में एकमात्र फर्क यही है कि आभासी बैंक गैर-जमा देयताओं का जबकि बैंक मूलरूप से जमा देयताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि बैंकों द्वारा उपयोग में लाई गई जमा देयताएं भी आभासी बैंकों द्वारा प्रयोग में लाई गई गैर जमा देयताओं की तरह ही लघु अवधि की और अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती हैं।

कई आभासी बैंकों को अत्यधिक लिवरेज्ड भी पाया गया है। अत्यधिक लीवरेज के साथ ही यह परिपक्वता/चल निधि अंतरण इन्हें बैंकों जैसे जोखिमों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है। ऐसी लघु अवधि जमा राशि जैसी लिखतों को प्रणाली से निकाल लिया जाए तो इस कारण से अप्रत्यक्ष प्रणालीगत परिणाम हो सकते हैं। इन चिंताओं के अतिरिक्त नियमित बैंकों के साथ आभासी बैंकों की अंतरसंबंधता से भी प्रणालीगत चिंताएं बढ़ जाती हैं। आभासी बैंकों में निर्मित लीवरेज प्रचक्रीयता के मुद्दों को भी बढ़ा सकती है। अकसर ऐसा भी मामला होता है कि हालांकि आभासी बैंक बैंकों की तरह ही कार्य करते हैं लेकिन ये बैंकों पर लगाए जाने वाले विनियामक दायरों से बाहर होते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली विनियामक आर्बिट्राश बैंकों को भी कमजोर कर सकती है और इससे पूरी प्रणाली में लीवरेज और जोखिम की भारी मात्रा निर्मित हो सकती है। आर्थिक संकट से पूर्व की अवधि में बहुत से बैंकों ने अपनी जोखिम भरी गतिविधियों को साधनों या संरचनाओं में निवेश किया जो कि उनके साथ समेकित नहीं थी। लेकिन जब बैंकों में निधि की कमी हुई तो उन्हें इन जोखिमों को अपने तुलन पत्रों में दर्शाना पड़ा। बैंकों को केंद्रीय बैंकों से अंतिम उधारदाता/छूट विंडो के रूप में विनियामक/सरकारी सहायता गांरटी, निक्षेप बीमा सुविधाएं आदि प्राप्त होती हैं। आभासी बैंकों को ऐसी किसी प्रकार की चल निधि सहायता उपलब्ध नहीं होती। वैसे तो ये विनियामक सहायता प्रणाली के दायरे से बाहर होते हैं जिसके कारण इनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और संकट के समय या फिर उस समय जब इनमें से किसी को ऋण चुकाने जैसे मुद्दों का सामना करने की शुरुआत होती है तो प्रणालीगत जोखिमों में इनका योगदान बढ़ सकता है।

आभासी बैंक की परिभाषा के अनुरूप आने वाली कुछ संस्थाओं/गतिविधियों के उदाहरण हैं- वित्त कंपनियां, आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी)वाहक, सीमित उद्देश्य की वित्त कंपनियां, प्रतिभूतिकृत साधन- स्ट्रक्चरड निवेश साधन, प्रतिभूति फर्म (ब्रोकर-डीलर्स), निवेश फर्म, मार्टगेज बीमा कंपनियां, अन्य क्रेडिट बीमा कंपनियां, क्रेडिट हेज फंड, मनी मार्किट म्यूच्यूल फंड, प्रतिभूतियों के उधारकर्ता और सरकार द्वारा प्रायोजित कई एन्टरप्राइजिस आदि।

भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान और निपटान इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य निष्पादकता सुदृढ़ बनी रही

4.41 जून 2011 में पिछली एफएसआर रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद की अवधि में देश में भुगतान और निपटान प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी रूकावट के कार्य करता रहा (चार्ट 4.9 और 4.10)।

डीआर अभ्यासों की श्रृंखला के दौरान कई असुरक्षितताएं सामने आईं, जिन्हें दूर किया जा रहा है

4.42 पिछली एफएसआर के बाद की अवधि के दौरान आपदा समाधान अभ्यासों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। केंद्रीय प्रणालियों और/या सदस्यों की डीआर साइटों से कई अभ्यास किए गए। इन डीआर अभ्यासों ने प्रचालनात्मक असफलताओं के प्रति प्रणाली की गतिशीलता को मुख्य रूप से प्रमाणित किया। हालांकि इसमें कई असुरक्षितताएं देखी गई जैसे कि कुछ सदस्यों की डीआर साइटों का प्रचालित नहीं होना, बैंथविड्थ के संबंध में अवरोध, केंद्रीय साइट के साथ जुड़ने के बारे में कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे आदि। इन असुरक्षितताओं को दूर किया जा रहा है।

भुगतान प्रणालियों के एक्सेस के लिए मानदंड का प्रणालियों के जोखिमों पर प्रभाव होगा

4.43 भुगतान और निपटान प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक्सेस मानदंड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये मानदंड विशेषरूप से अधिक मूल्य की भुगतान प्रणालियों में महत्वपूर्ण हैं

चार्ट 4.9: मूल्य में प्रवृत्तियां

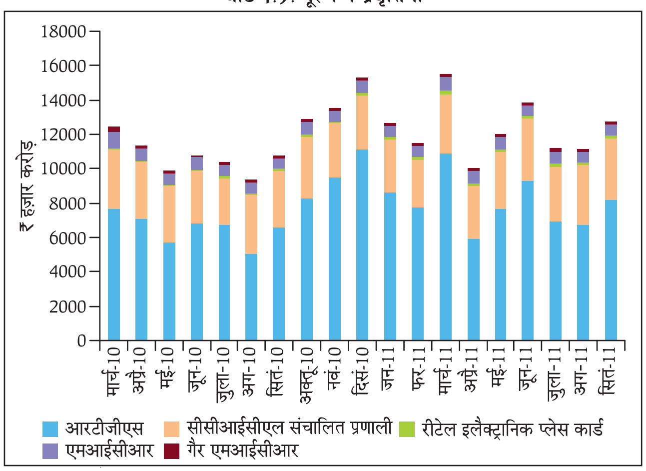

चार्ट 4.10: मात्रा में प्रवृत्तियां

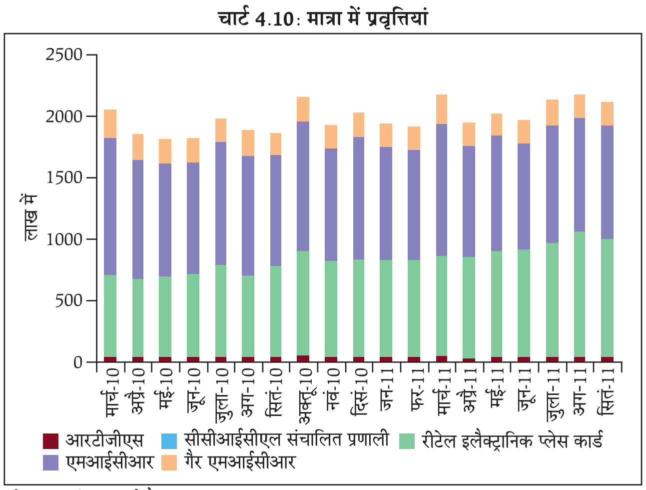

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

जहां कमजोर प्रतिभागी प्रणालीगत जोखिमों के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। ये मानंदड भुगतान प्रणाली में स्तरों (टियरिंग) की डिग्री का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अंतरराष्ट्रीय रूप से अधिक मूल्य वाली भुगतान प्रणालियों में एक्सेस के पैटर्न प्रणाली दर प्रणाली अलग-अलग हैं। जिनमें एक ओर स्पेक्ट्रम में अत्यधिक उच्च स्तर और बहुत ही कम प्रत्यक्ष सदस्य वाली प्रणालियों (उदाहरण के लिए यूके में सीएचएपीएस) से लेकर दूसरी ओर बिल्कुल शून्य स्तर वाली प्रणालियां हैं (उदाहरण के लिए हांगकांग की आरटीजीएस प्रणाली)। अत्यधिक स्तरीय भुगतान प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि केवल कम जोखिम वाले प्रतिभागी ही प्रणाली के प्रत्यक्ष सदस्य बनें। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष प्रतिभागी ही अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों के अनेक भुगतानों को अपनी बहियों में पूरा करते हैं (जहां कहीं इस तरह की प्रणालियां विद्यमान हैं वहां पर इन्हें 'अर्ध प्रणाली' कहा जाता है)। इसके परिणामस्वरूप जोखिम में वृद्धि हो सकती है क्योंकि किसी ग्राहक या दूसरे स्तर के बैंक में प्रचालन फेल हो जाने से प्रथम स्तर या कोरस्पोंडेंट बैंक का प्रचालन बाधित हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत परिणाम हो सकते हैं विशेषकर तब जब कि कोरेस्पोंडेट बैंक या समग्र प्रणाली की तुलना में ग्राहक बहुत बड़े आकार के हों।

एक्सेस मानदंड को हाल ही में संशोधित किया गया है जिससे व्यापक प्रत्यक्ष एक्सेस संभव हुआ है

4.44 भारत के संदर्भ में देखें तो देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए काफी अच्छी तरह से परिभाषित एक्सेस मानदंड उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में एक्सेस के लिए ये मानदंड अपेक्षाकृत अधिक कड़ें है विशेषकर अधिक मूल्य वाली प्रणालियों के लिए। सभी भुगतान प्रणालियों के एक्सेस मानदंडों को हाल ही में संशोधित किया गया है। इससे व्यापक एक्सेस संभव हो पाया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिभागियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम अधिक न बढ़ें। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों ही भुगतान प्रणालियों के लिए संशोधित एक्सेस मानदंड हैं - (क) न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत; (ख) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल एनपीए अनुपात 5 प्रतिशत से कम और (ग) संबंधित विनियामक विभाग की सिफारिश। केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए अतिरिक्त मानदंड रु.25 करोड़ की न्यूनतम निवल मालियत है। संशोधित एक्सेस मानदंड विशेषरूप से अधिक बैंकों खासतौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को अखिल भारतीय केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों जैसे तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड अंतरण (एनईएफटी) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) प्रणालियों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।

आरटीजीएस प्रणाली का नेटवर्क अपेक्षाकृत स्थिर है...

4.45 वर्ष के दौरान अलग-अलग दिनांकों पर आरटीजीएस प्रणाली के नेटवर्क का विश्लेषण (चार्ट 4.11) दो अलग-अलग दिनांकों पर निरूपण को दर्शाता है) अंतर बैंक एक्पोजर[6] की तुलना में आरटीजीएस प्रणाली में नेटवर्क टियरिंग के निम्न स्तर को दर्शाता है। नेटवर्क संरचना प्रभावी रूप से केवल दो टियरों को दर्शाती है। चित्र के बीच में जो बैंक दिखाए गए हैं वे प्रणाली में बड़े प्रतिभागियों को दर्शाते हैं और इस पूरी अवधि के दौरान ये बड़े प्रतिभागी लगभग समान ही रहे हैं। जैसाकि इस रिपोर्ट के अध्याय 5 में चर्चा की गई है, वित्तीय स्थिरता के लिए नेटवर्क की संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जिसमें कम टियर नेटवर्क की संरचना अधिक स्थिर होती है।

चार्ट 4.11: आरटीजीएस प्रणाली में बैंकों का नेटवर्क (दो अलग-अलग दिनांकों में)

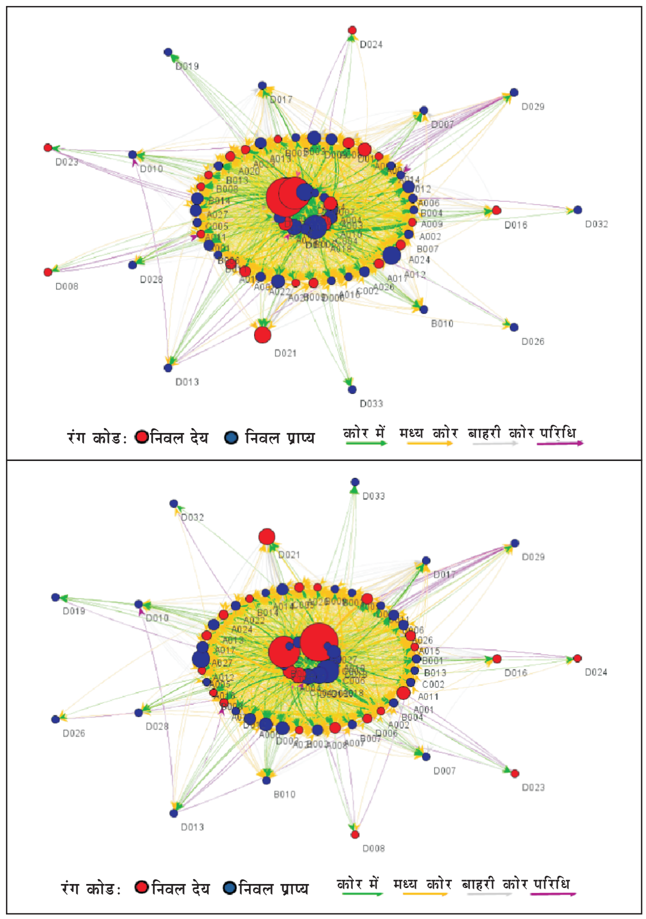

स्रोत : भारिबैं स्टाफ गणना

[6] नेटवर्क टियरिंग स्ट्रक्चर और नेटवर्क की स्थिरता के लिए उनके निहितार्थ पर पूर्ण परिचर्चा के लिए इस रिपोर्ट का अध्याय V देखें।

आरटीजीएस प्रणालियों में लेन-देन के निपटान में स्थगन क्रेडिट, प्रचालनात्मक और प्रणालीगत जोखिमों को उत्पन्न करता है......

4.46 सकल प्राप्तियों और भुगतानों के बीच में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए आरटीजीएस प्रणालियां विशिष्ट रूप से अंतर्दिवस फंडिंग आवश्यकता को पैदा करती हैं। अंतर्दिवस चलनिधि प्रबंधन इस प्रकार बैंकों के निपटान प्रचालनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। चूंकि अंतर्दिवस क्रेडिट महंगा[7] होता है इसलिए अपने भुगतानों का निपटान करने से पहले दूसरे भुगतानों के निपटान को अपराह्न में टालने से या फिर अन्य भुगतानों (अर्थात उनकी प्राप्तियां) के निपटान होने का इंतजार करने से प्रतिभागियों को लाभ मिलता है। *इस स्थिति का* चरम *यह हो सकता है कि बैंक प्राप्तियों के प्रति सक्रिय रहने की रणनीति अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे केवल आवक भुगतानों के द्वारा प्राप्त चलनिधि का उपयोग करके जावक भुगतान कर सकते हैं* [8]। किसी आरटीजीएस प्रणाली के प्रतिभागियों द्वारा इस प्रकार के रणनीतिक व्यवहार से किसी एक या एक से अधिक प्रतिभागी द्वारा भुगतान में देरी हो सकती है और इससे समग्र रूप से भुगतान प्रणाली में होने वाले निपटान में देरी हो सकती है। यह प्रणाली में चलनिधि के जोखिम को बढा सकती हैं और साथ ही किसी प्रचालनात्मक घटना (जब कोई प्रचालनात्मक घटना प्रणाली/प्रतिभागियों को प्रभावित करती है तो उस स्थिति में यदि बड़ी संख्या में भुगतानों का निपटान नहीं हो पाता है तो) के प्रभाव को भी कई गुणा बढ़ा सकती है जिससे क्रेडिट संबंधी और प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होते हैं।

....घरेलू आरटीजीएस प्रणाली में ऐसी कुछ प्रवृत्तियों के संकेतों को देखते हुए मॉनीटरिंग की आवश्यकता है

4.47 इस संदर्भ में देश में आरटीजीएस प्रणाली में (चार्ट 4.12) अंतर्दिवस भुगतान के पैटर्न पर किए गए अध्ययन[9] से पता चलता है कि दैनिक औसत भुगतान के लगभग 30 प्रतिशत (मूल्य और मात्रा दोनों द्वारा) का निपटान 3.00 अपराह्न के बाद किया जाता है और लगभग 50 प्रतिशत भुगतानों का निपटान दिन के अंत में किया जाता है। अध्ययन आरटीजीएस प्रणाली के सदस्यों द्वारा निपटान में की गई कुछ देरी को इंगित करता है जबकि भुगतान का पैटर्न काफी हद तक ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले भुगतान के द्वारा प्रभावित होता है जिस पर बैंकों का विशिष्ट रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। बैंकों द्वारा किए जाने वाले भुगतान व्यवहार में भी काफी अंतर है (चार्ट 4.13 और 4.14)। पूरी प्रणाली में लेनदेन के निपटानों को दिन के अंत में स्थगित किए जाने को रोकने की दृष्टि से इन प्रवृत्तियों की मॉनीटरिंग की आवश्यकता है।

चार्ट 4.12: आरटीजीएस प्रणाली में अंतर्दिवसीय भुगतान का पैटर्न (मूल्य और मात्रा)

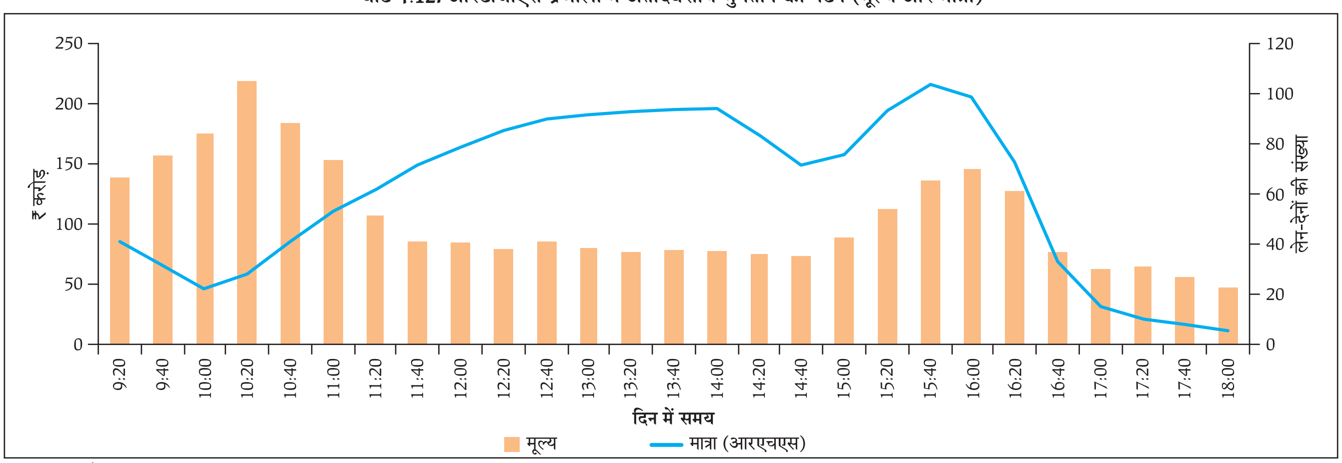

स्रोत : भारिबैं स्टाफ गणना

[7] आमतौर पर विश्व भर के केंद्रीय बैंक आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने लेने वालों को संपार्श्विक प्रतिपूर्ति के बदले में अंतर्दिवसीय ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ केंद्रीय बैंक इसके लिए शुल्क प्रभारित करते हैं। अत: अंतर्दिवसीय ऋण महंगा होता है- चाहे वह फीस के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हो या संपार्श्विक के अवसर की लागत के रूप में अव्यक्त रूप से हो।

[8] अंतर्दिवसीय चलनिधि: जोखिम और विनियमन, एलन बॉल, एडवर्डडेनबी, मार्क मैनिंग और एनी वेदेरिल्ट, वित्तीय स्थिरता पृष्ठ सं. 11, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जून 11

[9] शनिवारों को छोड़कर विश्लेषण एक तिमाही (जुलाई-सितंबर 2011) की अवधि के लिए आरटीजीएस प्रणाली के दैनिक लेन-देन डाटा पर आधारित है। इस विश्लेषण में औद्योगिक ईकाइयां जैसे कि रिजर्व बैंक, डीआइसीजीसी तथा सीसीआईएल को छोड़कर प्रणाली सभी सदस्यों के लेन-देन शामिल हैं।

चार्ट 4.13: कुछ चुने हुए बैंकों का अंतर्दिवसीय भुगतान पैटर्न (मूल्य ₹ करोड़ में)

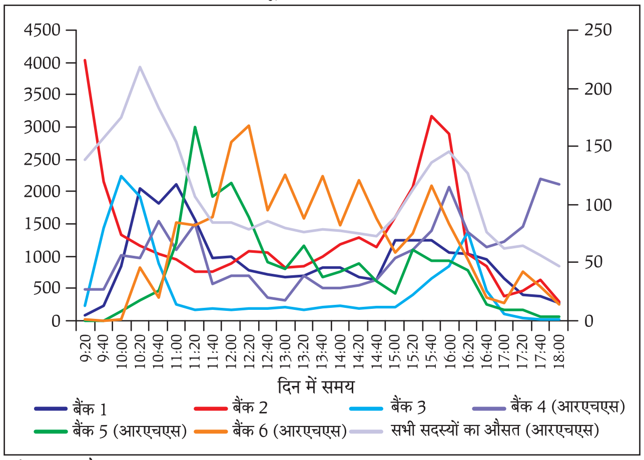

स्रोत : भारिबैं स्टाफ गणना

चार्ट 4.14: कुछ चुने हुए बैंकों का अंतर्दिवसीय भुगतान पैटर्न (लेन-देनों की संख्या)

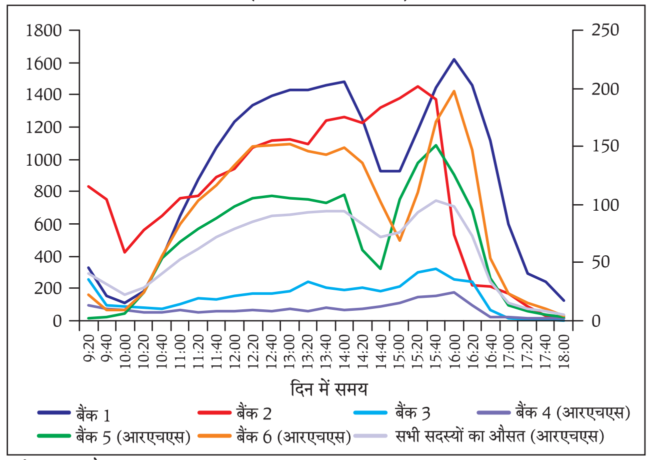

स्रोत : भारिबैं स्टाफ गणना

इक्विटी समाशोधन निगमों के बैंकों में एक्सपोजर को मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता है

4.48 गांरटिड निपटान प्रदान करने वाले समाशोधन निगम सदस्यों से लेनदेन आधारित मार्जिन लेने के अतिरिक्त विशिष्ट रूप से निपटान गांरटी फंड (एसजीएफ) को भी बना कर रखते हैं। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) जो कि भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार के लिए एक केंद्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, मुख्य रूप से एसजीएफ में योगदान के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है। तथापि इक्विटी समाशोधन निगमों के मामले में एसजीएफ में योगदान और मार्जिन को बैंक गारंटी और प्रतिभूतियों (जो कि बैंकों द्वारा जारी की जाती हैं) के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इससे समाशोधन निगम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से ऐसी गारंटियां/ प्रतिभूतियां जारी करने वाले बैंकों के प्रति एक्सपोज होता है। किसी बैंक के फेल हो जाने की स्थिति में बैंक से संबंधित जोखिम प्रणालीगत जोखिम में परिवर्तित हो सकता है। इस संदर्भ में एसईबीआई द्वारा और आंतरिक रूप से राष्ट्रीय स्टॉक समाशोधन निगम द्वारा भी एक्सपोजर मानदंड जारी किए गए हैं। फिर भी इस संबंध में होने वाली प्रवृत्तियों को मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता है।

ओटीसी डेरिवेटिव बाजार

डाटा एकीकरण के लिए जारी पहलों से ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन की मॉनीटरिंग में सहायता मिलेगी....

4.49 पिछली एफएसआरों में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में सुधार के लिए जारी अंतरराष्ट्रीय पहलों के सेट के बारे में रिपोर्ट किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माताओं में प्रमुख साझी प्राथमिकता किसी एक ट्रेड रिपोजिटरी को सभी ओटीसी डेरिवेटिव उत्पादों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है ताकि व्यापार के संबंध में प्राप्त जानकारी को उभरते हुए प्रणालीगत जोखिमों का पता लगाने के लिए किया जा सके। इस संदर्भ में डाटा एकीकरण डेरिवेटिव बाजार की प्रभावी मॉनीटरिंग की कुंजी है।

... परंतु इससे तरीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को दूर करने की आवश्यकता होगी

4.50 एक जैसी संपत्ति श्रेणी और अलग-अलग संपत्ति श्रेणियों दोनों में ही विभिन्न व्यापार रिपोजिटरियों में डाटा एकीकरण करने में समस्याएं हैं। इस संबंध में डाटा शेयरिंग के लिए वैश्विक आम सहमति और विधाई परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। डाटा शेयरिंग के प्रोटोकॉल और गोपनीयता की व्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

एलईआई से डाटा एकीकरण सुविधाजनक हो सकता है......

4.51 डाटा एकीकरण की मुख्य चुनौती किसी वित्तीय संस्था के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता की कमी होना है जो कि व्यापार रिपोजिटरियों को रिपोर्ट किए गए डाटा के एकीकरण में एक प्रमुख बाधा है। इस संदर्भ में ओटीसी डेरिवेटिवों से संबंधित डाटा के एकीकरण के लिए लिगल एन्टिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) की संकल्पना एक उपयोगी साधन के रूप में प्रस्तावित की गई है। वित्तीय बाजारों में कार्य करने वाली प्रत्येक लिगल एन्टिटी के लिए एलईआई एक विशिष्ट वैश्विक पहचानकर्ता है जो कि विभिन्न व्यापारों, समाशोधन और निपटान प्रणालियों में प्रतिभागियों की पहचान करने में सहायता कर सकता है। इससे घरेलू और वैश्विक दोनों ही स्तरों पर विभिन्न बाजारों और साथ ही संस्थानों के एक्सपोजर के एकीकरण और लिंकेज की पहचान में सुविधा होगी। एलईआई प्रणाली में अंतरण करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है और रिज़र्व बैंक ने भारतीय मानक ब्यूरों को एलईआई की संकल्पना के संबंध में अपनी सहमति दे दी है।

ओटीसी डेरिवेटिवों में काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम: संकट से प्राप्त सबक, विनियामक सुधार और शेष चिंताएं...

4.52 एक काउंटर पार्टी से दूसरी काउंटर पार्टी को जोखिम के अंतरण में वित्तीय डेरिवेटिव्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ओटीसी डेरिवेटिव इच्छित रूप में कार्य करते हैं लेकिन ये दो तरीके से अपने धारकों को घाटे के जोखिम से एक्सपोज करते हैं: आधारभूत संपत्ति की कार्यनिष्पादकता के माध्यम से और दूसरे काउंटर पार्टी द्वारा संभावित चूक के माध्यम से। इस प्रकार ओटीसी डेरिवेटिव्स बाजार में काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम प्रतिभागियों के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है।

डेरिवेटिव कांट्रेक्टों में काउंटर पार्टी जोखिमों के प्रणालीगत प्रभाव हो सकते हैं...

4.53 संकट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि डेरिवेटिव कांट्रेक्टों का बढ़ा हुआ प्रयोग बैंकों के बीच में अंतरसंबंधता को बढ़ा देता है जिसके कारण प्रणालीगत जोखिम निर्मित हो सकते हैं। अंतर बैंक लेन-देन में पारदर्शिता की कमी और कांउटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए बैंकों के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क विशेष रूप से बैंक टेस्टिंग, तनाव टेस्टिंग और काउंटर पार्टी की क्षमता संबंधी जोखिमों[10] (Wrong-way risk) में कमजोरी के कारण अंतरसंबंधता की समस्या और अधिक विकराल हो जाती है। परिणामस्वरूप एक संविदा जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह हमें बीमा उपलब्ध करवा रही है, प्रणालीगत दबावों की घटनाओं के दौरान उसके बारे में यह संभावना हो जाती है कि वह भुगतान करने में असमर्थ है[11]।

... संकट के बाद के विनियामक सुधारों में इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है

4.54 संकट से पूर्व वर्तमान में लागू विनियामक ढांचे ने उपर्युक्त प्रणालीगत जोखिमों के बारे में पर्याप्त संज्ञान नहीं लिया। विशेष रूप से जबकि बासल II मानक काउंटर पार्टी चूक के जोखिम को कवर करते हैं लेकिन वे सीवीए जोखिम[12] के बारे में ध्यान नहीं देते। संकट के बाद बासल समिति ने बैंक डेरिवेटिवों, रेपो और प्रतिभूतियों की फाइनेंसिंग गतिविधियों से उत्पन्न काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजरों के लिए पूंजी आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के उपायों की शुरूआत की। साथ ही लगातार बढ़ रही ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन की संख्या को सीसीपी व्यवस्था में बदलने की पहलों से इनसे संबंधित काउंटर पार्टी जोखिमों को दूर करने में सहायता मिलेगी। बासल समिति ने सीसीपी के माध्यम से निपटान किए गए एक्सपोजरों के लिए कम पूंजी आवश्यकताओं के लाभों को भी प्रदान किया है।

...लेकिन कड़े अनुमानों के साथ समग्र दबाव परीक्षणों की आवश्यकता महत्वपूर्ण बनी रहेगी

4.55 आगे देखें तो तुलनपत्र से इतर लेनदेनों में काउंटर पार्टी एक्सपोजरों के जोखिमों का प्रबंधन किए जाने के लिए इस बात का पर्याप्त संज्ञान लेना महत्वपूर्ण होगा कि दबाव परीक्षणों के दौरान समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली कैसे कार्य करती है। व्यक्तिगत काउंटर पार्टियों और प्रणालीगत जोखिमों का निर्धारण करने के लिए अधिक कठोर अनुमानों को शामिल करके विशेष रूप से समग्र दबाव परीक्षणों के व्यापक प्रयोग की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

डेरिवेटिव संविदाएं भारतीय बैंकों की अंतर्संबद्धता को बढ़ाती हैं

4.56 भारतीय संदर्भ में डेरिवेटिव संविदाएं बैंकों के बीच में अंतर्संबद्धता को बढ़ाती हैं (जैसा कि चार्ट 4.15) में तुलनपत्र से इतर एक्सपोजरों के स्तरीय नेटवर्क की आंतरिक तथा मध्य कोर में बैंकों के बीच में लाइनों की मोटाई के द्वारा दिखाई देता है)[13]। शीर्ष 20 बैंकों (आंतरिक तथा मध्य कोर में) के मामले में

चार्ट 4.15: बैंकों के बीच डेरिवेटिव एक्पोजर की नेटवर्क संरचना[14]

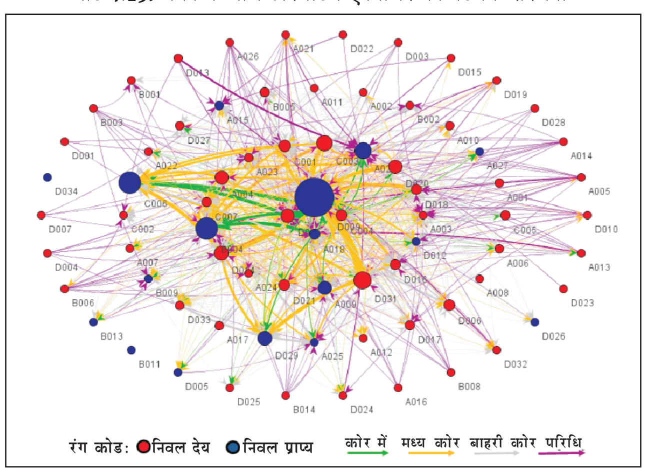

स्रोत : भारिबैं स्टाफ गणना

[10] काउंटर पार्टी की क्षमता संबंधी जोखिम तब उत्पन्न होते हैं जब काउंटर पार्टी एक्पोजर काउंटर पार्टी की ऋण गुणवत्ता के साथ प्रतिकूल रूप से सहसंबद्ध हो। काउंटर पार्टी की क्षमता संबंधी जोखिम सामान्यीकृत रूप में तब उत्पन्न होते हैं जब काउंटर पार्टी की ऋण गुणवत्ता अविशिष्ट कारणों के लिए अन्य माइक्रोइकोनॉमिक कारणों के साथ सहसंबद्धता के लिए रोक कर रखी जाए जो खुले डेरिवेटिव लेन-देनों के एक्पोजर को भी प्रभावित कर सकती है।

[11] 'टेल रिस्क एंड कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन फ्रॉम ए फाइनैंशियल स्टैबिलिटी पर्सपेक्टिव', पॉल फिशर, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सितंबर 2011

[12] ऋण मूल्य समायोजन (सीवीए) कांउटर पार्टी के ऋण पात्रता में कमी के कारण डेरिवेटिव स्थिति की उचित मूल्य में कमी का माप है।

[13] टियर्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर और वित्तीय स्थिरता के लिए उनके निहितार्थ पर विस्तृत चर्चा के लिए इस एफएसआर का अध्याय V देखें।

[14] 30 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार द्विपक्षीय अंतरबैंक डेरिवेटिव एक्पोजर डाटा पर आधारित। सीसीएल के माध्यम से निपटान किए गए फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट विश्लेषण में शामिल नहीं किए गए हैं।

अंतर्संबद्धता विशेष रूप से स्पष्ट है जिससे दबाव के हालात में प्रणालीगत विघ्न की संभावना बढ़ जाती है (चार्ट 4.16)। बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजरों के लगातार बढ़ने की हाल ही की प्रवृत्ति को देखते हुए इसकी मॉनीटरिंग की आवश्यकता है (जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय III में चर्चा की गई है)। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम फ्रेमवर्क से संबंधित प्रस्तावित परिवर्तनों से उन कुछ भारतीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव पड़ सकता है जिनकी ओटीसी द्विपक्षीय डेरिवेटिवों में स्थिति अधिक है।

चार्ट 4.16: 20 कोर बैंकों के बीच डेरिवेटिव एक्सपोजर की नेटवर्क संरचना

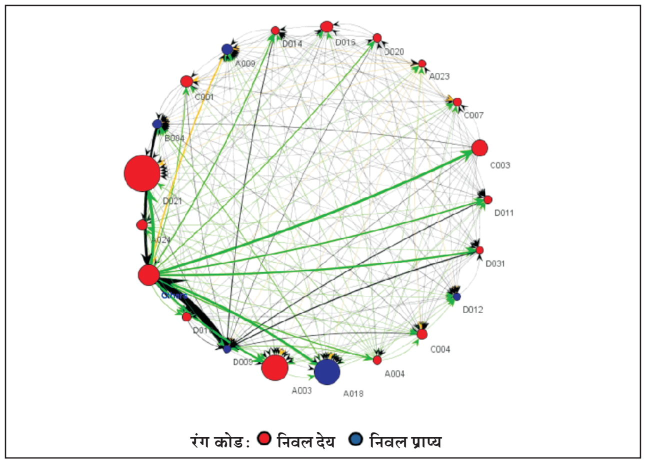

स्रोत : भारिबैं स्टाफ गणना

ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए सीसीपी व्यवस्थाओं की शुरूआत से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है

4.57 यह बहुपक्षीय निपटान प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले डेरिवेटिवों के लेनदेनों को सीसीपी के माध्यम से बढ़ाने की महत्ता को रेखांकित करता है। वर्तमान में विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का निपटान गारंटिड आधार पर किया जाता है जबकि ब्याज दर डेरिवेटिवों का गैर गारंटिड आधार पर केंद्रीकृत रूप में निपटान किया जाता है[15]। विदेशी मुद्रा ऑप्शनों के लिए केंद्रीय समाशोधन आवश्यकताओं की शुरूआत धीरे-धीरे किए जाने की उम्मीद है जबकि क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप के लिए गारंटिड निपटान के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब बाजार गतिविधि और चलनिधि की एक महत्वपूर्ण मात्रा प्राप्त की जा चुकी हो।

सीसीपी में वैकल्पिक एक्सेस विन्यासों के अपने समष्टि वित्तीय प्रभाव हैं

4.58 मानकीकृत ओटीसी डेरिवेटिवों को केंद्रीकृत समाशोधन में अंतरित करने के प्रयासों ने सीसीपी तक बाजार के प्रतिभागियों की एक्सेस के तरीके के बारे में विवाद को जन्म दिया है। इस प्रकार के एक्सेस विन्यासों के कई विकल्प हैं। ये विकल्प प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सदस्यता के माध्यम से वैश्विक सीसीपी तक एक्सेस बढ़ाने से लेकर घरेलू वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्रों में सीसीपी स्थापित करने तक हैं। प्रत्येक विकल्प के साथ समष्टि वित्तीय प्रभाव और स्थिरता तथा कार्यक्षमता के बीच में ट्रेड ऑफ हैं।

4.59 सीसीपी में प्रत्यक्ष एक्सेस में विस्तार करने से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है और डेरिवेटिव निपटान में कुछ ही वैश्विक डीलरों की प्रभुता के कारण उत्पन्न होने वाले केंद्रीकरण के जोखिमों को कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अधिक संख्या में प्रत्यक्ष सदस्यों के साथ लेनदेन करने के लिए सीसीपी की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में वास्तविक रूप से अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी। अपने क्षेत्राधिकार में डेरिवेटिवों की ट्रेडिंग गतिविधियों के बारे में निगरानी

[15] ब्याज़ दर स्वैप शीघ्र ही एक गारंटीगत निपटान प्लेटफार्म पर ला दिए जाएंगे। भारत में डैरिवेटिव बाज़ार का अधिकांश हिस्सा फौरेक्स फार्वेर्ड तथा आईआरएस का है।

रखने के लिए घरेलू सीसीपी स्थानीय प्राधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ बना सकती हैं। लेकिन घरेलू सीसीपी के एक बड़े नेटवर्क से संपार्श्विक संपत्तियों की पूरी प्रणाली में मांग बढ़ जाएगी और ट्रेडिंग और वित्तीय स्थितियों में विखंडन हो जाएगा। पुन: चूंकि सीसीपी के बीच में संबंधों को बढ़ी हुई बहुपक्षीय नेटिंग के लाभों को उठाने के लिए स्थापित किया जाता है इस कारण से विशिष्ट जोखिम विशेषकर प्रचालनात्मक और विधिक चुनौतियां और साथ ही साथ संबंधित क्रेडिट और चलनिधि जोखिमों का निर्माण हो सकता है।

घरेलू सीसीपी- भारतीय संदर्भ में उपयुक्त विकल्प

4.60 सीसीआईएल के पास अच्छी तरह से परिभाषित एक्सेस मानदंड हैं जिनसे सीसीपी में सीधा एक्सेस में मदद मिलती है और जहां पर सीधा एक्सेस व्यवहार्य नहीं है वहां पर ये नामित निपटान बैंकों (डीएसबी) के माध्यम से सीधे एक्सेस को बढ़ावा देता है। सीधी सदस्यता और डीएसबी निपटान मोड से उत्पन्न केंद्रीकरण दोनों के साथ ही जोखिम जुड़े हुए हैं जिन्हें निरंतर मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता है।

4.61 सीसीआईएल घरेलू सदस्यों के साथ घरेलू बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके द्वारा स्वीकार की जाने वाली संपार्श्विक भी अधिकांशत: घरेलू सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। घरेलू मुद्रा भी पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए वर्तमान बिंदु पर यह महसूस किया गया कि घरेलू सीसीपी विकल्प अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है।

डीएसबी मॉडल में केंद्रीकरण जोखिम देखे गए...

4.62 पिछली एफएसआर में अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में संस्थान आधारित अंतर्संबद्धताओं से उत्पन्न जोखिमों की पहचान की गई थी। इस संबंध में विभिन्न बाजार खंडों में कुछ चुनिंदा संस्थाओं द्वारा चलनिधि बैक स्टॉप प्रदाताओं, निपटान बैंकों और बड़े प्रतिभागियों के रूप में अनेक भूमिकाएं निभाने के कारण उत्पन्न केंद्रीकरण जोखिम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

4.63 इस संदर्भ में डीएसबी (सीसीआईएल के प्रत्यक्ष सदस्यों के लेनदेनों का निपटान रिज़र्व बैंक में होता है) के माध्यम से सीसीआईएल के सहयोगी सदस्यों के लेनदेनों के निपटान की प्रणाली भी महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न डीएसबी में सहयोगी सदस्यों का वितरण (सारणी 4.1) प्रत्यक्ष केंद्रीकरण जोखिमों को दर्शाता है क्योंकि किसी भी डीएसबी में निपटान की असफलता (उदाहरण के लिए सहयोगी सदस्यों की चलनिधि या प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण) का प्रभाव पूरे बाजार पर हो सकता है। चूंकि सीबीएलओ और प्रतिभूति दोनों ही खंडों में डीएसबी स्वयं भी बड़े प्रतिभागी होते हैं (प्रोपराइटरी स्थितियों के साथ) इसीलिए जोखिम और भी बढ़ जाते हैं।

सारणी सं. 4.1: भारिबैं/ डीएसबी के साथ निपटान सदस्य

	सदस्यों की संख्या	प्रत्यक्ष सदस्यों की संख्या	सहयोगी सदस्यों की संख्या				
			डीएसबी 1	डीएसबी 2	डीएसबी 3	डीएसबी 4	डीएसबी 5
सरकारी प्रतिभूति	163	131	21	6	2	2	1
सीबीएलओ	200	112	61	17	5	3	2

स्रोत: सीसीआईएल

सीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए पोर्टफोलियो कम्प्रेशन के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है....

4.64 पिछली एफएसआर में रिपोर्ट किया गया था कि रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) डेरिवेटिव बाजार के लिए सीसीआईएल व्यापार कम्प्रेशन सेवाएं विकसित करने की प्रक्रिया में था। सीसीआईएल ने अब पोर्टफोलियों कम्प्रेशन सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस सेवा का पहला लाइव रन 14 प्रतिभागियों के साथ किया गया जिसमें 94 प्रतिशत से अधिक का कम्प्रेशन अनुपात प्राप्त हुआ। कम्प्रेशन के लिए पात्र व्यापार की पहचान के लिए न्यूनतम सीमा और प्रतिभागियों (ताकि काउंटरपार्टियों द्वारा एक ही लेनदेन के लिए अलग-अलग एमटीएम मूल्य न रिपोर्ट किए जाएं) द्वारा एक समान मूल्यांकन तरीके के पालन को सुनिश्चित करने से संबंधित कुछ छोटे मुद्दों को दूर किया जा रहा है।

दबाव और बैंक टेस्टिंग कवायदों के प्रति सीसीआईएल गतिशील है...

4.65 सीसीआईएल ने विभिन्न बाजार खंडों के लिए आवधिक आधार पर बैंक टेस्टिंग और दबाव टेस्टिंग की एक प्रणाली स्थापित की है। बैंक टेस्टिंग के परिणाम सीसीआईएल की मार्जिनिंग प्रक्रिया की पर्याप्तता के बारे में इंगित करते हैं। दबाव परीक्षण परिणाम इंगित करते हैं कि सभी मामलों में संभावित घाटे सीसीआईएल के पास उपलब्ध संसाधनों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरे किए गए।

... और अधिक विस्तृत दबाव परिदृश्यों में गतिशीलता का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है

4.66 आगे, दबाव परीक्षणों की पर्याप्तता और कुशलता में दबाव परिदृश्यों को डिजाइन करने में ऐतिहासिक डाटा की सीमित उपलब्धता से आने वाली कठिनाइयों के साथ-साथ ऐतिहासिक डाटा की सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसके आगे, दबाव परीक्षणों को और अधिक व्यापक विफलताओं (दो या दो से अधिक बड़े प्रतिभागियों की या प्रणालीगत विफलता) के प्रभाव और चलनिधि की उपलब्धता पर दबाव का निर्धारण करने की आवश्यकता होगी। सीसीआईएल में जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को भुगतान तथा निपटान प्रणालियों (डीएसबी या बैंक जो कि सीसीआईएल को चलनिधि प्रदाता हैं, इनके निपटान

विफल हो जाने के कारण उत्पन्न जोखिम) की अंतर्संबद्धताओं को देखते हुए सीसीआईएल की दबाव सहने की क्षमता और अंतर बैंक तथा बृहत्तर वित्तीय क्षेत्र में अंतरसंबद्धता के प्रचलन के निर्धारण की आवश्यकता भी होगी।

निष्कर्ष

4.67 भारत में बैंक अच्छी तरह से पूंजी संपन्न हैं और जब बैंकिंग प्रणाली बासल III को अपनाने की तैयारी में है तो टियर I पूंजी की 6 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता उन्हें अच्छी स्थिति में रखेगी। फिर भी नए मानकों के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के लेंडिंग स्प्रेड में वृद्धि हो सकती है। प्रायोगिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि बढ़े हुए लेंडिंग स्प्रेड का जीडीपी पर प्रभाव कम होगा और यह प्रभाव विफलता की कम संभावना के कारण दीर्घावधि में होने वाले लाभों को देखते हुए कम होगा। नए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एसएलआर निवेशों से संबंधित मामला पेचीदा हो सकता है। चलनिधि अनुपात के परिकलन के लिए इसे शामिल करने की अनुमति नहीं दिए जाने की स्थिति में बैंकों को नए मानकों के अनुपालन में कठिनाई होगी।

4.68 किसी भी भारतीय बैंक के वैश्विक एसआईएफआई के रूप में योग्य पाए जाने की संभावना नहीं है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि एसआईएफआई फ्रेमवर्क को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए रूपांतरित किया गया है। बासल II के अंतर्गत उन्नत पद्धतियों को अपनाने के बारे में दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं, हालांकि इस संबंध में बैंकों की प्रतिक्रिया इतनी अधिक उत्साहजनक नहीं है। आगे, रिज़र्व बैंक को बैंकिंग क्षेत्र के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रावधानों की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है। बैंकों के लिए आईएफआरएस को अपनाने की तारीख समीप आ रही है लेकिन आईएफआरएस-9 अभी भी एक गतिमान लक्ष्य बना हुआ है।

4.69 एफएसडीसी की उप समिति परिषद की मुख्य प्रचालन शाखा के रूप में उभरकर सामने आई है। अपने अस्तित्व के एक वर्ष में इसने कई प्रकार के मुद्दों की समीक्षा की है जिसमें वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतर विनियामक समन्वयन, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं।

4.70 एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्र के बीच की विनियामक कमियों को दूर किया जा रहा है। इस संदर्भ में एनबीएफसी में मुद्दे और चिंताओं के बारे में गठित कार्यदल की सिफारिशों की जांच की जा रही है। बैंक के प्रभावी और तर्कसंगत प्रस्ताव के लिए बीआर अधिनियम के प्रावधान सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते और वित्तीय क्षेत्र के सभी कानूनों की समीक्षा के अंतर्गत इस बारे में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

4.71 पिछली एफएसआर की अवधि के बाद से भुगतान और निपटान प्रणाली ने सुदृढ़ तरीके से काम किया। आरटीजीएस प्रणाली में अंतर्दिवस निपटान के स्वरूप के विश्लेषण से प्रतिभागियों द्वारा निपटान को दिन के दूसरे हिस्से में स्थगित करने की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में पता चलता है, जिनकी ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। डाटा एकत्रीकरण और लिगल एन्टिटी पहचानकर्ता की स्थापना पर विचार किया जा रहा है जो कि ओटीसी डेरिवेटिवों की मॉनीटरिंग में सहायता प्रदान करेगा। ओटीसी डेरिवेटिव सुधार उपायों में काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिमों पर विचार किया जा रहा है लेकिन रांग-वे जोखिमों को सुदृढ़ दबाव परीक्षण के माध्यम से ध्यानपूर्वक मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता होगी। जबकि ओटीसी डेरिवेटिवों के केंद्रीकृत समाशोधन को बढाने के लिए उपायों को लागू कर दिया गया है, वैश्विक सीसीपी बनाम घरेलू सीसीपी के पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा जारी है। भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में जोखिमों से निपटने के लिए पोर्टफोलियो कम्प्रेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। डीएसबी सहित सीसीआईएल में केंद्रीकरण जोखिम बने हुए हैं जबकि सीसीआईएल द्वारा दबाव परीक्षणों और बैंक टेस्टिंग को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय V
प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन

भौगोलिक मंदी के बाद किसी भी ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अत्यंत विवेकपूर्ण निगरानी के लिए प्रणालीगत जोखिम को आंकने की आवश्यकता उभरकर सामने आ गई। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक वित्तीय व्यवस्था से जुडे ऐसे जोखिमों को बारीकी से आंकने के उपकरण और तकनीक विकसित करने में लगे हैं। भारत में भी, प्रणालीगत जोखिम को पहचानने और आंकने के लिए प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन और मौजूदा उपरण किट में उसको शामिल करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। उसी समय यह महसूस किया गया कि प्रणालीगत जोखिम बहुत ही जटिल है और अत्यंत सूक्ष्मता से उसको आंकना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाज़ार के प्रतिभागियों और हितधारियों के मत प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण का आयोजन किया गया ताकि उनके अपने और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और नीति निर्माण करनेवालों के मूल्यांकन की प्रतिस्थापना की जा सके। (यथा एफएसडीसी की उप समिति में प्रस्तुत)।

समष्टि अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाज़ार, राजकोषीय क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न जोखिम दिशाओं की गति को आंकने के लिए स्थिरता संबंधी सूचियों और मानचित्रों की शृंखला (जैसा कि इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है) तैयार की गई है। व्यवस्था में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की चलनिधि में मौजूद जोखिम को आंकने का प्रयास प्रणालीगत चलनिधि सांकेतित करता है। अंतर-बैंक और अंत: वित्तीय क्षेत्र ऋण जोखिम का नेटवर्क मॉडल उस संक्रामक जोखिम के विश्लेषण कारने का प्रयास करता है जो शुरुआत में किसी विशेष समस्या से पैदा होता है और बाद में बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के क्रॉस सेक्शन में फैल जाता है। बैंकिंग स्थिरता संबंधी उपाय किसी विशेष बैंकों के समूहों के बीच और किसी व्यक्तिगत बैंक से संबद्ध बैंकिंग क्षेत्र के संकट निर्भरता का नमूना तैयार करने का प्रयास करता है। अंत में, समष्टि वित्तीय दबाव संबंधी परीक्षणों की श्रृंखला वित्तीय व्यवस्था के ऊपर समष्टि अर्थव्यवस्था संबंधी झटकों के प्रभाव पर केंद्रित होता है।

5.1 हालिया वित्तीय संकट ने प्रणालीगत जोखिम से होनेवाले परिणामों का ठोस उदाहरण प्रस्तुत किया। यह व्यक्त किया है कि अगर प्रणालीगत जोखिम क्रमानुगत रूप से एक स्तर तक इकट्ठा हो जाता है तो एक छोटा सा झटका भी उसको बढ़ा सकता है और वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता के लिए व्यापक परिणाम लाया जा सकता है।

5.2 संकट के बाद, सभी ने माना कि वित्तीय अस्थिरता की ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वित्तीय प्राधिकारियों को वित्तीय क्षेत्र में मौजूद प्रणालीगत जोखिमों को बेहतर तरीके से पहचानने, आंकने और प्रबंध करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी महसूस किया गया कि प्रणालीगत जोखिम को पहचानना एक लक्ष्य है जो उसके सीधे अर्थ से काफी दूर है कि प्रणालीगत जोखिम जटिल और बहुआयामी है। यह भी व्यापक रूप से माना गया कि चूंकि वन और वृक्ष दोनों[1] को प्रभावात्मक रूप से देखभाल करना है, प्रणालीगत जोखिम के विभिन्न पहलुओं को प्रावरित कर रहे उपायों और उपकरणों के कई विकल्प की आवश्यकता है।

5.3 संकट के पश्चात एक अकादमिक साहित्य में कई नए प्रमात्रीकरण उपाय सामने आ गए जब केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के अपने प्रयासों के दौरान उपकरण और तकनीक तैयार कर रहे थे जो प्रणालीगत जोखिम को पहचानने और आंकने में सहायक है। व्यापक लक्ष्य था वित्तीय व्यवस्था को समष्टि-विवेकपूर्ण सहयोग प्रदान करना।

5.4 अन्य विषयों के साथ निरंतर आधार पर वित्तीय व्यवस्था का समष्टिगत निगरानी करने के लक्ष्य से 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक में वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन उपायों और परियोजनाओं की श्रृंखला तैयार की जा रही है। इसका लक्ष्य है ऐसे उपकरण और कार्य पद्धति तैयार करना जो देशीय वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता के

[1] **"सीईंग बोथ द फॉरेस्ट ऐंड द ट्रीज-सुपरवाइजिंग सिस्टमिक रिस्क"**, जोस वेनाल्स, आईएमएफ फिनान्शियल कौन्सिलर एंड डिरक्टर, मानिटरी एंड कापिटल मार्केटस डिपार्टमेंट ने वित्तीय क्षेत्र के लिए नीतिगत चुनौतियों पर वॉशिंगटन डीसी में 2 जून 2011 को हुई ग्यारहवीं वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटन भाषण में कहा था।

लिए संभाव्य चुनौती को पहचानने, आंकने और निगरानी करने में इस्तेमाल किया जा सके।

5.5 प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन संबंधी प्रयासों का लक्ष्य है विभिन्न तरीकों के ज़रिए प्रणालीगत जोखिमों के विभिन्न आयामों को पहचानना। स्थिरता संकेतकों / मानचित्रों की श्रृंखला जोखिम संबंधी विभिन्न आयामों को पहचानने का प्रयास करता है जो संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के साथ-साथ अर्थव्यवस्था (समष्टि अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाज़ार, राजकोषीय, बैंकिंग क्षेत्र) के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिरता को प्रभावित करता है। इन आयामों में किसी प्रकार के उतार-चढाव का इस्तेमाल यह आंकने के लिए किया जाता है कि कोई जोखिम है या नहीं। इन संकेतकों / मानचित्रों द्वारा दिए गए संकेत इस रिपोर्ट के उचित अध्यायों में दिए गए हैं। इस अध्याय के विभिन्न भाग प्रणालीगत जोखिम की गति को आंकने और पहचानने के व्यापक मूल प्रयासों के परिणामों को प्रस्तुत करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के इस अंक में वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों के संपूर्ण मूल्यांकन के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए पहलों / नमूनों की श्रृंखला पर आधारित ऐसे जोखिमों के उभरने के संकेतों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन को भी जोडा गया है।

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण जोखिम की बढ़त के मूल्यांकन का एक अतिरिक्त उपकरण है....

5.6 भारतीय वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम के प्रमुख स्रोतों के संबंध में बाज़ार के प्रतिभागियों और अन्य हितधारियों से अनुभव इकट्ठा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर - नवंबर 2011 में अपना प्रथम प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण वर्ष में दो बार किया जाता है। यह उम्मीद किया जाता है कि यह प्रयास वित्तीय स्थिरता के जोखिमों के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा।

सर्वेक्षण ने कई बाज़ार प्रतिभागियों और हितधारियों के विचारों को एकत्रित किया

5.7 सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देनेवालों में कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, प्राथमिक डीलरों और ब्रोकिंग फर्मों के 100 चुनिंदे व्यक्तियों का समूह शामिल है। प्रतिक्रियाकर्ताओं में उद्योग संगठन, रेटिंग एजेंसी, क्लियरिंग कार्पोरेशन के साथ-साथ चुनिंदा अकादमी सदस्य और चिंतक शामिल है।

...विशेष जोखिमों और व्यवस्था की स्थिरता में विश्वास का स्तर दोनों पर

5.8 सर्वेक्षण में दोनों अल्पावधि और मध्यम अवधि में वित्तीय व्यवस्था में आ रहे विशेष प्रणालीगत जोखिम पर बाज़ार के प्रतिभागियों और अन्य हितधारियों के दृष्टिकोण के साथ वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और भारतीय वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले उच्च प्रभाववाली घटनाओं की संभाव्यता पर उनके मूल्यांकन को भी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। सवालों के अलग सेट ने वैश्विक और देशी वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता में प्रतिक्रियाकर्ताओं के विश्वास के स्तर को उजागर किया और यह भी व्यक्त किया कि पिछले छह महीने के दौरान हुई घटनाओं से उसमें कैसे परिवर्तन आया।

आस्ति गुणवत्ता - जोखिम जिसके होने की सबसे ज्यादा संभावना है

5.9 प्रतिक्रियाकर्ताओं में अधिकांश लोगों ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को वित्तीय व्यवस्था के सबसे उल्लेखनीय जोखिम माना है और उसके बाद विनिमय दर की अस्थिरता, वैश्विक जोखिम, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर सहित उच्च बाज़ार गिरावट आता है। अन्य पहचान की गई जोखिमों में राजकोषीय जोखिम, अत्यधिक या धीमि नियामक प्रतिक्रियाओं से आ रहे जोखिम और कंपनी अभिशासन के जोखिम सहित कार्पोरेट जोखिम शामिल है। धीमी ऋण में वृद्धि, देश और देशी बैंकों की रेटिंग में गिरावट, आतंकवाद, आस्ति मूल्य बबल्स और साइबर क्राइम, भुगतान संरचना की असफलता जैसी तकनीकी जोखिम, वर्तमान राजनीतिक स्थिति से जोखिम आदि का भी कभी-कभार ज़िक्र किया गया है। (चार्ट 5.1)

चार्ट 5.1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के प्रतिक्रियाकर्ताओं द्वारा पहचान किए गए प्रणालीगत जोखिम[2]

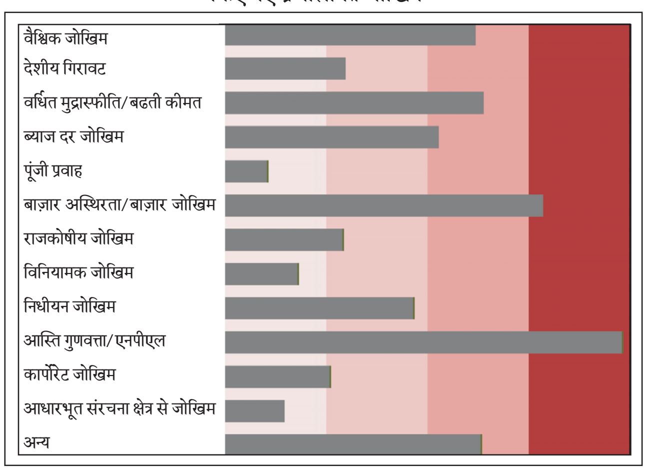

[2] चार्ट के बार उन उत्तर देनेवालों की संख्या का भारित एग्रिगेट दिखलाते हैं जिन्होंने संबंधित जोखिम, होने के संबंध में उत्तर देनेवालों द्वारा संभव्यता को दर्शाते हुए भार।

उच्च मुद्रास्फीति से आ रहे जोखिम का प्रबंधन देश के लिए सबसे कठिन है

5.10 सर्वेक्षण के प्रतिक्रियाकर्ताओं ने माना कि उच्च मुद्रास्फीति से आनेवाले जोखिम का प्रबंधन देश के लिए सबसे कठिन होता है। वैश्विक जोखिम और वर्धित बाज़ार अस्थिरता का प्रबंधन भी व्यवस्था के लिए मुश्किल होता है जैसाकि आस्ति गुणवत्ता (चार्ट 5.2) की गिरावट से जो जोखिम पैदा होता है। वित्तीय संस्थानों के प्रतिभागियों ने माना कि निधीयन संबंधी जोखिम, आस्ति गुणवत्ता की गिरावट, ब्याज दर और उच्च बाज़ार अस्थिरता से जोखिम का प्रबंध उनके संबंधित संस्थान के लिए सबसे कठिन होता है (चार्ट 5.3)।

वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उच्च प्रभाव की संभाव्यता देशीय वित्तीय व्यवस्था में भी असर डाल सकता है

5.11 सर्वेक्षण में भाग लिए आधे से भी अधिक लोगों ने महसूस किया कि अल्पावधि में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उच्च प्रभाववाली घटना होने की संभाव्यता अधिक थी लेकिन वे भारतीय वित्तीय व्यवस्था में अपेक्षाकृत विश्वास रखते थे। मध्यावधि में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उच्च प्रभाववाली घटना होनी की संभाव्यता भी अधिक थी लेकिन इसकी संभाव्यता अल्पावधि जैसी अधिक नहीं थी (चार्ट 5.4)। देशीय वित्तीय व्यवस्था में समान घटनाएं होने की संभावना काफी कम आंका गया। तथापि, प्रतिक्रियाकर्ताओं में अधिकांश लोगों ने महसूस किया कि वैश्विक गतिविधियां भारतीय वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करती है और 40% लोगों ने माना कि यह प्रभाव उल्लेखनीय होगी (सारणी 5.1)।

5.12 सर्वेक्षण ने यह सामने लाया कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता में बाज़ार को जो विश्वास है वह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। 50 प्रतिशत से भी अधिक प्रतिक्रियाकर्ताओं को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बहुत ही कम विश्वास था या बिल्कुल ही नहीं था। जबकि 90 प्रतिशत से भी अधिक प्रतिक्रियाकर्ताओं को भारतीय वित्तीय व्यवस्था में बहुत अधिक या पर्याप्त रूप में विशास था। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में

सारणी 5.1: वैश्विक घटना का देशीय वित्तीय व्यवस्था में प्रभाव (प्रतिशत)

अत्यधिक	उच्च	सामान्य	कम	कोई असर नहीं
9	**35**	**46**	**10**	**0**

चार्ट 5.2: जोखिम जिसका प्रबंधन देश के लिए अत्यंत कठिन है

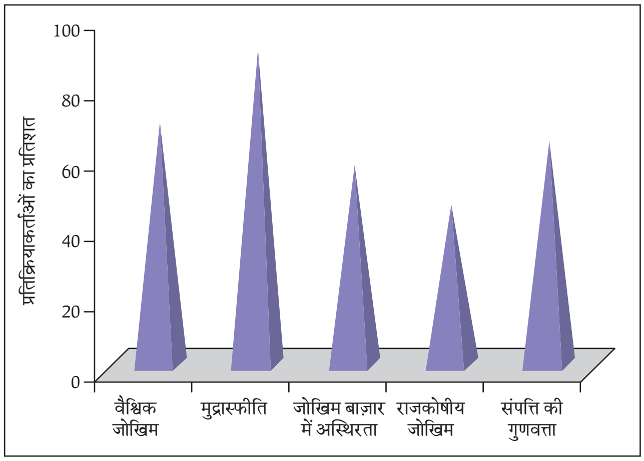

चार्ट 5.3: जोखिम जिसका प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के लिए अत्यंत कठिन है

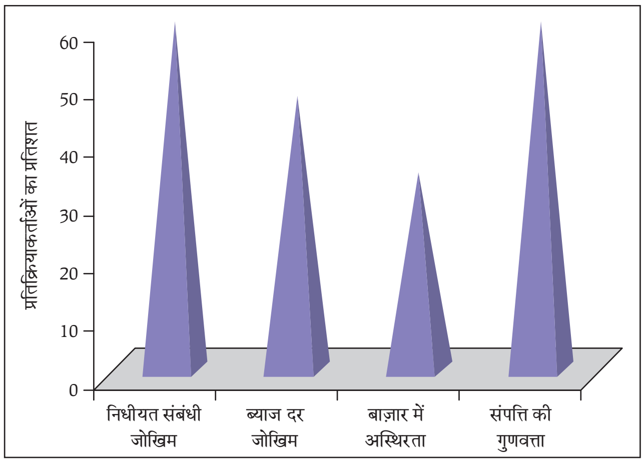

चार्ट 5.4: उच्च प्रभाववाली घटना की संभाव्यता (प्रतिशत)

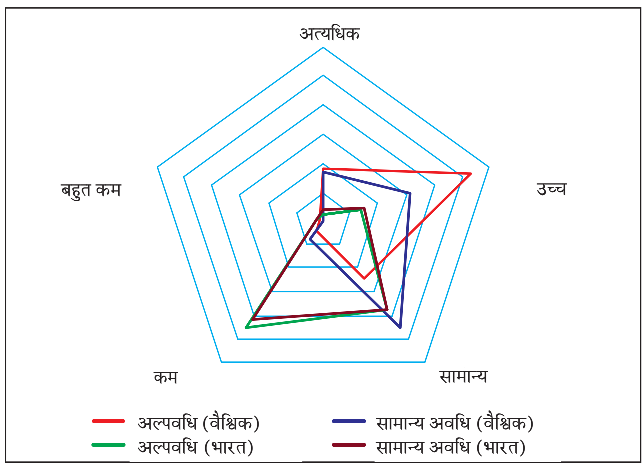

नोट: केंद्र बिंदु से दूरी प्रतिभागियों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें लगता हैं कि उच्च प्रभाववाली घटना होने की संभावना बहुत कम/कम/सामान्य/अधिक/बहुत अधिक है।

प्रतिक्रियाकर्ताओं का विश्वास पिछले छह महीनों में अत्यधि कम हो गया है जबकि भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर यह अटूट रहा (चार्ट 5.5 और सारणी 5.2)।

सर्वेक्षण ने रिज़र्व बैंक के प्रणालीगत जोखिमों के मूल्यांकन को प्रतिबिम्बित किया

5.13 समग्र रूप से, जोखिम सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने रिज़र्व बैंक के प्रणालीगत जोखिम के निजी मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जैसा कि इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में इसका उल्लेख किया गया है। यद्यपि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विश्वास का स्तर कम और ह्रासकारी था फिर भी निष्कर्षों से देशी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास की पुष्टि हुई।

भारत का प्रणालीगत चलनिधि सूचक (एसएलआई)[3]

चलनिधि के कई रूप हैं

5.14 आम तौर पर चलनिधि दो प्रकार के होते हैं: निधीयन और बाजार चलनिधि। निधीयन चलनिधि का संबंध नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिये विद्यमान प्रतिभूतियों की पुन: खरीद के जरिए या सावधि मुद्रा / वाणिज्यिक पत्र बाजारों में या बैंकों से धन उगाने के लिये संस्थानों की कार्यक्षमता से है। बाजार चलनिधि का संबंध नकदी उगाने के लिये कम लागत वाले संपत्तियों को बेचने की कार्यक्षमता से है। जब फर्म संपत्तियां बेचते हैं तो उनके तुलन-पत्र के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है जबकि मुद्रा बाजार में धन उगाने से उनके तुलन-पत्र के आकार में वृद्धि होती है। वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से इन दोनों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। सावधि मुद्रा बाजारों की बंदी के कारण वित्तीय संकट के दौरान प्रतिपक्षी ऋण संबंधी चिंताओं से फर्म परिसम्पत्तियों की बिक्री पर निर्भर रहे (तुलन-पत्र का संकुचन)। अंततोगत्वा यह वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल का कारण बना जिसका विस्तार अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था तक हुआ जो वैश्विक मंदी का कारण बना।

5.15 सूचक के प्रयोजन से प्रणालीगत चलनिधि को बैंकिंग क्षेत्र, गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, कॉर्पोरेट क्षेत्र में निधियन चलनिधि परिदृश्य और प्रबल विदेशी मुद्रा चलिनिधि के रूप में परिभाषि किया गया है। निधि की उपलब्धता और भविष्य में उनके दरों से संबंधित अपेक्षाओं से चलनिधि की वर्तमान आवश्यकताएं भी प्रभावित हुईं हैं।

चलनिधि को मापने के लिये बहुविध निर्देशकों को तरजीह दी गयी है

5.16 चलनिधि मापने के क्रम में, यह आवश्यक है कि बहुविध निर्देशक दृष्टिकोण को तरजीह दी जाए जो विभिन्न आयामों से चलनिधि को बेहतर तरीके से ग्रहण करने में सक्षम होगा। एसएलआई जो बाजार में चलनिधि की दशाओं को मापता है, के कई उपयोग हैं। प्रथमत: यह चलनिधि के स्तर को माप कर इसके वर्तमान स्तर का परिमाणात्मक मूल्यांकन

चार्ट 5.5: वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में विश्वास के स्तर में परिवर्तन

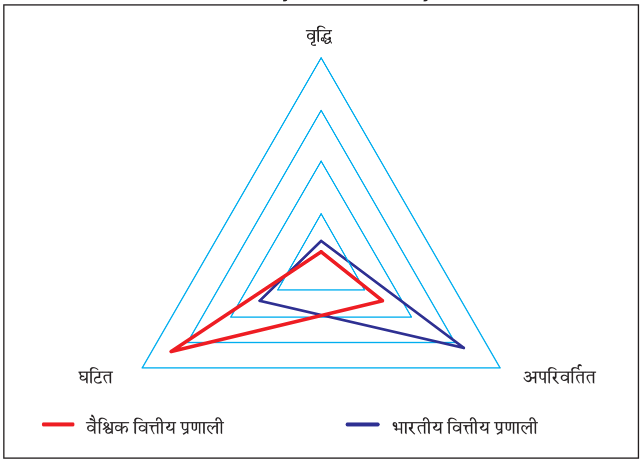

नोट: केंद्र से दूरी उन सहभागियों की संख्या को दर्शाता है जिनका प्रणाली की स्थिरता में विश्वास का स्तर बढ़ा/घटा/अपरिवर्ति रहा।

सारणी 5.2 वैश्विक और देशी वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में विश्वास (प्रतिशत)

में विश्वास	सम्पूर्ण विश्वास	अत्यंत विश्वास	काफी विश्वास	बहुत विश्वास नहीं	विश्वास नहीं
वैश्विक वित्तीय प्रणाली	0	1	45	52	2
भारतीय वित्तीय प्रणाली	0	39	58	3	0

[3] इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में कार्यप्रणाली दी गई है।

प्रदान करता है। द्वितीयत: विगत स्तरों की तुलना में चलनिधि दशाओं में सुधार की तुलना करने में सूचक का समय श्रेणी हमें समर्थ बनाता है।

5.17 एसएलआई बाजार के विभिन्न हिस्सों को दर्शाते हुए निम्नलिखित चार निर्देशकों का उपयोग करता है।

1. भारित औसत मांग दर-आरबीआई रेपो दर

आरबीआई रेपो दर के लिये समायोजित भारित औसत मांग दर बैंकिंग प्रणाली में निधियन संबंधी दबाव के स्तरों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। रिज़र्व बैंक की नीति और इसकी रेपो दर में परिवर्तनों के प्रभाव को खत्म करने के लिये भारित औसत मांग दर को समायोजित किया गया है क्योंकि बाद में इसमें वृद्धि चलनिधि की कठोर दशाओं के स्वत: अंतर्निहित नहीं करता है।

2. 3 माह का वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दर-3 माह का जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दर

वाणिज्यिक क्षेत्र के लिये चलनिधि की दशा को ऋण की राशि, लागत और परिपक्वता अवधि जो बढ़ायी गयी है, के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। एसएलआई वाणिज्यिक क्षेत्र के लिये निधि की लागत के निर्देशक के रूप में सीपी दरों का प्रयोग करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकिंग के साथ-साथ गैर बैंकिंग क्षेत्र के निधियन बाजारों में दबाव को एसएलआई के अंतर्गत शामिल किये जाने की मांग की गई है। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिये लागत में अतिरिक्त वृद्धि को कम करने के लिये बैंकों के निधि की लागत के जरिए सीपी की दर को कम किया गया है।

3. 3 माह का सीडी दर-3 माह का अंतर्निहित जमा दर

एसएलआई निर्देशक के रूप में 3 माह का सीडी दर और 3 माह का वायदा अंतर्निहित जमा दर के बीच के अंतर का भी प्रयोग करता है। इस निर्देशक का प्रयोग करने का कारण है निधियन बाजार की व्याप्ति को बढ़ाना। प्राय: बैंक रुपया निधि को उगाने के लिये एफएक्स स्वैप का प्रयोग करता है। कुछेक बैंक जो 24 प्रतिशत के एसएलआर के अतिरिक्त बड़ी राशि सुरक्षित नहीं रखते हैं वे निधियन के इस स्रोत को उपयुक्त पाते हैं। एफएक्स स्वैप से उन बैंकों को कम चलनिधि एसएलआर प्रतिभूतियों को धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। देशी जमा और विदेशी मुद्रा बाजार अंतर्निहित जमा दर के बीच अंतर विदेशी मुद्रा बाजार आधारित निधियन चलनिधि में दबाव का एक संकेत है।

4. भारित औसत मांग दर-3 माह का ओवरनाईट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) दर

एसएलआई आगे नज़र रखने वाले निर्देशक जैसे 3 माह का ओआईएस दर का प्रयोग करता है जो भविष्य में ओवरनाइट दर की बाजार में अपेक्षा को सांकेतित करता है। उदाहरण के लिये, ओआईएस बाजार नीतिगत दर में कई परवर्ती कटौती के साथ उसकी वृद्धि का मूल्य-निर्धारण कर सकता है। नीतिगत दरों की भावी समय की इस प्रकार की अपेक्षाओं के बारे में अंतरबैंक उधार और ऋण बाजार को ध्यान दिया जाना है। चलनिधि दबाव के समय ओवरनाइट दरें बढ़ जाती है लेकिन अगर ओवरनाइट दरों को संचालित करने वाले कारक स्थाई हों तो दीर्घ काल से संबंधित अपेक्षाएं परिवर्तित नहीं होती है। ओआईएस यिल्ड कर्व का समतल होना या ढालुआं होना चलनिधि की दशाओं और इन धारणाओं कि क्या ये स्थायी है या नहीं, के बारे में स्पष्ट संकेत देता है।

5.18 चार विभिन्न प्रणालियों[4] का प्रयोग करने के पश्चात सूचक तैयार किया गया है और 'मानकसामान्य' और 'अंतर-समान भारित' प्रणाली को अत्यंत उपयुक्त माना गया है। शून्य से ऊपर मूल्य चलनिधि में दबाव के सामान्य स्तरों से ऊपर की ओर संकेत करेगा।

चलनिधि की कमी पर नियंत्रण पाया जा चुका है पर यह स्थिति स्वीकार्य है

5.19 तिमाही अग्रिम कर अदायगी के कारण चलनिधि की कमी से जून 2011 में तंगी देखा गया जो जुलाई 2011 के प्रारम्भ में कम हुआ जिससे केंद्र सरकार की नकदी शेषराशियों और अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) में गिरावट आई। औसत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) इंजेक्शन, जो 2011-12 की प्रथम तिमाही में लगभग रु.49,000 करोड़ था जो 2011-12 की दूसरी तिमाही में गिरकर रु.47,000 करोड़ हो गया। लगभग पांच महिनों के अंतराल के बाद अक्तूबर 2011 के प्रारंभ में एलएएफ आमेलन की पद्धति में चला गया। तथापि, त्यौहार के समय मुद्रा की मांग के कारण संचलित मुद्रा में बढोत्तरी और अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के स्तर में गिरावट के कारण 7 अक्तूबर 2011 से चलनिधि की दशाओं में पुन: कमी आई। एसएलआई इन बातों पर और अन्य निधियन बाजार में संबंधित गतिविधियों पर नज़र रखता है। (चार्ट 5.6)

चार्ट 5.6: प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक

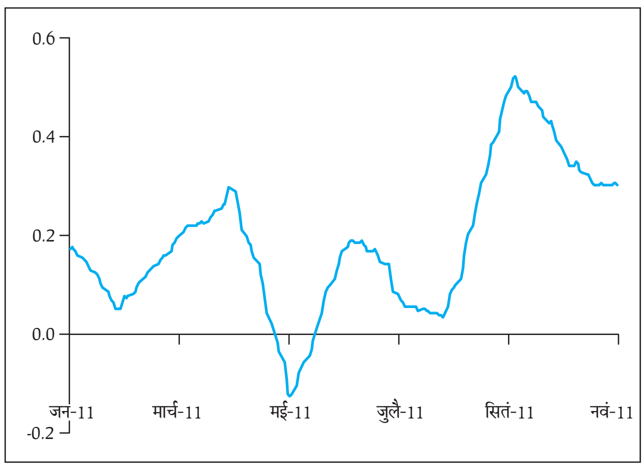

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

[4] मार्क इलिंग और यिंग ल्यू द्वारा रचित मिजरिंग फिनांशियल स्ट्रेस इन ए डेवलप्ड कंट्री: एन एप्लिकेशन टू कनाडा (2006)।

नेटवर्क विश्लेषण[5]

5.20 बैंकिंग प्रणाली में अंतर्संबंध को आंकने और संभाव्य संबंध से उत्पन्न जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिये भारतीय बैंकिंग प्रणाली का किया गया नेटवर्क विश्लेषण के परिणामों को पिछले एफएसआर में प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली में अंतर्सम्बन्ध का मूल्यांकन करने और बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय प्रणाली के नेटवर्क की प्रकृति में आगे की जांच के लिये इस विश्लेषण को आगे ले जाया गया। इसका उद्देश्य इस निहितार्थ को उद्घाटित करना है कि नेटवर्क की संरचना प्रणाली में स्थिरता और प्रणाली में एक या अधिक विभिन्न कंपनियों के आकस्मिक विफलता से हुई भेद्यता के लिये है। नेटवर्क की संरचना में परिवर्तनों की निरंतर निगरानी से मैक्रोप्रूडेंशियल सर्विलेंस[6] के लिये टूलकिट का एक क्रिटिकल भाग तैयार होता है।

अंतरबैंक के बाजार में तेज आयी लेकिन विदेशी बैंकों के क्रियाकलपों में तेजी से गिरावट आयी

5.21 सितम्बर 2010 से एक साल में अंतरबैंक के बाजार में 20 प्रतिशत से भी अधिक की तेजी आयी (चार्ट 5.7 और 5.8)। तथापि बाजार की प्रकृति में विशेषकर बाजार के विभिन्न भागों के क्रियाकलापों के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विदेशी बैंकों द्वारा ऋण लेने और देने की मात्रा में तेजी से गिरावट आई जबकि अन्य भागों में वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा अंतरबैंक ऋण लेने की मात्रा में वृद्धि उनके अंतरबैंक ऋण देने की मात्रा में वृद्धि से काफी अधिक था।

...परिणामस्वरूप बाजार में उनका हिस्सा गिरे

5.22 सितम्बर 2010 और सितम्बर 2011 के बीच सम्पूर्ण अंतरबैंक ऋण देने और लेने के क्रियाकलाप में विदेशी बैंकों का हिस्सा तेजी से गिरा जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयर में बढोत्तरी आई। निजी क्षेत्र के पुराने और नये दोनों बैंकों के हिस्सा में केवल नाममात्र की वृद्धि हुई (चार्ट 5.9 और 5.10)।

चार्ट 5.7: अंतरबैंक बाजार में बैंक समूह वार क्रियाकलाप

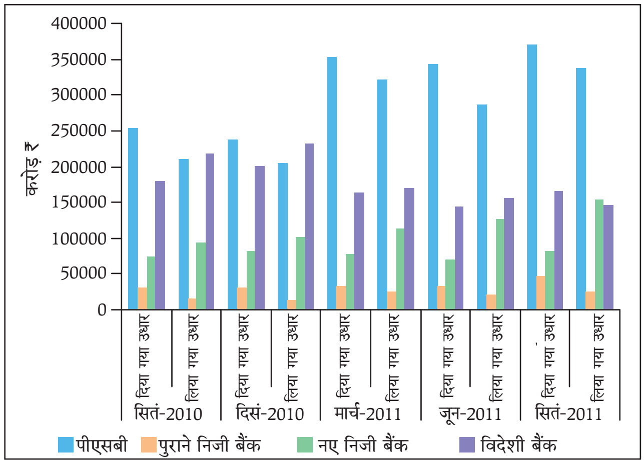

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.8: पिछले एक साल के क्रियाकलाप में प्रतिशत में बदलाव

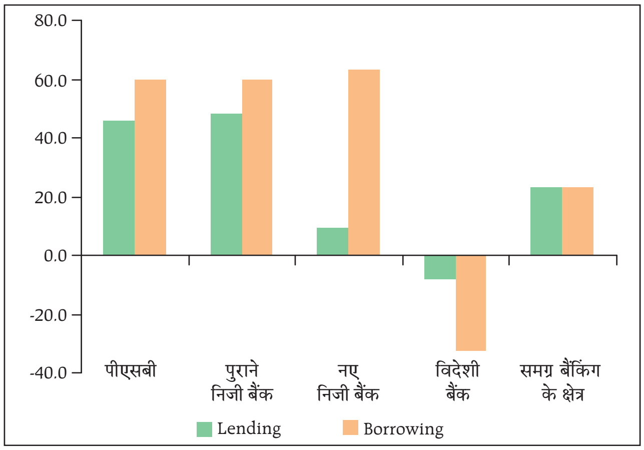

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.9: अंतरबैंक बाजार शेयर : सितम्बर 2010

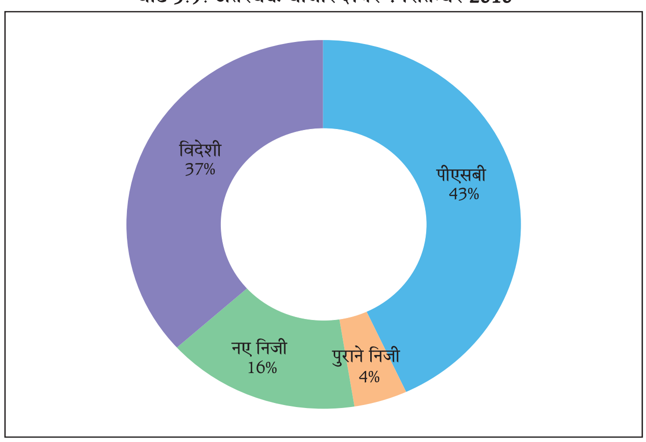

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

[5] विभिन्न तारीखों को नेटवर्क विश्लेषण बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, बीमा कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और शहरी सहकारी बैंकों के बीच द्विपक्षीय निधि आधारित और गैर निधि आधारित जोखिमों से संबंधित आंकड़े के आधार पर किया गया है। जहां एक केंद्रीय प्रतिपक्षी के जरिए निपटान होता है वहां लेनदेन का हिसाब नहीं रखा गया है।

[6] विश्लेषण में व्यवहृत नेटवर्क पद्धति को वित्तीय स्थिरता यूनिट, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से प्रोफेसर शेरी मार्कोज़ (यूनिवर्सिटी ऑफ एस्सेक्स) और डॉ. सिमोन जियनसांटे (बेथ यूनिवर्सिटी) द्वारा विकसित किया गया है।

चार्ट 5.10: अंतरबैंक बाजार शेयर: सितम्बर 2011

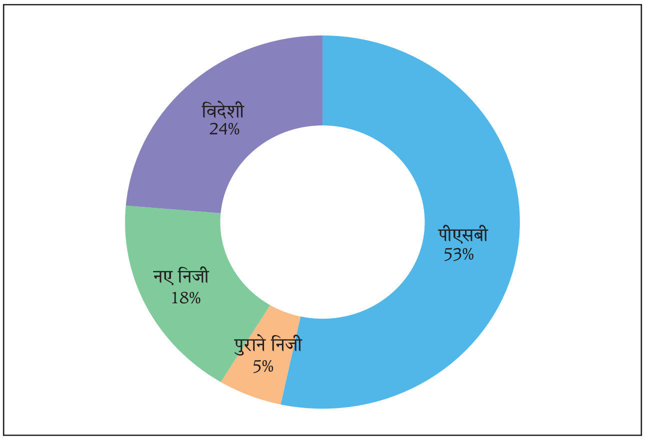

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

भारतीय अंतरबैंक नेटवर्क समूह में आबद्ध है और स्पष्ट रूप से एक क्रमिक वर्ग में है...

5.23 पिछले एफएसआर में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को काफी सम्बद्ध और समूह में आबद्ध पाया गया। पिछले एक साल में बैंकिंग प्रणाली में समूह सह-गुणांक और सम्बद्धता अनुपात क्रमश: 42 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से अधिक रहा जो प्रणाली में एक उच्च स्तर की अंतरसम्बद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त विश्व के अधिकतम अंतरबैंक और अंतर-वित्तीय प्रणालियों की तरह इस प्रणाली का नेटवर्क भी एक स्पष्ट टियर्ड संरचना भी प्रदर्शित करता है (बॉक्स 5.1) जो काफी समय तक स्थायी रहा (चार्ट 5.11 से 5.13 तक)।

.... नेटवर्क की स्थिरता की मंशा से यद्यपि अंतरबैंक जोखिमों पर विनियमकारी सीमाएं कंटेजियन जोखिम का नियंत्रित करता है

5.24 एक टियर्ड नेटवर्क संरचना में वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ है। आंतरिक कोर में एक बैंक की विफलता से प्रणाली में कंटेजियन हानि एक कम टियर्ड नेटवर्क में बैंक की विफलता से उत्पन्न हानि की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तथापि अंतरबैंक जोखिमों में विनियमकारी सीमाएं इस प्रकार के कंटेजियन हानि को नियंत्रित करता है जैसा कि पिछ्ले एफएसआर चर्चा की गयी।

अंतरबैंक व्युत्पन्नी बाजार में भी टियर्ड नेटवर्क संरचना का पालन किया गया

5.25 विदेशी बैंक होने के नाते इस बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी के साथ अंतर-बैंक व्युत्पन्नी बाजार का नेटवर्क एक स्पष्ट और स्थायी टियर्ड संरचना को भी दर्शाता है (चार्ट 5.14 और 5.15)। इस रिपोर्ट के अध्याय IV में विस्तृत विवरण के साथ इसपर चर्चा की गयी है।

चार्ट 5.11: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (सितंबर 2010)

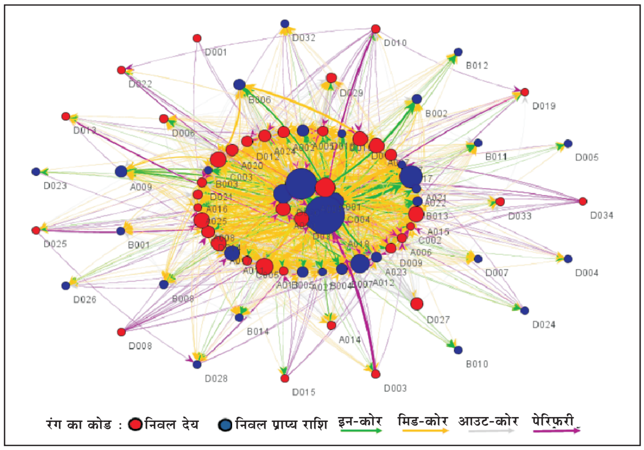

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.12: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (मार्च 2011)

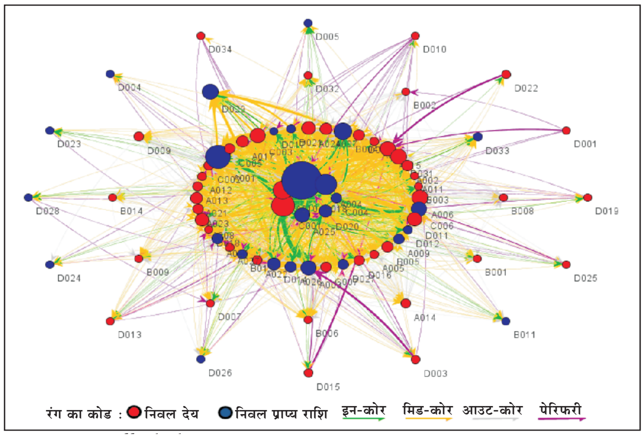

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.13: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (सितंबर 2011)

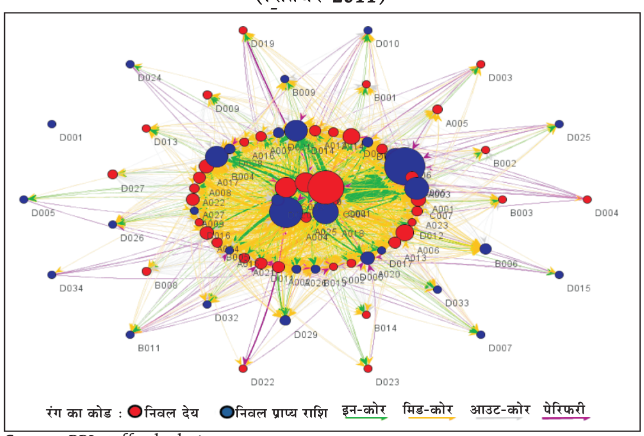

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

बॉक्स 5.1: नेटवर्क विश्लेषण अवधारणाएं

जैसा कि पिछले एफएसआर में चर्चा की गयी कि नेटवर्क विश्लेषण-वित्तीय क्षेत्र में कंपनियों के बीच द्विपक्षीय जोखिमों का एक विश्लेषण-के मूल में मैट्रिक्स बीजगणित है। प्रत्येक संस्था के ऋण लेने और देने के साथ-साथ प्रणाली में सभी अन्य आंकड़े को एक वर्गाकार मैट्रिक्स में आलेखित कर एक नेटवर्क ग्राफ में तैयार किया जाता है। ग्राफ में कटान-बिंदु (गोले) संस्थानों या कंपनियों को दर्शाते है जिसमें लाल गोले प्रणाली में निवल उधारकर्ताओं और नीले गोले निवल उधारदाताओं को दर्शाते हैं। कटान-बिन्दुओं के बीच कड़ियां (तीर के रूप में) किसी भी दो कटान-बिन्दुओं के बीच निवल जोखिम को दर्शाते हैं। प्रणाली में प्रत्येक कटान-बिन्दु या कंपनी एक या अधिक कंपनी/कंपनियों से जुड़ी है। यदि कोई कटान-बिंदु किसी निवल उधारदाता को दर्शाता है तो कड़ी को आवक दिशा में एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है (जिसे इन डिग्री कहा जाता है) जबकि यह किसी निवल उधारकर्ता को दर्शाता है तो कड़ी को जावक दिशा में एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है (जिसे आउट डिग्री कहा जाता है)। कटान-बिन्दुओं के आकार प्रणाली में कंपनी की निवल बकाया स्थिति को दर्शाता है। प्रत्येक कड़ी की मोटाई को कड़ी द्वारा जुड़े दो कंपनियों के बीच निवल स्थिति के अनुसार भारित किया जाता है।

तत्पश्चात प्रणाली में मौजूद क्रियाकलाप और अंतर्संबंद्धता के स्तर को मापने के लिये सांख्यिकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से मुख्य हैं क) सम्बद्धता का मापन; ख) समूह सह-गुणांक; और ग) केंद्रीयता का एजेनवेक्टर मापन।

क) सम्बद्धता का मापन: यह एक सांख्यिकी है जो एक सम्पूर्ण ग्राफ में सभी सम्भाव्य कड़ियों के सम्बंधित कटान-बिंदुओं के बीच कड़ियों की सीमा को मापता है। दिये गये ग्राफ में जहां कुल आउट डिग्रियों की संख्या बराबर है $K = \sum_{i=1}^{N} k_i$ और N कटान-बिंदुओं की कुल संख्या के बराबर है तो निटवर्क का कनेक्टिविटी इस प्रकार होगा $\frac{K}{N(N-1)}$।

ख) समूह सह-गुणांक: नेटवर्कों समूहन यह मापता है कि कैसे प्रत्येक कटान-बिंदु अंतर्सम्बंधित है। विशिष्ट तौर पर इसकी सम्भावना अधिक होनी चाहिए कि एक कटान-बिंदु के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंकों के प्रतिपक्षी) एक-दूसरे के भी पड़ोसी है। नेटवर्क के लिये एक उच्च समूहन सह-गुणांक प्रणाली में प्रचलित उच्च अंतर्सम्बद्धता से तादाम्य स्थापित करता है।

ग) केंद्रीयता का एजेनवेक्टर मापन: एजेनवेक्टर केंद्रीयता नेटवर्क में एक कटान-बिंदु (बैंक) के महत्व का मापन है। यह वर्णित करता है कि कैसे एक कटान-बिंदु के पड़ोसी सम्बद्ध हैं और एक कटान-बिंदु के पास स्थित प्रत्यक्ष 'पड़ोसी' या आउट डिग्रियों की संख्या से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करता है।

टियर्ड नेटवर्क संरचना

विशेष तौर पर, वित्तीय नेटवर्क एक टियर्ड संरचना प्रदर्शित करने के लिये प्रवृत होता है। साधारण तौर पर कहा जाए तो टियर्ड संरचना वह है जहां विभिन्न संस्थानों के पास नेटवर्क में अन्य के साथ सम्बद्धता के विभिन्न डिग्रियां या स्तर हैं। वर्तमान विश्लेषण में, अधिकांश सम्बद्ध बैंक (उनके एजेनवेक्टर केंद्रीयता के आधार पर) अत्यधिक आंतरिक कोर में हैं (5.11 से 5.13 तक की चार्ट में नेटवर्क आरेख के केंद्र में)। तत्पश्चात बैंकों को उनके संबंधित सम्बद्धता के स्तर के आधार पर मध्य कोर, बाहरी कोर और परिधि (आरेखों में केंद्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रित वृत्त) में रखा जाता है। बैंको की सम्बद्धता की सीमा को अत्यधिक सम्बद्ध बैंक द्वारा विभक्त प्रत्येक बैंक के इन डिग्री और आउट डिग्री के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। जिन बैंकों ने इस अनुपात के उच्च 10 शतमक में स्थान पाया है वे आंतरिक कोर में आते हैं। इसी प्रकार 90 और 70 शतमक के बीच स्थान पाने वाले बैंक मध्य कोर और 40 और 70 शतमक के बीच स्थान पाने वाले बैंक को तीसरे टियर में रखा गया है। 40 प्रतिशत से कम के सम्बद्धता अनुपात वाले बैंकों को परिधि की श्रेणी में रखा गया है।

टियर्ड नेटवर्क संरचना में कड़ियों की रंग-पद्धति नेटवर्क में विभिन्न टियरों से उधार को दर्शाता है (उदाहरणस्वरूप, हरे रंग की कड़ियां आंतरिक कोर में बैंकों से उधारराशियों को दर्शाता है)। नेटवर्क आरेख देश में टियर्ड अंतरबैंक नेटवर्क की विलक्षण विशेषताओं को दर्शाता है। बैंकों के बीच अधिकांश क्रियाकलाप आंतरिक कोर और मध्य कोर में होता है। ये बैंक एक दूसरे से घनिष्ट रूप से जुड़े होते है। दूसरी ओर, परिधि में स्थित बैंक आंतरिक और मध्य कोर में बैंकों के साथ सम्बद्ध है लेकिन इनमें परिधि में स्थित अन्य बैंकों के प्रति जोखिम सीमित है।

टियर्ड संरचना में वित्तीय स्थिरता के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। टियर्ड नेटवर्क की तरह अधिक संकेंद्रित नेटवर्क विशेष तौर पर कम स्थिर होते है। एक टियर्ड नेटवर्क संरचना का अर्थ है कि आंतरिक कोर और मध्य कोर में किसी भी बैंक की विफलता का कंटेजियन प्रभाव अधिक सम्पूर्ण और कम संकेंद्रित नेटवर्क की तुलना में अधिक गम्भीर होगा।

चार्ट 5.14: व्युत्पन्नी बाजार में शेयर (₹ करोड़ में)

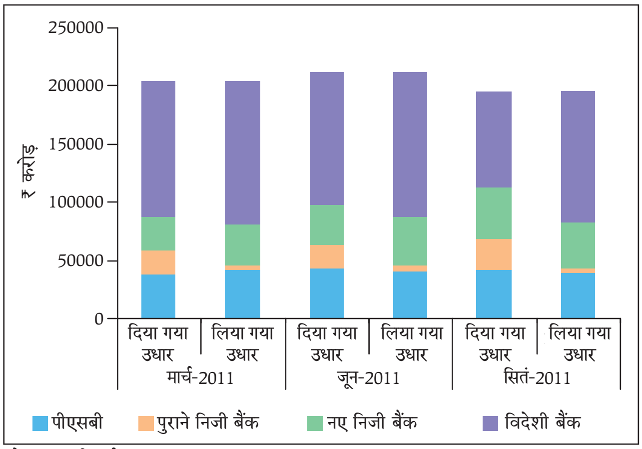

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.15: व्युत्पन्नी नेटवर्क-सितंबर 2011

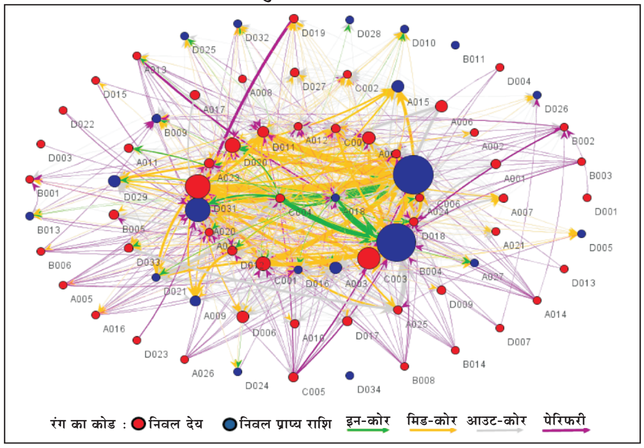

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

पिछले साल सम्भाव्य कंटेजियन हानियों में वृद्धि हुई जो बड़े उधारकर्ताओं के उच्च प्रणालीगत महत्व को दर्शाते है

5.26 एक या अधिक बैंकों के आकस्मिक विफलता के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिये व्यवहृत कंटेजियन साधन को पिछले एफएसआर में प्रस्तुत किया गया है। शीर्ष के पांच उधारकर्ताओं (एक समय में एक ही) की विफलता से प्रणाली में हुए कंटेजियन हानि का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इन पांच बैंकों में से तीन बैंकों की विफलता से बैंकिंग प्रणाली की पूंजी पर आघात पहुंचा जिसकी प्रतिशतता पिछले एक साल में बढ़ी। यह प्रणाली में एक बड़ी अंतर्सम्बद्धता का संकेतक है और यह भी कि बड़े उधारकर्ताओं के प्रणालीगत महत्व में वृद्धि हुई है (सारणी 5.3)।[7]

सारणी 5.3: शीर्ष के पांच निवल उधारकर्ताओं की विफलता के कारण कुल पूंजीगत हानि (बैंकिंग प्रणाली पूंजी की प्रतिशतता के रूप में)

	सितम्बर 2010	मार्च 2011	सितंबर 2011
बैंक 1	7.9	11.7	14.8
बैंक 2	4.2	8.5	7.6
बैंक 3	4.0	4.9	6.4
बैंक 4	3.8	4.7	6.1
बैंक 5	3.5	3.6	2.2

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

समग्र वित्तीय प्रणाली का मानचित्रण .... बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड चलनिधि प्रदाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रमुख उधारकर्ता ....

समग्र वित्तीय प्रणाली (चुनिंदा बीमा कंपनियों, परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शहरी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित) का नेटवर्क भी टियर्ड है और खासकर वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग, बीमा, और म्यूचुअल फंड भागों के बीच गहरी अंतर्सम्बद्धता स्थापित करता है। जब सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली का मानचित्र बनाया जाता है तो प्रणाली में अधिकांश चलनिधि प्रदाता (अर्थात अधिकांश निवल उधारदाता) बीमा कंपनियां और परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनियां (एएमसी)

[7] ऊपर की गई चर्चा के अनुसार प्रत्येक तारीख को पाचं बैंक उस विशेष तारीख को पांच शीर्ष निवल उधारकर्ता है।

हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक (जो अंतरबैंक नेटवर्क में बड़े निवल उधारदाता हैं) सभी उधार राशि के 50 प्रतिशत का लेखांकन करते हुए प्रणाली में बड़े निवल उधारकर्ता के रूप में उभरते हैं (सारणी 5.4 और चार्ट 5.16 और चार्ट 5.17)।

. . . बैंकिंग प्रणाली में किसी भी व्यवधान के प्रति चलनिधि प्रदाताओं को कमजोर रखना

5.28 वित्तीय प्रणाली में अंतरसंबद्धता के परिमाण (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई) का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि प्रणाली में एक या इससे अधिक बड़े निवल उधारकर्ताओं की यादृच्छिक विफलता से पूरी वित्तीय प्रणाली में होने वाली संभावित संक्रामण क्षति, केवल बैंकिंग प्रणाली पर होने वाले नुकसान की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक होगी। विशेष रूप से, वित्तीय प्रणाली के बीमा और म्यूचुअल फंड संबंधी क्षेत्र से अत्यधिक उधार वाले बैंक की यादृच्छिक विफलता का प्रभाव पूरी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे किसी एक बड़े उधारकर्ता (चार्ट 5.18) की विफलता का संक्रमण विश्लेषण अनुरुपता से तीन बीमा कंपनियों सहित दूसरे दस संस्थानों के लिए संकट हो सकता है।[8]

सारणी 5.4 अंतर सेक्टर एक्सपोज़र

रु. करोडों में	मार्च 2011		जून 2011	
	दिया गया उधार	लिया गया उधार	दिया गया उधार	लिया गया उधार
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	396080	639731	409427	574048
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	38744	40675	36862	42767
निजी क्षेत्र के नए बैंक	115747	218894	108224	236468
विदेशी बैंक	178695	173640	155829	170525
शहरी सहकारी बैंक	4286	1782	5514	1832
वित्तीय संस्थान	68238	55104	70587	47385
आस्ति प्रबंधन कंपनियां	126576	15377	141011	26785
बीमा कंपनियां	261692	4706	207620	4531
एनबीएफसी	59719	99870	60813	91548
कुल	1249778	1249778	1195888	1195888

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.17: वित्तीय प्रणाली की नेटवर्क संरचना

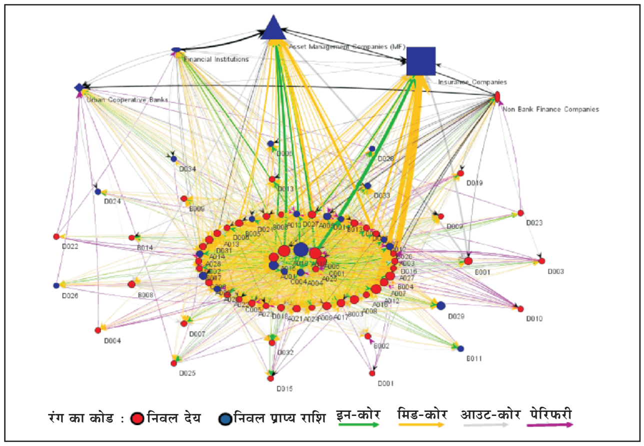

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.16: भारतीय वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क

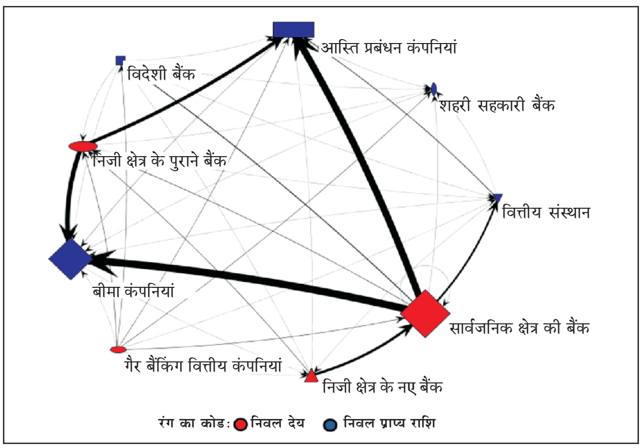

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.18: सबसे बड़े निवल उधारकर्ता बैंक की विफलता के कारण संक्रमण[9]

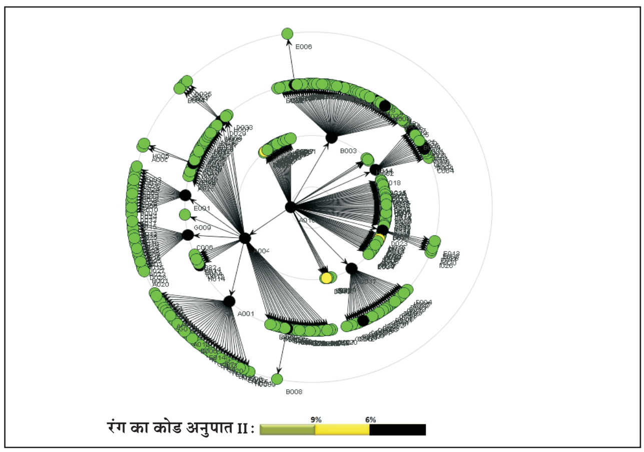

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

[8] बैंकों और एनबीएफसी के लिए संकट स्थितियां उनके पूँजी पर्याप्तता अनुपात के आधार पर परिभाषित की गई हैं जबकि बीमा कंपनियों के लिए यह ऋणशोधन क्षमता अनुपात पर आधारित है।

[9] रंग कोड:
ट्रिगर और संकटग्रस्त संस्थान : काला;
संस्थान जो प्रभावित हैं लेकिन संकटग्रस्त नहीं है:
(i) हरा: संस्थान जो ट्रिगर/संकटग्रस्त संस्थानों की विफलता से प्रभावित हैं लेकिन आघात को सहने में सक्षम नहीं हैं।
(ii) पीला: बैंक जो ट्रिगर/संकटग्रस्त बैंकों की विफलता से प्रभावित हैं और जिनकी पूँजी पर्याप्तता 9 प्रतिशत से कम हो लेकिन स्थायी पूँजी अनुपात 6 प्रतिशत से ऊपर रहे।

बैंकिंग स्थिरता संबंधी उपाय और प्रत्याशित कमियों का आकलन

5.29 संकट काल के दौरान, बैंकों की संपत्तियों में आमतौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लिंकों के माध्यम से साथ-साथ गिरावट आई जिसमें बाज़ार मूल्य के अनुरूप संपत्ति मूल्य, अंतर बैंक उधार और सूचना असमितियां शामिल हैं। इस खंड में, बैंकों के बीच संकट निर्भरता संबंधी प्रतिरूपण परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, वित्तीय प्रणाली की संकल्पना बैंकों के एक विशिष्ट समूह के पोर्टफोलियो के रूप में की गई है (सेगोवियानो और गुडहार्ट 2009)। विशेष रूप से, बैंकों के पोर्टफोलियो के व्यक्तिगत और संयुक्त, दोनों ही संपत्ति मूल्य संचालनों की विशेषताओं को दर्शाने वाली बैंकिंग प्रणाली का पोर्टफोलियो मल्टीवेरिएट सघनता (बीएसएमडी)[10] की वसूली विश्लेषणाधीन बैंकों की संकट से लाभप्रदता (पीओडी) से हुई है। पीओडी को आनुभविक रूप से बैंक के दैनिक इक्विटी मूल्य लाभ के 99.5 प्रतिशत जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के आधार पर देखा गया है।

प्रणाली में सामान्य संकट : जेपीओडी और बीएसआई

5.30 संकट की संयुक्त संभाव्यता (जेपीओडी) द्वारा यथा मापित सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली के संकट की संभाव्यता को हाल के दिनों में अत्यंत कम देखा गया है। बैंकिंग प्रणाली में सामान्य संकट का दूसरा उपाय बैंकिंग स्थिरता सूचकांक (बीएसआई) (जो ऐसे बैंकों की प्रत्याशित संख्या की गणना करता है जो संकटग्रस्त होंगे, यह मानते हुए कि कम-से-कम एक संकटग्रस्त होता है) है। अप्रैल 2010 से बीएसआई एक के आसपास रहा है जिसका तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में फिलहाल अंतर-निर्भरता अत्यंत कमजोर स्थिति में है। तथापि, यह भी देखा गया है कि पिछले वर्ष के दौरान समान रहने वाला बीएसआई चालू वर्ष में पुन: आंशिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ता दिखने लगा है (चार्ट 5.19)।

विशिष्ट बैंकों के बीच संकट: टॉक्सीसिटी और भेद्यता सूचकांक

5.31 विशिष्ट बैंकों के बीच संकट को टॉक्सीसिटी सूचकांक (टीआई) और भेद्यता सूचकांक (वीआई) के आधार पर मापा जाता है। टीआई ऐसी औसत लाभप्रदता है जितना कोई संकटाधीन बैंक प्रणाली में किसी दूसरे बैंक के लिए संकट का कारण बन सकता है। संकट के दौरान बैंकों की विषाक्तता 60 प्रतिशत पंजीकृत की गई थी जो अब महत्वपूर्ण रूप से घटकर हाल की अवधि में 5 प्रतिशत हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2011 के पहले अर्धवर्ष में आंशिक रूप से बढ़ोतरी दिखाने वाला टीआई अगस्त 2011 से नीचे का रूझान दिखा रहा है (चार्ट 5.20)।

चार्ट 5.19 : जेपीओडी और बीएसआई का संचलन

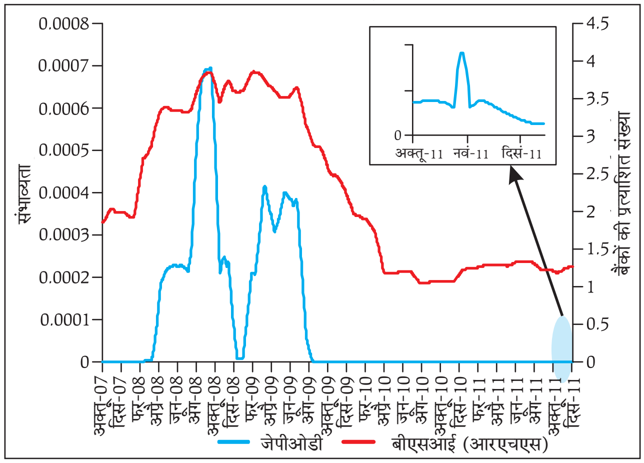

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.20 : टॉक्सीसिटी सूचकांक का संचलन : चुने हुए बैंक

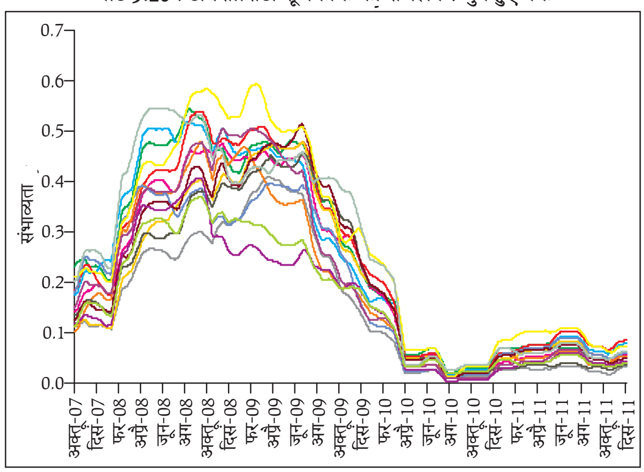

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

[10] जून 2011 के एफएसआर में जानकारी उपलब्ध है।

5.32 प्रणाली में दूसरे बैंकों को संकट देने वाले बैंक की भेद्यता की मात्रा निर्धारित करने वाला भेद्यता सूचकांक, 2007-09 के वित्तीय संकट के दौरान उच्च था। संकट के दौरान उच्चतम संभाव्यता लगभग 30 प्रतिशत थी जिसमें काफी हद तक गिरावट आई और जून 2010 से यह शून्य के बिल्कुल आसपास है। हाल में, भेद्यता सूचकांक आंशिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ता दिखा है (चार्ट 5.21)।

प्रणाली में किसी बैंक विशेष में संकट से जुड़ा हुआ संकट : प्रपाती प्रभाव

5.33 प्रणाली में किसी बैंक विशेष के संकट से जुड़ा हुआ संकट इस संभावना का प्रतिनिधित्व करता है कि सम्पूर्ण प्रणाली संकटग्रस्त हो जाती है जो प्रणालीगत महत्व और बैंक विशेष के संकट का 'डोमिनो' प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोगी है। वर्तमान में, पूरी बैंकिंग प्रणाली की विफलता के लिए डोमिनो प्रभाव अत्यंत निम्न है (चार्ट 5.22)।

प्रत्याशित कमियां

5.34 बैंकिंग प्रणाली की प्रत्याशित कमियों (यानी चरम हानि क्षेत्र में आस्तियों की अनुमानित हानि) में हाल की अवधि में गिरावट देखी जा रही है। यह मार्च 2009 में बैंकिंग प्रणाली में कुल आस्तियों का लगभग 6.6 प्रतिशत था जिसका दिसम्बर 2011 में केवल1.8 प्रतिशत हो जाना स्पष्ट करता है कि बैंकिंग प्रणाली चरम प्रणालीगत हानियों को झेलने में सक्षम होगा जैसा कि मॉडल से व्युत्पन्न होता है (चार्ट 5.23)।

चार्ट 5.21 : भेद्यता सूचकांक का संचलन : चुने हुए बैंक

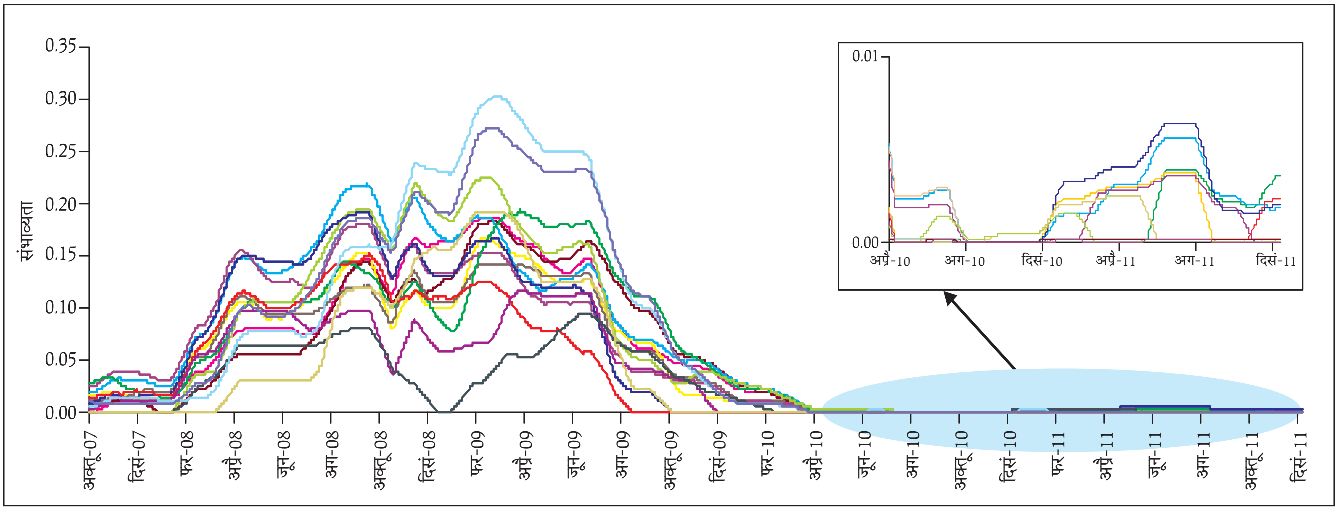

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 5.22 : प्रपाती प्रभाव का संचलन : चुने हुए बैंक

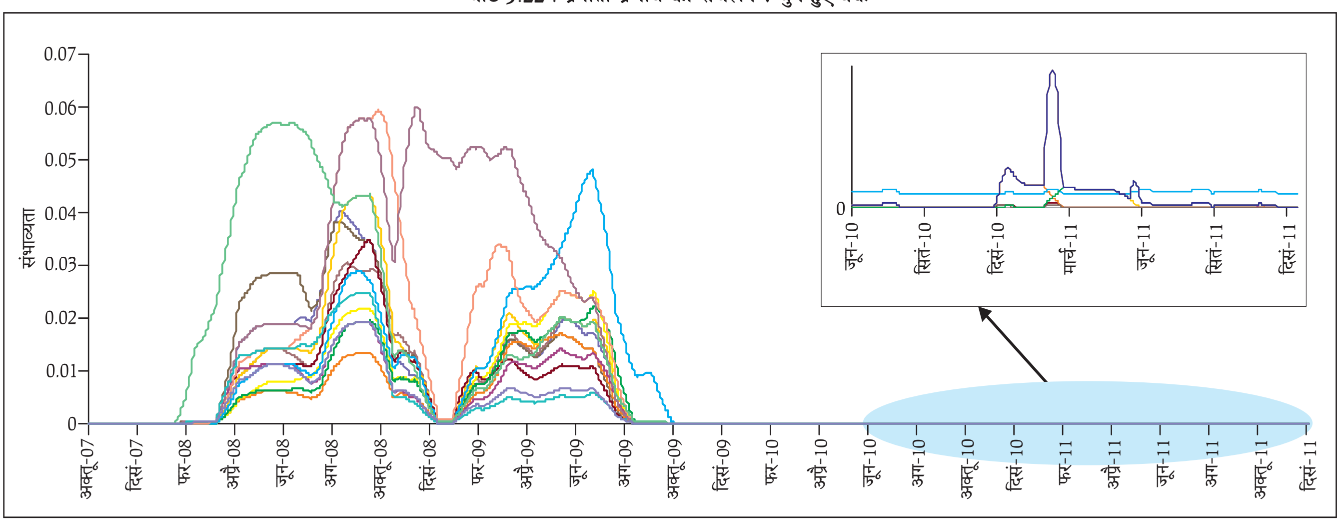

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

समष्टिगत वित्तीय दबाव परीक्षण

5.35 समष्टिगत परीक्षण कार्यकलापों के दो सेट निष्पादित किए गए थे- इनमें से एक बहुविधअंतर प्रतिगमन (मल्टीवैरिएट रिग्रेशन) पर आधारित था और दूसरा वेक्टर स्वत: प्रतिगमन (वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव) (वीएआर) मॉडल पर आधारित था। इसमें पहले क्रमवाला सेट बैंकिंग प्रणाली के पूंजी और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) अनुपात पर किसी विशिष्ट समष्टि आर्थिक वेरिएबल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा सेट फीडबैंक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्रीय चरों के प्रभाव को विभिन्न परंतु पूरक दृष्टिकोणों से समझने के लिए प्रणालीगत जोखिम के प्रभाव को अनेक प्रकार के मॉडलों के जरिए आंका जाता है।

दबाव के परिदृश्य

5.36 समष्टिगत दबाव परीक्षणों में एक आधार-रेखा और तीन प्रतिकूल व्यापक आर्थिक परिदृश्यों का इस्तेमाल किया जाता है जो इस प्रकार हैं - कम जोखिम, मध्यम जोखिम और गंभीर जोखिम (सारणी 5.5), इसके लिए अनुमान तिमाही 2-वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के आंकड़ों पर आधारित थे। ये विशिष्ट उतार-चढ़ाव ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर मानकीकृत किए गए थे।

अर्थमितीय मॉडल की श्रृंखला का उपयोग करते हुए ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) का मॉडल बनाना

5.37 ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) समष्टिगत दबाव परीक्षणों के लिए मुख्य लक्षित क्षेत्रों में से एक था। ऋण जोखिम दबाव परीक्षण अनेक अर्थमितीय मॉडलों[11] का उपयोग कर डिजाइन किए गए हैं, जो बैंकिंग प्रणाली की समग्रताओं को व्यापक आर्थिक चरों से संबद्ध करते हैं, जैसे (i) समग्र प्रणालीगत एनपीए आंकड़ों पर बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) लॉगिट प्रतिगमन, (ii) स्लिपेज अनुपात (नये एनपीए का आगम) के संदर्भ में बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) प्रतिगमन; (iii) स्लिपेज अनुपात का उपयोग करते हुए समग्र वीएआर; (ऑटोरिग्रेसिव स्वत: प्रतिगमन/वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव); (iv) बैंकवार स्लिपेज अनुपात आंकड़ों पर बहुविधअंतर पैनल प्रतिगमन, जो बाद में बैंक समूहों के आधार पर एकत्रित किए गए थे: और (v) समग्र क्षेत्रगत एनपीए के लिए बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) प्रतिगमन। बैंकिंग प्रणाली के समग्रों में समग्र एनपीए (एनपीए अनुपात) और नये एनपीए का आगम (स्लिपेज अनुपात) के वर्तमान और पूर्ववर्ती मूल्य शामिल हैं जबकि समष्टिगत आर्थिक चरों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर, अल्पावधि ब्याज दर (कॉल दर), थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रति निर्यात का अनुपात शामिल हैं। उक्त तालिका से जोखिम परिदृश्यों का निर्माण किया गया है जिसके तहत प्रमुख समष्टिगत आर्थिक मापदंडों में विशिष्ट उतार-चढ़ाव साथ- साथ आते हैं। दबावों का परीक्षण बैंकों के घरेलू परिचालनों से संबंधित असमेकित तुलन पत्र आंकड़ों पर किया गया था।

5.38 दबाव परीक्षण मॉडल जून 2001 से सितंबर 2011 तिमाही के आंकड़ों पर आधारित थे। समग्र बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) और बैंकवार पैनल

चार्ट 5.23: अनुमानित कमी: प्रणालीगत स्तर

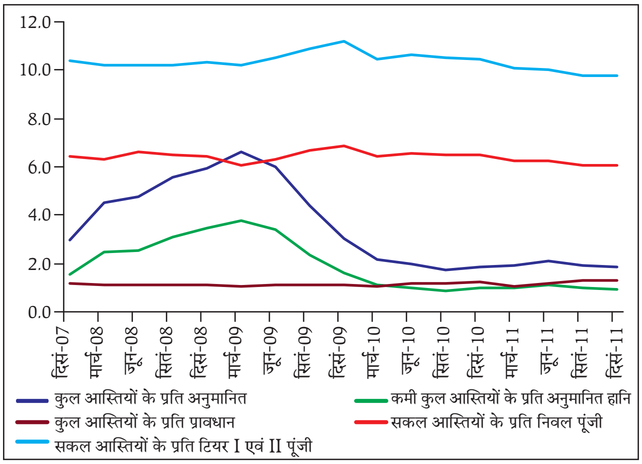

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

सारणी 5.5: समष्टिगत अर्थशास्त्रीय प्राक्कलन

(प्रतिशत)

	दिसं-11	मार्च-12	मार्च-13
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर*			
बेसलाइन	7.5	7.5	7.9
कम जोखिम	7.0	7.0	7.4
मध्यम जोखिम	4.5	4.5	4.9
गंभीर जोखिम	3.5	3.5	3.9
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर			
बेसलाइन	7.7	7.4	6.2
कम जोखिम	8.7	8.4	7.2
मध्यम जोखिम	9.2	8.9	7.7
गंभीर जोखिम	9.7	9.4	8.2
अल्पकालिक ब्याज (कॉल) दर			
बेसलाइन	8.5	8.4	8.2
कम जोखिम	10.0	9.9	9.7
मध्यम जोखिम	11.0	10.9	10.7
गंभीर जोखिम	12.0	11.9	11.7
निर्यात / सकल घरेलू उत्पाद अनुपात			
बेसलाइन	16.1	16.3	17.6
कम जोखिम	15.1	15.3	16.6
मध्यम जोखिम	14.6	14.8	16.1
गंभीर जोखिम	14.1	14.3	15.6

* बाजार मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
समष्टिगत अर्थशास्त्रीय विशिष्ट उतार-चढ़ाव तिमाही 3 :वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए माने गए हैं।

[11] यह कार्यप्रणाली इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गई है।

प्रतिगमन के लिए, साथ ही वीएआर (ऑटोरिग्रेसिव स्वत: प्रतिगमन/वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव) के लिए आधारगत चर, स्लिपेज अनुपात (नए एनपीए का आगम) था, जबकि लॉगिट प्रतिगमन और क्षेत्रीय आंकड़ों के लिए एनपीए अनुपात आधारगत वेरिएबल के रूप में था।

प्रणालीगत स्तर पर क्रेडिट जोखिम परीक्षण: जब अनुमानित एनपीए बढ़ जाता है, सीआरएआर पर प्रभाव नियंत्रित हो।

5.39 समग्र क्रेडिट जोखिम प्रक्रिया के परिणाम, संभावित प्रभावों के लिए व्यापक संकेत प्रदान करते हैं। विभिन्न मॉडलों के माध्यम से सकल एनपीए अनुपात के अनुमान (सारणी 5.6) दर्शाते हैं कि समग्र बैंकिंग प्रणाली सकल एनपीए अनुपात, जो विभिन्न मॉडलों के जरिए लगाए गए अनुमान के अंतर्गत बेसलाईन परिदृश्य के तहत मार्च 2013 तक 3.2 प्रतिशत से 3.5 के बीच होने की उम्मीद है, वह गंभीर जोखिम परिदृश्य के तहत 4.7 प्रतिशत से लेकर 5.8 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बढ़ सकते हैं। वीएआर (ऑटोरिग्रेसिव स्वत: प्रतिगमन /वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव) पर आधारित एनपीए का अनुमानित स्तर, बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) प्रतिगमन के आधार किए गए अनुमानों के स्तर से अधिक है, क्योंकि वीएआर मॉडल फीडबैंक प्रभाव को भी शामिल करते हैं, तथा इसके अलावा छह तिमाहियों की स्थिति के लिए प्रारंभिक विशिष्ट उतार-चढ़ाव प्रणाली में बना रहेगा, जबकि बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) प्रतिगमन में ऐसा नहीं होता, बल्कि वह क्रमिक रूप से विलुप्त हो जाता है। हालांकि, सीआरएआर पर प्रभाव नियंत्रित रहता है (सारणी 5.7)।

बैंकों के समूह स्तर पर क्रेडिट जोखिम: विदेशी बैंक सबसे अधिक प्रभावित है, लेकिन सीआरएआर सुदृढ़ है।

5.40 जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव बैंक के समूहों के आधार पर अलग-अलग होता है। एनपीए पर अधिकतम प्रभाव विदेशी बैंकों पर देखा जाता है क्योंकि उनके वाणिज्यिक ऋण अपेक्षाकृत छोटे और कम होते हैं। इन बैंकों की बेसलाईन में एनपीए में बड़ा अंतर आ जाता है और अन्य बैंक समूह (सारणी 5.8) की तुलना में इनके संबंध में गंभीर जोखिम परिदृश्य निर्मित हो जाते हैं।

5.41 सीआरएआर में परिवर्तन के द्वारा मापा जानेवाला सकल क्रेडिट जोखिम यह दर्शाता है कि इससे विदेशी बैंकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अन्य बैंक समूहों (सारणी 5.9) को यह प्रभावित करते हैं। गंभीर जोखिम परिदृश्य में विदेशी बैंकों के औसत सीआरएआर में अगली छह तिमाहियों में 287 आधार अंक की गिरावट हुई और यह 13.4 प्रतिशत हो गया लेकिन यह विनियामक अपेक्षाओं के स्तर से अधिक था। गंभीर दबाव परिदृश्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के भी ऋण पोर्टफोलियो पर इसी प्रकार समान प्रभाव परिलक्षित होगा, जिसके परिणामस्वरूप इन समूहों का सीआरएआर नीचे हो सकता है। तथापि, गंभीर जोखिम परिदृश्य के तहत भी सीआरएआर विनियामक अपेक्षाओं के स्तर से अधिक रहता है।

सारणी 5.6: विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हुए अनुमानित सकल एनपीए अनुपात

(कुल अग्रिम का प्रतिशत)

	दिसं -11	मार्च -12	मार्च -13
बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) लॉगिट प्रतिगमन			
बेसलाइन	2.89	3.05	3.37
कम	2.89	3.05	3.85
मध्यम	2.89	3.05	5.00
गंभीर	2.89	3.05	5.49
बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) प्रतिगमन			
बेसलाइन	2.72	2.97	3.19
कम	2.73	3.07	3.75
मध्यम	2.74	3.14	4.39
गंभीर	2.75	3.16	4.73
वीआर (वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव)			
बेसलाइन	2.71	2.96	3.46
कम	2.71	3.03	4.26
मध्यम	2.71	3.05	5.17
गंभीर	2.71	3.08	5.78

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

सारणी 5.7: विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हुए अनुमानित सीआरएआर

(कुल अग्रिम का प्रतिशत)

	दिसं -11	मार्च -12	मार्च -13
बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) लॉगिट प्रतिगमन			
बेसलाइन	13.19	12.57	11.09
कम	13.19	12.57	11.03
मध्यम	13.19	12.57	10.91
गंभीर	13.19	12.57	10.86
बहुविधअंतर (मल्टीवैरिएट) प्रतिगमन			
बेसलाइन	13.21	12.59	11.11
कम	13.21	12.58	11.06
मध्यम	13.21	12.57	11.00
गंभीर	13.21	12.57	10.96
वीआर (वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव)			
बेसलाइन	13.21	12.59	11.08
कम	13.21	12.58	11.01
मध्यम	13.21	12.57	10.92
गंभीर	13.21	12.57	10.85

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

सारणी 5.8 : बैंक समूहवार अनुमानित एनपीए (मल्टीवैरिएट पैनल प्रतिगमन)

(कुल अग्रिम का प्रतिशत)

	दिसं -11	मार्च -12	मार्च -13	दिसं -11	मार्च -12	मार्च -13
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		
बेसलाइन	2.86	2.97	3.25	2.39	2.56	3.24
कम	2.92	3.11	3.80	2.45	2.70	3.79
मध्यम	2.95	3.23	4.39	2.48	2.82	4.38
गंभीर	2.97	3.32	4.78	2.51	2.91	4.77
	निजी क्षेत्र के नए बैंक			विदेशी बैंक		
बेसलाइन	2.82	2.83	3.03	2.76	3.15	4.48
कम	2.88	2.97	3.57	2.82	3.29	5.00
मध्यम	2.91	3.09	4.15	2.85	3.41	5.57
गंभीर	2.94	3.18	4.53	2.87	3.50	5.94

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

सेक्टोरल ऋण जोखिम : खाद्य प्रसंस्करण, अभियंत्रण और लौह व स्टील सेक्टरों पर अपेक्षाकृत उच्च प्रभाव

5.42 एनपीए (अनर्जक आस्तियों) में परिवर्तन द्वारा मापा गया सेक्टोरल ऋण जोखिम बताता है कि आठ प्रमुख सेक्टरों में खाद्य प्रसंस्करण, अभियंत्रण और लौह व स्टील सेक्टरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है (सारणी 5.10)। इस समष्टिगत दबाव परीक्षण विश्लेषण में कृषि क्षेत्र में एनपीए (अनर्जक आस्तियों) पर प्रभाव बेहद कम लगता है। ऐसा ही प्रभाव आधारभूत संरचना क्षेत्र में एनपीए (अनर्जक आस्तियों) के लिए देखा गया है।

सारणी 5.9 : बैंक समूहवार अनुमानित एनपीए (मल्टीवैरिएट पैनल प्रतिगमन)

(प्रतिशत)

	दिसं -11	मार्च -12	मार्च -13	दिसं -11	मार्च -12	मार्च -13
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		
बेसलाइन	12.05	11.41	10.06	12.85	12.12	10.83
कम	12.04	11.40	10.01	12.84	12.10	10.76
मध्यम	12.04	11.38	9.95	12.84	12.09	10.67
गंभीर	12.03	11.37	9.91	12.83	12.07	10.62
	निजी क्षेत्र के नए बैंक			विदेशी बैंक		
बेसलाइन	16.28	15.67	13.76	15.61	15.35	13.52
कम	16.28	15.65	13.70	15.61	15.34	13.48
मध्यम	16.27	15.64	13.63	15.60	15.33	13.44
गंभीर	16.27	15.63	13.58	15.60	15.32	13.41

स्रोत: पर्यवेक्षी व ब्लूमबर्ग डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

सारणी 5.10: अनुमानित सेक्टोरल एनपीए

(कुल अग्रिम का प्रतिशत)

सेक्टर	मार्च-12				मार्च-13			
	बेसलाइन	निम्न जोखिम	मध्यम जोखिम	गंभीर जोखिम	बेसलाइन	निम्न जोखिम	मध्यम जोखिम	गंभीर जोखिम
कृषि	4.06	4.11	4.20	4.32	3.70	3.89	4.24	4.72
खाद्य प्रसंस्करण	5.82	6.31	7.13	8.29	6.81	8.40	12.18	15.75
निर्माण	2.64	2.66	2.81	3.01	3.00	3.09	3.63	4.35
सीमेंट	2.57	2.57	2.57	2.57	3.27	3.78	5.12	6.95
आधारभूत संरचना	0.67	0.71	0.80	0.91	0.72	0.88	1.43	2.16
लौह व स्टील	3.69	3.95	4.38	4.99	4.43	5.42	7.28	9.87
अभियंत्रण	3.36	3.63	4.09	4.73	3.80	4.82	6.65	9.13
ऑटोमोबाइल	1.68	1.68	1.68	1.68	2.03	2.37	3.19	3.94
अन्य	3.03	3.11	3.24	3.42	3.08	3.38	3.98	4.80

स्रोत: पर्यवेक्षी डाटा और आरबीआई स्टाफ गणना

निष्कर्ष

5.43 वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम का आकलन करने के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला का लक्ष्य कई प्रकार के मॉडलिंग ढ़ांचों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रणालीगत घटनाओं और जोखिमों का अभिग्रहण करना है।

5.44 प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण ने प्रणालीगत स्थिरता के लिए जोखिम पर बाज़ार के सहभागियों के एक बड़े हिस्से का इनपुट प्रदान किया। प्रतिक्रिया देने वालों ने बैंक की आस्ति गुणवत्ता में ह्रास को वित्तीय प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम और उसके बाद विनिमय दर अस्थिरता, वैश्विक जोखिमों, उच्च महंगाई से जुड़ी जोखिमों और उच्च ब्याज दरों सहित बाज़ार की बढ़ती हुई अस्थिरता के रूप में चिन्हित किया। इसके बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के बारे में उनका आत्मविश्वास उचित रूप से बना रहा। प्रणालीगत चलनिधि संकेतक दर्शाते हैं कि चलनिधि संबंधी स्थितियां हाल के महीनों में मजबूत हो गई हैं। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के नेटवर्क की संरचना टियरयुक्त है लेकिन अंतर बैंक देयताओं पर सीमाएं संक्रमण जोखिमों को कम करती हैं। बैंकों के बीच संकट निर्भरता का कम होना जारी है।

5.45 इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में वर्णित प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन संबंधी पहलों की श्रृंखला विवेकदर्शी निगरानी की समग्र प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यदि आवश्यक हो तो खरीद पूर्व नीति कार्रवाई के द्वारा बढ़ती भेद्यता और अधिकताओं को पहचानने, मापने और उसका प्रबंध करने का प्रयास करता है। तथापि, प्रणालीगत जोखिमों की आंतरिक जटिलताओं और प्रणालीगत जोखिम पर सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य अनुसंधान अभी भी अपने विकास के आरंभिक चरण में होने के कारण ऐसा करने के बजाय कहना आसान है। यह सब स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रकार के जोखिमों या यहाँ तक कि हमेशा की परिशुद्धता के साथ केवल एक प्रकार के जोखिम के लिए प्रणालीगत जोखिमों के एकल उपाय की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं होगा। यह, इसके बदले में, समष्टिगत विवेकदर्शी प्राधिकारियों के लिए *''वित्तीय प्रणाली के विभिन्न भागों में प्रणालीगत जोखिम के विभिन्न पहलुओं को समाहित करने वाले टूल्स और उपायों की व्यापक रेंज का निर्माण करने, जिसमें प्रत्येक टूल की अपनी विशिष्ट उद्देश्य, फायदे और सावधानियां हैं जिन्हें इसके परिणामों की व्याख्या करते समय हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए''* [12] की आवश्यकता को सृजित करता है। इस अध्याय में प्रस्तुत मॉडलों/उपायों की श्रृंखला के साथ-साथ इस रिपोर्ट के दूसरे अध्यायों में प्रस्तुत स्थिरता संकेतकों/मानचित्रों की श्रृंखला प्रणालीगत जोखिमों को विभिन्न आयामों और परिप्रेक्ष्यों से आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर किए गए प्रयासों को दर्शाते हैं।

[12] ''इम्प्लिमेंटिंग ए मैक्रोप्रूडेंशिएल फ्रेमवर्क: ब्लेंडिंग बोल्डनेस एंड रियलिज्म'' क्लाउडिया बोरियो. बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जुलाई 2010।

परिशिष्ट

कार्यविधियाँ

वित्तीय स्थिरता मैप और संकेतक

वित्तीय स्थिरता मैप और संकेतक, भारतीय वित्तीय व्यवस्था में समग्र स्थिरता स्थिति को दर्शाते हैं। वित्तीय स्थिरता संकेतक (एफएसआई) तीन मुख्य संकेतकों, नामत: व्यष्टि स्थिरता संकेतक (एमएसआई), वित्तीय बाज़ार स्थिरता संकेतक (एफएमएसआई) और बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई) पर आधारित होते हैं। एमएसआई, एफएमएसआई और बीएसआई के साधारण औसत से एफएसआई निकाला गया है। एमएसआई, एफएमएसआई और बीएसआई के परिकलन की कार्यविधियां नीचे बतायी गई हैं।

व्यष्टिआर्थिक स्थिरता मैप और संकेतक

व्यष्टिआर्थिक स्थिरता संकेतक (एमएसआई) सात उप-संकेतकों पर आधारित होता है। प्रत्येक उप-संकेतक व्यष्टिआर्थिक जोखिम के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होता है। व्यष्टिआर्थिक जोखिम के प्रत्येक उप-संकेतक में उस क्षेत्र में जोखिमों को दर्शाने वाले चयनित मानदंड समाहित होते हैं। व्यष्टिआर्थिक या वित्तीय चर-कारकों (वैरिएब्ल्स) यथा; जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों अथवा बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता पर इन उप-संकेतकों के समुचित प्रभावों का आकलन करके इन उप-संकेतकों को प्रमाणिक बनाया गया है। समग्र व्यष्टिआर्थिक स्थिरता सूचकांक के इन सात उप-संकेतकों और उनके घटकों का नीचे वर्णन किया गया है।

वैश्विक जोखिम सूचकांक

वैश्विक जोखिम सूचकांक, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक परिणामों और कीमतों पर आधारित होता है। वास्तविक परिणामों के मामले में, यू.एस., यूरो क्षेत्र और जापान के जीडीपी की वृद्धि दरों के भारित औसत के आधार पर एक संमिश्र सूचकांक तैयार किया गया है। इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हुए, इन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के लिए भी एक सूचकांक तैयार किया गया। जीडीपी सूचकांक को आरोही क्रम में रखा गया है जबकि मुद्रास्फीति सूचकांक को अवरोही क्रम में रखा गया है। वैश्विक जोखिम सूचकांक, इन समान भार वाले सूचकांकों से तैयार एक संमिश्र सूचकांक है।

बाह्य भेद्यता

बाह्य भेद्यता चालू खाता घाटा/जीडीपी, चालू भुगतान/चालू प्राप्तियों, औसत मासिक आयातों/रिज़र्व, कुल ऋणों में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा, ऋण स्टॉक-जीडीपी अनुपात, ऋण सेवा अनुपात पर अधारित होती है।

राजकोषीय भेद्यता

पहले, केंद्रीय और राज्य सरकारों के सकल प्राथमिक घाटा (जीपीडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और कुल देयताओं के आधार पर एक राजकोषीय दबाव का सूचकांक तैयार किया जाता है। यह मोटे तौर पर बाल्डाकी, मैह्यूग और पेटरोवा (2011) तथा बाल्डाकी, पेटरोवा, बेलहोसिन, डोबरेस्कू और मैजरानी (2011) के दो आईएमएफ वर्किंग पेपरों में सुझाई गई कार्यविधि पर आधारित है। राजकोषीय जोखिमों में परिवर्तन को आंकने के लिए, जीएफडी और जीपीडी के इस तरह निकाले गए भारों को महालेखाकार के कार्यालय से प्राप्त जीपीडी और जीएफडी के ताजे आँकड़ों पर लागू किया गया।

विकास

घरेलू विकास का अनुमान करने के लिए, कई चर-कारकों यथा; निर्यात/जीडीपी, महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास, जीएफसीएफ/जीडीपी, रियल बैंक क्रेडिट, पीएमआई और यील्ड कर्व (दस वर्ष वाले यील्ड और एक वर्ष वाले यील्ड के बीच अंतर) के साथ विकास के संबंधों की पड़ताल की गई। इन चर-कारकों में से, यील्ड कर्व और पीएमआई -विनिर्माण विकास के सबसे सटीक संकेतक पाये गए।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति का अनुमान तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन, विनिमय दरों और वैश्विक मुद्रास्फीति पर आधारित है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र

कॉर्पोरेट क्षेत्र की सेहत का अंदाजा मुनाफे (प्रॉफिट मार्जिन) से लगाया जाता है। इस क्षेत्र से निकलने वाले जोखिमों का इस क्षेत्र से प्रतिलोमी संबंध होता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र का वित्तीय क्षेत्र से संबंध पता लगाने के लिए, कॉर्पोरेट क्षेत्र के सूचकांक में बिक्री में ब्याज के अंश की भी पड़ताल की जाती है।

घरेलू क्षेत्र

परिवारों की ऋणग्रस्तता संबधी नियमित आँकड़ों के अभाव में, घरेलू क्षेत्र पर बैंक के बकाया ऋण यथा; खुदरा ऋण को ही घरेलू ऋणग्रस्तता का अनुमान मान लिया जाता है। साथ ही, वैयक्तिक व्यय-योग्य आय के आँकड़ों की उपलब्धता में देरी को देखते हुए, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) को ही इसके अनुमान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन दो चर-कारकों के आधार पर, घरेलू क्षेत्र का सूचकांक घरेलू क्षेत्र से उभरने वाले जोखिमों का जायजा लेने का प्रयास करता है।

वित्तीय बाज़ार स्थिरता मैप और संकेतक

वित्तीय बाज़ार की स्थिरता मापने के उद्देश्य से, वित्तीय बाज़ार स्थिरता मैप और संकेतक (एफएमएसआई) तैयार किया गया है, जो चार क्षेत्रों/बाज़ारों नामत: बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी मुद्रा बाज़ार, ईक्विटी बाज़ार और ऋण बाज़ार के संकेतकों पर आधारित है। विभिन्न क्षेत्रों/बाज़ारों से चयनित संकेतक निम्नानुसार हैं: i) बैंकिंग क्षेत्र: CNXBANK सूचकांक और निफ्टी सूचकांक का बैंकिंग बीटा, सीडी दर तथा सीडी दर घटाव अभिप्रेत वायदा दर। ii) विदेशी मुद्रा बाज़ार: रोजाना रुपया-डॉलर विनिमय दर का CMAX, जो X_t/Max (X_i, $i \in$ 1,2.., एक वर्ष तक) के रूप में पारिभाषित है, जहां X_t, t समय पर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल पर रुपया-डॉलर विनिमय दर है। iii) ईक्विटी बाज़ार: निफ्टी CMAX और इंडिया VIX का विलोम, और iv) ऋण बाज़ार: कॉर्पोरेट बांड, जो A, AA और AAA श्रेणी वाले कॉर्पोरेट बांड के प्रतिलाभ, 10-वर्षीय गवर्नमेंट बांड के प्रतिफल और सीपी दर का औसत है।

इन सभी संकेतकों के सम्मिलित करने के लिए वैरिएंस-इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया गया है।

पहले स्तर पर, इन चार चयनित क्षेत्रों/बाज़ारों के इन चार संकेतकों को बुनियादी संकेतकों के साधारण औसत के आधार पर तैयार किया गया था, और बाद में पहले स्तर पर निकाले गए इन चार संकेतकों के साधारण औसत को आधार बनाकर एफएमएसआई निकाला गया। हर दिन के आँकड़ों के आधार पर एफएमएसआई का आकलन किया जाता था।

इसके बाद, एफएमएसआई का पूर्वानुमान मासिक एफएमएसआई के आधार लगाय जाने लगा, जो हर दिन के एफएमएसआई, ऋण वृद्धि, WPI-विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति और REER का मासिक औसत है, जो निम्नलिखित रिग्रेशन समीकरण का प्रयोग कर निकाला जाता है:

$$FMSI_t = \alpha + \beta_1 * FMSI_{t-1} + \beta_2 * FMSI_{t-2} + \beta_3 * Credit\ Growth_{t-1} +$$
$$\beta_4 * Inflation(Manufactured\ Products)_{t-1} + \beta_5 * DL(REER)_{t-4} + u_t$$

बैंकिंग स्थिरता मैप और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मैप और संकेतक (बीएसआई) एफएसआर दिसंबर 2010 में शुरू किए गए थे, ताकि उन पाँच आयामों में बदलावों का समग्र आकलन किया जा सके जिनका बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर असर पडता है। इन पाँच में से प्रत्येक आयाम के लिए अन्य चर-कारको को शामिल करके इसकी कार्यविधि को और अधिक बेहतर बनाया गया था, जिनको एफएसआर, जून 2011 में प्रस्तुत किया गया था। प्रत्येक संमिश्र सूचकांक को तैयार करने के लिए निम्नलिखित अनुपात प्रयोग में लाए गए थे:

सारणी : बैंकिंग स्थिरता मैप और बैंकिंग स्थिरता संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त संकेतक

आयाम	अनुपात			
सुदृढ़ता	सीआरएआर	टियर-I पूँजी- टियर-II पूँजी	लिवरेज अनुपात कुल आस्तियाँ- पूँजी और रिज़र्व	
आस्ति-गुणवत्ता	निवल अनर्जक आस्तियां- कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां- कुल अग्रिम	निम्नस्तरीय अग्रिम- सकल अनर्जक आस्तियाँ	पुनर्गठित स्तरीय अग्रिम - स्तरीय अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर लाभ	निवल मुनाफा मार्जिन	मुनाफे में वृद्धि	
नकदी	नकदी आस्तियाँ- कुल आस्तियाँ	ग्राहक-जमा- कुल आस्तियाँ	गैर-बैंकीय अग्रिम-ग्राहक-जमा	एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली जमा- कुल जमा
क्षमता	लागत- आय	कारोबार (ऋण + जमा)-कुल कर्मचारी		

ये पाँच संमिश्र संकेतक सुदृढ़ता, आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता, नकदी, क्षमता के पाँच आयाम प्रस्तुत करते हैं। बैंक के कारोबार को दर्शाने वाला प्रत्येक सूचकांक का मान शून्य (न्यूनतम) से एक (अधिकतम) के बीच होता है। प्रत्येक सूचकांक, इसको तैयार करने के लिए प्रयुक्त

नमूना अवधि के दौरान एक सापेक्षिक पैमाना है, जहाँ उच्च मान का अर्थ है कि उस आयाम में जोखिम ज्यादा है। इसलिए किसी आयाम विशेष में सूचकांक के मान में वृद्धि, अन्य अवधियों की तुलना में उस अवधि विशेष में उस आयाम के जोखिम में बढ़ोतरी दर्शाती है। किसी आयाम हेतु प्रयुक्त प्रत्येक सूचकांक के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के लिए भारित औसत निकाला जाता है, जहाँ भार कुल बैंकिंग सिस्टम की आस्तियों में किसी एक बैंक की आस्तियों का अनुपात हैं। प्रत्येक सूचकाकं को दी-गई-तारीख-को-अनुपात घटाव नमूना-अवधि-में-न्यूनतम-मान को नमूनावधि-में-अधिकतम-मान घटाव नमूना-अवधि-में- न्यूनतम-मान से भाग देकर नमूना अवधि के लिए नियमित (नॉर्मलाइज्ड) किया जाता है। किसी आयाम के लिए प्रयुक्त नियमित (नॉर्मलाइज्ड) अनुपातों के भारित औसत के रूप में उस आयाम के एक संमिश्र पैमाना की गणना की जाती है, जहाँ ये भार CAMELS रेटिंग हेतु मूल्यांकन में दिए गए अंकों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक आयाम के वैयक्तिक संमिश्र सूचकांकों के आधार पर, इन पांच संमिश्र उप-सूचकांकों के औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक तैयार किया जाता है।

मौजूदा मैप और संकेतक के लिए, मार्च 2006 से सितंबर 2011 तक को मूल्यांकन की नमूना अवधि के रूप में लिया गया था। ऑटो रिग्रेसिव मुविंग एवरेज (ARMA) पद्धति का प्रयोग करते हुए बीएसआई का पूर्वानुमान किया गया था।

एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण- तनाव परीक्षण

तिमाही निगरानी के अंग के रूप में, ऋण, ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा और नकदी जोखिम को शामिल करते हुए तनाव परीक्षण किए जाते हैं। इन झटकों के प्रति वाणिज्य बैंकों के लचीलेपन का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शामिल किया जाता है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण जोखिम के मामले में एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया जाता है।

ऋण जोखिम

बैंकों की मजबूती का अनुमान लगाने के लिए, एनपीए स्तर में बढ़ोतरी करके उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो को झटका दिया गया, जिसमें पूरे पोर्टफोलियों के साथ-साथ कुछ चयनित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। इसके साथ ही, प्रवाधान-आवश्यकताओं में भी समानांतर बढ़ोतरी की गई। ऋण-संकेंद्रण जोखिम (क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क) जाँचने के लिए, शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं तथा सबसे बड़े समूह उधारकर्ता की चूक (डिफॉल्ट) को गणना के लिए लिया जाता है। इस प्रकार गणना करके अनुमानित प्रावधान-आवश्यकताओं को पहले बैंकों के लाभ में से समायोजित किया गया और अवशिष्ट प्रावधान-आवश्यकताओं, यदि हो, को बैंकों की पूँजी से घटाया गया।

सितंबर 2011 की तिमाही के पर्यवेक्षी आँकड़ों के आधार पर, हरेक बैंक के स्तर और सभी बैंकों को मिलाकर समग्र स्तर पर विश्लेषण किया गया। जो परिदृश्य सामने आया उसमें एनपीए के मौजूदा स्टॉक में स्तरीय, निम्नस्तरीय और संदेहास्पद/डूबने वाले अग्रिमों के लिए क्रमशः 50, 100 और 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित की गई और इनके लिए प्रावधान-आवश्यकताओं में क्रमशः 1 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित की गई। एनपीए की अनुमानित बढ़ोतरी को स्तरीय, निम्नस्तरीय और संदेहास्पद/डूबने वाले अग्रिमों में ठीक उसी अनुपात में संवितरित किया गया जिस अनुपात में वे मौजूदा स्टॉक में थे। अतिरिक्त प्रावधान-आवश्यकताओं को क्रेडिट पोर्टफोलियो के परिवर्तित रूप पर लागू किया गया।

ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम

ईक्विटी मूल्यों में परिवर्तन, रुपये (INR) के अधिमूल्यन/मूल्यह्रास, आईएनआर यील्ड कर्व में बदलाव के कारण पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट या आय में घाटे को, दिए गए झटके के परिणामस्वरूप, बैंकों को हुए कुल घाटे के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार निकाले गए कुल घाटे को पहले बैंकों के लाभ में से समायोजित किया गया और अवशिष्ट प्रावधान-आवश्यकताओं, यदि हों, को बैंकों की पूँजी से घटाया गया।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम के लिए, दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए गए: (1) आय संबंधित दृष्टिकोण (इनकम अप्रोच), जो बैंकों के अर्जन को आईएनआर यील्ड कर्व में बदलाव के कारण प्रभावित करता है और (2) अवधि अंतर विश्लेषण (ड्यूरेशन गैप अनालिसिस), जो मूल्य निर्धारण प्रभाव (पोर्टफोलियो घाटे) की गणना करता है। इंटरेस्ट बियरिंग एक्सपोजर गैप पर, आय में घाटे को एक वर्ष के लिए प्रत्येक टाईम बकेट के लिए, अलग-अलग परिकलित किया जाता है। इंटरेस्ट बियरिंग एक्सपोजर गैप पर, पोर्टफोलियो घाटे को, प्रत्येक टाईम बकेट के लिए, अवधि अंतर विश्लेषण (ड्यूरेशन गैप अनालिसिस) का प्रयोग कर परिकलित किया जाता है। ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर झटकों के लिए, व्याज-धारी आस्तियों पर हरेक टाईम बकेट के लिए, ड्यूरेशन अप्रोच का प्रयोग कर, मूल्य निर्धारण संबंधी घाटे परिकलित किए जाते हैं।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि तनाव जांचों का लक्ष्य बाहरी चलनिधि की सहायता के बिना, अप्रत्याशित चलनिधि निकास का सामना करने की बैंक की क्षमता का विश्लेषण करना है। सितंबर 2011 के अंत तक की स्थिति में यह मूल्यांकन किया गया। यह दृश्य, जमाकर्ताओं का विश्वास आकस्मिक रूप से खो जाने के कारण अप्रत्याशित जमा आहरणों के विभिन्न अनुपात (जमाराशियों के प्रकार पर आधारित) और उनके निधीयन के लिए उपलब्ध चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता का विश्लेषण दर्शाता है। चल आस्तियों की दो विभिन्न परिभाषाएं मानी गयी हैं।

- पहली परिभाषा के अनुसार चल आस्तियों में नकदी निधि, रिज़र्व बैंक के पास रखे बकाया अतिरिक्त आरक्षित नकदी निधी अनुपात (सीआरआर), अन्य बैंकों के पास बकाया और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश।
- दूसरी परिभाषा मानती है कि चल आस्तियों में नकदी निधि, रिज़र्व बैंक के पास रखे बकाया अतिरिक्त सीआरआर, अन्य बैंकों के पास रखी बकाया राशि, जो एक महीने में देय है और एक महीने में परिपक्व होनेवाले निवेश।
- यह माना गया है कि बैंक, चल आस्तियों की बिक्री के माध्यम से जमाराशियों का दबावपूर्ण आहरण पूरा करेंगे।
- निवेशों की बिक्री उनके बाज़ार मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से की गयी है।
- यह तनाव जांच स्थिर (STATIC) तरीके से की गयी है।

शहरी सहकारी बैंक-ऋण जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण जोखिम पर तनाव जांच जून 2011 के अंत तक की अवधि के लिए उनके आस्ति संविभाग का इस्तेमाल करते हुए की गयी। ये जांच एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। सीआरआर पर प्रभाव का तीन विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत अध्ययन किया गया। अनुमानित परिदृश्य निम्नानुसार थे :

परिदृश्य I:

- आघात का प्रयोग : कुल अनर्जक आस्तियों में 50% वृद्धि
- प्रावधानन आवश्यकता में 50% वृद्धि
- अतिरिक्त प्रावधानों से पूंजी (टियर I और II) में कटौती

परिदृश्य II

- आघात का प्रयोग : कुल अनर्जक आस्तियों में 100% वृद्धि
- प्रावधानन आवश्यकता में 100% वृद्धि
- अतिरिक्त प्रावधानों से पूंजी (टियर I और II) में कटौती

परिदृश्य III

- आघात का प्रयोग : प्रतिकूल मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के कारण सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का नुकसान या शून्य लाभ (कोई लाभ नहीं)
- जिन बैंकों ने लाभ संबंधी रिपोर्ट किया, उनके मामले में पूंजी (टियर I और II) में लाभ की राशि कम हुई (नुकसान संबंधी रिपोर्ट किया हो तो कोई परिवर्तन नहीं)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनडी- एसआइ) ऋण जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जमाराशि न लेनेवाली और प्रणालीगत (सिस्टीमिकली) महत्वपूर्ण के ऋण जोखिम पर तनाव जांच मार्च 2011 के अंत तक की अवधि के लिए उनके आस्ति संविभाग का इस्तेमाल करते हुए की गयी। ये जांच एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। सीआरआर पर प्रभाव का दो विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत अध्ययन किया गया। इस परिदृश्य से अनर्जक आस्तियों के विद्यमान स्टॉक में 200 और 500 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। अनर्जक आस्तियों में यह अनुमानित वृद्धि अनर्जक आस्तियों

के विद्यमान स्टॉक के प्रचलन के अनुसार सब-स्टैंडर्ड, संदेहास्पद और नुकसान श्रेणी में उसी अनुपात में बांटी गयी। चालू पूंजी स्थिति से अतिरिक्त प्रावधानन आवश्यकता का समायोजन किया गया।

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक बाजार के विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार संकेतकों का प्रयोग करता है:

1. भारित औसत मांग दर-भारतीय रिज़र्व बैंक रेपो दर
2. 3 माह के वाणिज्य पेपर दर-3 माह के जमा प्रमाणपत्र दर
3. 3 माह के जमा प्रमाणपत्र दर-3 माह के निहित जमाराशि दर
4. भारित औसत मांग दर-3 माह के ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप दर

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक तैयार करने के लिए चार विभिन्न प्रणालियां, अर्थात् सापेक्ष अंतर, स्डैंडर्ड नॉर्मल, प्रिंसिपल कॉम्पोनंट विश्लेषण, पर्सेंटाइल रैंक्स पर विचार किया गया। भारत के लिए स्डैंडर्ड नॉर्मल या वेरियेंस इक्वल भारित प्रणाली अधिक उचित समझी गयी है।

मैक्रोफाइनान्शियल तनाव जांच

बैंकों का लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक परिवर्ती वस्तुओं के कार्य के रूप में ऋण जोखिम मॉडेल तैयार किया गया। ऋण जोखिम तनाव जांच की गणना ऐसे विविध इकॉनॉमैट्रिक मॉडलों का इस्तेमाल कर की गयी, जो बैंकिंग प्रणाली से मैक्रोइकॉनॉमिक परिवर्ती वस्तुओं से संबंधित हो, जैसे (i) सकल प्रणाली के अनर्जक आस्तियों के आंकडों की बहुपरिवर्तनशील लॉगिट गिरावट (ii) गिरावट अनुपात (नयी अनर्जक आस्तियों का प्रवाह) की दृष्टि से बहुपरिवर्तनशील परावर्तन (iii) गिरावट अनुपात का इस्तेमाल कर सकल वीएआर (iv) बैंक-वार गिरावट आंकडों पर बहुपरिवर्तनशील पैनल परिवर्तन, जो बाद में बैंक समूहों में एकत्रित किया गया और (v) सकल क्षेत्रीय अनर्जक आस्तियों के लिए बहुपरिवर्तनशील परावर्तन। कुल बैंकिंग प्रणाली में कुल अनर्जक आस्तियों (अनर्जक आस्ति अनुपात) का चालू और पिछला मूल्य तथा नयी अनर्जक आस्तियोँ का प्रवाह (गिरावट अनुपात) शामिल है तथा मैक्रोइकॉनॉमिक परिवर्तनशील वस्तुओं में सकल देशी उत्पाद वृद्धि, अल्पावधि ब्याज दर (मांग दर) थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, निर्यात - सकल देशी उत्पाद अनुपात $\left(\frac{Ex}{GDP}\right)$ और REER का समावेश शामिल है।

मॉडलिंग ढांचा

कुल अनर्जक आस्ति / गिरावट अनुपात (एसआर)[1] पर मैक्रोइकॉनॉमिक आघातों के असर का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बहुपरिवर्तनशील मॉडल चलाये गये :[1]

- कुल बैंकिंग प्रणाली बहुपरिवर्तनशील लॉगिट[2] परावर्तन:

$$logit_npa_t = \alpha_1 + \beta_1\, logit_npa_{t-1} + \beta_2\, \Delta AgriGDP_{t-2} + \beta_3\, \Delta IndustryGDP_{t-2} + \beta_4\, TBill_{t-2} + \beta_5 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-2}$$

- कुल बैंकिंग प्रणाली बहुपरिवर्तनशील परावर्तन:

  समस्त वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए सकल स्तर पर गिरावट अनुपात का विश्लेषण किया गया

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1\, SR_{t-1} + \beta_2\, \Delta GDP_{t-2} + \beta_3\, Call_{t-1} + \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \Delta WPI_t$$

- वेक्टर ऑटोरिग्रेसेव (वीएआर):

  विभिन्न मैक्रोइकॉनॉमिक आघातों पर बैंकों के लचीलेपन का अनुमान लगाने के लिए वेक्टर ऑटोरिग्रेसेव (वीएआर)[3] दृष्टिकोण

---

[1] स्लिपेज अनुपात, निर्यात/सकल देशी उत्पाद और मांग दर सामयिकता से समायोजित किये गये हैं।

[2] विस्तृत मॉडल विशेषताओं के लिए कृपया दिसंबर 2010 का एफएसओ देखें। एनपीए कए लॉगिट ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा इसतरह की गयी है:

$$Logit_npa_t = L(NPA_t) = Ln\left(\frac{NPA_t}{1-NPA_t}\right)$$

[3] VAR मॉडल की विस्तृत विशेषताओं के लिए कृपया जून 2011 का एफएसआर देखें।

अपनाया गया है। इस वीएआर मॉडल का फायदा यह है कि वह मैक्रोइकॉनॉमिक परिवर्ती वस्तुओं और बैंकों के स्थिरता वेरिएबल के बीच पारस्परिक प्रभाव को पूर्ण रूप से परिग्रहण करने की अनुमति देता है। साथ ही वह अपरिवर्तनीय फीडबैंक प्रभाव भी प्राप्त करता है।

आनुमानिक फॉर्म में ऑर्डर पी (वीएआर) (p) के mean-adjusted वीएआर को इस तरह लिखा जाता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + ... + A_p y_{t-p} + u_t;\ t = 0,1,2,3,...$$

जहां t समय पर $y_t = (y_{1t},......,y_{Kt})'$ (K×1) वेक्टर चर, A_i (i=1,2,...p) स्थिर (K x K) कोइफिशियंट मेट्रिक्स तथा $u_t = (u_{1t},......,u_{Kt})'$ K- डैमेन्शलन वाईट नोईस या नवीनता प्रक्रिया है

न्यूनतम जानकारी मापदंड तथा अन्य निदान-शास्त्र के आधार पर वीएआर का यथोचित ऑर्डर दो पाया गया। तदनुसार वीएआर ऑफ ऑर्डर 2 (वीएआर (2)) का अनुमान लगाया गया तथा एआर कैरेक्टरीस्टिक बहुपदी के आधार पर मॉडल की स्थिरता की जांच की गयी। चूंकि सभी आधार यूनिट सर्कल के अंदर पाये गये, चयनित किया गया यह मॉडल स्थिरता की शर्त पूरी करता है। चयनित वीएआर की प्रेरणा प्रतिक्रिया कार्य का इस्तेमाल कर विभिन्न मैक्रोइकॉनॉमिक आघातों का प्रभाव निश्चित किया गया।

- बैंक-वार पैनल निर्धारित प्रभाव परावर्तन

  बैंक-वार पैनल परावर्तन का स्वरूप तैयार किया गया, जहां स्लिपेज अनुपात को मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभावित करने वाली वस्तुओं के कार्य के रूप में माना गया। बैंक प्रभाव की समग्र मॉडल विशिष्टताओं के साथ पहचान की गयी। बैंक-वार अनुमानों को एकत्रित कर बैंक समूह-वार परिणाम प्राप्त किये गये।

$$SR_{it} = \alpha_i + \beta_1\ SR_{i(t-1)} + \beta_2\ \Delta GDP_{t-1} + \beta_3\ Call_{t-4} + \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_t + \beta_5 \Delta WPI_t$$

  जहां α_i बैंक विशिष्ट पैरामीटर है।

- क्षेत्रीय बहुचर परावर्तन :

  हर क्षेत्र के लिए स्वतंत्र रूप से कुल अनर्जक आस्ति अनुपात का प्रयोग करते हुए बहुचर परावर्तन का इस्तेमाल कर विभिन्न क्षेत्रों पर मैक्रोइकॉनॉमिक आघातों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। प्रभावित करने वाली संश्रित वस्तुओं में पिछड़ी हुई अनर्जक आस्तियां, क्षेत्रीय सकल देशी उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर समाविष्ट हैं।

स्लिपेज अनुपातों से अनर्जक आस्तियों और सीआरएआर की व्युत्पत्ति जो उपर्युक्त ऋण जोखिम इकॉनॉमैट्रिक मॉडलों से अनुमानित है, निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थी: 18 प्रतिशत ऋण वृद्धि, 6 प्रतिशत वसूली दर, बट्टे खाते कुछ नहीं, जोखिम भारित परिसंपत्ति वृद्धि 20 प्रतिशत और लाभ वृद्धि 10 प्रतिशत। यह माना गया है कि नियामक पूंजी वृद्धि न्यूनतम रहेगी यह समझते हुए लाभ के 25 प्रतिशत का आरक्षित खाते में अनिवार्य अंतरण होगा। विभिन्न उप-श्रेणियों में नयी अनर्जक आस्तियों का वितरण अनर्जक आस्तियों के विद्यमान स्टॉक में प्रचलित तरीके से किया गया। अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लेए प्रावधानन आवश्यकता मानक अग्रिमों के लिए 0.4 प्रतिशत उप मानक अग्रिमों के लिए 10 प्रतिशत, संदेहास्पद अग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत और हानि अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत है। अनर्जक अग्रिमों के अनुपात के अनुमानित मूल्य ''तुलनपत्र दृष्टिकोण'' का इस्तेमाल कर पूंजी अनुपातों में परिवर्तित किये गये, जिसके द्वारा तुलनपत्रों की पूंजी पर प्रावधान और निवल लाभों के द्वारा प्रभाव पड़ेगा। यह माना गया है कि भावी प्रभाव के लिए विद्यमान ऋण हानि प्रावधानन व्याप्ति अनुपात स्थायी रहेगा।